**General Budget (2024-2025) ? Demands for Grants- Ministry of Education**

माननीय अध्यक्ष **:** अब सभा में शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग संख्या 25 और 26 को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जायेगा ।

सभा में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर सभापटल पर पर्चियां भेज दें, जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

इस प्रकार प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली सूची कुछ समय पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी । यदि सदस्यों को उस सूची में कोई विसंगति मिले तो वे उसकी सूचना तत्काल सभापटल पर मौजूद अधिकारी को दे सकते हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तम्भ में मांग संख्या 25 और 26 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों के भुगतान के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाए ।?

**Demands for Grants, 2024-2025 in respect of the Ministry of Education submitted to the Vote of Lok Sabha**

**No. of Demand Name of Demand Amount of Demand for Grant submitted to the**

**vote of the House**

**Revenue Capital**

25-Department of School Education and Literacy 127874,34,00,000 76,00,000

26-Department of Higher Education 63309,20,00,000 11,06,00,000

....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** श्री तेजस्वी सूर्या ।

श्री तेजस्वी सूर्या **(**बंगलौर दक्षिण**) :** माननीय अध्यक्ष जी, देश के युवाओं से संबंधित और देश के भविष्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष जी, इस बजट का जो सबसे इम्पोर्टेंट फोकस है, वह इस देश के युवाओं के ऊपर है । देश के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आने वाले 50 साल में उनको हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए इस बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं । मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं । इस बजट में चार करोड़ युवाओं को डायेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से सक्षम बनाने की योजना लागू करने के लिए, विजन एवं ब्लूप्रिंट लगाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को देश के युवाओं की ओर से बधाई देना चाहता हूं तथा धन्यवाद देना चाहता हूं ।

**13.26 hrs**

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

Madam Chairperson, over the last ten years there has been a significant improvement in the infrastructure of the country's education system, and in the quality of our education system. Thanks to the multi-dimensional reforms that the Government under hon. Prime Minister Narendra Modi ji has made. It was always felt that under the Governments after Independence with the exception of the Atal Bihari Vajpayee Government, which introduced the Sarva Shiksha Abhiyan, which gave great primacy to improving the quality of our infrastructure in public schools, especially in rural schools our education system was largely neglected. It did not have adequate finance. The syllabus, the curricula was very rigid. I dare say it was out of date, and it was not keeping up with the pace and need of times. It was not accessible, and affordable to all sections of the people. As a result of that, the quality of human resource that the country produced over the last so many years, is painfully low, is painfully inadequate for a country as large as ours.

However, in the last ten years, things have changed drastically, especially the kind of budgetary allocations, the important Ministry of Education has received under the Narendra Modi Government is something spectacular. Madam Chairperson, I would want to draw your attention to the difference in the quantum of funding that our Education Department has received. In 2013-14, the budget of the Higher Education Department was only Rs. 26,750 crore for a country as large as ours.

Today, ten years hence, the Education Ministry's budget has increased by 78 per cent under the Narendra Modi Government, and it is Rs. 47,619 crore.

India is the world's most populous young country. Around 650 million young people in India are in the age group of 18 to 35. What is the size of this 650 million? If you understand it in terms of the population of the United States, the population of young people in India in the age group of 18 to 35 is two times more than the total population of United States of America. That is the amount of young people that we have to empower, upskill, educate, and provide employment opportunities with, especially at a time when the world is facing the challenge of emerging technologies like artificial intelligence, internet of things, and automation. Finding gainful employment foe such a large number of young people in a democratic country is a huge task. No country in the world has faced a challenge of this kind. In that sense, it is an unprecedented challenge.

Keeping this global context and domestic context in mind, the hon. Finance Minister has presented five schemes under the Prime Minister?s Employment and Skilling Yojana, which is going to touch the lives and transform the lives of more than four crore young people in the next five years.

This is historic in every sense of the word. Madam, in the last ten years, thanks to the renewed support, infrastructure and the political capital that was expended on the Education Department, the country has seen a massive growth in the education infrastructure. I would want to highlight, to your attention and to the august House?s attention, just a few data points on the quantum leap the country has made in the educational infrastructure that we have made available to our young people.

Pre-2014, India had 723 universities. Today, India has 1,113 universities as 390 new universities were built in the last ten years. In the last ten years, 7,262 new colleges were built. Pre-2014, we had 36,000 colleges in the country while today, we have 43,000 colleges in India. Before 2014, we had 49,000 higher education institutions in the country and today, we have 56,000 higher education institutions in the country. There has been an increase of 14 per cent. Now, I come to the density of colleges. The number of colleges to a lakh population has increased 20 per cent in the last ten years. In other words, education and the creation of education infrastructure has made education more affordable, more accessible to the young people in this country.

मैडम, आप जानती हैं कि इस देश में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से मध्यम वर्ग की जनता, जिनके पास उनके जीवनस्तर से ऊपर उठकर जीवन में अच्छे लेवल पर आने के लिए उनके पास केवल एजुकेशन का ही एक मौका होता है । ऐसे मिडिल क्लास के लोग सांसदों के पास एडमिशन के लिए जाते थे, एमएलएज के पास उनकी सिफारिश के लिए जाते थे । इसका मूलभूत कारण डिमांड एंड सप्लाई के बीच का फर्क था । चूंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई कम था, इसकी वजह से, कैपिटेशन फीस, मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट कोटा के रूप में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पूरे देश में था । लेकिन आज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करने से ग्रॉस एंरोलमेंट रेशियो, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, जितने युवा कॉलेजेज में एडमिशन पाते हैं, उसमें बहुत फर्क हो चुका है । मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि in the last ten years, in higher education, there has been a 26 per cent increase in the gross enrolment ratio from 3.42 crores to 4.33 crores.

मैडम, हम सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हायर एजुकेशन में फीमेल एन्रोलमेंट, जो युवतियाँ कॉलेजेज में जा रही हैं, पिछले 10 सालों में उसमें 32 परसेंट इंक्रीज हुआ है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी का ?बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ? का जो संकल्प था, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम इसमें देख रहे हैं ।

हम जानते हैं कि आज के जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथेमैटिक्स, इंजीनियरिंग आदि सबसे महत्वपूर्ण फील्ड्स होते हैं because the world is progressing towards a tech-led, tech-dependent world. In STEM education, पिछले 10 सालों में महिलाओं और युवतियों का एन्रोलमेंट 43 परसेंट ज्यादा हुआ है, पिछले 60 सालों की तुलना में । यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के विमेन एम्पॉवरमेंट का एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है । यूनिवर्सिटीज में 51 परसेंट एन्रोलमेंट में इंक्रीज हुआ है । There has been an increase of 81 per cent in enrolment for Ph.Ds, which shows a qualitative increase, a qualitative throughput of our higher education institutions. नॉर्थ-ईस्ट में भी यही हालत है ।

Madam, I must draw the attention of this House to another very important aspect. यह जो ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशियो देश में बढ़ता जा रहा है, इसका सबसे बड़ा लाभार्थी इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस देश के एससीज हैं, इस देश के एसटीज हैं और इस देश की महिलाएं हैं ।

माननीय सभापति महोदया, कल-परसों से रिज़र्वेशन के ऊपर बहुत चर्चा हो रही थी ।

माननीय सभापति महोदया, नेता प्रतिपक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ओबीसी विरोधी, एससी विरोधी और एसटी विरोधी के रूप में पेंट करने का, चित्रण करने का प्रयास हो रहा था । आज मैं आपके सामने फैक्ट्स के आधार पर और एक-दो हिस्टॉरिकल इंसिडेंट्स के आधार पर बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर मंडल रिकमनडेशन का इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ होता और पिछले दस सालों में मोदी जी के नेतृत्व में एससी, एसटी और ओबीसी युवाओं को विशेष रूप से इनकरेज करने का प्रयास नहीं हुआ होता, तो आज के इस ग्रॉस इनरोलमेंट रेश्यो में क्या फर्क होता?

सभापति महोदया, पिछले दस सालों में देश के युवा, जो एससी समाज से आते हैं, उनका हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट 44 परसेंट इनक्रीज़ हुआ है । ? (व्यवधान) एससी समाज से जो महिलाएं आती हैं, युवतियां आती हैं, पिछले दस सालों में उनका इनरोलमेंट 51 परसेंट इनक्रीज़ हुआ है । ? (व्यवधान) जनजातीय समुदाय से जो आते हैं, ऐसे एसटी स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट पिछले दस सालों में 65 परसेंट इनक्रीज़ हुआ है । ? (व्यवधान) जनजातीय

महिलाओं और युवतियों का इनरोलमेंट पिछले दस सालों में 82 परसेंट इनक्रीज़ हुआ है । ? (व्यवधान) ओबीसी युवाओं का इनरोलमेंट पिछले दस सालों में 45 परसेंट इनक्रीज़ हुआ है । ? (व्यवधान) ओबीसी महिलाओं और युवतियों, स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट पिछले दस सालों में 49 परसेंट हो चुका है । ? (व्यवधान) यह श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता है ।

On the other hand, Madam, when the Mandal Commission recommendations were tabled for more than 10 years, neither Indira Gandhi ji, nor Rahul Gandhi ji moved an inch on implementing the Mandal Commission reforms. If there is any Government and if there is any party that has been the most anti-OBC, the most anti-SC/ST party, it is the Congress Party and the Congress Party?s Governments.

मैडम, ओबीसी के खिलाफ, एससी, एसटी के खिलाफ इनकी नफरत कितनी ज्यादा थी, यह एक इंटरव्यू में बाहर आता है । 03/03/1985 को माननीय श्री राजीव गांधी ने नवभारत टाइम्स के एडिटर श्री आलोक मेहता को एक इंटरव्यू दिया । इस इंटरव्यू में माननीय श्री राजीव गांधी, तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजीशन एक बयान देते हैं । यह बयान मैं पढ़ना चाहता हूं और इस अगस्त हाउस के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं । श्री राजीव गांधी जी कहते हैं ? ?आरक्षण के नाम पर *?** को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं ।? जो आरक्षण का अधिकारी वर्ग है, उसको श्री राजीव गांधी जी ने *?** कहा था । This is the quality; this is the intention; and this is the thinking of the Congress Party?s top leadership. आज आप देखिए कि कर्मा कैसे वापस आता है? जिस वर्ग को *?** कहा गया था, उस पार्टी के नेता को जनता क्या कह रही है, यह आप देखिए, कर्मा कैसे वापस आता है?

Hon. Chairperson, Madam, we have also made tremendous progress in the quality of our education system, thanks to the introduction of the National Education Policy. देश की एजुकेशन पॉलिसी लगभग तीन दशकों से रिव्यू नहीं हुई थी । एजुकेशन ऐसी फील्ड है कि उसमें हर तीन साल में, हर पांच साल में उसमें अपडेशन की जरूरत होती है । If you do not update our curricula, if you do not update our syllabus, and if you do not update the quality of education that we are providing to our children, there is a very high chance of them learning things which are not required.

एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू नहीं करने की वजह से इस देश के एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी हो गई थी कि आपमें जो भी क्वॉलिटी है, टैलेंट है, यदि आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे या आप एक-दो प्रोफैशनल कोर्सेज़ नहीं करेंगे, तो आपकी वैल्यू ही नहीं थी । इसलिए, पूरे देश में एक प्रकार से ?रैट-रेस? शुरू हुई । सबको एक ही वैरायटी में जाना है, सबको इंजीनियरिंग ही करनी है । मैं बेंगलुरू से आता हूं, बेंगलुरू में ऐसा है कि आप लाइफ में पहले इंजीनियरिंग करो, उसके बाद आप जो करना चाहते हो, वह करो ।

This was the quality of our education system because we did not review our education system or the quality of our education system to make it flexible, to make it up to date and I would flatly blame all the previous Governments in 70 years, which did not review the education system properly and make it more

creative, innovative, making it more problem-solving centric. This was changed by the introduction of the National Education Policy 2020.

34 साल के बाद, लगभग तीन दशक के बाद देश के एजुकेशन सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, एक नई पॉलिसी का इंट्रोडक्शन वर्ष 2020 में हुआ । इसमें 3-4 बड़े-बड़े चेंजेज हैं । मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ । सबसे बड़ा जो चेंज हो चुका है, वह अपनी एजुकेशन च्वाइस की फ्लैक्सिबिलिटी पर है । इससे पहले क्या होता था?

If I were interested to study, say history and also study, along with it, say physics, then I did not have the opportunity of choosing both a science subject and a social science subject. If I wanted to study economics and at the same time if I also wanted to study, say art or if I wanted to study mathematics, I would not get the opportunity because there was an inherent rigidity that did not allow for these multi-disciplinary courses to be taken. For the first time, the National Education Policy has now introduced a flexibility in our higher education where the student is now free to choose the subject that he wants to study.

I think this was a long-pending reform that crippled the creativity and the talent of our young people by crippling this choice or by not giving them this choice. I think making available the flexibility of choice for a student to choose the option that he wants or the subject that he wants, is a very welcome reform that the NEP has brought.

The second big reform that the NEP has brought is with respect to changing the focus of our education system from what was essentially a Euro-centric or Euro-created colonised education system to an India-centric education model. Two big aspects demonstrate the change that has taken place in this sector. Firstly, the focus on mother tongue-based education system. All over the world it has been proven through various education systems and education surveys that the most effective medium of teaching, especially in the formative years of two to eight years old for children is in the mother tongue. Those children who learn non-trivial educational concepts in the mother tongue, their retention capacity, their understanding capacity, their comprehensive capacity is far higher compared to students who would have learnt a particular concept in a non-mother tongue language. But for a long time, there has been this colonised obsession of English medium education. I am not taking away the importance of learning the English language, but the obsession of English medium education even at the primary

stage was a very big challenge for our young people, especially the children from rural areas, to understand the fundamentals of any subject.

For the first time, the education policy has made it mandatory for primary education to be in the mother tongue in the country, thereby strengthening the regional languages of this country and also the mother tongue languages of this country. ? (*Interruptions*)

**SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE):** What about Hindi? ? (*Interruptions*)

**SHRI TEJASVI SURYA :** I am coming to Hindi imposition. I also come from Karnataka, which is a non-Hindi speaking State. Please give me two minutes. I will come there.

महोदया, इस एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी का जो विजन स्टेटमेंट है, इस विजन स्टेटमेंट के बिगनिंग में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी जाती है that we are moving towards an India-centric education system.

What is the meaning of this India-centric education system? मैं अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि for a long time, our education system, ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन सिस्टम बनाकर गए थे, उसके हिसाब से हम चल रहे थे । आठ या दस साल पहले कर्नाटक के एक गांव में किसी कार्यक्रम के लिए गया था । उस समय मैं एक सामान्य किसान के घर गया । For the benefit of our friends from Tamil Nadu, I would want to state this in English. I had visited the House of a farmer in one remote part of Karnataka about eight or ten years ago. In the evening, we were sitting and chatting with the farmer who had a young child. That young child came back from school and removed his bag and changed into home clothes and immediately started studying and doing his homework. He was a good boy who came back from school and immediately started doing homework. But the farmer father seemed very agitated. He asked him to get inside. He said, ?don?t sit in front of me?. I told the farmer that his son seemed to be an Adarsh balak, he went to school and came back and immediately started homework. I asked him why he was so angry. The farmer father said, ?for the last four years, we have not had rainfall in our village but every evening the boy who goes to the English medium school comes home and keeps saying, ?rain rain go away, little John wants to play??. What he meant to say was that the rhymes that are taught in our schools neither had any context or relevance to the immediate local culture and understanding. This is not to say that we must not learn the English language. We must learn every language in the highest quality possible but unless education is made available in the primary standard in the mother tongue, we will not be able

to communicate and transmit the culture of this soil. So, if there is one Government in the 70 years that has given importance to impart education in mother tongue and made available through the National Education Policy provision for medium of instruction to be in the mother tongue, it is only the Narendra Modi Government. No other Government has done that.

On the point of Hindi imposition, my friends from the DMK Party have been asking pointed questions.

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य, आप अपनी बात कम्प्लीट कीजिए ।

? (व्यवधान)

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI):** Madam, who is he? Is he the Minister? I asked the question to the hon. Minister and the hon. Minister would reply.

**SHRI TEJASVI SURYA:** I am a Member of the Bharatiya Janta Party and most importantly, Kanimozhi ji, I come from Karnataka, which like yours is a non-Hindi speaking State. I am as opposed to imposition of Hindi as possibly you are, rather more sincerely because I have seen the DMK Party being hypocritical about their opposition to Hindi imposition. Let it be that as it may, let me take a minute.

In 1968, the first National Education Policy was introduced. The first National Education Policy mandated a three-language policy.

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

**SHRI TEJASVI SURYA:** Madam, from the first National Education Policy to the 2020 National Education Policy, other than the Narendra Modi Government's education policy, every education policy that introduced the three-language formula said that you must compulsorily learn Hindi and another Indian language. ? (*Interruptions*) Please listen to what I am saying.

माननीय सभापति **:** आप बैठ जाएं । आप अपनी बात समाप्त कीजिए ।

**SHRI TEJASVI SURYA:** You should have asked this question to your Congress Party people. Why did they impose?

माननीय सभापति **:** माननीय सदस्य डॉ. मोहम्मद जावेद जी ।

? (व्यवधान)

**SHRI TEJASVI SURYA:** Madam, our learned Member from the DMK seems to have inadequate understanding of the National Education Policy (NEP). ? (*Interruptions*) The National Education Policy 2020, for the first time has introduced an education policy that provides the choice for the students to learn any two Indian languages and not necessarily just Hindi. ? (*Interruptions*) So, what happened, was that in the last 65 years, there was imposition of Hindi on the Southern States and non-Hindi Speaking States by the Congress Party. ? (*Interruptions*)

**CUT MOTIONS**

**(TOKEN)**

**THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD 25 DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY (PAGE 89) BE REDUCED BY RS. 100.**

**SHRI HANUMAN BENIWAL (NAGAUR):** I beg to move:

Need to approve a new Navodaya Vidyalaya in Khinwasar of Nagaur district. (21)

Need to open Kendriya Vidyalaya (KV) by granting approval on pending KV proposals in Merta of Khinwasar, Parbatsar, Didwana and in Nagaur region. (22)

Need to approve proposals for opening of new Kendriya Vidyalaya at Makrana, Jayal and Ladnun subdivision headquarters of Nagaur parliamentary

constituency. (23)

Need to fill up all vacant posts through regular recruitment in all Kendriya Vidyalaya located in Rajasthan. (24)

Need to ensure availability of all facilities including pure drinking water in the Navodaya Vidyalaya in Kuchaman of Didwana-Kuchaman district of Nagaur parliamentary constituency. (25)

**(TOKEN)**

**THAT THE DEMAND UNDER THE HEAD DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION (PAGE 93) BE REDUCED BY RS. 100.** **26**

**SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA):** I beg to move:

Need to establish a Central Women University in Purnea district of Bihar which shall cater to extremely backward block of Rupouli, Kodha. (8)

Need to establish a Central University in

Purnea district of Bihar. (9)

Need to set up an IIT and an IIM in Purnea district of Kosi-Seemanchal region of Bihar. (10)

Need to set up Institution like NIFT in Purnea district of Kosi-Seemanchal region of Bihar. (11)

**SHRI HANUMAN BENIWAL (NAGAUR):** I beg to move:

Need to conduct an audit of the National Testing Agency by an independent agency and making the report public. (26)

Need to increase the grant/amount received by the universities of Rajasthan. (27)

Need to fill up the vacant academic and non academic posts of SCs, STs and OBCs in all the Central Universities including Delhi. (28)

Need to regulate the fees charged by coaching institutes for preparation of various recruitment

and entrance
examinations. (29)

**डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज) :** मैडम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है । मैं इस मौके पर अपनी पार्टी लीडरशिप को और किशनगंज की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे यहां बैठने का और उनकी समस्या उठाने का मौका दिया है ।

Madam, I stand here to speak on the Demands for Grants pertaining to the Ministry of Education. मैडम, किसी भी मुल्क में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा होता है, वह शिक्षा और तालीम होती है । हमने देखा है कि मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में धीरे-धीरे इस फाउंडेशन को बर्बाद कर दिया है ।

Education is the bedrock of any society?s progress, yet for the past decade, the Modi Government has systematically dismantled our education system and institutions. Today, I stand before you to highlight some of the policies and hollow promises.

मैडम, बापू महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ?Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.? पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि ? Every child deserves timeless gift of education.? इसी भावना के साथ कांग्रेस ने 2009 में एक लॉ बनाया, फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 21 ए में यह किया कि छह से 14 साल के सभी बच्चे-बच्चियों को फ्री एण्ड कम्पलसरी एजुकेशन दी गई । उसके बाद इसको बढ़ाने की बात हुई । आदरणीय मोदी जी ने भी बहुत ऊंची आवाज़ में कहा कि हम 18 साल तक बढ़ाएंगे, 12 वीं कक्षा तक बढ़ाएंगे लेकिन अभी तक उन्होंने बढ़ाया नहीं है । हमने मुल्क से वादा किया था कि अगर तालीम को सही रास्ते पर लाना है तो इसको तीन पर्सेंट से बढ़ा कर छह पर्सेंट तक हमें ले जाना है । कांग्रेस के वक्त में, यूपीए के वक्त में 3.36 था और इस मोदी सरकार ने, जो खाली ढोल बजाती है, वह कहती है कि हम जीडीपी का सिर्फ 2.9 पर्सेंट देंगे । मैडम यह बहुत ही अफसोस की बात है । मैं एक फिगर देना चाहता हूँ कि स्कूलों में लगभग साढ़े 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं । 4.3 crore people study in the schools and universities. हमारे 11 करोड़ स्किल्ड इंस्टिट्यूशंस में अपना हुनर सीखते हैं । लगभग 1.1 करोड़ टीचर्स और स्टाफ हैं । यह एक तिहाई आबादी है । This amounts to almost 43 crore. इसमें आपने कितना दिया है? 1.48 लाख करोड़ रुपये दिए हैं । अगर वह आप डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 रुपये प्रति महीना भी नहीं होता है । इसमें आप तालीम देना चाहते हैं? इसीलिए मोदी सरकार नए-नए इंस्टिट्यूशंस की बात करती है, लेकिन जो पुराने इंस्टिट्यूशंस हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है । हमारे किशनगंज को 12 साल पहले एक इंस्टिट्यूट दिया गया था, उसके लिए आज तक फंड नहीं दिया गया है । I respect the hon. Minister. He always meets me with great affection. सर, प्लीज़ अब तो पास करा दिजिए ।

मैडम, करीब चार लाख अस्सी हज़ार वैकेंसीज़ टीचर्स की हैं । बिहार में, जहां से मैं ताल्लुक रखता हूँ, वहां सवा लाख टीचर्स नहीं हैं । बताइए कहां से तालीम हासिल होगी? पढ़ाने वाले ही नहीं हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? इसीलिए हमारे बिहार के लोग मज़दूरी करने के लिए बाहर जाते हैं । हमारे रूड़ी भाई यहां बैठे हैं । सर, आपने 13 करोड़ में से चार करोड़ बोला था या तीन करोड़ लोग कहा था? बिहार से चार करोड़ लोग पूरे हिन्दुस्तान में, अलग-अलग प्रोफेशंस में काम करने गए हैं । ? (व्यवधान) मैडम, ये मेरा टाइम नहीं लेंगे । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** नहीं, माननीय सदस्य ने कोई नाम नहीं लिया है ।

? (व्यवधान)

**DR. MOHAMMAD JAWED:** After I speak, you can put your point. ? (*Interruptions*)

मैडम, वही नहीं, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 6,180 वैकेंसीज हैं । आईआईटीज में 425 वैकेंसीज हैं । आईआईएम में 484 वैकेंसीज है । केंद्रीय विद्यालय में विद्यालय में 12,000 वैकेंसीज हैं । जवाहर नवोदय विद्यालय में 3271 वैकेंसीज हैं । बच्चा क्या पढ़ेगा? इसीलिए, वह कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है । आप जानती हैं कि अभी कोचिंग सेंटर में क्या हुआ? अभी दिल्ली के कोचिंग सेंटर में क्या हुआ? कोटा में क्या हो रहा है? हर हफ्ते और हर महीने हम लोगों को स्यूसाइड केसेस की खबर सुननी पड़ती है ।

मैडम, अभी हमारे यंग ऑनरेबल मेम्बर बोल रहे थे कि मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है । सबसे अफसोस की बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 42 परसेंट वैकेंसीज हैं । यह वैकेंसीज किनकी है? यह ओबसी, एससी और एसटी की वैकेंसीज हैं । यह सरकार हर मामले में माइनॉरिटीज, ओबीसी, एससी और एसटी को टारगेट करती है । ये आँकड़े बता रहे हैं । ये मेरे आँकड़े नहीं हैं ।

मैडम, यह ऑफिशियल रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2018-19 में 51 हजार गवर्नमेंट स्कूल्स बंद कर दिए गए । पिछले आठ सालों में 78 हजार गर्वनमेंट स्कूल्स बंद कर दिए गए । उसमें कौन पढ़ता है? उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं । लगभग 2 करोड़ बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही है । यह है मोदी सरकार ।

दूसरी बात यह है, सरकार कहती है कि हम अच्छी तालीम दे रहे हैं । आप कैसे तालीम देंगे? अभी बहुत चर्चा में था और जरूरी भी है- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनायी गई । इसे आदरणीय मोदी जी की सरकार ने बनाया और हमने क्या देखा । सात साल में 70 ऐसे केसेस हुए, जिनमें पेपर लीक हुए । किसी ने ट्विटर पर लिखा है कि बाहर टेस्ट पेपर लीक होता है और अंदर हमारे पार्लियामेंट में रूफ लीक हो रहा है, जिससे पार्लियामेंट बह गया । यह है मोदी सरकार । मोदी है तो मुमकिन है ।

मैडम, यूजीसी, एनईटी एग्जाम में 23 लाख कैंडीडेट्स ने फॉर्म भरा था । तीन डिफरेंट लेवल्स हैं । 9 लाख से ज्यादा कैंडीडेट्स ने across 300 countries, यूजीसी और एनईटी में अप्लाई किया । आपने एक-एक हजार रुपये उनसे फीस ली । पता नहीं और कितने हजार रुपये उनको एग्जाम देने और फीस भरने में लग गया होगा ।

आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं । मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं । उन्होंने यहीं पर कहा था कि integrity of the exam may be compromised. It is not only the integrity of the exams, but it is the integrity of this Government which has been compromised.

मैडम, यह बड़ी अफसोस की बात है । इन सब हालात को देखते हुए, बच्चों पर जितना प्रेशर है, वे नहीं ले पा रहे हैं । आपको एक आँकड़ा बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है । पिछले कुछ सालों में हमारे हिन्दुस्तान में लगभग 13 हजार स्टूडेंन्ट्स ने आत्महत्या की । आपको पता है, क्यों, क्योंकि उनको सही सुविधा नहीं मिल नहीं है । उनको सही सपोर्ट नहीं मिल रहा है । उनको कास्ट का तनाव झेलना पड़ता है । Therefore, around three suicides, every two hours, are happening in India. यह किसी भी मुल्क के लिए बहुत शर्मनाक है । इसीलिए, हमारे आदरणीय नेता कहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए । उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको जितना हक है ।

मैडम, जो हायर एजुकेशन है, उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया है । बर्बाद इसलिए किया, क्योंकि जैसा मैंने बताया है ।? (व्यवधान)

मैडम, अभी तो मेरा पाँच ही मिनट हुए हैं । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आपका 10 मिनट पूरा होने वाला है । आप एक मिनट में अपनी बात पूरा कर लीजिए ।

डॉ**.** मोहम्मद जावेद **:** मैडम, अभी तो दो ही मिनट हुए हैं ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात दो मिनट में कंप्लीट कर लीजिए ।

**14.00 hrs**

डॉ**.** मोहम्मद जावेद **:** महोदया, हमारे बच्चों की जो यहां स्थिति है, मैं उसके बारे में बताता हूं । लगभग सवा 13 लाख बच्चे वर्ष 2022 में बाहर पढ़ रहे थे । इनकी पढ़ाई का खर्च लगभग 60 से 70 बिलियन डॉलर्स है । That is between Rs. 5 lakh crore and Rs. 6 lakh crore. आपने हायर एजुकेशन में 47 थाउजेंड करोड़ रुपये दिए । हमारा 12 गुना से ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है । अगर वह हम यहां खर्च करते तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाते ।

**14.01 hrs**

(Shri A. Raja *in the Chair*)

सर, पिछले तीन सालों में लगभग साढ़े 24 हजार बच्चों का वहां देहान्त हो गया, मर गए । आप समझ सकते होंगे कि किस तरह के लोग वहां जाते होंगे । जिनकी एक या दो ही औलाद होती होंगी, उनकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है ।

सर, मैं माइनोरिटी इश्यूज़ पर आता हूं । यहां बापू जी की मूर्ति थी । हम लोग बैनर लगाकर प्रोटेस्ट करते थे । वह भी आपने पीछे करा दी । मेरी आपसे गुजारिश है कि जो डिफरेंट स्कीम्स माइनोरिटीज़ के लिए हैं, उनको चालू कीजिए, स्कॉलरशिप को चालू कीजिए । आपने यूपीएससी के लिए एक स्कीम दी थी । मुझे याद है कि वर्ष 2020 में कुछ लोगों ने कहा कि यह यूपीएससी जिहाद है । 4 पर्सेंट मुस्लिम कंडीडेंट्स उसमें पास हुए थे और हमारी आबादी 15 पर्सेंट है । आपने वह स्कीम बंद कर दी । मैं चाहता हूं कि आप उसे फिर से चालू करें । उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल वह 4 पर्सेंट घटकर 3.6 पर्सेंट हुआ और उसके अगले साल वह घटकर 3.1 पर्सेंट हो गया । We also have as much intelligence as anybody else. We can contribute as

much as anybody else in this country, and we have contributed. That is why, I appeal to you that you should not discriminate. I know this Government stands on discrimination. This Government is anti-Muslims, anti-SCs, anti-*Dalits*, anti-students, anti-poor. सेंटीमेंट जगाकर यह राज कर रही है । अगर हम मुस्लिम न होते आपके हिन्दुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता । ? (व्यवधान) पास में एक मुल्क है, उसका नाम मैं बताना चाहता हूं । ?(व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Please address the Chair.

? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Please wind up your speech.

? (*Interruptions*)

**DR. MOHAMMAD JAWED:** About 13.25 lakh Indian students are studying abroad, and in India, only 40,000 foreign nationals are coming here to study. ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं । बांग्लादेश की जीडीपी हमसे बेहतर है । यही नहीं, हमारे यहां के साढ़े 9 हजार बच्चे वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,600 बच्चे यहां पढ़ते हैं । आप कहते हैं कि बांग्लादेश चले जाओ । मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है, उस पर माननीय मंत्री जी गौर करें, मुल्क की एजुकेशन को बचाएं, बेहतर करें । मुगलों का नाम हटा देने से कुछ होने वाला नहीं है । मुगल अगर 330 साल रहे, तो वह आपके हटाने से हटने वाले नहीं हैं । बहुत-बहुत शुक्रिया, जय हिन्द ।

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN):** Hon. Chairperson, Sir, my name was taken. ? (*Interruptions*) Marshal was there. I have a right to respond. ? (*Interruptions*) When the hon. Chair was there, he took my name on a subject of Bihar. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** I will check the record.

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** You will check, then he will come, and then, I will do it four days later. Please give me two minutes.

**HON. CHAIRPERSON:** Without going through the record, how can I tell you?

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** It is my right. He has taken my name. Let me respond to him. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Nothing will go on record. I will call you back.

*? (Interruptions) ?**

**HON. CHAIRPERSON:** I will go through the record.

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** If an hon. Member has taken my name, then am I not allowed to reply him back? When will you fix a time for me?

**HON. CHAIRPERSON:** I will come to you.

? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Mr. Rudy, you are a senior Member. I was not in the Chair. I will go through the record. I will call you back.

? (*Interruptions*)

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** The Marshal is there.

**HON. CHAIRPERSON:** Nothing will go on record. I will go call you back.

*? (Interruptions) ?**

**SHRI RAJIV PRATAP RUDY:** This is not a right way of doing it. I am just responding to what he has said. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** I will go through the record and then, I will call you.

**डॉ. शिव पाल सिंह पटेल (प्रतापगढ़) :** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मैं पहले एक शिक्षक हूं और बाद में एक सांसद । बहुत खुशी की बात है कि सौभाग्य से माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं । उनके सामने मैं अपना उद्गार रखना चाहूंगा । मैं माँ सरस्वती और भारत के संविधान को नमन करता हूं । चूंकि शिक्षा के बजट पर चर्चा है, इसलिए मैं सदन में अपनी बात आज के शिक्षक की भूमिका और उनकी समस्याओं पर रखना चाहता हूं ।

मैं आपको इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं, प्राचीन काल में जहां शिक्षा सिर्फ चंद लोगों के लिए थी, उस समाज में सिर्फ दो वर्गों को ही शिक्षा दी जाती थी । भारत का शेष समाज शिक्षा से वंचित था । यहां तक की स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था । अपाला, घोषा जैसी शिक्षित स्त्रियों के बहुत कम ही उदाहरण इतिहास में मिलते हैं । सदन में बार-बार महाभारत की चर्चा हुई । महाभारत के पात्रों को लेकर चर्चा हुई । मैं भी एक उदाहरण गुरू द्रोणाचार्य का रखना चाहूंगा, जो केवल राजा और महाराजा के बच्चों को ही शिक्षा देते थे । कभी उन्होंने गरीब-दलित और पिछड़े को शिक्षा नहीं दी । कर्ण के गुरू परशुराम ने उन्हें शिक्षा दी लेकिन जब पता चला कि कर्ण शुद्र पुत्र है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया ।

कितनी विडम्बना है कि एकलव्य जैसा विद्यार्थी यदि अप्रत्यक्ष रूप से धनुर्विज्ञा सीख भी लेता है तो उस समय के शिक्षक ने अपने शिष्य का अंगूठा ही गुरू दक्षिणा में मांग लिया था । ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे देश में हुए हैं । आज भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक ताना-बाना को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं । उसमें आप देखें तो जातिवाद को बढ़ावा देने में हमारे सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा योगदान है ।

अब मैं आपको वर्तमान में लाना चाहता हूं । हम शुक्रगुजार हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिन्होंने भारत के संविधान में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों एससी/एसटी,ओबीसी और अल्पसंख्यक, यहां तक कि स्त्रियों

को भी पूर्ण शिक्षा का अधिकार दिया । इसी का परिणाम है कि आज का समस्त शिक्षक समुदाय बिना किसी भेदभाव के अमीर और गरीब इत्यादि सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षित कर रहा है ।

संविधान के कारण ही आज का शिक्षक अपने विद्यार्थी से गुरू दक्षिणा में अब अंगूठा नहीं मांग सकता है अर्थात भेदभाव नहीं कर सकता है । यह हमारे संविधान की देन है । जात पांत से ऊपर उठकर सोचने लगा है । ऐसा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था, इसी संविधान को बचाने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी और समूचा विपक्ष भारत की सड़कों पर उतरा, जिसे भारत की ऊर्जावान जनता ने हृदय से लगाया और संविधान की रक्षा की और बहुत सारे लोगों का घमंड भी चूर-चूर किया । आप देखें जो देश दुनिया में सबसे आगे हैं, अमीर है, वह शिक्षा में भी सबसे आगे है । उन्हीं देशों में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, जहां हर वर्ष भारत के लाखों छात्र पढ़ने जाते हैं । वहां की यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं क्योंकि वहां भेदभाव करके अप्वाइंटमेंट या एडमिशन नहीं होता है । भारत इतना बड़ा देश है कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी यहीं है । यह कितनी शर्म की बात है कि टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है ।

हम उच्च शिक्षा के मामले में कहां खड़े हैं? इसका मुख्य कारण है भाई-भतीजावाद और मनुवादी व्यवस्था के अनुसार एपाइंटमेंट होना । आप स्वयं देखें कि हायर एजुकेशन में कितने वाइस चांसलर और कितने प्रोफेसर्स ओबीसी, एससी और एसटी से हैं, नगण्य हैं, बहुत कम संख्या में हैं । नाते-रिश्तदारों की ही सिर्फ भर्ती होती है इसीलिए विश्वविद्यालयों का स्तर वर्ल्डक्लास नहीं होता है । इन्हीं लोगों ने व्यवस्था भी दी और रूल बनवाया ? एनएफएससी, यानी नॉट फाउंड स्यूटेबल कैंडीडेट्स । इसके द्वारा ओबीसी, एससी,एसटी और माइनोरिटी कैंडीडेट्स को योग्य होते हुए भी अयोग्य करार दिया जाता है । इनको एपांइट नहीं किया जाता है और अपने लोगों को रखने का मौका मिल जाता है । यह सब खुलेआम चल रहा है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष रूप से ध्यान दें । आरक्षण के अनुपात में प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर आदि की सीटों पर हर जगह प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से बिलांग करता हूं और यहां से सांसद चुना गया हूं । मैंने देखा है कि कितना भेदभाव होता है । हाई स्कूल और इंटर में भी ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को बोर्ड प्रेक्टिकल में दूषित मानसिकता के टीचर्स द्वारा कम अंक दिए जाते हैं । यह बात इस सरकार के समय में ज्यादा हो रही है । ओबीसी के कैंडीडेट्स को देखें, आईआईटी, नीट, आईएएस, पीसीएस जैसी हर परीक्षा में टॉप करते हैं, फर्स्ट पोजीशन तक लाते हैं लेकिन इनको प्रोफेसर बनने में नॉट फाउंड स्यूटेबल की श्रेणी में रख दिया जाता है । माननीय शिक्षा मंत्री जी, इसमें सुधार कैसे हो, इस पर सख्ती से निर्णय लें ताकि सभी को न्याय मिल सके, वरना आज के द्रोणाचार्य हजारों-लाखों छात्रों के अंगूठे गुरु दक्षिणा में लेते रहेंगे अर्थात् मनमानी करके दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय करते रहेंगे ।

माननीय सभापति जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय प्रधान मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस हेतु भारत की शिक्षण प्रणाली में कौन से मौलिक प्रयास किए हैं? भारत को अगर वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो पहले शिक्षक को गुरु बनाइए, इससे भारत स्वयं ही विश्व गुरु बन जाएगा । हमारी व्यवस्था में शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा चुनाव, मतगणना, मतदाता पर्ची, पल्स पोलियो अभियान, जनगणना, मिड-डे मील जैसे कार्य कराए जाते हैं, इस कारण उनका मूल कार्य विद्यार्थियों को शिक्षा देकर सर्वांगीण विकास करके अच्छा नागरिक बनाना कहीं न कहीं बाधित होता है । इससे समाज पिछड़ता है और देश भी पिछड़ता है । मेरा अनुरोध है कि उनको अन्य विभागीय कार्य से मुक्त किया जाए तथा प्रशासन अपना कार्य करे और शिक्षक अपना कार्य करे ।

मैं भारतवर्ष के शिक्षकों को नमन करता हूं जो सरकार एवं प्रशासन द्वारा दिए गए हर कार्य को सहज एवं सकुशलता से संपादित करते हैं और साथ ही बचे हुए समय में भारत के विद्यार्थियों के भविष्य को भी सुधारते हैं । शिक्षक देश के रीढ़ की हड्डी हैं । मेरा सुझाव है कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए, जिसे इस सरकार ने खत्म कर दिया है । शिक्षा मित्रों को उचित मानदेय और पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिया जाए । शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए और ढाई परसेंट से बढ़ाकर छ: परसेंट किया जाए । दलित एवं पिछड़ों के रिक्त पदों पर बैकलॉक के चलते आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए और दलितों एवं पिछड़ों को अधिक से अधिक स्कॉलरशिप दी जाए ।

**SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR):** Hon. Chairperson Sir, on behalf of the All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Demands for Grants under the control of Ministry of Education for 2024-25.

Sir, I rise today to voice my deep concern about the current state of the education system in India. The Government policies have not only failed to uplift the educational standards of our nation but have also systematically eroded the foundational principles that ensure equal opportunity and holistic growth of our students.

The importance of education cannot be overstated. Yet our nation has consistently underfunded this crucial sector while countries like China, Japan, and South Korea have invested heavily in education decades ago. Our India, our country, remains hesitant despite the recommendations by Kothari Commission in 1964 to increase educational expenditure to 6 per cent of the GDP. Our Budget has never exceeded 3.5 per cent. The National Education Policy, 2020 reiterates this need. Yet the Government has shown little commitment to achieving it.

Free and compulsory education is a fundamental right under our Constitution. However, public expenditure on education has touched new lows dropping to 2.7 per cent under the Modi Government. The inadequacies in our education system are glaring despite the imposition of a 4 per cent Education and Health Cess since 2019, which now funds 70 per cent of all educational spending. Our education sector remains underfunded and overburdened.

India has around 50,000 colleges and 1100 universities, half of which are private. While enrolment has increased, the quality and uniformity of education has not kept pace. The Annual Status of Education Report 2023 -Beyond Basics (ASER) highlights that 25 per cent of students aged 14 to 18 in rural India struggle to read even class two level text materials fluently in their native language. The Budget neglects research and development with only three Indian Universities in the top 200 globally without substantial investment. Our institutions struggle in the global

arena risking a brain drain. The Budget also fails to prioritize skill development program crucial for aligning educational outcomes with market needs. Inequitable access to higher education remains a concern with inadequate enhancement to scholarship and financial aid. The failure to fund public institution creates a fertile ground for privatization widening the gap between the rich and the poor.

I stand to highlight the crisis of suicide by students in Kota where around 250,000 students suffer intense schedules and immense pressure. Out of one million JEE aspirants, only 10,000 make it to IIT; and for NEET, two million vie for 1,40,000 medical seats. The odds are scary and the stress is unbearable. The commercialization of coaching in Kota valued at 500 million dollars adds to the problem. Misleading advertisements and isolating living conditions create a toxic mix of competition and loneliness. I would like to draw the attention of this House towards the NEET scam.

The future of students across the country is dark. The Central Government and the Minister of Education remain silent on such a sensitive issue in this grave situation. I would like to request the Minister to take action to solve this problem.

The West Bengal Assembly recently passed a Resolution labelling NEET-UG as an education scam, a claim that highlights the significant problems plaguing this exam under National Testing Agency. The inconsistent administration of NEET-UG has had a detrimental impact on students and the medical community.

The fluctuating difficulty level of the examination and the arbitrary awarding of grace marks have created an atmosphere of uncertainty and mistrust. In the light of these issues, I would like to request the hon. Education Minister to consider reinstating the State's previous Joint Entrance Medical Examination as proposed by the West Bengal Assembly. This would restore a sense of fairness and transparency.

The systematic revision of school text-books under the current Government poses a threat to our children?s education and intellectual integrity. In 2018, the then Minister, Satya Pal Singh, declared Darwin?s Theory of Evolution ?scientifically wrong? and called for curriculum changes. By 2021-22, Darwin?s Theory was removed from class 9 and class 10 syllabi. By 2022-23, it was removed from text-books. Millions of students now lack formal education on a foundational theory of modern biology.

Sir, deleting a chapter on significant Muslim rulers and their contribution from the NCERT?s curricula, omitting reference to events like the 2002 Gujarat riots and altering narratives around Gandhi?s assassination and promoting mythological theories over scientific ones have been widely criticised by academicians, with 33 academicians, including the political scientist Shri Yogendra Yadav, and Shri Suhas Palshikar demanding the removal of their names from the current text-books in 2023. These changes are leading to intellectual stagnation, political manipulation, and they are targeting the intellectual rigour of Indian students.

Sir, in the past decade, under the BJP-led NDA regime, budgetary allocations have significantly decreased. The Department of School Education and Literacy?s share in the Budget halved from 3.16 per cent in 2013-14 to 1.53 per cent in 2024-25. The number of government schools declined from 15,51,000 in 2018-19 to 14,89,115 in 2021-22.

The number of rising private schools is creating accessibility issues for the marginalized communities. An acute shortage of teachers exists as there are 10 lakh vacancies out of 62.71 lakh sanctioned posts. The marginalized sections like the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the minorities face declining gross enrolment ratios at all levels. Without education, how is the Government planning to ensure Education for All? Without special educators, how is the Government planning to ensure education for the special students?

Sir, I would like to draw the attention of this House to the Kasturba Gandhi Schools and Navodaya Schools which are facing the problem of acute shortage of teachers. Under my parliamentary constituency, there are two Kasturba Gandhi Schools in Basanti and Kultoli. You cannot imagine the infrastructural condition of these schools. So, in this regard, I would like to request the Government to take action immediately and allow fund for this purpose.

Sir, regarding the Government?s recent push for establishing campuses of foreign higher education institutions in India, I would say that the intention behind this initiative may seem noble, but I would like to put certain questions to the hon. Minister. Are we building bridges to an opportunity or merely constructing a facade of accessibility? With the Cross-Border Education Research Team indicating that only a handful of top tier universities have ventured abroad, will world-class universities like Harvard or Stanford truly find values on our soil? As the former HRD Minister Mr. Kapil Sibal rightly pointed out, we cannot expect these institutions to flock to India when only 41 institutions in China, of which only NYU

Shanghai is of significant global standing, have established campuses. Are we to believe that India will somehow be different? Mr. Kapil Sibal's observation that foreign universities will ?serve not the needs of education but the rich?, resonates deeply.

Moreover, I now come to the very notion of becoming a Vishwa Guru. I would say that inviting foreign institutions undermines our rich educational heritage. We cannot allow our rich traditions rooted in the millennia of knowledge to be over-shadowed by foreign influences.

The great universities of Nalanda, Takshashila, and *kavi* Guru Rabindranath Tagore?s Visva-Bharati in Santiniketan, West Bengal once attracted scholars from around the world, not through the attraction of foreign campuses but through the depth of knowledge and wisdom they offered. Are we now abandoning this legacy in pursuit of fleeting recognition on the global stage?

Sir, finally, I would like to draw the attention of this House to this matter. मुझे दस साल उस सदन में बैठने के लिए मौका मिला । मुझे यह आशीर्वाद मेरे क्षेत्र के लोगों ने ही दिया । उस सदन का जो कॉरीडोर है, उसके सामने एक नोटिस ऑफिस है । उस नोटिस ऑफिस के ठीक सामने एक टूटे-फूटे वूडन फर्नीचर के ऊपर एक पेंटिंग है । उस पेंटिंग के चित्रकार नंदलाल बसु हैं, who was a pioneer of modern Indian art and who became a principal of Kala Bhavana, Visva-Bharati, Santiniketan. मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से यह बोलना है कि आप उस पिक्चर को सम्मान नहीं दे सकते हो, मान नहीं दे सकते है, क्योंकि वह अंधकार में पड़ी हुई है और उसके ऊपर धूल जमी हुई है । अगर इतने बड़े सदन में उसे रखने के लिए जगह नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को दे दीजिए । हम उसे आर्ट गैलरी में रखेंगे और उसको मान देंगे । यह गनर्वमेंट तो कुछ सम्मान नहीं देती है और हेरीटेज को नहीं रखती है । ? (व्यवधान) सर, एक मिनट में अपनी बात खत्म करती हूं । हम लोग यह सोचते हैं कि बड़ों को प्रणाम करके शुभ काम में जाएं । इस सदन में गांधी जी और बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैच्यू हटा दिया गया है । आप उसको पुन: स्थापित कर दीजिए, जिससे हम इस ट्रेडिशन को ले सकें ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for this opportunity. *Thanthai Periyar* said, ?Knowledge and self-respect ensure the beauty in humans?. People understand that knowledge we get through education. Self-respect and self-dignity we get through the knowledge gained by education. Education was denied to the suppressed and oppressed sections of the people of the society for not to make them achieve knowledge and self-respect, as some wanted them to remain suppressed and oppressed for generations together. Some are standing firmly upholding this denied justice are still fighting from the side of the ruling dispensation. We are on our firm stand opposing them. In the 2014 manifesto of BJP, it said, ?Investment in education

yields the highest returns.? We are still waiting to see when the day will come for investing in Education. During the UPA Government, 4.77 per cent of the GDP was allocated to Education. In Tamil Nadu, Our hon. Chief Minister has allocated 12 per cent of GDP for Education. But this Union Government in their Budget, only 2.5 percent of GDP is allocated for Education. In the neighbouring country Bhutan, they allocate 8 per cent for Education. But in India, we have not even touched the target of spending 6 per cent of GDP on Education. Education in in the Concurrent list. But the Union Government behaves in such a fashion that they are provided with these things and they only have all the rights on Education. Union Government should give 60 per cent of the funds meant for Education and the remaining 40 per cent is to be provided by the respective State Government. But in reality, they collect 4 per cent cess in the name of Health and Education. They have to allocate a particular percentage of this cess for ?Education? from the amount collected from the ordinary people of this country and from the States. If you see you will come to know that the States governments are providing more than 50 per cent of their funds for Education. Education is in Concurrent list. But for education, we are giving more funds. You are collecting almost all our funds in the name of tax and GST. But you deny to give the funds meant for Education in the States to the States. It looks like you are snatching away the divine vessel *Akshaya Patra* from our hands, from the States and giving us a bowl to ask for alms. States are left in lurch. You are dictating. You are holding us for a ransom. Shameful. Samagra Shiksha Abhyan, SSA is an inclusive education programme. As regards this programme, approximately Rs. 3585 Crore has been allocated for Tamil Nadu. Out of this the Union Government?s contribution is Rs 2151 Crore. But out of this Rs 2151 Crore, the first instalment amount of Rs 500 Crore which was to be released by June this year has not been released to Tamil Nadu till today. What is the reason behind this? PM Shri Schools is a Scheme which is just aimed at imposition of the New Educational policy on every State of this country. Hon Chief Minister of Tamil Nadu till today has clearly and categorically stated that Tamil Nadu will not accept the new educational policy. Today you have denied to provide Rs 500 Crore to Tamil Nadu for education sector. How is this looking like? You take away all our money and you dictate terms that only when we follow your new education policy you will give the funds meant for us. Are we not elected representatives? Is not the State Government of Tamil Nadu elected by the people? Is it not our hon. Chief Minister elected by the people? Are you the ones who are the only elected representatives? What right you have? When the Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, he was voicing his concern for upholding the rights of States. But after

becoming the Prime Minister, he changed himself to be the one snatching away the rights of the States. I want to ask you what role the Union Government has to play in interfering in the educational policy, on the people?s belief and in the rights of the elected representatives of the people. The new educational policy put forth by you. Some Members who spoke here said that they were not aware of the three-language policy. They also criticized that the DMK is deceiving and doing politics in the name of language policy. Have you seen anywhere in the world that hundreds of people sacrificing their lives in the language agitations? Can you show them? You don?t know. You have not even taken part in the country?s freedom struggle. You do not understand what sacrifice is. I can cite a example of Kendriya Vidyalayas and their functioning in India. You will come to know how you are carrying yourself as regards language policy. I am saying this to explain this to some of you here. You say that the regional and local language of the State will be taught in Kendriya Vidyalayas. There are 45 Kendriya Vidyalayas in Tamil Nadu. How will you teach Tamil in these Schools? Some students, at least 20 from a class should together go and meet the Principal of that School and place a demand in this regard. If they place a demand, then a teacher may be appointed if available, and Tamil will be taught. This is the situation of KVs in Tamil Nadu. Students have to put forth the demand and struggle hard to learn Tamil. Out of 45 Kendriya Vidyalayas, only 15 of them teach Tamil Nadu. You administration in Kendriya Vidyalaya is in such a fashion and in this scenario how can we believe that you will act in a just manner? In every place the situation is such. We are unable to purchase tickets from railway stations. There again you are imposing Hindi on us. How can we believe that you will not impose Hindi on us? Not only Hindi you are imposing Sanskrit on us. How can we believe you will act in a just manner as regards the language policy? Not only that, our hon. Chief Minister has brought the morning breakfast Scheme for school students. More than 21,87 Lakh children are being benefitted under this breakfast Scheme in Tamil Nadu. We can say with pride that Tamil Nadu is the State which brought the midday meal scheme. There is a nationwide Poshan programme implemented by this Union Government and for this Scheme, the budget estimate was Rs 11,600 crore. Out of which you have allocated only Rs 10,000 crore for the Poshan Scheme aimed at providing food to children. You are not able to allocate adequate funds for this important programme of children. How can you teach us about education? How can you expect us to bow before you and accept whatever you say? A National Sample survey was taken and it was found through the survey that the drop-outs in females are due to domestic work at homes. The drop-outs in boys are due to economic activities as they have to engage in some work and earn

to assist their families economically. These were found from that survey. Today in your new educational policy, you have brought a new Scheme called as Viswakarma. You want to deny education to these children. You want to once again bring back the caste-based education which was opposed by DMK, and the Dravidian parties for so long. How can we accept your new educational policy through which you want to destroy the future of the children of this country by bringing back alive the caste-based education system? I want to say about imposition of a language. In Telangana, in the Eklavya Model Schools as many as 47 persons were recruited. Out of these 47 persons, 44 were from Haryana. They have come from Haryana to teach the students of Telangana. How can the students learn in these Schools? Through these Eklavya Schools meant for tribal students in the name of new educational policy, you are finding ways to spoil the education of our tribal children rather you are not concerned about their future and education. You have not devised a syllabus meant for the students? development. Similarly, in Higher Education, you have been reducing the allocations meant for higher education year after year.

Beyond that the Cluster Schools. In Tamil Nadu, even if there is one student in a School, we continue to run that, School. We have never tried to close such schools. But what do you do? You close the schools which do not have sufficient numbers of students. You make those students to go to a School which is at a distant place of several kms from there. If you do so, you should think how those students, boys and girls, from villages, mountain areas and remote areas will get education by going to attend Schools which are far away? Girls who live is small towns and those students belonging to families with less opportunities cannot pursue their education as they do not have the facility to come and stay in Cities. To facilitate them Our visionary Leader of DMK Hon Dr. Kalaignar created colleges in such areas where these people can study comfortably. He created such higher education institutions ensuring educational development of these students. You are dreaming to achieve 50 per cent in higher education after 30 years from now. But Tamil Nadu had achieved it long ago. This is because of the farsighted vision and plan executed by our Leader Dr. Kalaignar in creating colleges even in small town and villages and the able administration of our present government in Tamil Nadu in the footsteps of Dr. Kalaignar. I want to ask you that how the present Government in Tamil Nadu will accept your new education policy which is aiming to close such colleges? I have a lot more to say. Sir, just give me few more minutes.

**HON. CHAIRPERSON:** You have many things to say. Please conclude soon.

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** Sir, I will soon conclude. Hon Leader Dr. Kalaignar brought government medical colleges in every district of Tamil Nadu with a view to facilitate children from rural and ordinary families to pursue their medical studies. But you brought NEET and through which you continue to shatter the dreams of all those children from poor families with rural background. How many students have committed suicide? You are not concerned about them? After this government came to power, only one industry has seen growth. This is the industry with lot many Coaching Centres having a worth of Rs. 5750 Crore. Yes, these Coaching Schools have grown in plenty. National Testing Agency, NTA, conducts 28 examinations. Is there anyone in that NTA who is a permanent Government Employee? I asked this question and the reply from you is. ?There is not one single person who is the permanent employee who is answerable?. How can you protect the secrecy of Question papers prepared for conduct of examinations by this NTA? From day one, our Hon Chief Minister of Tamil Nadu has been repeatedly insisting that there is no need for NEET. You forget when you try to implement new education policy that ?Education? is in the Concurrent list. That is why you say that you will create the syllabus. You say that only the syllabus created by you can teach the culture, civilization and political history of our country. What is the political history that you try to teach? You will not talk about Mughal emperors. Your political history will not talk about the assassination of Mahatma Gandhi. It will not talk about the leaders of Tamil Nadu. Definitely you will not talk about Thanthai Periyar. But it will talk about a leader who came out of Andaman Jail. I don?t know whether a Bulbul bird or a broom stick through something that leader flew out from the prison as per your textbooks. Is this the Scientific temper you are talking about? If you will teach such things, how can you expect us to accept?

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude.

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** Just one minute Sir. Dravidian movement has for so long worked hard for creating a casteless society by destroying the base for castes and its presence. They have worked continuously for achieving this. From Justice Party, Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Dr. Kalaignar and today till our hon. Chief Minister Shri M.K. Stalin, all great leaders have dedicated their lives for achieving this goal. I wish to say with pain here. This I register in this House as the agony of a mother, a father or a sister. Yesterday in this august House. A Member of Parliament is enquiring to know about the caste of another MP sitting by his side. What is so prideful to know about the caste of another Member? I do not

understand. We should live without carrying a caste. There is a pride to live without caste affiliation. Such is the policy of Dravidian movement.

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Member, please conclude.

**SHRIMATI KANIMOZHI KA0RUNANIDHI:** All the more painful is that the Hon Prime Minister was in support and praise of such a speech. This Government is trying to portray caste as a pride and it talks high about caste. This Prime Minister supports those who insult the ones who do not know what their caste is? Tamil Nadu will never accept the syllabus created by such a Prime Minister. Our Hon Chief Minister of Tamil Nadu will oppose this till the end. Thank you. Vanakkam

**SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI (VISAKHAPATNAM):** Thank you, Sir, for giving me this opportunity to speak about education which is a subject very close to my heart. Before I speak on the Demands for Grants of the Ministry of Education, I would like to just respond to some comments made by the Opposition. They mentioned about the division of Budget allocation over the number of students. I would like to highlight here that as was mentioned by Members of the Opposition, education is a Concurrent Subject. Whatever Budget amount is being spent by the Central Government, it is on the Central Government institutions and not on the State Government institutions and private institutions. So, the number should be divided by students and faculty members and the staff who are in the Central Government institutions. Regarding any drop in the number of schools and the amount of budget that is being spent, I think every State is accountable to speak about it because the schools are largely run by the State Government and not by the Central Government. So, I think we should be careful about how we attribute blame.

I think, in this changing world, it is very important for us to recognise what the role of the Government is. Is it to spend money only or is it to also enable them? I think, there is a balance between the both. It is to regulate, to create good policies for the growth of the education ecosystem, and for those who can afford it, to provide high quality education. For those who cannot, I think the Government should step in and invest in the future of such citizens of India.

So, with this prefacing comment, I would like to get into the Demands of Grants of the Ministry of Education. I am only speaking about the Ministry of Education, not commenting on the budget for skill development or entrepreneurship. I would like to get into specific points appreciating the Government. I think, overall, the Budget

has increased from about Rs.1,12,000 crore to Rs.1,20,000 crore over the last year. I think, that is about seven per cent increase. That is beating inflation. But as a fellow educator myself, I always hope that we are able to give more money to education. I think that will keep happening.

Going into specific issues, I think, in the budget for Kendriya Vidyalaya Sangathan there is an increase of 11 per cent from Rs. 8,300 crore to Rs. 9,300 crore. It is reinstating the strong commitment to enhancing these quality schools in India.

The PM SHRI programme was mentioned. The budget amount has been increased from Rs. 4,000 crore in the last year to Rs. 6,050 crore. This is a strong commitment to enhancing the educational infrastructure and quality across India. Currently, about 10,855 schools have been impacted across 763 districts, and there is a target of impacting more than 14,500 schools through this programme.

I would like to also appreciate the budget allocation for STARS Programme which is largely to increase the teachers? effectiveness through specialised teacher training. Right now, we have got about 3,75,000 schools impacted, and 15 lakh teachers are trained through this programme. About 4,40,000 crore students have benefited across six States.

I have mentioned this in my speech on the Budget and I would like to mention it here again. I would like to specifically appreciate the e-vouchers being provided to about one lakh students every year to secure loans of up to Rs.10 lakh to pursue higher education in domestic institutions and three per cent interest subvention on student loans.

Hon. Chairperson, Sir, now, I come to higher education, a subject which is very close to my heart. As regards higher education, the budget has increased by 8 per cent since the last year particularly in two aspects. The budget to world-class institutions, like the institutes of eminence, has increased by 20 per cent, from Rs. 1500 crore to Rs. 1800 crore this year. And the support to Central universities has increased by a large 38 per cent, from about Rs. 11,500 crore to close to Rs. 16,000 crore now.

Sir, while the allocation has increased overall, the budget for the Central University of Andhra Pradesh and the Central Tribal University of Andhra Pradesh, which are the subjects of the A.P. Reorganisation Act, has been subsumed into the larger support to the Central universities. I request that the budget -- whatever has to be

allocated to these two specific universities in Andhra Pradesh -- continue as expected in the Act, and we are supposed to establish them as soon as possible.

Now, I would like to go over the achievements of the NDA over the last 10 years. I think one of the foremost things has been the New Education Policy that was announced four years ago. Various aspects of implementation are between the States and the Centre. There is a huge responsibility on the State Governments and the Central Government to really see this into reality. As an educator myself, I am really looking forward to see it in a reality.

What are the achievements of the Central Government? The Members, representing the BJP, have spoken also about the number of universities that has increased from 700 to 1100 and the number of colleges that has increased from 37,000 to 44,000. The number of Central Government institutions, the institutes of national importance, has doubled from 75 to about 149 in 2020-21 and more have come in the last two or three years.

Many Members have spoken about the educational outcomes before me. But I would like to reinstate my appreciation for the increase in women enrolled from 1.5 crore to close to 2.1 crore, indicating a 32 per cent jump in women enrolment. The ratio between male and female students in higher education is 1.01. That is a fantastic improvement. That means that more women are actually coming into education than before, and I appreciate the efforts of the Government in achieving that.

The Seventh Pay Commission was implemented in 2016 for faculty and teachers? salaries and also, for staff?s salaries across institutions in the State and the Centre. I think it has done a great job in making education an attractive employment opportunity for the citizens of India. We run a private university. We pay salaries and we are constantly competing with the Government institutions on attracting talent, and we still fight for talent vis-à-vis those who go to institutions like the IITs and IIMs. I think the benefits that the Government provides and the stability it provides really attract high-quality talent into educational institutions in the Government.

The private sector is growing. As was mentioned, about 50 per cent of the students and faculty are in private sector institutions. But I fear that many private institutions are not able to recruit faculty at the quality that the Government institutions are able to recruit.

Another measure that has come about a decade ago is the NIRF, the rankings for institutions across the country. I think, now, it has made a very clear race for the institutions everywhere, that if you want to get recognition and if you want to get access to funding, you need to do well on these rankings. I want to request the Government to pay more attention to this one aspect. I think, we have reached a good place now, but I would like it to become more qualitative in the future. There are some matrix which reward you for quantitative growth -- which is good -- but once we have reached some quantitative level of success, I think, the emphasis on quality -- whether it be the quality of publications, PhDs -- is going to be the next level for NIRF to lead institutions to the global rankings. There are some institutions in the Global 200 rankings from India today, and there can be many more. I think, we are well underway in that direction. I think, the evolution of NIRF is going to help us get in that direction.

Now, I am coming to some requests for our State, to begin with. The Ministry of Education ? (*Interruptions*) Sir, I am the only Member to speak from my Party. I think, our Party has about 20 minutes.

**HON. CHAIRPERSON:** Take one more minute.

**SHRI SRIBHARAT MATHUKUMILLI:** The Andhra University was committed to provide about Rs. 1000 crore over the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), and we have received some money in Phases I and II to the tune of Rs. 20 crore and Rs. 100 crore. The previous State Government has not paid its share, and hence, further devolution of funds has not happened.

So, my request is that the State is in a bad shape. This programme should continue to support Andhra University and the allocation to RUSA overall has increased to Rs. 1,814 crore this year for funding such State Universities across the country. I appreciate the intention of the Government to keep taking that forward.

Again, coming back to the Central University, the Central Tribal University of Andhra Pradesh, the IIM, the IIT, NIT, ICER, all Central Government institutions, many of which are in various stages of completion, I request the Ministry of Education and the Government to continue allocating funds in a speedy manner, and whatever support is needed from the State Government, we will provide it.

I would like to highlight in particular the Central Tribal University where a campus was allocated in my Parliament constituency during our regime between 2014-19 in the State when Mr. Chandrababu Naidu was the Chief Minister. But the previous

State Government had created a lot of confusion, tried to move it to a very different area where they did not allocate the land fully and the campus did not start. There is a request from the staff of the Central Tribal University to come back to the campus that was allocated in Kothavalasa Mandal in my Parliament constituency where 500 acres of land has already been allocated.

I would like to end with the recommendations to the Government on certain points. One is the One Nation One Subscription initiative where you give access to journals for the institutions across the country. If the Central Government can get that access, I think the institutions around the country will benefit. Integrating social and emotional learning into the Indian curriculum and encouraging alternative education models is critical because we have seen mental health challenges growing across the country and I think that support is essential for our education to change. Giving more support to repairs and maintenance is necessary. I see the Government institutions are suffering from lack of repairs and maintenance budgets.

And lastly and most importantly, I would like to request for a Budget on research on how outcomes of school education and outcomes of higher education are changing. Our Government school students are going to college and our college students are getting jobs. We need to track them with the help of Aadhar and create a national database and change the way we invest money into education because with the advent of AI, with the advent of technology, things around the world are changing and our education system does not seem to be equipped enough to face those changes. I would request the Central Government to invest into that research and change the way we invest our money into the future.

Thank you for this opportunity.

**श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) :** सभापति महोदय, आपका धन्यवाद । आज मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए 2024-25 के आम बजट में शिक्षा संबंधी डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लाकर एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है । इस शिक्षा नीति से रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । छोटे छोटे बच्चों को भी भारी-भरकम पुस्तकों का थैला लेकर विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा यह एक सराहनीय कदम है । माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एंव बिहार के माननीय मुख्य मंत्री विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया है । डबल इंजन की सरकार बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है ।

सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने शिक्षा, कौशल विकास पर जोर देने वाला रोजगारोन्मुखी और विकासोनमुखी बजट पेश किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं । इस बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के

लिए बजट आवंटन में 30% की वृद्धि हुई है । इससे यह राशि एक लाख 48 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि अपने आप में एक मिसाल है ।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है, उसे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए ई-वाउचर पेश किए गए हैं । भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक स्टूडेंट्स को दस लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन के लिए ई-वाउचर दिया जाएगा । ये ई- वाउचर्स हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को ऋण राशि के तीन प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर की छूट के लिए दिए जाएंगे । इस ऋण की राशि से आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवा सकेंगे । केंद्र सरकार का यह निर्णय स्वागतयोग्य है ।

सभापति महोदय, 15 साल से 29 साल के आयु वर्ग के केवल 4.4 प्रतिशत युवाओं ने औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है । इस हिसाब से बजट ने युवाओं के कौशल-सेट में सुधार के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना पेश की है । हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है, जो युवाओं के कौशल विकास में सहायक साबित होगा । इस बजट के प्रावधानों के तहत ई-श्रम पोर्टल को अन्य के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से कनेक्ट किया जा सके । इस योजना के माध्यम से 1,000 जॉब ट्रेनिंग सेंटर खोलकर 25,000 युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देने की योजना है ।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह भी अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र और पश्चिम चम्पारण जिले में भी इस तरह के जॉब ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, क्योंकि वहां रोजगार की संभावनाएं काफी कम हैं । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का डेवलपमेंट और कौशल विकास कार्यक्रम ?हब एंड स्पोक सिस्टम? के तहत पांच सालों में 1,000 आईटीआई डेवलप किए जाएंगे । सरकार के निर्णय का भी स्वागत होना चाहिए । इसके अंतर्गत राज्यों और उद्योगों के सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र अति पिछड़ा व जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है । इसलिए, इस 1,000 की सूची में बाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र के आईटीआई संस्थानों को भी शामिल कर उन्हें विकसित किया जाए, ताकि स्थानीय युवा भी तकनीकी व औद्योगिक प्रशिक्षण लेकर दक्ष हो सकें ।

**15.00 hrs**

महोदय, बजट में यह व्यवस्था की गई है कि शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप योजना के तहत भारत की शीर्ष कंपनियाँ 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण यानी स्किल ट्रेनिंग देंगी । 5 हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप उन्हें मिलेगी । सरकार से मेरा आग्रह है कि आज के महँगाई के दौर में यह राशि बहुत कम है । इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक किया जाना चाहिए ।

**15.01 hrs**

(Shri Awadhesh Prasad *in the Chair*)

महोदय, सरकार ने निर्णय लिया है कि कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएंगे । छात्रावास और क्रेच के जरिए कामकाजी महिलाओं की उच्च भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा । हमारी सरकार समग्र विकास के

लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी । साथ ही ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी । इस निर्णय का अभिनन्दन करते हुए मेरी सरकार से माँग है कि जनजाति बहुल बाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र के हरनाटांड, बेल्सेंडी के अलावा रतनपुरवा या कदमहवा में थारू व उरांव आदिवासी समाज की महिलाओं के लिए इस तरह के कामकाजी महिला छात्रावास स्थापित किए जाएँ ।

महोदय, अंत में, मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए सरकार से माँग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाल्मीकिनगर में केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए । बिहार के मधेपुरा लोक सभा क्षेत्र में भी एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए । सुपौल लोक सभा के बीरपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है । जमीन की रजिस्ट्री के लिए फंड दिया जाए ।

अंत में, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि महात्मा गाँधी की कर्मभूमि बाल्मीकिनगर ही है, नरकटियागंज में गाँधी दर्शन पर आधारित एक रिसर्च संस्थान खोला जाना चाहिए, जहाँ गाँधीयन स्टडीज की पढ़ाई होनी चाहिए । इसके साथ ही इस माँग पर सहमति जताते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**SHRI SANJAY UTTAMRAO DESHMUKH (YAVATMAL-WASHIM):** Hon. Chairperson, today's Indian education system is paralyzed with too many problems and challenges. We need to resolve these problems to provide quality and productive education. It is expected that there will be a significant improvement in education sector in the budget. During year 2013-14, the Education Budget was around Rs 70,000 crore, but it was only four per cent of the total Budget. Now, it is further reduced to 2.5 per cent only.

The cases of paper leak are rampant in our country. NEET-2024 paper leak case was given a wide publicity by the media. There is an organized education mafia which is working behind it in a planned manner. Around 60 students topped the NEET exam and six of them belonged to the same exam centre and this is a matter of grave concern.

I would like to ask the Govt to clarify how this has happened and why there are so many irregularities in the results. These exam papers leaked through various companies and lakhs of students had to suffer. It questions not only the exam mechanism but also the quality of doctors we are going to produce. A high-level Committee should be set up to investigate this scam thoroughly and also to take strict action to stop this kind of incidents in the future.

Sir, there is a huge gap between the quality of education being imparted in the urban and the rural areas. At Pusad, in Yavatmal district, only one teacher was available to educate 52 students. The Government schools in my constituency are in very bad shape. No teaching staff is available at schools to provide education. The construction of school buildings and appointments of teachers are two very important aspects. There is a sizeable tribal population in my constituency and

education is very important for them. To impart quality education and to protect their cultural identity, Eklavya Schools should be opened in the tribal areas for their overall development.

Kendriya Vidyalaya should also be opened in my Yavatmal District. In this way, the students residing in that area would get a chance to get quality

education through this Kendriya Vidyalaya. This school is not only a symbol of educational excellence but it also serves as a tool to improve the quality of education in that entire area. On the basis of the Performance Grading Index -2 declared by the Ministry of Education, the performance of Maharashtra has been deteriorated in comparison to other States. According to this Index, Maharashtra topped it during 2017-19 but it was at second position during 2020-21.

The budget allocation for UGC was around Rs 6,409 crore last year but it is only Rs 2,500 crore this year. This Budget has completely failed to provide the basic infrastructure like school buildings, teachers and staff for primary and secondary education. This Budget is creating a favorable atmosphere for privatization of school education. It would only promote the private schools and institutions. The gap between the rich and the poor would become wider as the poor cannot afford the fees of private schools.

Through the NEP-2020, it is recommended that around six per cent of the total GDP should be spent on education. But this Govt has allocated only 2.5 per cent of the GDP and it is not sufficient to ensure easy access to education for all.

Hon. Chairperson, through you, I would like to request the Union Government to promote investment in education, to distribute the resources equally, to develop infrastructure, to start continued training programme and also to provide financial assistance to the marginalized students.

I would also like to request the Government to provide the benefits of OPS to the retiring teachers and staff. But no budget provision has been made for it. It is my earnest request to you to resume the OPS once again for all the retired teaching staff.

Thank you.

**SHRI BHASKAR MURLIDHAR BHAGARE (DINDORI):** Hon. Chairperson, I would like to thank you for giving me this opportunity to deliver my maiden speech. I would also like to thank the voters of Dindori Lok Sabha Constituency. I also congratulate

the Finance Minister Nirmala Sitharaman for presenting her seventh Union Budget. Today, I rise to express my views on the Demands for Grants of the Ministry of Education. People were expecting a lot from this Budget but they are totally disappointed now. The farmers, youth, marginalized section of society -- all were expecting a kind of relief through this Budget but in vain. The Government?s Internship Scheme in the name of providing employment, is a complete eyewash. This so-called solution is not sufficient. Our Maharashtra gives the highest share in the GST collection but we have received very little.

Education is the very basis of any developed country but no significant allocation has been made for education. We are implementing the NEP gradually and phase-wise. I hail from Dindori, a tribal dominated area. No sufficient education infrastructure is available there. There is a huge gap between the educational facilities being provided in the rural and in the urban areas. To bridge this gap, a larger allocation for education is needed. The people and students residing in the rural areas are facing many problems and challenges in comparison to the urban population and that is why, necessary provisions should have been made in this Budget.

The students in the rural areas are also meritorious and full of talent but they are deprived of opportunities. They have to move to big cities to appear in the competitive exams like MPSC, UPSC etc. But due to their weak financial background, they cannot grab the opportunity. Hence, I would like to request you to kindly open a UPSC coaching centre at Nashik.

Olympic Games-2024 are being organized at Paris and our athletes are performing very well. There are many Olympians in my constituency like Kavita Raut, Monica Atre and Dattu Bhokanal who had represented Dindori, Maharashtra State and our country too. One Sports Academy should be opened in my constituency to sharpen this sports talent.

The tribals from the places like Ped, Dindori, Kalvan, Surgana move to other places to earn their livelihood. So, their children?s education gets hampered due to this migration. Hence, I would like to request you to provide employment opportunities by setting up MIDC like projects. The intake capacity of ITs and the number of courses should be increased.

The UGC grant has been decreased by 61 per cent and it would have an adverse effect on higher education. It would lead to create problems in providing

scholarships, fellowships and also to continue with quality research programmes. The students deposit the fee online for the competitive exams but due to paper leak cases, they get demoralized. The Government should bring a full proof mechanism to curb this menace.

There are many Constitutional provisions made to provide free and compulsory education to the students aged 6-14 years. The Sarv Shiksha Abhiyaan is also being implemented to ensure primary education to all. It is also to ensure development of educational infrastructure, 100 per cent enrolment and registration of students, 100 per cent attendance, to provide quality education, to reduce social and gender gap and to improve learning capacity etc.

It is mandatory for the Government to provide basic infrastructure and other facilities under the RTE Act. But still many challenges and problems are being faced by the teachers and students too.

We only keep on talking about providing quality education to the poor and marginalized students but how can it be ensured without employing good teachers? The Government is not ready to provide the benefits of OPS to our new teachers. Our teachers are divided on the basis of pension scheme.

In tribal areas, the vacant posts of teachers should be filled immediately. There are many students? welfare schemes which should be implemented properly. Other assignments should not be given to teachers. The schools with lesser number of students should not be closed. I am also a teacher by profession.

Thank you.

**श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) :** महोदय, आज शिक्षा के बजट पर हो रही चर्चा पर बोलने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । महोदय, मैं आज सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी को नमन करता हूँ । उनकी आज पुण्यतिथि है । साथ ही, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी की जयंती है । महोदय, आज हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, जिसे विकसित करने का काम लोकमान्य तिलक जी ने किया है । एक अध्यापक के तौर पर और फिर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी ।

महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, जो महात्मा ज्योतिबा फूले और सवित्री बाई फूले की भूमि है, जिन्होंने महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा का अभियान शुरू किया था । हम आज शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं । उसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र में शाहूजी महाराज ने की थी, जब कोल्हापुर में उन्होंने 1917 में फ्री एण्ड कंपलसरी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन शुरू किया था । हमारा भारत देश उस संस्कृति का जनक है, जिसने शिक्षा और शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया है ।

महोदय, एक शिक्षक भारत को एक विकसित भारत बना सकता है । एक शिक्षित भारत ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा कर सकता है और शिक्षित भारत ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है ।

महोदय, मैं पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी की एक बात का स्मरण करना चाहूंगा । उन्होंने कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करना भी सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है । मैं उनकी विचारधारा को नमन करता हूँ, जिसने भारत की संस्कृति को सम्मान देने का काम किया है । एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं, जो औरंगज़ेब और मुगलों की संस्कृति का प्रचार करते थे और हमारे स्कूली शिक्षा की हर कक्षा में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता था । लेकिन कांग्रेस वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में कुछ नहीं बताते थे । आज उस विचारधारा को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है । भारत की भाषा चाहे मराठी हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, सबको सम्मान दिया है, जिसमें आज गांव का बच्चा भी, पूरे विश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहा है ।

Hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji is implementing the NEP and this is a revolutionary decision. This policy would bring sweeping changes in the Indian education system and it has been designed to impart world-class education. We need to welcome this change with positive attitude. It is an important step taken to ensure independent and self-reliant India. The development of any country solely dependent on educational progress. The main objective of this NEP is to help India to become a world power.*

अभी हमारे विपक्ष के एक साथी नीट पर सवाल कर रहे थे । मैं उनको बता दूं कि यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है । यह सरकार भारत के युवाओं के बारे में सोचती है । नीट में भी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है । जल्द ही सारी प्रणाली फिर से बेहतर ढंग से शुरू हो जाएंगी । पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य देश के युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है । उन्हें विश्व के सामने एक सशक्त नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना है ।

महोदय, सबसे पहले हम विद्यालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग की बात करें, तो यह गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 73,498 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है । यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है । वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान से वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन में 12,024 करोड़ रुपये (19.56%) की कुल वृद्धि हुई है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के लिए अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन क्रमशः 9,302 करोड़ और 5,800 करोड़ रुपये देखा जा सकता है । समग्र शिक्षा योजना में 4,500 करोड़ रुपये की वृद्धि, पीएम-पोषण योजना में 2,467 करोड़ रुपये की वृद्धि और पीएम-श्री योजना में 3,250 करोड़ की वृद्धि की गई है, जो वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में अधिक है ।

अगर हम उच्च शिक्षा विभाग की बात करें, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल बजट आवंटन 47,619.77 करोड़ रुपये है, जिसमें योजना आवंटन 7,487.87 करोड़ रुपये और गैर-योजना आवंटन 40,131.90 करोड़ रुपये है । वर्ष 2024-25 के लिए उच्च शिक्षा विभाग के बजट आवंटन में वर्ष 2023-24 की तुलना में 3,525.15 करोड़ रुपये (7.99%) की कुल वृद्धि हुई है ।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आवंटन 15,928.00 करोड़ रुपये रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से वर्ष 4,314 करोड़ रुपये से अधिक है । स्वायत्त विश्वविद्यालयों को वर्ष 2024-25 में 596 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 से 96 करोड़ अधिक है । आईआईटी के लिए वर्ष 2024-25 में 10,202.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 841.00 करोड़ रुपये से अधिक है । एनआईटी के लिए वर्ष 2024-25 में 5,040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 219.40 करोड़ रुपये की वृद्धि है ।

प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (PM-USHA) के लिए बजट 1,814.94 करोड़ रुपये रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 314.94 करोड़ रुपये अधिक है । प्रतिष्ठा संस्थानों (IOE) के लिए 1,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 300 करोड़ रुपये अधिक है । प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए वर्ष 2024-25 में बजट आवंटन 1,558 करोड़ रुपये रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 4 करोड़ रुपये अधिक है ।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) के लिए वर्ष 2024-25 में 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 160.00 करोड़ रुपये अधिक है । आईसीटी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन योजना के लिए वर्ष 2024-25 में 480 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 80 करोड़ रुपये अधिक है ।

बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान में तकनीकी शिक्षा-ईएपी (MERITE) योजना के लिए वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वर्ष 2023-24 के आवंटन से 100% अधिक है । कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्र (CoEs) की स्थापना योजना की घोषणा वर्ष 2023-24 में की गई थी । वर्ष 2024-25 में इसके लिए 255 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

पिछले 10 वर्षों में भारत में 7 नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेजेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं । मेरी सरकार लगातार भारत के युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास के लिए नई पहल कर रही है । इसके लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है । इसे तेजी से लागू किया जा सकता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया गया है । इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में शुरू हो गई है । स्कूल छात्रों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार 14,000 से अधिक पीएमश्री विद्यालयों पर काम कर रही है । इनमें 6,000 से अधिक स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है । मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट दर कम हुई है । उच्च शिक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ा है । अनुसूचित जाति के लिए छात्रों का नामांकन लगभग 44 प्रतिशत बढ़ा है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन 65 प्रतिशत से अधिक ओर ओबीसी के छात्रों का नामांकन 44 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है ।

Sir, more than 10 per cent of the colleges and more than 25 per cent of the colleges of National Importance are in Maharashtra.

Sir, give me a minute's time. We also have the best quality private institutions in Maharashtra.*

माननीय सभापति **:** माननीय प्रताप षडङ्गी जी, आप अपना भाषण शुरू करें ।

? (व्यवधान)

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी **(**बालासोर**) :** सभापति महोदय, धन्यवाद । मैं शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों के समर्थन में कुछ बोलना चाहता हूं । The budget allocation is Rs. 1,21,117 crore. This Budget is quite revolutionary under the able leadership of our champion, Shri Narendra Modi ji, our hon. Prime Minister. The Budget in general and the Demands for Grants in particular are very crucial for the implementation of the National Education Policy which is aimed at transforming the entire system of education. The role of the hon. Minister of Finance, Shrimati Nirmala Sitharaman, and our hon. Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan, is very significant in this process.

महोदय, मैं कल्पना में हजारों साल पहले ले जाना चाहता हूं । वैदिक युग में हमारी शिक्षा व्यवस्था सारे विश्व में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । प्रतापगढ़ से एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था । यह एक अपवाद है । द्रोणाचार्य ने अंगुली काट ली, इसको हम पाप मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थिति ऐसी नहीं थी । बाजार में कोई 5 पैर वाली गाय देखने से प्रबन्ध में गाय के पांच पैर नहीं लिखे जाते हैं । ?(व्यवधान) गार्गी, मैत्रेयी, विश्वम्भरा, अपाला, घोषा, ऐशा, ब्रह्मवादिनी, ऋषिका उस समय में निकले थे । पहले नारी शिक्षा भी थी । हर एक जाति में शिक्षा थी । शिल्पशास्त्र, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, आयुध शास्त्र, महाकाश विज्ञान, अणु विज्ञान, यांत्रिकी, ऋतु विज्ञान आदि सारे विषयों में, हमारे देश में ज्ञान-विज्ञान का अविष्कार हुआ था । अगर शून्य का अविष्कार भारत में नहीं होता तो गणित आज कितना असहाय हो जाता । ज्यामिति, त्रिकोणमिति सब भारत से निकले हैं ।

सर, हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली का विशेषत्व क्या था? आज तो हम गरीबों के लिए स्टडी लोन, स्कॉलरशिप की बात करते हैं । लेकिन उस जमाने में गरीब हो या अमीर हो, राजपुत्र हो या भिखारी हो, सबको मुफ्त में शिक्षा देने की गारंटी थी । यह गारंटी क्या है? जब यूरोप और अमेरिका में कोई एक विद्यालय भी नहीं था । इस देश में गांव-गांव में, वनारण्य में आरण्यक विश्वविद्यालय था । नालन्दा, तक्षशिला, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, पुष्पगिरी में जगत विख्यात विश्वविद्यालय हमारे देश में थे और सारे विश्व से विद्यार्थी लोग आकर यहां विद्या अध्ययन करते थे । इनमें फूडिंग फ्री, लॉजिंग फ्री, क्लोदिंग फ्री, एजुकेशन फ्री होती थी । ऐसी व्यवस्था हमारे देश में थी, जो आज किसी देश में भी है । अरण्य में प्रकृति निवास, प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण लव फॉर नेचर डेवलप करता था । आज कितनी निर्दयता से, क्रूरता से, निष्ठुतरता से, वैधव्य से पेड़ों को काटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं था । आधुनिक काल में दो महात्माओं ने, बंगाल के महात्मा रबीन्द्र नाथ ठाकुर और ओडिया के पुण्यात्मा, गोपबंधु दास ने वन विद्यालय प्रारम्भ किया । इनमें प्रकृति के साथ बैठकर पेड़ों के नीचे शिक्षा का लाभ लेते थे । आज भी विश्वभारती में यह व्यवस्था है ।

प्रकृति के परिवेश में मन की एकाग्रता सिद्ध होती है । शिक्षा के लिए पहली आवश्यकता है-श्रद्धा और एकाग्रता । आज यांत्रिकी सभ्यता में एकाग्रता विछिन्न हो गया है । एकाग्रता इस शक्ल ग्यारह लाख का आधार है । विश्वविद्यालय में सभी को समान अपॉच्युर्निटी मिले, equal opportunity for all; equal treatment for all. That is the speciality of our education. हमारा करिकुलम क्या था? सारे विषयों में था, इसके अतिरिक्त, कृषि, कुटीर, शिल्प, गणित और व्याकरण सब था । इसमें जो निकलता है, कभी नौकरी और भीख मांगने के लिए किसी के द्वार पर नहीं जाता है ।

आज हम सगर्व बोलते हैं, एडम स्मिथ, फॉदर ऑफ मॉर्डन इकोनॉमिक्स, मैकियावेली, फादर ऑफ पॉलीटिकल साइंस, लेकिन हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझने की ताकत नहीं रखते हैं । जो वास्तव में दुनिया में अर्थ तत्व का ज्ञान और विज्ञान सारा दुनिया को प्रदान करता है । हम इसका ताकत नहीं जानते हैं क्योंकि संस्कृत भाषा के प्रति हमारा विद्वेष और अज्ञानता के कारण इस भाषा पेटिका में इस विषय को हम जानते नहीं हैं । ऐसे शिक्षण पद्धति से इंटीग्रेटेड ह्यूमन बिइंग आ रहे हैं । इसका उद्देश्य था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन । अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन किया, हमारी मूल शिक्षा को ध्वंस कर दिया । लार्ड मैकाले ने जब इंग्लिश एडुकेशन सिस्टम इधर चालू किया तो ब्रिटेन में हल्ला हो गया कि भारतीयों को शिक्षित करना है, उनके पिता जी और उनकी सिस्टर चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में उसने जो मार्मिक उत्तर दिया, ? My dear father, I am not educating Indians. India was 100 per cent educated by the time. I am making them fools. My dear father, I am going to introduce such a pattern of education in India by which Indians will be on par with Europeans in test, and no Hindu will remain a Hindu without the slightest attempt to proselytize 10 years since.? Sir, this was an imperial design of the British people and we fell prey to it. अंग्रेजों ने हमारे देश की शिक्षा और शिल्प को समाप्त कर दिया । वेदों में बताया गया, विद्या दरिद्रता से मुक्ति प्रदान करता है, अज्ञानता से मुक्ति प्रदान करता है, अपूर्णता से मुक्ति प्रदान करता है, दुर्बलता से मुक्ति प्रदान करता है, जन्म-मरण चक्र से मुक्ति प्रदान करता है । वेदों में एक प्राचीन ऋषि को जब उनके ब्रह्मचारी शिष्यों द्वारा पूछा गया,

?स्मिन नु भगवो विज्ञाते सर्वानिंद विज्ञातं भवतीति । ?

Is there any principle through which we can learn the whole universe? Is there any common principle? जैसे पानी का धर्म क्या है, H2O, दुनिया में कितना पानी है, समुद्र का पानी है, कुएं का पानी है, सब पानी का कॉमन प्रिंसपल है । Is there any common principle? The teacher answers, yes. There is a common principle.

?दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद ब्रह्म विदोवदन्ति पराचैव अपराश्च ।?

दुनिया में दो प्रकार की विद्या होती है, एक होती है अपरा, दूसरी होती है परा । हमारे ऋषि लोग पहले साहस करके बताया दुनिया में जितना ज्ञान-विज्ञान आवरण करता है, इतिहास गणित, भूगोल, विज्ञान, दर्शन, वेद, उपनिषद पर्यंत सब है, अपराविद्या । जो दृश्यमान नहीं होता है, सबके अंदर शक्ति रूप में विराजित है, उनको ज्ञान प्रदान होता है, परा विद्या मानते हैं । Education brings out this potentiality in the human being. What is education? Education is not just book learning. Swami Vivekananda asks what is education? Is it book learning? No. Is it diverse knowledge? No, not even that. He says, ?the training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education.? Since our current and expression are not brought under control, we say something nonsense sometimes. So, we have to be educated. It means our mind has to be educated. He further says, ?Education is the manifestation of perfection achieved in a man. Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot

there, undigested all your life.? How does it remain undigested? हम इस हाऊस में सुनते हैं, देखते हैं ...* चलती है, कोई संविधान को पकड़ कर आता है ।

Even devils can quote scriptures for their own purpose. जो आज गणतंत्र की बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को विभाजित किसने किया? जो भारत जोड़ो कार्यक्रम चलाते है, वे कौन सी लीगेसी को लेकर प्राइड करते हैं? वे जिस लीगेसी पर गर्व करते हैं, उसी लीगेसी ने देश को बार-बार खंडित किया ।? (व्यवधान)

सर, हमने कभी नहीं बोला था । ? (व्यवधान) एक मान्यवर सदस्य ने कहा कि हम मुगल हैं, जब मुगल जब आए थे, आप मुगलों को उखाड़ कर नहीं फेंक सके । सर, इस देश में विदेशी आक्रांता, जो तादाद में आकर अपने संबंध स्थापित करते हैं, वह इस देश के नहीं है । मैं साहसपूर्वक कहता हूं, हम रहीम और रसखान का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन हम आक्रांता जैसे बाबर, तैमूरलंग और नादिरशाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे । उनकी औलादों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मान्यवर, अपना भाषण समाप्त करें ।

? (व्यवधान)

**SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI:** Sir Swami Vivekananda said: ?We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded and by which one can stand on one?s own feet.? इस बजट में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत व्यवस्था है । नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है । जिन्होंने इस देश पर लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार करने की कोशिश नहीं की । सपना भी नहीं देखा क्योंकि कोई विज़न नहीं था । मान्यवर, मोदी जी का विज़न है, मिशन है, सपना है । सपना क्या है? अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपना वह नहीं होता है जो रात में सोते हुए देखते हैं, सपना वह होता है जो दिन और रात में सोने ही नहीं देता है । मान्यवर, मोदी जी ने जो सपना देखा वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है ।

Our universities, for more than 50 years, took it for granted that remembrance is the only criterion of knowledge. Had it been so, then encyclopaedias would have been the greatest of Rishis and Professors. But that is not so. The inner perfection is to be drawn out, and we cannot reach perfection because we are already perfect. That is to be discovered.

I remember one incident. Newton was a big scientist. He was walking on the road. He saw that an apple was falling. He asked to himself, ?Why the apple is falling? Why is it not going upward or downward? Why is it not going southward or northward or eastward or westward?? He asked this question to himself. He thought over it very deeply. He meditated on it and discovered a missing link in his own brain and named it the Law of Gravitation. If somebody discovers a truth in

the material world, he is called a scientist. If somebody discovers a truth in the spiritual world, he is called a Rishi.

?ऋषया: मंत्र दृष्टार: न तु वेदस्य करणम्,

नकश्चित् वेद कर्तारम् वेद स्मर्ता चतुर्मुखम् ।?

The National Education Policy has been designed to fulfil this objective. The Demands for Grants are also designed to fulfil this great goal.

Swami Vivekananda said: ?What we say learning is in strict psychological sense what we discover.? But this discovery was thrown out of the Congress administration. They were only getting by heart. That was the method of their teaching. We spend so much energy on processing crude energies, coal, petroleum and draw out saccharine, radium and all that, but we never spent so much of money during the Congress period on processing human energy. Education is nothing but processing of human energy. What is the limitation? Sky is the limitation. Infinite potentiality, tremendous possibility is there within every human being. This has been recognised in this National Education Policy. Modi ji revolutionised this idea. A nation is not great and good because its Parliament is efficient. A nation is great and good because its people are great and good with integrity. अंग-अंग में बल विक्रम भरा, तेजस्वी, ओजस्वी चरित्रवान, देशभक्त, राष्ट्रभक्ति में ओतप्रोत, अन्याय के प्रतिकार करने में सामर्थ्यशाली, ऐसे संगठित सामर्थ्य के अधिकारी नवयुवकों का निर्माण करना, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ध्येय है । इसके आविष्कर्ता मान्यवर नरेन्द्र मोदी जी हैं ।

सर, ढाई लाख गांवों से, पंचायतों से जो सुझाव आए, दीर्घ विचार-विमर्श के बाद, विचार मंथन, समुद्रभूत अमृतधारा वाली यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और हम इसे क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ।

**SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to take part in the discussion and voting on the Demands for Grants under the control of Ministry of Education.

Hon. Chairperson, Sir, a university stands for humanism; for tolerance; for reason; for the adventure of ideas; and for the search for truth. It stands for the onward march of human race towards ever higher objectives. These were the lofty ideals of a vision unfolded by Shri Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of our country. This vision embodied the spirit of our freedom struggle which sought to create an India, which is self-reliant, not only in economic terms, but also, in terms of intellectual and scientific manpower. But today, education in India is in a deep

crisis. It is facing several problems, and this year?s budget, has no proposal or vision to address these concerns.

It is an accepted fact that the money well spent on education will be critical in improving the employability and productivity of the future generations. But this Government has failed to live up to its own promise of allotting six per cent of the GDP to the education sector. In fact, the current allocation of only 2.51 per cent of the total budget represents a decrease from the 2.57 allotted in 2023. Compare this with the annual allocation for education by other developing nations. Brazil spends six percent of its GDP on education. South Africa and Indonesia spend 6.6 per cent and 3.5 per cent respectively. We should be ashamed of this paltry sum that we spend for education. How can we expect to become a knowledge-society if we cannot provide adequate resources for education? The reduced allocation reflects this Government?s policy of centralization of education sector in flagrant disregard of the federal concept.

Hon. Chairperson, Sir, this Government has an inherent apathy towards the institutions that have raised our prestige in the international arena. The IITs and IIMs are the symbols of excellence across the globe. There should have been efforts to strengthen these institutions by providing them all the help they need. But since 2014, fees in these institutions have been increased many times. And above all that, this year?s budget has experienced a reduction in the allocation to these institutions compared to the last year. The allocation for the IITs has been reduced from Rs. 560 crore to Rs. 515 crore. The allocation for the IIMs has been reduced from Rs. 300 crore to Rs. 212 crore. Is this the way a responsible Government treats its premier institutions?

Hon. Chairperson, Sir, India cannot boast of a single university in the world?s top 100. This should have been a matter of deep concern for a country with the largest population in the world, and it should have been addressed with top priority by focusing on, at least, a handful of such institutes with the intent that some of them would make it to the top listings soon.

Hon. Chairperson, Sir, funds should have been earmarked for this in the Budget. But this Government has no respect for excellence in the intellectual arena. Our once great institutions of learning are beset by multiple crises -- a financial crunch at the university level, a deficit in research opportunities for faculty, and poor infrastructure and learning outcomes for students. This apathetic and anti-academic Government is preventing universities from blooming. The students and

teachers of this country are not free to express their opinions. Great centres of learning flourish only when there is an atmosphere conducive for enquiry and independent research.

The Freedom House Political Advocacy NGO, which publishes annual index of the degree of political freedom in the countries of the world, has said in its 2024 report for India that I quote-

?Academic freedom has significantly weakened in recent years as Professors, students and institutions have faced intimidation over political and religious issues.?

Faculty members and students have time and again been suspended for criticizing and protesting against the Government. The atmosphere of fear that the hon. Leader of the Opposition, Shri Rahul Gandhi ji has been talking about which pervades in all walks of life in this country and has gripped the education sector also.

It is like a garden filled with hundreds of beautiful flowers when new generations come together in a campus, transcending differences in caste, religion, language and culture. Please do not destroy this wonderful social fabric of the country with communal divisions.

This atmosphere of fear that exists in the educational field is forcing the students to flee from this country. In the recent years, there has been a surge of Indian youth migrating abroad for studies, crossing 7.5 lakh in 2022 and 8.5 lakh in 2023. One of the major implications of migration due to educational opportunities is brain drain which leads to a loss of human capital. The ruling party and its affiliates are responsible for this grave situation.

The marginalized sections of this country got education not only because of the efforts of Governments but also the interventions of the missionaries and visionary leaders. Their service was not restricted to any one community. They provided universal education. Saint Chavara Kuriakose Elias was the pioneer of Dalit and weaker section's education in the State of Kerala. When people belonging to these marginalized sections did not even have the right to walk on the public roads, these institutions provided them with quality education. I am happy to inform this august House that in 1846, Saint Kuriackose founded the first Catholic Sanskrit School at Mannanam. The slogan of the Saint was 'a school for a church'. We cannot forget the contributions of social reformers and educationalists like Mannath

Padmanabhan and R Shankar. They have contributed immensely for establishing educational institutions and uplifting the downtrodden and dalit communities in the state. The first President of the Indian Republic from the dalit community Dr. K R Narayanan and the first dalit Chief Justice of the Supreme Court KG Balakrishnan were all products of these institutions. Both are from my district. I am proud of that. The current crop of the rabid communal elements may not be aware of the great contributions these institutions have made to our nation. These elements are creating an atmosphere of fear in the institutions run by the Christian community. Your Government in various States are arresting and persecuting the Christians on flimsy charges. This is not only a disgrace considering the great contributions rendered by the community in the field of education and healthcare for the most backward people but also denies opportunities for the weaker sections to get educated. The Union Government should ensure the security of the Christians and their institutions if you are serious about the welfare of the poorer sections of our society. You can find Keralites in every nook and corner of the world because of the quality education and their attitude towards people. The total remittances from the Non-Resident Keralites also reached a record Rs. 2,16,893 crore in 2023, which is threefold of Kerala's annual budget.

Sir, our State has been repeatedly requesting for the establishment of an AIIMS in Kerala. But it was denied. We strongly demand for an AIIMS in our State, Kerala. My constituency, Pathanamthitta has a literacy rate of 97 per cent which is among the highest in the country. But higher educational opportunities are very limited in the region.

The distance to the nearest Central University from Pathanamthitta is 500 kilometres. The Central University of Kerala started a South Campus School of Legal Studies at Thiruvalla in my constituency, Pathanamthitta. In this connection, I would like to express my sincere gratitude to the former Chief Minister of Kerala, Late Shri Oommen Chandy who granted 10 acres of land, valued approximately Rs.200 crore, for setting up of the South Campus on my interventions. I request the hon. Minister for Education to start a full-fledged University Campus with more courses and teaching staff in the South Campus at Thiruvalla.

According to the latest data of Centre for Monitoring Indian Economy(CMI), the unemployment rate stood at 9.2 per cent in June, 2024. It is a sharp increase from 7 per cent in the month of May, 2024. If the trend continues like this, it will reach up to 11 per cent. The number of unemployed persons is increasing day by day. Many

of them have taken educational loans for their studies. But they are not in a position to repay their loans. Therefore, I request the Government to reduce the rate of interest on educational loan.

Gandhiji believed that education should teach individuals to seek truth, speak the truth and practice non-violence in all aspects of life. But this Government is far away from it. With these words, I conclude my speech. Thank you. Jai India.

**श्री राजेश वर्मा (खगड़िया) :** सभापति महोदय, आज आपने शिक्षा पर अनुदानों की मांग पर हो रही चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं बिहार से आता हूं और जब शिक्षा की बात हो तो बिहार के दो विश्वविद्यालयों को कभी नहीं भूला जा सकता है । वे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं । जी-20 के समय जिस प्रकार से आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने नालंदा की विरासत को पूरे विश्व के सामने सम्मान देने का काम किया है, हम सभी बिहार के लोग अपने प्रधान मंत्री जी का कोटि-कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं । एक युवा सांसद होने के नाते मुझे इस बात का भी आभास है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या वर्तमान और भविष्य दोनों तरीके से देखें तो जहां एक अवसर दिख रहा है, वहां एक चुनौती भी है । एक शिक्षित भारत ही पांच ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है ।

सभापति महोदय, हम लोगों को गर्व होता है कि आज गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या आईबीएम हो, इन सबका नेतृत्व एक भारतीय कर रहा है । आज भारत पूरे विश्व को इंजीनियर्स और डॉक्टर्स देने का काम कर रहा है । यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की देने है और इसी शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूती देने का काम हमारी सरकार ने किया है । इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । बजट में घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है, जिससे प्रति वर्ष एक लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे । इस वर्ष के बजट में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,928 करोड़ रुपये आवंटित किए गए । वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का कुल बजट आवंटन 2023-24 में 1,12,899 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,20,627 करोड़ रुपये से 6.8 प्रतिशत बढ़ा है । आईआईटीज़ को इस वर्ष 1,202 करोड़ रूपये आवंटित किये हैं, जो पिछले वर्ष 841 करोड़ थे । एनआईटीज़ को 5,040 करोड़ रुपये दिए गए, जो पिछले वर्ष 4,820 करोड़ रुपये थे ।

सभापति महोदय, आम बजट भाषण, 2024 में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी पांच खूबसूरत स्कीम लॉन्च की हैं, मैं उस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें पहली स्कीम फर्स्ट टाइम एंप्लॉयमेंट स्कीम है, जिसमें 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 3 किश्तों में 15 हजार रुपये की मदद दी जाएगी । दूसरी स्कीम है - जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग । इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एंप्लॉइज को EPFO जमा करने के आधार पर शुरुआती 4 सालों में इंसेंटिव दिया जाएगा । इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा ।

तीसरी स्कीम- सपोर्ट टू एम्प्लॉयर । इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने में मदद करेगी । इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रिब्यूशंस (Combin पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3 हजार रुपये का रीइम्बर्सेमंट करेगी ।

चौथी स्कीम - पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल, फ्रेश और कई तरह के विमेन स्किलिंग प्रोगाम शुरू किए जाएंगे ।

पांचवी स्कीम ? स्किलिंग । इसके तहत 20 लाख युवाओं को 5 साल में खास स्किल्स से ट्रेनिंग दिया जाएगा । 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे । हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा । सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी ।

सरकार ने 2014 से 2024 तक 7 नए IIT और 7 नए IIM खोले हैं । देश में 3 हजार नए ITI बनाए गए हैं । 16 IIITs और 390 यूनिवर्सिटीज शुरू की गयी हैं और पिछले 10 सालों में हायर एजुकेशन में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है ।

आज, विभिन्न स्टार्टअप्स के माध्यम से, युवा विश्वभर में भारतीय ध्वज को ऊंचा उठा रहे हैं । पिछले 10 वर्षों में, उच्च शिक्षा संस्थानों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 316 से बढ़कर 480 हो गई है, तकनीकी विश्वविद्यालयों की संख्या 90 से बढ़कर 183 हो गई है, और कॉलेजों की संख्या 38,000 से बढ़कर 53,000 हो गई है ।

माननीय सभापति महोदय, इन सभी के विकास और बेहतर शिक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) के माध्यम से 5116 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में 7.07 लाख छात्राएं पढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री उन्नत भारत विद्यालय (PM-SHRI) के माध्यम से 14,500 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जा रही है । इस वर्ष में 10,080 PM-SHRI स्कूलों के लिए 5942.21 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं एक प्रमुख विषय बिहार का भी है, उसको यहां उठाना चाहूंगा । यह सैशन डिले का विषय है । जहां एक तरफ बिहार के हमारे नौजवान साथी शिक्षा-दीक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं यूनिवर्सिटीज़ का सैशन तीन साल के बजाय पांच सालों में पूरा होता है, जिससे वह आने वाली पढ़ाई को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । यह बात बिहार की है तो मैं कहना चाहूंगा ?

?बीज बो लो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे

आप दिशा दे दो, बिहार के नौजवान इस राष्ट्र को संवार देंगे ।?

महोदय, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि खगड़िया तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग कर रहा है । मैं चाहूंगा कि इस ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट हो । इसके अलावा जितने भी हाई स्कूल्स हैं, उनको मॉडल स्कूल्स के रूप में परिवर्तित किया जाए । ज्यादा न कहते हुए मैं अंत में कहना चाहता हूं ?

?तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी

और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी ।?

महोदय, मैं शिक्षा की अनुदानों की मांग का पूरा समर्थन करता हूँ और आदरणीय प्रधान मंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री सुधाकर सिंह **(**बक्सर**) :** माननीय सभापति महोदय, मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में संघीय बजट वर्ष 2024-25 के बारे में अपनी ओर से देश के नागरिकों की चिंताओं को सांझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

**16.00 hrs**

(Shri Krishna Prasad Tenneti *in the Chair*)

यह बजट देश की शिक्षा के विकास के प्रति प्रतिबद्ध दिखाई नहीं दे रहा है । कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुमान से कम निवेश होने से हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव को खतरे में डाल दिया गया है । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी प्रगतिशील समाज की नींव होती है । यह व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, नवाचार को बढ़ावा देती है और देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करती है । तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में हमारी शिक्षा प्रणाली के द्वारा छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और फलने-फूलने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए । शिक्षा में निवेश भारत को तीव्र गति से आगे ले जाएगा, मगर पिछले 10 वर्षों में यह देखा जा रहा है कि लगातार शिक्षा में निवेश कम किया जा रहा है और संविधान के निर्माताओं की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विखंडित किया जा रहा है । इस कारण से राज्य अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं और युवा त्राहिमाम कर रहे हैं । यह बजट देश के नागरिकों के बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर रहा है । यह बजट आज की आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम है जैसे कुपोषण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और डिजिटल विभाजन । इस बजट में कहीं भी इसकी चिंता नहीं की गई है । इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धनराशि का 90 प्रतिशत भाग केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में जा रहा है, जहां देश के 10 प्रतिशत से भी कम छात्र पढ़ते हैं, वहीं यूजीसी मानकों पर आधारित राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों में मात्र 10 प्रतिशत बजट जा रहा है, जहां पर 90 प्रतिशत छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं । यह स्थिति बेहद दुखदपूर्ण है ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल आवंटन राशि 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये की है । इस धनराशि के बावजूद शिक्षा क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए यह धनराशि अपर्याप्त है । वर्ष 2013-2014 के बजट में भारत अपनी जीडीपी का लगभग 4.77 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहा था और 6 प्रतिशत की सिफारिशी खर्च की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश में नई सरकार बनी और उसके बाद से यह आवंटन लगातार घट रहा है और अब यह मात्र 2.5 प्रतिशत का रह गया है, जिसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है और जो लगभग 65,000 करोड़ रुपये है ।

यदि हम इसे आवंटित राशि से हटा दें, तो हमारे पास केवल 55,000 करोड़ रुपये बचते हैं, जो अन्य देशों की तुलना में कुछ भी नहीं हैं । लगभग 2.5 प्रतिशत जीडीपी का वर्तमान आवंटन ?विश्वगुरु? बनाने की महत्वाकांक्षा को साकार करने में असफल साबित होगा ।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी का बजट वर्ष 2023-24 में 6,409 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में मात्र 2,500 करोड़ रुपये हो गया है, जो 61 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है । ऐसी कटौती को स्थापित सार्वजनिक संस्थानों को कमजोर करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है । अगर इस तरह से कटौती जारी रहती है तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली की बुनियादी संरचना को ठीक नहीं कर पाएंगे ।

इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए आवंटन वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों में 57 हजार 244 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2024-25 में 47 हजार 620 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16.8 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है । इस देश में सरकार चलाने वाले लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश नहीं करना चाहते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, यह कठोर कटौती हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास और रखरखाव को कमजोर करती है, जिससे शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता प्रभावित होगी । स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए बजट में केवल एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि की गई है । बच्चों में कुपोषण और अपर्याप्त स्कूली बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हुए यह मामूली वृद्धि अपर्याप्त है । पीएम-पोषण के बजट में कटौती और बच्चों में कुपोषण के निरंतर मुद्दों के साथ इस समस्या को हल करने के लिए आवंटन को काफी बढ़ाने की आवश्यकता है । आंगनवाड़ी के लिए बजट, जो कि बाल पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे 1.5 प्रतिशत कम कर दिया गया है । पीएम-पोषण योजना पहले से ही पर्याप्त धनराशि के अभाव में संघर्ष कर रही है ।

विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का पीएम-यूएसपी योजना में विलय खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में चिंताएं बढ़ाता है । यह विलय वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की पहुंच को सीमित कर सकता है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है । सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बजाय ऋण लेने के लिए मजबूर कर रही है । हम देख सकते हैं कि वंचित और हाशिये पर जो समाज है, उनके लिए छात्रवृत्तियों में हाल के समय में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है और मजबूरन लोग शिक्षा ऋण की तरफ मुड़ रहे हैं ।

सरकार यहां तक कि देश के प्रसिद्ध उच्च शिक्षा संस्थान जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गठित HEFA से ऋण लेने पर मजबूर कर रही है । ऋण की अदायगी के लिए ये संस्थान फीस बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे और देश में उच्च शिक्षा महंगी होती जाएगी एवं जो गरीब पढ़ना चाहते हैं, उनको उच्च शिक्षा हासिल नहीं हो पाएगी ।

वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए, उच्च शिक्षा को एक महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और कम से कम जीडीपी का छ: प्रतिशत खर्च करना, उच्च आवंटन प्राप्त होना चाहिए । अंतरराष्ट्रीय उदाहरण सुझाते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान एवं विकास में बढ़ा हुआ निवेश समृद्ध देश बनाने में सहयोग करता है । हमें विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास और अनुसंधान के लिए बड़े पैमाने पर बजट आवंटनों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता देखने की जरूरत है । भारत अनुसंधान एवं विकास खर्च में पिछड़ रहा है, जो केवल जीडीपी का 0.7 प्रतिशत आवंटन कर रहा है, जबकि जैसे चीन 2.64 प्रतिशत और अमेरिका 3.44 प्रतिशत या यहां तक कि विश्व औसत 2.6 प्रतिशत से भी कम भारत खर्च कर रहा है ।? (व्यवधान)

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि मैं बक्सर की उस धरती से आता हूं, जहां भगवान राम को ज्ञान प्राप्त हुआ था । केन्द्र सरकार वहां विश्वामित्र के आश्रम, भगवान राम की ज्ञानभूमि पर उनके गुरु विश्वामित्र के नाम पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे । इसी तरह से नालंदा और विक्रमशिला में विश्वविद्यालय बनाने का काम किया गया है । वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री जी ने विशेष पैकेज की घोषणा में भागलपुर में विक्रमशिलाा केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है । आज वर्ष 2024 है, लेकिन आज तक उसके लिए एक भी पैसे का आवंटन नहीं होना दु:खद है । विशेष पैकेज की घोषणा हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा में पैसा निवेश नहीं किया गया है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Members, those who want to lay their written speeches, they can do so. It will be treated as part of the proceedings.

**DR. GUMMA THANUJA RANI (ARAKU):** Hon. Chairman, Sir, for the past 10 years, Andhra Pradesh has faced significant challenges due to its reorganisation. Despite the unique circumstances, the State has not been granted Special Category status leading to funding constraints similar to those of other States.

The lack of Special Category status has significant repercussions on various sectors, particularly the education sector. Andhra Pradesh has to divert resources towards building basic infrastructure, leaving limited funds for educational development. Establishing schools, providing quality education, and integrating modern teaching technologies require substantial investment, which the current funding model does not adequately support.

Sir, in June 2023, Andhra Pradesh became the first State in the country to launch 10,000 digital classrooms through the usage of Interactive Flat Panels (IFPs). We have been continuously emphasising about the need for IFPs and moving beyond traditional textbook teaching. The former Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy *Garu* aimed to elevate all Government schools to the level of corporate schools and achieved the same in many cases.

Moving to IFP classrooms is a significant step by the Government to enhance the education quality. We completed the renovation of all 45,000 schools under *Nadu-Nedu*, now known as *Mana Badi ? Mana Bhavishaythu*, with ultra-modern facilities and spent nearly Rs.16,000 crore on modernising schools. These schools were once in a pitiable condition have now have become inspiring learning centres with new furniture, fans, lights, RO drinking water, and washrooms with running water.

Sir, Jaganmohan Reddy Garu used to say and follow this quote in Telugu,

*Oke deepam gaddi ki matrame veluguni istundi kaani chaduvu*

*ane deepam oke kutumbaniki samajani ki velugunistundi*

एक दीपक अंधकार में एक कमरे को रोशनी देता है, लेकिन शिक्षा का दीपक परिवार और पूरे समाज में रोशनी ला सकता है ।

Sir, the Jagananna Amma Vodi Scheme - renamed as Thalliki Vandanam Scheme - initiated by the former Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy *garu*, has significantly decreased the drop-out rate and ensured a minimum of 75 per cent attendance of students. The Government had allocated approximately Rs. 19,618 crore to support an estimated 84 lakh students, ensuring that they continue their education.

Sir, adequate funding plays a pivotal role in enhancing infrastructure, improving faculty quality, bolstering research capabilities and fostering overall academic excellence. Such investments are crucial for cultivating a robust and effective education system.

Sir, a proposal for the establishment of more than 100 new Kendriya Vidyalayas is awaiting sanction. I would like to request the hon. Minister to sanction a new Kendriya Vidyalaya, and allocate funds for the establishment of the same, especially in my constituency of Araku which is a reserved constituency. My constituency has a large number of ST population, but it does not have a Kendriya Vidyalaya till date. This would complement the Eklavya Schools and increase the avenues of education for the ST Students.

Thank you.

**SHRI SACHITHANANTHAM R. (DINDIGUL):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. My salutations to this august House including the Chair. I thank the voters of Dindigul parliamentary constituency for electing me to this House. I also express my heartfelt thanks to the leaders of INDIA Alliance led by DMK who worked hard to secure my success in the Election. I am happy to deliver my maiden speech here on the Demands for Grants pertaining to Education. This Ministry was earlier called as Human Resource Development. This has now been changed as Ministry of Education. There is no big change visible other than this change of name. Separate fund allocations have been made for literacy programmes, School education and Higher education departments. Keeping in view the future needs of our country in the field of education, I urge that the allocation should be increased accordingly. Public Schools are administered throughout the country by the respective State governments. Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, and Sainik School are the Schools run by the Union Government. Samagra Siksha Abhyan is a scheme for the stable development these Public Schools and the funds under this Scheme should be enhanced and distributed among States unconditionally. PM SHRI is a Scheme to set up model schools all over the country. These two Schemes have different aims and objectives. This Lok Sabha has given approval under different Heads for these two schemes separately. Union Government is wrong when it says that the funds meant for Samagra Shiksha Abhyan would be distributed only when PM SHRI Scheme is implemented in Tamil Nadu. I urge that the funds under Samagra Shiksha Abhyan due for Tamil Nadu should be released immediately. Educational Polcies were brought in our country during Congress regime in the years 1968,

1986 and 1991. Although there were some criticism, these policies were not imposed on the States of this country. It is being forced on the State Governments to implement mandatorily the New Education Policy of 2020 brought out by this Union Government. Moreover, the Union government wants to control the States which run Schools, Colleges and Universities. NEET for medical education, JEE for Engineering education, CUET for Arts and Science education and so many entrance exams are conducted. It is wrong to decide admission to higher education by way of entrance exams even though one has passed twelfth standard with a high score. There were irregularities in UG-NEET such as question paper leak, awarding of bonus marks etc. PG-NEET was original planned to be conducted on 11 March 2024. Then the exam date was changed to 7th June and 23rd June 2024 subsequently. On June 22, at 10 pm the candidates were informed about the cancellation of this Exam scheduled to be held on

June 23, 2024. Now it is rescheduled to be held on 11 August 2024. There is confusion prevailing in selecting the Exam Centre as well. Candidates from Tamil Nadu are allotted an Exam Centre in Odisha. I urge you to do away with these irregularities and confusions prevailing around the conduct of PG-NEET and other exams. As per the rights of the States, as enshrined in the Constitution of India, Tamil Nadu Legislative Assembly Bil No 43 was passed in the State Legislative Assembly and sent to the Hon Governor of Tamil Nadu for his assent. Hon Governor, without signing and approving this Bill, returned it to the State Government. Once again this Bill was discussed and passed in the Tamil Nadu Legislative Assembly. Such a Bill has been kept pending by the Union Ministry of Home Affairs for the last 3 years. I urge that Hon President should accord assent to this Bill. I urge that Hon Governor who is not cooperating with the State Government of Tamil Nadu should not be given extension of his term. In the NCERT syllabus, in the name of revision, unscientific statements are made to appear in the text books 11th and 12th standards besides Social Science textbook of Class 6. Actual history since the period of King Ashoka to Baba Saheb Ambedkar is said to have been removed from the textbooks with a *malafide* intention. Gandhigram University was created for ensuring quality education to rural students. Due to CUET, the educational opportunities are denied for rural students in this University. I urge that many new Courses should be started in this University by encouraging research in different fields. Central Universities like the Tiruvarur Central University and Avinashilingam University in Coimbatore should be expanded. New Universities should be opened in backward districts of Tamil Nadu such as Viluppuram and Ramanathapuram. Ayush University should be set up a Palani.

Central Horticulture University should also be set up in Ottanchatram. The regional centre of the Sheep and Wool Research Institute under ICAR at Kodaikkanal should be expanded with a view to benefit research scholars and students. PM Poshan Scheme. In Tamil Nadu, the State Government has started a breakfast Scheme for school children-a pioneer programme- to be emulated by other States in India. I urge that the allocation under PM Poshan Scheme should be done through the Ministry of Education. I request that all competitive exams are to be conducted in all the regional languages. One Hon MP who spoke here said New Educational Policy is a policy to create Saints or Rishis in our country. We done want an Education Policy which can create saints. We want an educational policy which can create scientists in the country. With this I conclude this. Thank you.

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भन्डारा-गोंदिया) :सरकार विश्वगुरु बनने का सपना दिखा रही है । लेकिन आज मैं बडे ही उदास मन से भारत के गुरुजनों से, विद्यार्थियों से क्षमा मांगता हूं कि आपकी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकेंगे । क्योंकि हमारे पास में शिक्षा के लिए धन नहीं है । सस्ती और अच्छी शिक्षा की उम्मीद आप छोड दीजिए ।

"शिक्षा से ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है,

बिन शिक्षा के जीवन का हर सपना ध्वस्त होता है ।"

गरीब से गरीब माता पिता भी अपने बच्चों पढाई के लिए कुछ न कुछ करता है । सरकार हमारी माई बाप है । उसको अपने बच्चों पर तरस आना चाहिए । यह मुद्दा हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों और युवाओं की शिक्षा से जुड़ा है । हम सब जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश की मानव पूंजी Human Capital का निर्माण करती है । हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी । लेकिन आज, भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, वे हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं ।

2014 से, शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट में लगातार कमी आ रही है । इस साल के बजट में, स्कूल शिक्षा के लिए 16.8% और शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 7% की कमी की गई है । मुझे हैरानी होती है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना कैसे संभव होगा, जब सरकार खुद ही फंड में कटौती कर रही है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का बजट बीई 2023-24 की तुलना में 53.35% और पिछले वित्त वर्ष के आरई की तुलना में 60.99% घटा दिया गया है । और यह तब हो रहा है जब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जो यूजीसी के तहत आती है, राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे NEET और NET को सही ढंग से आयोजित करने में असफल हो रही है । पिछले 7 वर्षों में, हमारे देश ने 15 राज्यों में 70 परीक्षा पेपर लीक देखे हैं, जिससे लगभग 1.7 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं । कहीं से नहीं लगता कि सरकार हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है?

"जहाँ शिक्षा के मंदिरों में दिया बुझने लगे,

समझिए कि वहाँ विकास के सपने खुद ही मिटने लगे ।"

यह सरकार आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित पेशेवर शिक्षा संस्थानों के लिए फंड में कमी करने का सोच रखती है । क्या यह सरकार यह सोचती है कि हमारे देश का विकास बिना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के संभव है?

मुझे मेरी मेडिकल शिक्षा के दिन याद आते है । आंखे भर आयी है कि मेरे माता पिता ने मेरी पढाई के लिए क्या क्या नहीं झेला है । मैं नहीं चाहता कि देश की वर्तमान पीढ़ी भी यही सहती रहे । देश में डाक्टर या इंजीनियर बनना महंगा है । पूरी जिंदगी की कमाई लगा दें, तब भी मिडीलक्लास माता पिता पैसे नहीं जुटा पाते है । मजबूरी में विदेश भेजना पडता है । अपने मां बाप की गरीब को जानते हुए बेटा बेटी तंगहाली में पढाई करते है । हवाई जहाज का टिकट महंगा होता है । तीन तीन साल परिवार से मिलना नहीं होता । पराई जमीन, पराई भाषा और पराया खाने में क्या वितती है, मुझसे ज्यादा कोई नहीं बेहतर बता सकता ।

मुझे उम्मीद थी कि देश में नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र सरकार कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाएगी । लेकिन उम्मीद टूट गयी है । क्या मेरा देश इस तरीके से विश्वगुरु बनेगा । क्या मेरा देश मेडिकल एज्युकेशन का वैश्विक लोकेशन (Global hub of medical education) नहीं बन सकता । हमारा अतिथि देवो भव एवं वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र कब काम आएगा । बच्चों को देश की मिट्टी, देश की रोटी खाने मिलेगी ।

युवा इंटर्नशिप कार्यक्रम

परीक्षा में नकल करना अपराध है, उसके लिए सजा भी होती है । बजट में घोषित युवा इंटर्नशिप प्रोग्राम दोषपूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण है । यह कांग्रेस के घोषणा पत्र में घोषित 'पहली नौकरी पक्की' अप्रेंटिसशिप के अधिकार की कोरी कोरी नकल है । नकल में थोडा तो बदलाव करते । आप नकल करते हुए पकड़े गए हैं । आप हमारे हेडमास्टर हो, आप ही फैसला करें कि क्या सजा दी जाए । मैं सवाल करना चाहता हूं, आपसे वादा लेना चाहता हूं कि क्या आप टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करेंगे । अनिवार्य करेंगे । अगर हां तो स्वागत है । अगर नहीं तो बताईए कि यह इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके लिए है?

देश के गुरुओं को, देश के विद्यार्थियों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए । हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकें । पैसे की तंगी में बच्चों की पढाई सपने की हत्या नहीं होनी चाहिए ।

धन्यवाद ।

**SHRI RAJU BISTA (DARJEELING):** Under the leadership of Hon'ble Prime Minister Sh, Narendra Modi ji and Hon'ble Finance Minister Ms. Nirmala Sitharaman ji, our education sector has seen massive transformation. In the past 10-years the Central budget allocation for education has more than doubled, 2013-14: 71495 crores; and 2024-25: 1.48 lakh crore. Allocation of funds towards Skill Development, Higher Education, STEM and Technical Courses have seen massive rise. Allocation for school education and developing grassroots infrastructure in the region has been substantially raised. Financial support to students from SC, ST, OBC, EWS and PH sections have seen significant increase. Modernization of education system, introduction of the New Education Policy, and development of better centres for Higher Education here in the country itself, has contributed massively towards

boosting the education sector. In the past 10-years, our government has established 15 New AIIMS, 90 New Universities, 9 New IIT, 16 IITs, 9 New IIM and 70 Medical Colleges.

I believe that the budget 2024-25 will be a game changer for our nation. The Central Govt will provide Rs 10 lakhs of loans for higher education. It will enable the students, from economically marginalized families to pursue their dreams without having to worry about the money. Focus on Research and Innovation, Skill Development, Apprenticeships, Teacher Training Centre of Excellence in Al, Digital e-learning, and quality Higher Education will enable our youths to be prepared to face the real world. I thank PM Modi ji and FM Nirmala ji for this forward thinking budget. Which, will definitely pave way for a "Vikshit Bharat".

**LIST OF DEMANDS**

**1. Darjeeling Central University**

I come from Darjeeling Lok Sabha Constituency. Our Darjeeling hills, Terai and Dooars areas of North Bengal is home to many tribal communities. The northern most districts of Bengal comprises of Darjeeling, Kalimpong Alipurduar, Jalpalguri, Cooch Behar, North Dinajpur, South Dinajpur and Malda. It has a population of around 3 crore. Majority of the people here work as labourers in the tea estates, or are engaged in farming for their sustenance. Majority of the workers are women. The average income for a family in our region is only around Rs 6000 per month. Our students therefore, are unable to afford expensive education in other states or far away cities like Kolkata. In North Bengal, the education facilities are still very primitive. The WB Govt has continued to deprive our region of proper education facilities. since time immemorial, Darjeeling-Kalimpong has remained a hub of education. Not only in India, but also across the South Asian, and South-East Asian countries.

Darjeeling region, is home to some of the best schools in India. Students from all over Asia come to study in the hills. We share border with Bangladesh, Bhutan and Nepal. So a lot of cross-border international students also get their education in our region. Yet in terms of higher education, this region severely lags behind as compared to the rest of India. TMC Govt announced a University in Darjeeling, but it has never functioned. Students who joined courses there, are learning through distant education mode. This, is how TMC Govt has kept our region and people deprived. The lack of proper higher education facilities and courses have seen brain

drain of colossal proportions occur in the Darjeeling region, Sadly, the best and the brightest from this region are forced to take their knowledge, skills and passion elsewhere. Establishment of an institution of higher and technical learning in the region, has been a long-standing aspiration and pertinent demand of our people. Establishing a Central University in Darjeeling can help to turn it into one of the hubs for higher education in India. It will also become an important education centre in all of South and South East Asia. This will also greatly compliment Modi ji's Act East Policy. Sir, WB has a population of nearly 10 crores. But we only have 1 central university. So, we there is scope and space for establishing a second Central University in North Bengal. I therefore, request you to kindly establish Darjeeling Central University without any further delay.

**2. AIIMS North Bengal**

North Bengal comprises of 8 districts out of the 23 districts of West Bengal. Darjeeling, Kalimpong, Alipurduar, Jalpaiguri, Cooch Behar, North Dinajpur, South Dinajpur and Malda. Our region is home to around 3 crore people. Majority of the people are dependent on working for the tea estates, cinchona plantation or are engaged in farming for their sustenance. The average monthly income of a family in our region is only around Rs 7000 per month. Due to low income, people here cannot afford treatment in private hospitals. Government run facilities are inadequately staffed, and lack even the most basic equipment. Most of the hospitals, especially in hill region offer only referral service - every patient is referred to hospitals in the plains. Hundreds of patients from our region die, due to the lack of proper healthcare facility. Patients who need specialized care like pregnant women and children are dying due to lack of proper facilities. Our region and people continue to suffer due to the lack of health facilities. North Bengal Medical College, severely lacks doctors, equipment, amenities and facilities for Medical Students, and poses risk for the patients too. Given the circumstances, there is an urgent need to establish AIIMS in North Bengal. I therefore request the Ministry of Education to work with the Ministry of Health to Establish AlIMS in Siliguri.

**3. Establishment of the Central Academy for Natural Resources Education (CARE).**

The Himalayan region of NE states in India, starting from Darjeeling hills, Terai and Dooars are part of the Eastern Himalayan region. It is one of the IUCN 34 global biodiversity hotspots. This region has a fragile geography, and ecology. Livelihood

of the people here are mostly dependent on natural resources, agriculture and forestry related activities. In the past three decades, our region has witnessed immense changes, however, there has been no research focus on studying these phenomena, understanding them and taking informed policy and developmental decisions. The Eastern Forest Rangers College in Kurseong is ideally situated to fill in this gap. EFRC Kurseong is spread over an area of 31 Acres, and carries with it immense potential for being developed as a premier research institute for our region. Hon'ble Environment Minister Bhupendra ji had assured me that the Ministry is going to take a positive step in this regard. I request Hon'ble Minister to kindly work with the Ministry of Education to expedite my request and take necessary action for upgrading EFRC Kurseong to a national level institute to teach Environmental and Natural Resources Management, Disaster Mitigation and Management, Climate Change and related disciplines. Fulfilling of these demands will enable the youths from North Bengal, as well as North East to get world class education. I commend the budget and whole heartedly support the request for grants of Education Ministry.

डॉ**.** आलोक कुमार सुमन **(**गोपालगंज**) :** मैं शिक्षा मंत्रालय के तहत अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ । आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक नये कवि की शिक्षा पर लिखी कुछ चंद लाइनों से करना चाहूंगा-

?शिक्षा के अभाव में, खिले न गुण का फूल ।

शिक्षा में ही है बसा, जगत प्रगति का मूल । ।

निर्धनता भी दूर हो, मिले मान ? सम्मान ।

शिक्षित मानव के लिए, शिक्षा है भगवान । ।"

मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, हमारे गृह-प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अपनी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । वर्ष 2024-2025 के लिए शिक्षा विभाग में ₹1.21 लाख करोड़ का आवंटन, जो पिछले बजट की तुलना में 4.3% की अधिक है, अत्यंत प्रशंसनीय है । विशेष रूप से, स्कूली शिक्षा विभाग को ₹73,008 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो ₹68,804 करोड़ से बढ़कर है । महोदय उच्च शिक्षा विभाग को ₹47,619 करोड़ का आवंटन किया गया है, जो ₹44,090 करोड़ से बढ़कर है । इसके अतिरिक्त, 500 बड़ी कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने और घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए ₹10 लाख तक के वित्तीय ऋण की पहल अत्यधिक सराहनीय है ।

मैं विनम्रतापूर्वक हमारे माननीय मंत्री जी, से अनुरोध करता हूं कि वे बिहार के गोपालगंज जिले के लिए प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करें । शिक्षा किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की नींव होती है, और इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है । डिग्री

कॉलेज की स्थापना से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक लाभ होगा, जिससे गोपालगंज का समग्र विकास संभव हो सकेगा ।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि गोपालगंज केंद्रीय विद्यालय वर्तमान में किराए की बिल्डिंग में चल रहा है । क्षेत्र के लोगों की यह लम्बे समय से चली आ रही माँग है कि विद्यालय के पास स्वयं की जमीन, बिल्डिंग एवं अन्य सुविधाएँ हों ताकि संसदीय क्षेत्र के विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके । मैं गोपालगंज जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का भी अनुरोध करता हूं । विश्वविद्यालय न केवल उन्नत शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए बुनियादी ढांचे और सेवाओं में भी सुधार करेगा । इसके अतिरिक्त, मैं गोपालगंज जिले में स्नातकोत्तर डिग्री की पढ़ाई हेतु कॉलेज में व्यवस्था की जाय । जो हमारे नागरिकों की भलाई के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये । सैनिक विद्यालय सिपायाँ, कुचायकोट में नई बिल्डिंग बनकर तैयार है । लेकिन काफी दिनों से प्रयास के बावजूद किराये के मकान से नई जगह विद्यालय का स्थानांतरण नहीं हुआ । मैं मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ, कृपया इस सम्बंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दें, ताकि विद्यालय का स्थानांतरण हो सके । अंत में, मैं बिहार के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की दीर्घकालिक माँग का पुरजोर समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री महोदय, इस सन्दर्भ में जितनी जल्दी संभव हो, आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें ।

गोपालगंज संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में, ये पहल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं । मैं माननीय मंत्री जी से इन अनुरोधों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह करता हूं । मुझे पूर्ण भरोसा है कि वे गोपालगंज और बिहार के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे । धन्यवाद ।

**DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR):** I'm very happy to express my views on the demand for grants on Education. I request for having a Sainik School and Eklavya School at Chikkaballapur Lok Sabha constituency. I humbly request for consideration of an Indian Institute of Technology at Chikkaballapur. I also propose the idea before you, that we have central schools for Central government servants, we have Sainik schools for future soldiers, we have Indian Institutes for various professional courses, along the same lines why don't we form farming schools? Or why don't we make farming a mandatory part of the school curriculum? Similar to sports a period can be dedicated to provide practical lessons on farming practices. Such schools are most needed for mentoring the future generations into farming studies. This is just a humble suggestion from my end. Now let me go into the demand for grants.

We as a nation are committed to implementing the Sustainable Development Goals of the United Nations. As everyone of us is already aware, United Nations Sustainable Development Goals 4 says,

?Ensure **inclusive** and **equitable quality education** and **promote lifelong learning** opportunities for all?

I'll explain how our government is implementing this, our Government aims to enhance digital infrastructure, provide educational resources in regional languages, expand skill development opportunities, and prioritize special needs education. We prioritize the importance of nurturing creativity and critical thinking in students to equip them for future challenges. It is for this we have brought in a New Educational Policy in 2020. There will be no linguistic, cultural, ethnic, religious barriers to education under our regime. Differently abled are given more opportunities in education. Ignored, oppressed and deprived have now more access to education under Prime Minister Modi. According to the IndiaTimes.com reporting on a major ranking for 2024 regarding Asia, ?India is now the most represented higher education system, with 148 featured universities, 37 more than last year. It is followed by Mainland China with 133 and Japan with 96 ?

Our government under Prime Minister Modi has only one vision, and that is to leverage upon the new and advancing technologies in education and to ensure that every child regardless of his/ her background has access to quality education. Over 26 crore students now rely upon public and private schools across India. It is with a vision to transform education and skilling that we have announced over 1.48 lakh crores this year in the Union Budget. This year's educational Ministry? allocation alone has risen up to 6.8 percent to over 1.2 lakh crores. Over the last decade, the average budget-allocated utilization has stood at 92.4%. In 70 years after Independence, only 7 AIIMS were constructed, but during Modi Ji?s tenure, the number of AIIMS in the country has increased to 23. In 70 years, 387 medical colleges were built in the country, but in the last 10 years, the Prime Minister has increased this to 706. Earlier, there were 51,000 MBBS seats, but Prime Minister Modi has increased the number of these seats to 1,07,000.

There has been a growth of over 26.5 per cent in student enrolments in schools and higher education institutions after the Narendra Modi government assumed office in 2014. There has been a 31 per cent growth in enrolment among girls between 2014-15 and 2021-22 and the figure for girls belonging to Scheduled Castes (SC) stood at 50 per cent. The enrolment growth rate for SC and Scheduled Tribe (ST) students was 44 per cent and 65 per cent. The tribal girl?s enrolment has now increased to over 80 percent from the UPA era. This is what we will do when we are in power. Babasaheb Ambedkar has said, ?Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence?

It is through good, quality and affordable education. We are committed to this. This is exactly what we are doing We are implementing our country's founding fathers? vision. We will continue to do so.

**प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड (मुम्बई उत्तर-मध्य):** महामानव भारत रत्न डॉ बाबासाहेब अंबेडकर का कहना था कि किसी भी समाज का विकास इस बात पर निर्भर है कि वहाँ शिक्षा का कितना विकास हुआ है । अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने में विश्वास नहीं रखती । इस बजट में पिछले साल के मुकाबले, उच्च शिक्षा में यूजीसी का बजट 53.35% घटा है । स्कूली शिक्षा का बजट 16.8% और शिक्षा विभाग का बजट 7% से घटाया गया है । गरीब और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा उन्नति का मार्ग है । पर सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक सरकारी निर्णय लाया गया की यदि 1 किमी की दूरी पर कोई सरकारी विद्यालय हो, तो प्राइवेट विद्यालयों को राइट तो एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को अड्मिशन देने की जरूरत नहीं । कोर्ट के संज्ञान के बाद ही ये निर्णय वापस लिया गया ।

भारत हंगर इंडेक्स में लगातार पीछे जा रहा है, पर PM पोषण योजना की फन्डिंग को न के बराबर ही बढ़ाया गया है । महाराष्ट्र में हमने एक और कारनामा देखा । अपने ठेकेदार मित्रों को खुश करने के लिए, सरकार ने २ अलग अलग गणवेश लागू करने का निर्णय लिया ।

उच्च शिक्षा की बात करें तो बार बार जिस तरह से यूनिवर्सिटी के, NEET के और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उससे देश का भविष्य खतरे में हैं । पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं । NTA के निंदनीय कारभार की लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है । हमारा मानना है कि शिक्षा को लेकर ये सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है । बजट में घटता आ रहा प्रावधान इसका सबूत है ।

पहली राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अंर्तगत शिक्षा का सर्वांगिकरण और गांव तक शिक्षा ले जाने की कोशिश कि थी, दूसरे राष्ट्रीय शिक्षा Policy के अंर्तगत भारतरत्न श्री राजीव गांधी ने हर बच्चें को शिक्षा का अधिकार IIT, ITM की स्थापना की । साथ में शिक्षा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान किया ।

फिर आज वर्तमान शिक्षा जो मोदी सरकार दे रही है । वह धोखा है, उसमें बड़े उद्योगपतियों को स्थान देने काम किया है । बड़े शिक्षा कॉमलेक्स निकलने का प्रावधान किया । Credit system जो बहुत मुश्किल काम है वो लाये । हमारे राज्य के 1200 करोड़ रू. जो केन्द्र सरकार को RTE के अंर्तगत मिलना चाहिए था वो मिला नहीं ।

**SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI):** The Budgetary Allocation 2024-25 in general budget 2024-25 has been comparatively lower as compared to the previous year in terms of GDP. Despite the fact, New Education Policy in 2020 has reiterated that Education Budget should be 6% of GDP. However, the Country's Education Budget has never been more than 3.5% of GDP. The Kothari Commission has also recommended increasing education expenditure to 6% of GDP. Budget Allocation on technical education has been reduced from Rs. 28049.08 croes in RE 2023-24 to Rs. 26736.62 crores in RE 2024-25 which will further hurdle in increase the economic growth and development, even on R&D in education sector is much lower in comparison to Japan and China etc. India spends only 0.7% of GDP on R&D in comparison to 1.8% of global average.

Furthermore, I wish to state that the State of Tamil Nadu should get its Budgetary Allocation for imparting suitable education to the children of the State so that they played pivotal role in the country's economic progress. I would appeal to the Government to bring forth constitutional amendment for shifting the subject Education from Concurrent List to State List.

It is sorry state of affairs that we come across incident of paper leakages and impersonation/cheating in significant exam like NEET UG which must be stopped for a golden future of the Nation. I also urged the Union Government to explore the feasibility of implementing Dravidian Model of Education at National Level. The Government should make budgetary provision for incentives, scholarship for the students. Besides the Mid-day-Meal in the school, the Union Government may introduce, "Tamil Nadu Chief Minister Breakfast Scheme" at the National Level. Particularly, I appeal to the Union Government to introduce special schemes for tribal education in Tamil Nadu in general and my Parliamentary Constituency Tiruvannamalai in particular.

**SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** I would like to express my views on the Demands for Grants under the control of Ministry of Education. There are several shortcomings of the education sector and I want to draw the attention of the Central Government towards these shortcomings. The Central Government has given very less amount in the Budget for the education sector. We talk about becoming ?Vishwaguru? or teachers/leaders of the world but the weakness and flaws of the education policy is spoiling our image in the world.

At the time of UPA Government in 2014, the allocation for education in the Budget was 4% of the GDP. However, this BJP Government has reduced it to just 2.5%. This is injustice towards the poor people. The poor people also want to see a good future for their children. If the Central Government will slash the amount of money allotted to education sector, the future of the children of the poor will suffer.

The Government must pay more attention towards the primary education. There is an acute shortage of teachers from primary to +2 level. The Government must recruit more teachers for schools. At the SSA level, the Government must give more attention towards schools of border areas. These school buildings need to be renovated. A large area of my constituency Amritsar shares its border with Pakistan.

There are almost 1100 universities in the country. However, only 4 universities can be said to be of the level of international standard. The Government should grant a special package to Guru Nanak Dev University so that the students of my border area can receive education of high standard. If our Government education policy is not upto the mark, it will directly benefit the private sector. It is the duty of the Government to provide high level education to the children of all classes of people, especially the poor class. But this Government gives more attention towards the policies of caste and religion. This will endanger the future of the children of our country.

I urge upon the Government to set up Government schools at Majitha, Ajnala, Lopoke, Attari and Ramdas etc. in my parliament constituency. This entire area is rural belt and is adjacent to the Indo-Pak border. For the spread of education, the Central Government must open Government schools soon.

The students are being provided very sub-standard mid-day food in the schools by the Punjab Government. The Education Minister of the Central Government must take special cognizance of this fact. A delegation must be sent in schools of my constituency to probe this matter, so that those who provide sub-standard food to the students could be punished.

The paper leak scandals of exams like NEET are endangering the future of the students of our country. Those guilty should be given severe punishment. In the last 10 years during the tenure of this Government, 70 paper leak scandals have come to light. It is a matter of shame.

A Central University should be set up in my constituency. A Central university was proposed to be set up earlier in Amritsar. However, the then Akali-BJP Government shifted the university to Bathinda. This was a grave injustice to Amritsar. More higher education institutes should be set up in Amritsar.

I urge upon the Central Government to ensure that next year?s education Budget of India should be akin to the education budget of a developed country. This is important so that in future, our students can get higher quality and inexpensive education.

**SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** I would like to oppose the Demands for Grants for Education in the Budget 2024-25. This is a decrease of 7% in the Ministry's allocation from the revised estimate for 2023-24. The budgeted expenditure for education has seen a reduction of 2.2% as compared to the actuals in 2023-24. This

is appalling, given the fact that the education sector in India has seen a systematic erosion in the recent past. The lacunae in our system have been uncovered by large-scale scams like NEET and NET. The entire system needs a revamp, and this has to be aided by proportionate budgetary allocations. But unfortunately, the union government has neglected education in its Budget.

The NDA II government, on average, spent only 0.4% of the GDP on education, whereas the UPA II government spent 0.7% of the GDP. This, despite the fact that the then-Union HRD minister, Prakash Javadekar (under the NDA II government), had said that the government is hopeful of increasing spending on education to 6% of the GDP.

The reduced spending on education is symbolic of the 'new welfarism' model that the BJP government has followed, as described by Arvind Subramanian. This model shifts focus away from the creation of public goods like health and education. Instead, it has focused on providing subsidies for essential goods, This is because public goods are intangible and may not work to influence voter sentiment in their favour.

The Samagra Shiksha Abhiyan takes up a lion's share of the education budget. It is a flagship scheme that focuses on achieving universal access to school education as envisaged in the NEP. The school education department in my state Tamil Nadu school is receive the first instalment of Rs 500 crore from the union government under yet Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) for the financial year 2024-25. The funds should have disbursed by June, but have still not been released. This can have a considerable pact on the implementation of the scheme in the state. According to the SDG India. Index 2023-24, Tamil Nadu was one of the top-performing states in multiple SDGs. It cannot be made to fall behind due to a lack of funds.

Other opposition-ruled states like Delhi, Punjab, Kerala, and West Bengal were faced with a similar predicament. The Central government is withholding funds due to the state's denial to implement the PM SHRI scheme, which seeks to develop schools to "showcase" the National Education Policy (NEP), 2020.

The Tamil Nadu government had rejected the NEP. It is against the imposition of Hindi in the name of a third language, as a part of a larger project of the Modi government to make India into a Hindi State. It focuses on imposing the ruling party's ideology rather than reforming the education system.

The Centre has cornered states into implementing the PM-SHRI scheme. This is another desperate attempt to trick people into conflating the Prime Minister with development. Aggressively pushing clever acronyms to feign development will not hide the truth. What is the point of increasing allocations for the scheme if the Centre does not comply with its federal obligations to the states?

Another component of Samagra Shiksha Abhiyan is teacher-training. The last five years have seen a decreasing trend in the expenditure on teacher-training under SSA. This is a matter of concern as, according to the Unified District Information System for Education Plus 2021-22, 10% of all government school teachers do not possess professional qualifications. This casts aspersions on the quality of education offered in government schools. This, în turn, has led to an increase in the number of children seeking admissions in private schools. As of 2021-22, one-third of school-going students are enrolled in private unaided schools

The Budget has also slashed UGC allocations by 61% from Rs 6,409 crore to Rs 2,500 crore. This seems like an attempt to do away with the UGC and replace it with the Higher Education Commission of India, as envisaged by the NEP. Students will have to bear the brunt of this as they will be compelled to take up more self-financing courses. ersities looking to expand the duration of courses to four years will have to increase their dependence on the HEFA for loans. State governments are responsible for the maiority of the enrollment, and so they may bear the brunt of the reduction in funds.

While the Union Government has been pushing the NEP, it has not paid heed to one of its own policy suggestions - that recommended universities could accept common entrance exams at their own discretion. The Anandakrishnan Committee (2006), formed to examine the ramifications of the abolition of the Tamil Nadu Professional Courses Common Entrance Test (CET), recommended the abolition of the test. The recommendation was based on the severe disadvantages encountered by different vulnerable sections of the student population such as rural households, Tamil medium students and underprivileged categories. The same was found to be true for NEET in the A K Rajan Committee report. It observed a fall in the number of Tamil medium students by an average of 12.58% in MBBS admissions, after the introduction of NEET in government medical colleges, between 2017 to 2021. Tamil Nadu has been campaigning to scrap NEET for many years. Until then, it has also made a plea for exempting states from NEET, as per their will. But to no avail.

The India Employment Report 2024 by the ILO stated that unemployment in India was highest among the youth. And yet, the Department of Higher Education has seen a reduction in budget by 17% compared to last year's Revised Estimates. The schemes that the Honourable Finance Minister announced to provide a fillip to employment will not compensate for the gaps in higher education left behind by inadequate budgetary allocations. It is also important to note that India ranked 40th in the Global Innovation Index by WIPO in 2023. While there was an improvement in India's rank, this calls for an increased focus on strengthening the link between academia and industry. Easing the regulatory framework and encouraging private sector participation would be effective ways to achieve this.

It is our duty to ensure we are securing the futures of our children. Investing in their education is the most meaningful way to do so. As their representatives, we must leave no stone unturned until we successfully deliver the goal of quality education for all. Thank you.

**SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT):** Between 2013-14 and 2022-23 though the expenditure the Ministry has been increased at an annualised rate of 4 per cent but expenditure, as a share of overall Union Budget, has come down drastically during this period.

I would like to highlight some concerns in school education and higher education. We have seen a significant drop in enrolment after primary level. The enrolment in primary education even though it reaches 100 per cent, the enrolment rate in higher secondary school is almost half the enrolment at primary education. Similarly, the drop-out rate increases in case of higher levels of school education. As of 2021-22, Government schools constituted 69 per cent of all schools and 54 per cent of all school enrolment in the country.

The share has seen a constant decline since 2012-13. The main reason for students preferring private aided educational institutes is due to the usage of English, low quality of education in Government institutions, proximate location of private institution and better facilities such as teaching aid, transport, hostel facilities and extracurricular activities. one other Key concern being the availability of quality teacher across States. The learning outcomes continue to be poor mainly due to lack of infrastructure in most of the schools.

On the higher education side, the socio-economic disparity is a main concern when it comes to enrolment. Even as the enrolment of students from SC and ST

communities has increased over time, it remains relatively lower. According to the Standing Committees on Education, Women and children, Youth and Sports (2023), the ideal PTR in higher education is 15:1 (one teacher in 15 students). However, 0this is not true in case of the most of the States like Bihar (64:1), Jharkhand (54:1) and UP (361). About one third post in the Centrally funded universities are vacant. Faculty from SC and ST communities constitute nine per cent and 3 per cent of filled up posts. A few other points like higher unemployment for graduates and the fact that higher educational institutions play a limited role in research continue to be a key concern.

I would also like to highlight key issues related to my Constituency. I would request the Government to commission a Kendriya Vidyalaya at Jeypore, Odisha at the earliest. The land has been acquired and temporary accommodation /building to start the session hay already been provided. Kindly approve the project at the earliest.

The Central University of Odisha at Koraput has been facing many challenges and requires financial support as grant in aid from the Government to start many science streams. Also, the vacancy in faculty needs to be addressed at the earliest.

A shaheed Laxman Nayak research Chair should be established at Central University Odisha, Koraput. We need another Kendriya Vidyalaya in Muniguda due to the presence of many Central Government employees and strong demand from the people of Muniguda in Rayayeda District. Thanks.

**SHRI KRIPANATH MALLAH (KARIMGANJ):** I support the Demands for Grants placed by hon. Minister for the development of Education Department. I want to place following requirements of my constituency Karimganj - One Kendriya Vidyalaya at Ramkrishna Nagor LAC, one Kendriya Vidyalaya at Patharkandi LAC and one at Hailakand, LAC. There is only one Kendriya Vidyalaya in my constituency at Karimganj Town. So, I request hon. Minister of Education through you sir to please sanction the above demand of Kendriya Vidyalaya in my Constituency.

Thank you.

**SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR):** The criteria for giving educational loans is very stringent. The nationalised banks ask for guarantor now, which was not the case earlier. It is very difficult for students to meet this criteria.

Earlier, the students could pay back their loans after the completion of the said educational course. But now, it is mandatory for them to repay their loans while they are studying. It is not possible as this becomes possible only after they get a job after the completion of their education.

The fee structure for SC/ST students studying for UPSC and MPSC should be revised and regularised, and should be made affordable.

There is also a request for the establishment of an engineering university in Solapur along with the continuation of Government polytechnic.

**SHRI AMARSING TISSO (DIPHU):** I support the Demands for Grants on Ministry of Education that are placed before the House by Shri Dharmendra Pradhan.

I thank hon. Prime Minister Shri Narendra Modi for introducing New Education Policy 2020. In Assam, the Government has taken some special measures to make education for all.

I seek Ministry of Education to upgrade the Central University Diphu Campus into a full-fledged Central University and to strengthen education in the interior areas of Karbi Anglong District, West Karbi Anglong District and Dima Hasaro District of Assam.

Thanking you.

**DR. M. K. VISHNU PRASAD (CUDDALORE):** Kendriya Vidyalas are Present in almost all major cities. In Tiruvannamalai and Cuddalore districts KV?s are functioning. But the teachers are mostly from North India. They are unable to teach the Primary Students because of language barrier. Teachers of local language can make the students understand much better. I humbly request the Ministry for directing the concerned authority to recruit the teachers of local language.

श्री कौशलेन्द्र कुमार **(नालंदा) :** मैं वर्ष, 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ ।

माननीय वित्त मंत्री जी अपने बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए करीब 1,20,628 करोड़ रूपए का आवंटन किया है । यह काफी अच्छा कदम है । नई शिक्षा नीति को लागू करने में काफी सफलता हासिल करने का काम करेगा । नई शिक्षा नीति रोजगार आधारित प्रोग्राम को लागू करने जा रही है ।

आज देश में युवाओं को गुणवत्तायुक्त और रोजगार को सृजन करने वाली शिक्षा की आवश्यकता है । प्रारम्भिक स्तर से ही शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है और आज परिणाम है कि प्राईमरी लेवल में उपस्थिति करीब 100

प्रतिशत तक पहुंच चुकी है । इसमें मिड-डे मिल का भी अहम योगदान है । किन्तु मिड-डे मिल की गुणवत्ता पर काफी शिकायतें आ रही हैं । उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है ।

शिक्षा ही किसी भी देश की प्रगति का मुख्य द्वार होता है । शिक्षा की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकार की पहली जिम्मेदारी है । किन्तु अन्य देशों की अपेक्षा भारत में शिक्षा पर जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत खर्च किया जाता है । फिर अन्य देशों की शिक्षा से अपने देश की तुलना करना बेमानी होगा । आज विकसित देशों की शिक्षा प्रणाली को देखें, तो वहां की गुणवत्ता और भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई तुलना करना अपने आपको संतोष करने वाली बात होगी । यही कारण है कि आज देश से अमीर लोगों के बच्चे और सक्षम परिवारों के बच्चे विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आतुर रहते हैं । फिर मध्यम वर्ग के लोगों और गरीब परिवार के बच्चों का क्या होगा? यह एक नीति की बात है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । देश में विश्व स्तर के गुणवत्ता वाली, रोजगार को सृजन करने वाली, रिसर्च को बढ़ावा देने वाली एवं अपने भारतीय संस्कारों को संजोने वाली शिक्षा की जरूरत है ।

देश में समग्र शिक्षा अभियान काफी सफल रहा है । केन्द्र सरकार का केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भी काफी सफल हो रहा है । अब सरकार को सभी ब्लॉकों में कम से कम दो केन्द्रीय विद्यालय और दो नवोदय विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए । यह देश में अच्छी शिक्षा के लिए मुख्य आधार प्रदान करेगा । आज बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई है और अगर केन्द्र सरकार इसे आधार प्रदान करे, तो देश में 100 प्रतिशत शिक्षा दर पाने में जल्द सफलता हासिल कर सकती है । हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी की पोषाक और साईकिल योजना इस सफलता का उदाहरण है कि बिहार में स्कूलों में इनरोलमेन्ट कितना अच्छा है । विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक परिवारों के बच्चे, जो कभी पढ़ने के लिए राजी नहीं होते थे । उनके माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे । आज सभी बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं । हां, उच्च शिक्षा में उनका जुड़ाव कम है, यह आर्थिक असमानता के कारण है । सरकार की योजनाएं उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा हैं । लोन दे देने से ही नहीं होगा, वे इसका भुगतान कैसे करेंगे? यही सब सोचकर वे पीछे हट जाते हैं ।

माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का बाजारीकरण होता जा रहा है । प्राईवेट संचालकों ने इस क्षेत्र में शिक्षा को दो भागों में बांट दिया है । एक प्राईवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यानी सक्षम और अमीर लोग और दूसरा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यानी गरीब और कमजोर तबके के लोगों का परिवार । यह प्रवृत्ति भविष्य में काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है । पहले तो महानगरों में ही प्राईवेट स्कूल हुआ करते थे, आज तो गली और मोहल्लों में भी प्राईवेट स्कूल खुल चुके हैं, जहां दिखावे के नाम पर ठगी व वसूली होती है । सरकार को शिक्षा के लिए एक समान नीति बनानी चाहिए । शिक्षा नीति प्राचीन और भविष्यकाल के नीतियों पर आधारित होनी चाहिए । बिहार के नालंदा की ऐतिहासिक शिक्षा नीति पर अध्ययन के आधार को मानना चाहिए । तभी हम एक समान शिक्षा सभी नागरिकों को दे सकते हैं । शिक्षा को मात्र अधिकार का दर्जा देकर खुश नहीं होना चाहिए । केन्द्र सरकार को देश में अधिक से अधिक आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, आईआई एसईआर्स की स्थापना करनी चाहिए । यह उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा । देश विकसित होगा, हम तभी विश्वगुरू बनने के सपने को साकार कर सकेंगे ।

सक्षम शिक्षकों की कमी आज एक बड़ी समस्या है । नई शिक्षा नीति के आधार पर 30 अनुपात 1 कहीं भी किसी भी संस्थान में नहीं है । यही कारण है कि करीब 39 प्रतिशत आईआईटीज, 54 प्रतिशत ट्रिपल आईटीज, 29 प्रतिशत एनआईटी और 31 प्रतिशत आईआईएम्स में शिक्षकों के पद रिक्त हैं । यह आंकड़ा हमारी आँख खोलता है ।

इस बार के बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है । अब हमारे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार को सृजन करने वाला शिक्षा मिलता रहेगा । शिक्षा से ही कौशल का विकास होगा । मैं नालंदा में एक अन्तर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी खोलने और पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का काफी पुराना विश्वविद्यालय है, उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग सरकार से करता हूं । मैं बिहार में दो और केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति देने की मांग करता हूं ।

सरकार डिजिटलीकरण की बात करती है । तो देश के सभी शिक्षण संस्थाएं प्राईमरी लेवल से उच्च शिक्षा केन्द्रों को डिजिटल-युक्त करने की आवश्यकता है । शिक्षा भविष्य की राह दिखाती है । अतीत से भविष्य की ओर ले जाने की आवश्यकता है । नैतिकता एवं मूल्यपरक शिक्षा एवं रोजगार को सृजन करने वाली शिक्षा देश के भविष्य को सवांरने का काम करेगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

धन्यवाद ।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** At a time when important examinations in the country are facing criticism over the controversies related to it we are discussing the Demands for Grants under the control of Ministry of Education for 2024-25. The new National Education Policy 2020 completed four years on July 29. Despite ambitious policies, India has yet to priorities education and research to the same extent as other countries. While countries like China, Japan and South Korea spent a lot on education in 60s, India is still waiting for an appropriate budget. Public expenditure on education in India has been comparatively low since the beginning. Most States spend 2.5 to 3.2 of their GDP on education. In 1964 educational expenditure from 2.9% to 6% of the GDP, but even after five decades, the country's education budget has never been more than 3.5% of the GDP. Free and compulsory education is a fundamental right for every child in the age group of 6 to 14 years under our Constitution. Education which is on the concurrent list has rarely been a priority for the Union or State Governments. Public education expenditure accounted for 3% of GDP in 2004-05 and rose to 3.4% of GDP in 2008-09. Education spending was 3.1% in 2014-15 during first NDA period but it dropped to 2.8% -2.9% from 2016-17 to 2023-24 since then. China spends 4.2%, Brazil 6.2% and Argentina 5.5% and other developing nations are spending more than we are. Even a poor country like Cuba is spending roughly 12% in education.

Currently, India has approximately 50,000 colleges and 1100 Universities with approximately 50% of them being in the private sector. India's education sector has experienced substantial growth in terms of enrolment, schools, colleges and universities over past two decades. This expansion resulted in two issues a) lack of quality, b) uniformity. The AESR 2023 Beyond Basics' report, published this year

states that youth aged 10 to 18 in rural India, reveals that 86.8% of the 14?18-year age group in the country is enrolled in educational institutions, but 25% of these students are unable to read even class two level text materials fluently in their native language.

As we aim to achieve a 50% Gross Enrolment Ratio (GER) by 2035 and envisions a developed India by 2047 the education budget should grow by at least 1.5%. There is a need to create a dedicated fund for climate technology and AI startups Goods and Service Tax (GST) on educational services should be reduced from 18% to zero. Foreign Direct Investment in the education sector should be increased in the country by the Singapore model. To improve skill development, fintech firms and educational institutions should collaborate. Over 75% of corporate social responsibility (CSR) funds should be invested in education and healthcare.

Today access to digital infrastructure is relatively limited when we talk about schools. There is a need to bridge digital divide. There is a need set up a dedicated unit to build digital infrastructure in educational infrastructure.

As on 2021-22 only 26% of all schools have desktop facilities and 34% have access to the internet. In 2024-25 the Department of Schools Education has been allotted Rs. 73,008 crore. 51% of this allocation in towards Samargya Shiksha Abhiyan at Rs. 37,010 crore. POSHAN accounts for 17% of the department's expenditure at Rs. 12,467 crore.

Coming to Higher Education, in 2024-25 Rs. 47,620 crore has been allocated. I would like to mention that Gross Enrolment Ratio (GER) in higher education has increased overtime. Even as the enrolment to students from SC and ST communities has increased over time, it remains relatively lower. Participation of women is lower in certain education streams. Accordingly, to the AISHE (21-22) in engineering, women constitute only 29% of under Graduate students, 32% of PG students and 34% of PhD students.

The major issue that is of concern in Higher Education is high vacancies in higher education institution. About one-third posts in the centrally-funded universities are vacant. Faculty from SC and ST communities constitute 9% and 3% of filled posts. According to a report by the International Labour Organisation (ILO), unemployment amongst youth at all levels of education in India increased between 2008 and 2022. Amongst social groups SC students with a graduate degree or

above had the highest unemployment rate at 35% followed by those from ST community at 33%.

But my concern here is that Higher educational institutions play a limited role in research. In 2020-21 India spent 0.64% of its GDP on research and development. This is lower than expenditure made by South Korea, USA, Japan, Germany, France, China and Italy. There is no doubt, therefore, budgetary allocation for higher education needs to be increased.

Coming to my Constituency Cuttack, I would like to draw the attention of the Government through you Sir, about more than century old institution of higher education, Ravenshaw University. I would urge the Government to declare this institution as a Central University. There are more than one Central Universities in many major states. But only one Central University being established in Central part of Odisha has a hoary past since nineteenth century deserves to be declared as a Central University.

I would like to draw the attention of the Government towards the High School where Netaji Subash Chandra Bose did his schooling and passed with flying colours. Ravenshaw Collegiate School established in mid-19th Century is the cradle of education in Odisha. This school be declared as a National School and adequate Central fund be provided for development of infrastructure of the school. The first Girls school named Ravenshaw Girls School is also more than century old which encouraged girl students to pursue studies when it was a taboo. This Girls school had suffered during the wrath of super cyclone in 1999. There is a need to develop modern infrastructure of this school. I would request the Government to provide special allocation for this age-old Girls' school.

With these words I conclude.

**ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI):** The education sector of the country needs great investments to be able to meet the aspirations of the 1.4 billion Indians. However, this government has consistently failed short in ensure that education is funded well. Between 2013-14 and 2020-21 (latest year for which data is available), combined spending on education by states and centre has ranged between 3.9%-4.6% of GDP. The National Education Policy (2020), and its previous iterations, have recommended government spending on education to be at least 6% of GDP. Even before NEP, various experts have recommended this spending. We have always fallen short. Even this year, things are not different. I would like to make public my

disapproval of this policy decision that keeps large number of Indians - especially the backwards, marginalised and minorities out of the India growth Story.

No Kendriya Vidhyalaya was allotted by the government in the last five years. The Kendriya Vidhyalaya at Thodupuzha is one of the biggest dreams of the people of Idukki. As per the challenge method, all the requirement for the Kendriya Vidyalaya at Thodupuzha was fulfilled by us. Still, it is not sanctioned by the government. In fact, it is amongst the 87 such KVs that are yet to be sanctioned by the government. I would like to use this opportunity to raise this matter in our august house. I request that the house recommend to the government that the Kendriya Vidyalaya at Thodupuzha is sanctioned and works expedited so that it is completed at the earliest.

In 2024-25, the Ministry has been allocated Rs 1,20,628 crore. This is a decrease of 7% from the revised estimate for 2023-24. The Department of School Education and Literacy has been allocated Rs 73,008 crore (61% of the Ministry's expenditure). This is a marginal increase over the revised estimate for 2023-24 (0.7%). The Department of Higher Education has been allocated Rs 47,620 crore (39% of the Ministry's budget). This is a decrease of 17% from the revised estimate for 2023-24. This policy shows the neglect of Higher Education, which is a ticket to prosperity for a vast majority of Indians. I urge upon the government that higher education is given a larger share of the budget and also new resources are found by the government to fund Higher Education of the masses.

Between 2013-14 and 2022-23, expenditure by the Ministry has increased at an annualised rate of 4%. Expenditure towards the Ministry as a share of overall Union Budget has also come down during this period. The allocation towards Higher Education in 2024-25 is estimated to be decrease by 17% from than the revised estimate for 2023-24. Allocation towards the University Grants Commission (UGC) is estimated to reduce by 61%. These are indicative of the systematic assault on the higher education ecosystem in the country.

It is no secret that the ideological fountainhead of the ruling party has a disdain towards free thinking and rational education that is the hallmark & of Indian higher education institutions. They are also the portals through which Indian students learn the cosmopolitan culture of India and the world. We need to ensure that they are protected. I urge upon the house to disapprove this fund cuts.

The education policy should ensure that India sees great growth in the coming years. I urge upon the house to instruct government such that the spend in education is increased to at least 6% of the GDP, and also higher education is prioritised for development by the Government.

**CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA):** a) There is an option for selection of languages in R2 and R3, If in case a student selects Hindi in R2 and another student selects Hindi in R3 then, will there be separate textbooks? If this happens then the time table will clash, examination time table will have problems, Question papers will differ, need for appointment of additional teachers and many such problems will arise. Subjects offered in R2 should not be offered in R3.

b) What is the definition of native language? Portuguese happens to be the language used by many native Goan population. Will it be considered as native language under R3? As per the original document of NEP 2020 at 4.20 (Annexure 1 para 3) in addition to Indian languages and English foreign languages such as Korean, Portuguese, French? will also be offered at the secondary stage. This is not taken into account in the implementation.

c) In the inter-disciplinary subjects Environment Education is in the first term and financial literacy road safety, electoral literacy and general laws in the second term. As per instructions from the Director of Education, training programs will be held to train the social science teacher for inter-disciplinary subjects. Can a short-term training of teachers to teach such subjects make them experts in the subject? The Director of Education has made it clear that NO ADDITIONAL TEACHERS WILL BE GIVEN to teach the subject that has 4 credit points and 120 instructional hours. Is it not a mockery of the system where untrained and unqualified teachers will teach and do disservice to the students and the entire educational system. In addition, no text books are available and further still syllabus will be uploaded on the website on 31$^{st}$ July 2024. What kind of planning is this? The first 2 months of the year is a time when most of the syllabus is covered. Such haphazard planning will be detrimental to the cause of education and the current batch of students will be treated as guinea pigs of the system.

d) As far as CWSN (Children With Special Needs) students are concerned, no mention is made of CWSN (Children With Special Needs) students. How are the schools to deal with such students? As per the main document of NEP 2020 Chapter 6 from 6.1 to 6.20 (Annexure 2, 6.1 to 6.20) a whole chapter is dedicated on inclusive education for all. In the implementation no mention is made of such

students. It is very evident that the Policy document and the implementation circular are not in sync with each other. It appears as though the implementation is done in a hurry without even referring to the policy document.

e) Regarding the workload of the teachers, it is to be noted that Rule 20 (i) para 2 of Goa School Education Rules 1986 which states that the teacher shall not get more than 21 hours of workload including non-academic subjects per week (Annexure 3) However when the calculations are done the following is the working. Every teacher gets between 34 to 36 periods per week. Even if we take a minimum of 34 periods multiplied with 40 minutes per period it works out to be 22.7 hours per week which is way more than the maximum workload contemplated under rule 20 of Goa Education Rules of 1986.

f) Also, the credits earned by students and the corresponding hour that the students will earn does not correspond to the workload of the teachers.

g) A circular of the DoE, Goa mentions that the assembly in school is exclusive of 5 and half instructional hours. I would like to state that the best instructions take place during the assembly where the students learn about different values, and true education takes place during the assemblies where students are given inputs to make them worthy citizens of the nation.

h) The workload of heads of schools is 12 lectures which is way too much compared to the numerous responsibilities that they have to handle by way of handling their workload, administrative duties which are never ending, circulars to comply on a day-to-day basis which are sent overnight, counselling of students, parents and other stake holders. Hence the work load of Heads should either be removed completely or reduced drastically to allow them to function smoothly.

i) With the setting of papers for each of the semesters for Std. IX by the Goa Board, it will lead to stress amongst students and their parents as well. This will lead to further promotion of the tuition culture which the original document of the NEP Policy 2020 promised to do away with (Annexure 4: NEP 4.36)

**1. General Points regarding NEP and its implementation:**

a) The entire document of NEP was prepared keeping in mind the CBSE pattern of schooling where the system of schools already had nursery to Std. XII in one bracket. The same system does not exist in the schools run by the State Boards. The state boards have a 10+2 system where +2 is called Higher Secondary School in

some states, Junior College in some states and PUC (Pre-University Course) in some states. The school system has a Headmaster who leads the school and the Hr. Sec. School has a Principal who leads the school. In the new system the classes 9 to 12 come under one category. Hence there is no clarity whether the Headmaster or Principal will lead the school.

b) The NEP speaks of multi-disciplinary approach. The students right from the 9th standard are allowed to select subjects of their choice from amongst a basket of subjects. Will the Directorate of Education allow the schools to appoint additional teachers on regular basis to work in their schools? What will be the status of the time-table if students opt for different subjects? How will it be managed? At present even the existing regular vacancies are converted into contract basis posts. The entire educational system will collapse with teaching posts being converted to temporary basis posts.

c) There are fillers that in certain subjects the Government may appoint teachers at a school complex level. If so, how can teachers do justice when they go to different schools. Where is the accountability? If there are temporary appointments can you expect commitment, dedication and hard work from the teachers? Will it not lead to degradation of our educational system rather than uplifting of the system?

d) There are different types of Managements in the state of Goa viz Private unaided, Private Aided, Minority institutions and Government institutions. How can the government appoint and send teachers to these schools? it is against the rules in force.

e) Besides the Minority institutions under Article 30 (1) of the constitution has a right to appoint and administer their institutions. This will lead to infringement of their right.

f) There are stand-alone High Schools and stand-alone Higher Secondary schools in the state. Attempts to add Higher secondary sections in stand-alone High Schools will only lead to closure of the existing Hr. Sec. Schools as data clearly reveals that all students who pass SSC are accommodated in the Hr. Sec. Schools. They may not get the institution of their choice but they can surely get admission in some H55. Besides in the current academic year there are several HSS which do not have a full strength of students enrolled due to lack of sufficient students as the pass percentage of SSC was less compared to the previous year.

g) Quality infrastructure is directly related to quality education. When proper infrastructural facilities are not in place it is not proper to start or implement NEP in a hurry. This will cause more harm than good to the system.

h) When things are half cooked the result will be disastrous for education as a whole. When the curriculum is not ready why are we in a mighty hurry to introduce it in the current year? When all systems are in place we can properly introduce it in the next academic year.

i) The NEP document mandates that sufficient funds be made available before the introduction of the policy. When there is no provision made for additional funds to implement NEP it cannot be introduced with the current funding structure. Hence it should be deferred till all arrangements are put in place.

After meeting with various school authorities and their managements, it emerged that:

1. The institutions are not against NEP being implemented in the state. However, they are against the haphazard and irrational way of implementing the same. The managements want that the schools/institutions be given sufficient time and resources to improve the infrastructure as per the requirements of NEP.

2. The managements also want the government to make proper budgetary provisions for the effective and efficient implementation of NEP. There should not be any compromise in the regular appointment of teachers as it is crucial for quality education.

3. The managements want that all teachers should be provided proper training in order to effectively implement NEP. Short and ineffective training programs by non-professionals will only lead to degradation of the educational standards in the state.

4. It appears that the Govt. of Goa is in a hurry to implement NEP in order to impress the centre that they are the first state to implement it. No attention is given to quality and everything is done in a mighty hurry to win the race o being the first state to implement NEP.

5. The state should adapt the syllabus and curriculum to suit the needs and requirements of the state and should not just ape the national curriculum. This is also envisaged in the NEP policy document.

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीया वित्त मंत्री जी एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा विद्यार्थियों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु शिक्षा की स्थिति को मजबूत एवं गुणवत्ता व पारदर्शिता बनाने के साथ रोजगार हेतु विद्यालय / महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा क्षेत्रों की अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए सार्थक रूप से प्रयास किया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी राष्ट्रहित के सार्थक नीतियों से प्रेरित, एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शैक्षणिक क्षेत्रों को मजबूत बनाने हेतु विकसित भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं के स्थापित करने हेतु माननीया वित मंत्री जी के द्वारा भारतीय शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु रिकॉर्ड धनराशि 1,048,000/ करोड़ रुपये आवंटित की गई है, जिससे शिक्षा प्रणाली एवं शैक्षणिक अवसंरचना का एक नई ऊर्जा के साथ तेजी से विकास होगा ।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काफी तेजी से विकास हुआ है एवं हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के साथ मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है । स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु सभी छात्र एवं छात्राओं को 4 लाख रुपये बिना ब्याज के दिये जाते हैं । मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना के तहत ट्राईसाइकिल एवं हेलमेट दिये जाते हैं ।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल की मुख्य लंबित मांगो की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । बीरपुर एसएसबी कैंप में स्थित केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है किन्तु भूमि का पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है । उसके लिए निबंधन शुल्क के रूप में 3,30,0250/ रुपये की लागत राशि केन्द्र सरकार के द्वारा देने की कृपा की जाय, जिससे केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके । कोशी क्षेत्र के सुपौल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय । इसी के साथ, मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

धन्यवाद ।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल **(**महाराजगंज**) :** मैं शिक्षा सम्बन्धी अनुदानों की माँगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ । वितीय वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि इस बजट में देश के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए छात्रों को दस लाख रूपये कर्ज के तौर पर वित्तीय सहायता, बीस लाख युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में निपुण बनाने की योजना, एवं एक हजार आई.आई.टी. को अपग्रेड करने की व्यवस्था देश के करोड़ों छात्र-छात्राओं उच्च शिक्षा सहित अन्य प्रकार के क्षेत्रों में अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वरदान सवित होगा ।

इस बजट में शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान, अपने देश में लागू नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा के सामानांतर खड़ा करने के लिए एक क्रान्तिकारी कदम है । इस व्यवस्था के लिए मैं शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को हृदय से बधाई देता हूँ ।

अंत में, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार के सारण (छपरा) एवं जिला-सिवान तथा अपने प्रमंडलीय मुख्यालय छपरा में निम्न कार्यों का कराने का अनुरोध माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ:

1. जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कर स्थापित किया जाये ।

2. सारण जिला अंतर्गत मशरक केन्द्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली की पढ़ाई आरम्भ कराया जाये ।

3. सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज केन्द्रीय विद्यालय को महाराजगंज में भूमि उपलब्ध कराते हुए भवन निर्माण कराकर उसमें उसका संचालन कराया जाये ।

4. महाराजगंज लोकसभा, बिहार के अंतर्गत एक IIT की स्थापना कराया जाये ।

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा) : हम मिथिला क्षेत्र से आते हैं । मिथिला क्षेत्र आदिकाल से ही ज्ञान की भूमि रही है । सभ्यता और संस्कृति के विकास के आदिकाल से ही षट दर्शन में सांख्य, मीमांसा न्याय जैसे दर्शन मिथिला क्षेत्र की देन है । माता जानकी की यह भूमि कृपा की आदि के पीठ के साथ-साथ निष्पापा तथा निरपेक्षा के रूप में चर्चित है । प्राचीन काल से ही मिथिला देश भर में शिक्षा संस्कृति और संस्कार की आज भूमि रही है । जनक, याज्ञवल्क्य, गौतमी, गार्गी, अष्टावक्र मैत्रेयों के स्थापित सिद्धांत ही भारत को विश्व गुरु बनाने के रास्ते में सबसे बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं । लेकिन 60 सालों में कांग्रेस तथा उनके सहयोगियों के शासन में मिथिला के शैक्षणिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया पूर्व काल से यहां के स्थापित तथा शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आयामों एवं संस्थाओं को धराशायी कर दिया ।

इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने दरभंगा में 1951 ई० में जिस मिथिला संस्कृति शोध संस्थान की आधारशिला रखी आजादी के 60 सालों तक उसका शिलापट यह अपनी दुर्दशा का गवाह बना रहा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संस्थान को पुनर्जीवित करने की पहल की ।

60 सालों में कांग्रेस द्वारा इस क्षेत्र की शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मिथिला की शिक्षा व्यवस्था को पर पटरी पर लाने की पहल शुरू की तथा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसे धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न कदम उठाए । श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 8 करोड लोगों की जनभाषा मैथिली भाषा को अष्टम सूची में स्थान दिया तो मोदी जी की सरकार ने इसे सीबीएसई में शामिल कर 8 करोड़ मैथिली भाषी लोगों के छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य की नींव मजबूत की ।

कांग्रेस के शासन में जहां 2013-14 तक देश स्तर पर शिक्षा का बजट 68.728 करोड़ था जबकि वर्तमान में 2024 में 22200.35 करोड़ है जिसने बिहार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 13840 करोड रुपए आवंटित हुए हैं जिसे यह साबित होता है कि पूर्व के कांग्रेस सरकार द्वारा चौपट किया गए शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कितना जागृत है ।

वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन हमारी इन निम्न मांगों पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है ताकि 8 करोड़ मिथिला के लोगों को मिथिला फिर से शिक्षा का हब बन सके ।

बिहार के लिए मांग

1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू द्वारा 1951 में स्थापित दरभंगा में संस्कृत शोध संस्थान का कायाकल्प किया जाए तथा इसका स्वामित्व राज्य से केंद्र सरकार अपने हैंड ओवर में ले।

दरभंगा स्थित चर्चित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं डॉ० कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए । ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा को फिर से चालू किया जाए दोनों विश्वविद्यालय का सीमांकन कराकर इसकी चार दिवारी एवं आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जाए । दरभंगा स्थित बालिका इंजीनियरिंग कॉलेज (WIT) एवं ला कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था एवं

आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए । मिथिला क्षेत्र में आईआईटी, आईआईएम, सीए, cma जैसे आधुनिक एवं रोजगार पूरक शिक्षा का संस्थान खोला जाए । मैथिली भाषा झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा है तथा दिल्ली मुंबई, कोलकाता, जैसे बड़े शहरों में करोड़ों मैथिली भाषी है इसलिए मैथिली भाषा को यूपीएससी, बीपीसीएस परीक्षाओं के लिए शामिल किया जाए । प्राथमिक कक्षा से 12 वीं कक्षा तक मिथिला अक्षर लिपि में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए केंद्र एवं बिहार राज्य में मैथिली अकादमी का गठन एवं पुनर्जीवित किया जाए । संपूर्ण मिथिला में बिहार एवं भारत सरकार के सभी संस्थाओं के कार्यालयों का नाम मिथिला अक्षर में अंकित किया जाए । सर्व शिक्षा अभियान की सभी गतिविधियों की जानकारी सांसद को दी जाए तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास सांसदों के द्वारा कराया जाए ।

लहरिया सराय के पटोरी में जमीन उपलब्ध है तथा वहां केंद्रीय विद्यालय खोला जाए इसके सिवा बिरौक अनुमंडल तथा बेनीपुर अनुमंडल में भी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो । बाढ़ प्रभावित बिरौक अनुमंडल में आवासीय नवोदय विद्यालय तथा कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना हो ।

**DR. PRADEEP KUMAR PANIGRAHY (BERHAMPUR):** I would like to express my views on the Demand for Grants for the Ministry of Education.

This historic Budget by the hon. Finance Minister has made adequate provisions in all sectors and this has further strengthened the pace of development required so as to achieve the vision of Viksit Bharat 2047 of Prime Minister, Modi. Under the Prime Minister?s leadership, India has become a global leader in various sectors and has seen unprecedented growth for all sections of the society.

This Budget rightly identifies the need to strengthen our education sector so as to ensure the upliftment of the citizens of this country. The provisions and allocations made under this Budget have a two-pronged approach to both make educational infrastructure improvements as well as provide benefits to the people to ensure they can access and afford not just basic schooling but quality and uplifting education.

This is the beginning of Modi 3.0, but the first two tenures have already proven how capable this Government is in providing for the education related needs of the youth of this country.

I find it important to highlight that since the 2014 Economic Survey, the total number of senior secondary schools as well as universities have also approximately doubled. I would further like to highlight that under this Government?s two successful tenures, 10,000 colleges have come up in different parts of the country in just ten years. Even for female literacy, the Government has taken steps which have directly resulted in an increase in the percentage of women with more than ten years of schooling from 36 per cent to 41 per cent in just five years gap between NFHS-4 and NFHS-5. Admittedly, several measures are still required for

improving these statistics even further, but this Government through these improvements has proven its dedication and capability in making the required interventions for the welfare of Bharat?s citizens.

This year?s Budget allocations for education are significantly higher than the allocations made by the UPA in the 2013-14 Budget, with a 40 per cent increase in allocations towards the Department of School Education and Literacy and an astounding 80 per cent increase in allocation towards the Department of Higher Education. This growth indicated that under the leadership of PM Modi, the Government is committed to not only ensure appropriate schooling in the country but also to equip our youth with appropriate higher-level education, allowing them to aspire for better livelihoods and contribute directly to the development of Bharat?s citizens.

This Budget has set ambitious targets and relevant allocations through various schemes to achieve outcomes such as an adjusted Gross Enrolment Ratio of 98 per cent for ST/SC and girl students in elementary education among several other key metrics. The Government is focusing on a multi-dimensional approach to improve the educational environment in the country and even compete internationally in terms of education being provided in the country.

At the schooling level, schemes like Samagra Shiksha, PM SHRI, PM POSHAN, and STARS are contributing to this approach and the outcomes include opening and upgradation of schools, providing special training to six lakh out of school children, providing transportation facilities to eight lakh students, providing six crore free textbooks, coverage of 32,000 schools under digital initiatives, training of eight lakh teachers and 12 crore beneficiaries under PM POSHAN.

This Budget has also given incredible focus to higher education through efforts like World Class Institutions or WCI, PM USP Yojana, National Apprenticeship Training Scheme, and PM USHA. The Government has set ambitious targets including having six WCI in the top 500 in world rankings, higher numbers of patents filed and papers published, two lakh students to get credit guarantee funds, three per cent interest subvention annually for one lakh students, 50 per cent females receiving scholarships, special scholarships for Jammu and Kashmir, and Ladakh and finally grants and support to higher education institutes.

I come from Odisha, a State that has historically been left deprived and not proportionately focused upon based on its needs. In the past 24 years, the State

was under the leadership of the BJD, a leadership which failed to acknowledge the developmental needs of the people and hence the people of Odisha got left behind in several sectors, including education. Even Central Government efforts could not be as effective as they could be due to the nature of working of the State Government.

The people of Odisha understood this and this time gave a historic mandate to the NDA Government in both the State and in the Centre to create a double engine Government and that is why I want to raise my State?s issue here because I trust the leadership of this Government to help fulfil the aspirations of Odisha?s people.

The Odisha State Economic Survey recently brought to light that the State has the highest secondary level dropout rates in India at 27.29 per cent. Another highly concerning fact is that while the Gross Enrolment Ratio or GER, which is the percentage of the official school-age population enrolled in a particular level of education, at upper primary and secondary is 91.3 percent and 80.4 percent respectively, the GER for higher secondary level is at a shocking 43.6 percent against the target of 100 per cent, which means that out of 1,000 children in that age group, only 436 are enrolled at that level. Further, the GER for higher education is estimated to be between 20-25 per cent. The additional transfer to the Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) worth Rs. 23,500 crore made in the Budget can help in this regard.

It is also important to note that other than social and economic reasons, lack of access to quality education and proper infrastructure are also causes of dropouts. According to UDISE+ 2021-22, Odisha also has severe issues relating to school infrastructure including 25 per cent of schools not having electricity and 45 per cent schools not having toilets for children with special needs. I would like to emphasize that only 18.3 per cent of schools have a computer facility. As we move further towards our goal of digitization, this level of infrastructure will lead to Odisha?s children struggling due to lack of access to computers and internet.

My constituency too is a witness to issues in the education sector. Gajapati, one of the districts in my constituency, is ranked 6$^{th}$ lowest district in Odisha in the Performance Grading Index of the Ministry of Education.

Since Odisha is a victim of years of mismanagement in the education sector under the previous State leadership, it required additional support to rise up and compete

with the rest of the States. This double engine Government is best suited and highly capable in addressing the problems and so I want to make certain requests.

Firstly, there is a need for upgrading of existing schools and establishment of new schools in the State. The Budget already makes provisions for this under Samagra Shiksha, and I request the benefits of this reach Odisha, including the setting up of Sainik School in Berhampur. Further, Odisha requires digitization and setting up of appropriate labs in existing schools as the current situation in the schools is very poor, in this regard, even in my district of Ganjam, from where the ex-Chief Minister also belongs to but disregarded and failed to contribute to its development. Action can be taken under Samarth Shiksha as it also makes provisions of science labs and computer classrooms. Odisha would also benefit from schools under PM SHRI which are linked to the local entrepreneurial system and make counselling and technology available to children.

The State also requires support in higher education, especially in southern Odisha. Odisha, despite being a large State, under the Ministry of Education has zero medical universities, only one law university, zero veterinary universities, and so on. Despite being the 8$^{th}$ largest State population-wise, it has only five out of the 165 Institutes of National Importance in the country. I request that the Ministry sets up suitable universities in the State, especially in the district of Ganjam, where people from the entire South of Odisha come for various purposes.

I make these requests so as to ensure that the youth of Odisha do not get left behind in this age of digitization and have to drop out and join the workforce at a young age in a time where India is growing at such a rapid pace under such competent and visionary leadership.

I once again congratulate the Prime Minister and the Finance Minister for making the people of India once again believe that the country is in safe hands.

**SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI):** I would like to express my views on the Demands for Grants under the Ministry of Education. I would like to thank our hon. Prime Minister and our hon. Minister of Education Shri Dharmendra Pradhan ji for the exemplary work done in the field of education for India. Today, our students are in the best of places and best of jobs all over the world. It would not be wrong to say that our educated students from India are leading companies which are ruling the world and its economy. This is only because of the vision of our hon. Prime Minister and our hon. Minister of Education.

I would like to thank our Prime Minister and our Minister of Finance Shrimati Nirmala Sitharaman ji for the fabulous Budget and for giving Rs. 1.21 lakh crore for the Education Department in the Budget 2024-2025, which is an approximate increase of seven per cent from the last time in the previous Budget. There is an increase to Rs. 73,008 crore from Rs. 68,804 crore in the allocation that has been given for the Department of School Education, and Rs. 47,619 crore from Rs. 44,090 crore in the allocation that has been given for higher education, which is a substantial improvement for our country.

One crore youths will be provided internships in 500 big companies and financial loans of up to Rs. 10 lakh for higher education in domestic institutions. Even in Odisha, there is the highest resource allocation of Rs. 33,865 crore for school mass education, that is 9.71 per cent share in the total Budget size.

I would like to request our hon. Minister Shri Dharmendra Pradhan Ji to please sanction a Kendriya Vidyalaya for Junagarh block in the district of Kalahandi in Odisha. Education is the foundation for an overall development of any area and we need a good high school in this area. This is a long-standing demand of the people of Kalahandi. We would be very grateful if this is granted as it will lead us, that is, the children in Junagarh to get good education and, hence, will add to the overall development of Kalahandi. I would like to request for the establishment of an agriculture college in the sub-division of Dharamgarh. I would like to request for a medical college in Nuapada district of my constituency of Kalahandi in Odisha. Another very important demand is the demand for an agriculture college in Khariar.

I would like to demand for an Eklavya model residential school in my ITDI blocks of Kalahandi and Nuapada districts where I would also like to make a special request for teaching of our original Adivasi language - which is getting lost and forgotten in today's times - as a part of the curriculum.

We need to bring to the attention of the hon. Education Minister the need to open a school for the study of Vedas, which are the Rigveda, the Yajurveda, the Samaveda and the Atharvaveda.

On behalf of all the divyang people of Odisha, I demand a "Divayang Vishvavidyalaya? in Kalahandi for all the disabled people of Odisha State. It will help these people to uplift their lives, and through the establishment of this university,

Divyangjans will also be able to contribute in the development of the State and our great nation.

I would also like to make a special request for a skill development university in my districts of Kalahandi and Nuapada as we have a lot of children who will benefit, and get good job opportunities after passing, from them.

Our Kalahandi and Nuapada districts are high on production of cotton. Hence, I would like to request for a weaver university, 'Bunkar Vishwavidyalaya' as we also have weaver communities in Kalahandi. This would be highly educational and helpful to people all over Odisha.

**SHRI ANANTA NAYAK (KEONJHAR):** I would to like mention that the education budget has been doubled in the Modi Government as compared to the previous UPA Government. Since 2014 under the visionary leadership and guidance of Modiji, 344 new colleges, 15 new AIIMS and 7 IITs have been established in the country resulting in improvement in the rankings of our colleges and universities and opening avenues for educational opportunities and jobs for the youths.

Initiating skilling programme to provide tainting to 20 lakh youth in five years, upgrading 1000 industrial training institutes, internship programme to provide practical experience to one crore youth along with loans upto Rs.10 lakh for pursuing education in domestic institutions to prioritize financial support for higher education to poor talented youth shows the proactive intent of Modiji's Government towards education and empowering youth through education which was completely lacking in previous UPA Government.

The initiative of Atal Tinkering lab to foster creativity and innovation among students in fields like science, technology, engineering and mathematics is a master stroke of Modi Government to nurture the young minds. With almost all States and Union Territories and more than 60 percent Government schools covered under Atal Tinkering Labs more than 1.1 crore students are being benefitted under the initiative.

Budget allocation of Rs. 6,050 crore towards PM SHRI (PM Schools for Rising India) programme launched in 2022, by the Government under NEP 2020 will not only provide learning environment to 18 lakh beneficiary students but will also encourage youth to participate actively in acquiring education.

My Parliamentary Constituency, Keonjhar, Odisha is a tribal dominated area and establishment of a tribal university in Keonjhar will not only open educational opportunities for tribal people of my constituency but will help them in connecting to mainstream. Odisha is an agriculture dominated State with more than 70 percent of population dependent on agriculture. Therefore, I request the hon. Minister to open an agriculture university in Keonjhar. Government College of Engineering, Orissa School of Mining and Engineering, North Odisha University along with Dharnidhar University at Keonjhar are important technical and non-technical educational institutes in my constituency. But they are not in good condition and even lack basic facilities. It would not be an exaggeration if I say that these are the higher educational institutes just for name?s sake. These educational institutions need to be upgraded with state-of-the-art facilities for students to acquire excellence in the education for students of not only Keonjhar but students from all over who are coming in Odisha to study here.

In view of the above facts, Hon?ble Minister is humbly requested to look into it favourably. As Hon?ble Minister is aware that southern part of Jharkhand adjoining to my constituency, Keonjhar and Mayurbhanj and Sundergarh districts of Odisha are tribal dominated areas. Hon?ble Minister is requested to establish a Tribal Chair in educational institutes of these areas so that tribal culture, music and tradition may be conserved through research in these educational institutes.

Thank you.

**SHRI NAVASKANI K. (RAMANATHAPURAM):** I would like to express my views on the Demands for Grants related to the Ministry of Education for 2024-25.

Education is the most important sector that determines the future of our country. Basic education can shape the development and history of future generations. However, I regret to note that the funds allocated by this Government for such a crucial sector are entirely inadequate, showing a lack of concern for our future generations. The percentage of GDP allocated to education is very low. The Union Government currently earmarks only 2.5 per cent of GDP for education, whereas, during the previous Congress regime, 4.77 per cent of GDP was allocated. In Tamil Nadu, our hon. Chief Minister allocates 12 per cent of the State's GDP for education. This clearly demonstrates who is truly leading and capable of leading a Government that cares about its people and envisions a brighter future for the next generations.

The Union Government's commitment to education appears to be limited to its intention to introduce tribal education through the new education policy. Today, even students from poor families have the right to pursue higher studies, research, and medical education, a right to social justice that our forefathers fought for over time. The BJP Government is attempting to revoke such a right and reintroduce a system of elitist education.

The new education policy must be withdrawn. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu has made it clear that he will never accept this new policy in our State. The Union Government is deceiving the public by withholding outstanding education funds from the States that reject the new education policy, which goes against social justice. I urge the Union Government to abandon this trend and request the immediate release of the pending "Samagra Shiksha" project funds to the Tamil Nadu School Education Department, considering the educational interests of the students in Tamil Nadu.

Our country is a union of diverse States, each with its own governance systems and policies based on its cultural heritage and climate. The kind of development each State desires, the growth of its future generations, the type of education to be provided, and how the State's culture and history should be taught can only be decided by the respective State Governments. Therefore, it is appropriate that Education, one of the most important aspects determining the history of future generations, be included in the State List. I urge the transfer of Education from the Concurrent List back to the State List.

Regarding NEET, it has failed to produce quality doctors and has instead created a market for coaching centres. Tamil Nadu, the State with the highest number of medical colleges in the country, has consistently opposed NEET. This examination adds unnecessary stress and burden to the students who have already studied for twelve years in the State education system and have excelled in their twelfth-standard exams. Tragically, many students have taken their own lives due to this stress. The Government must understand that at stake are not just the lives of these students but the very foundation of India's future. I request the cancellation of all entrance exams, including NEET.

Lastly, I want to raise the important issue of Hindi imposition. Hindi is gradually being imposed indirectly in all sectors under the control of the Union Government, with projects being renamed in Hindi. Imposing a single language in a diverse country like ours is shameful, especially in States like Tamil Nadu, which is

committed to bilingualism. It is condemnable to repeatedly attempt to impose Hindi. As early as 1949, during the debate on the official language in the Indian Parliament, hon. Quaid-e-Millat, a member of the Indian Union Muslim League, stated that if there were to be one official language in India's multifaceted motherland, it should be Tamil as our mother tongue. The current new education policy encourages language immersion, but I urge that everyone be given equal rights in our multifaceted India. Thank you.

**DR. T. SUMATHY *ALIAS* THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):** In our country, both the union and State Governments have responsibility for education. But the role of State Governments is ultimately important and decisive for building the strong foundation of the education system especially school education.

Though both Union and State Governments operate schools and higher education Institutions (HEls) the responsibility and onus are very much on the State Governments only.

In 2024-25, the Union Government has allocated Rs. 1,20,628 crore for Education, out of that School Education gets Rs. 73,008 crores and Higher Education Rs. 47,620 crores. The Government of Tamil Nadu in its budget 2024-25, has allocated Rs. Rs. 52, 253 crores for Education, out of which Rs. 44,042 crores for School Education and Rs. 8,212 for Higher Education.

Tamil Nadu for its population of 8 crores is spending Rs. 52,000 crores for Education. Uttar Pradesh for its huge population of 24 crores has allocated Rs. 84,000 crore Karnataka for its 7-crore population has allocated Rs. 40,945 crores, Maharashtra with a population of 13 crores has allocated Rs. 96,000 crores for Education.

It is very obvious that the funds allocated by the Union Government for education very low comparing to the total spending by all the states put together. Even for establishing some Kendriya Vidyalayas the State Governments allocate sufficient land through the District administration.

But the Union Government enjoys maximum dominance and wield its power to infringe upon the federal rights of the States in education through its regulatory bodies like the UGC, AICTE, NCTE, NCERT, and CBSE. It is very sad, undemocratic and unwarranted intrusion.

The recommended Government spending on education to be at least 6 per cent of GDP. But the Union Government is lacking way behind in this regard. The Department of School Education funds for the Samagra Shiksha Abhiyan and PM-POSHAN schemes. The Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) is a non-lapsable fund in which proceeds of secondary and higher education cess are credited.

Only two glittering announcements are made in the budget on education,

1) Interest subvention of 3 per cent annually will be given for education loans up to Rs 10 lakh One lakh students will be supported every year.

2) Creation of Digital public infrastructure for the education sector to improve productivity and encourage innovation.

Our great poet Thiruvalluvar has written a separate Chaptercontaining 10 couplets about the importance of Good Education 2000 years ago. "The wealth which can never decline is not riches but learning" (Thirukkural 400).

Tamil Nadu pioneers in higher education catering to the aspirations of the youth being locally appropriate and context-specific while also being globally relevant to the needs of all sections of the society in terms of access and equity thereby fostering inclusivity reaching to the marginalized and disadvantaged sections to evince an overall development of the people.

This is primarily because of our State Educational Policy propounded by our Thanthai Periyar, Perarignar Anna Muthamil Arignar Dr. Kalaignar who have propelled a revolution in education, employment and efficiency. The basic principles of Dravidian model government equality, social justice, women liberation and welfare economy. Our hon. Chief Minister Thalapathy MK Stalin's determined policies and unclenched will to serve the people.

As said by hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy M K Stalin, "Society or Economic condition or Political situation should not be an obstacle for our students in getting their education. This is the policy of the Dravidian model of governance."

One of the standing testimonies to the emergence of Tamil Nadu in the sphere of Education is the colossal building enshrine the University of Madras established in 1857 by the Act of the Legislative Council of India on the model of the University of London, has been the bedrock for the establishment of other Universities in India.

There are more than 1000 Technical Institutions in Tamil Nadu and includes 520 engineering colleges and 502 polytechnic colleges in Tamil Nadu.

The gross enrolment ratio of Tamil Nadu in higher education stands first in India as per the data in All India Survey on Higher Education (AISHE). This is almost double the National average.

In Tamil Nadu, six State Universities are in Top 100 in overall category while eight state universities are in Top 100 in Universities Category. Six State Universities have secured A++ in NAAC, 2 State Universities have secured A+ NAAC while 4 State Universities have secured A in NAAC among the 13 State Universities.

Alagappa University is ranked among Category I Universities by MHRD.

Four Government Arts and Science Colleges are in Top 100 with Presidency College in the 3rd position for the 3rd consecutive year.

Three State Universities are in Top 50 Research Institutions Category viz., Anna University (13), Bharathiar University (38) and Alagappa University (43). Sir, we have been inculcating the Outcomes-based curriculum for development of cognitive skills viz. Knowledge, Skills & Attitude (KSA) that fosters critical thinking, reflection, project-based learning, problem solving to match local and global needs and standards.

One of the most powerful tools and popular schemes implemented in Tamil Nadu is the Incentivizing of Rs. 1,000 to girl students who pass out from Government and girl students studying in Tamil Medium in aided schools to pursue higher education through Pudhumai Penn monthly stipend scheme.

Introduction of Tamil Pudhalvan monthly stipend scheme of providing Rs. 1,000 for boys who pass out from Government Schools to pursue higher education from the current academic year (2024-25).

The Chief Minister Research Grant (CMRG) for faculty members engaged in frontier areas of research to propel academic research environment conducive for research, incubation and technology transfer.

Chief Minister Research Fellowship (CMRF) to encourage scholars pursue research programmes in their preferred areas of study. Placement drives enabled by Naan Mudhalvan post implementation of industry-oriented skilling courses.

The Government Polytechnic Colleges will be upgraded to Industry 4.0 standards in collaboration with Industry Partners at a cost of Rs. 3,014 crore. The quality in higher education is inextricable from Research and Development. In order to propel research, the Government have been working on establishing industry-aligned research parks in Chennai, Madurai and Coimbatore in collaboration with TIDCO.

Enhancing quality in education includes appropriate accreditation in place. Measures have been taken to persuade Higher Educational Institutions (HEls) to go for NAAC accreditation and participate in NIRF, Times Higher Education and QS rankings to upgrade on par with peers at the National and International levels.

In order to increase the enrolment in polytechnic colleges and help the polytechnic students to excel in their studies, Free text books are being distributed to all the first-year diploma students of Government Polytechnic Colleges from the academic year 2007-08 by Muthamilarignar Dr. Kalaignar. Under this scheme, the books are being distributed at free of cost in the subjects of English, Engineering Physics, Engineering Chemistry and Engineering Mathematics.

The issue of free bus pass scheme to all the diploma students studying in the Government Polytechnic Colleges was introduced by the Government of Muthamil arignar Dr. Kalaignar from the academic year 2007-08 to facilitate students to reach the Institutions without any financial burden. The waiver of tuition fees for Diploma students studying in Government Polytechnic Colleges from the academic year 2008-09 by the Government of Muthamilarignar Dr. Kalaignar.

The Government have sanctioned the stipend, Post Graduate Assistantship of Rs. 6,000 per month to the 1200 postgraduate students studying in Government Engineering Colleges.

The First-Generation Graduate Scholarship scheme was started by the Government of Muthamiarignar Dr. Kalaignar with the objective of promoting higher education among the families where no member is a graduate. The scholarship is given to the students irrespective of their caste and income. In the academic year 2023-24, Rs. 380 crore have been given to 1,57,342 first graduate students of engineering colleges.

Internship Training to the students of Government Engineering (2,500 students) and Polytechnic Colleges (7,500 students) towards financial support at the rate of

Rs. 16,600 per student for 25 days internship training to enhance the technical skill of the students covering 10,000 students every year.

"The Tamil Nadu Admission to Undergraduate professional courses on preferential basis to students of Government Schools Act, 2021" was enacted in order to take affirmative action to bring about equality between students studying in Government schools and private schools. The Hon'ble Chief Minister has announced that, the entire fees such as Tuition Fee, Hostel Fee, Transportation Fee, etc. be borne by the Government for these students admitted under this seat. Accordingly, in the academic 2022-23, Rs.129.08 crore have been disbursed to 8,719 first year and 6,278 second year students. In the academic year 2023-24, Rs.185.59 crore have been disbursed to 9,795 first year, 8,375 second year and 6,162 third year students.

In order to motivate Government School students to aspire to join premier Higher Education Institutions like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science and All India Institute of Medical Sciences, the Government will bear the full cost of their undergraduate education. The entire fees for all the years, have been sanctioned to the students by the Government.

In order to encourage and motivate the economically weaker section meritorious students to pursue their engineering courses (B.E. / B.Tech.) the Government provide financial assistance from Chief Minister's Public Relief Fund. The financial assistance of Rs. 50,000 each has been given to 24 students during the academic year 2023-24.

Women friendly diploma courses have been introduced from the academic year 2022-23 in the following colleges with a view to increase the women enrolment in polytechnic colleges and also motivate them to take up higher studies for better employment opportunities: (1) Mechanical Engineering (CAD) in Central Polytechnic College at Chennai (2) Office Management and Computer Application in State Institute of Commerce Education at Chennai (3) ECG Technology in Government Polytechnic College at Coimbatore (4) Web Technologies in Tamil Nadu Polytechnic College at Madurai (5) Bio-Medical Electronics in Government Polytechnic College at Nagercoil and (6) Interior Decoration in Dr. Dharmambal Government Polytechnic College for Women, Chennai.

For providing intensive coaching for 500 students in 11 Government Engineering Colleges for competitive examinations CAT / GMAT / GRE and IELTS / TOEFL from

the year 2021-22. The intensive coaching would not only enable the students to succeed in these competitive examinations, but to enhance their employment opportunities with reputed firms at the National and International level. Entrepreneurship Development and Innovation Programmes in Polytechnic Colleges through 5 Hubs in collaboration with Entrepreneurship Development Innovative Institute (EDII), Chennai. 5 ED Hubs have been established in 5 Polytechnic Colleges. The programmes conducted under 5 ED Hubs were merged with Naan Mudhalvan Scheme from October 2023.

As far as the Chief Minister's Research Grant Scheme is concerned, in order to motivate faculties, Research scholars and under graduate and post graduate students to do research on current challenges, "Chief Minister's Research Grant Scheme" have been introduced from the academic year 2023-24 and the Government have sanctioned a sum of Rs. 50.00 crore as recurring grant towards the allocation of funds for all Government Higher Educational Institutions and Universities in Tamil Nadu. For the year 2023-24, 61 projects are identified in Technical Education domain and funds being released. In Collegiate Education domain, action is being taken to identify the projects.

We have the establishment of world skill academy and smart manufacturing technology centres. In order to provide skills and develop the students as per World skills in Electrical Installation, Industrial Controls, Industrial Automation, Building Automation, World Skill Academy, Smart Manufacturing Centres are being established in 6 Government Polytechnic Colleges at Chennai, Coimbatore, Dharmapuri, Mayiladuthurai, Tiruchirappalli and Thoothukudi in collaboration with Schneider Electric India Ltd and the financial assistance of Tamil Nadu Skill Development Corporation, Chennai at a cost of Rs.10.00 crore.

The Pudhumai Pen Thittam ? the assistance of Rs. 1,000 per month is being issued to Higher Education Pursuing Girls students who studied in Government Schools from sixth to twelfth standard under "Pudhumai Pen Thittam" of Social Welfare Department. 4,039 students from Government Polytechnic Colleges and 12,135 students from Government Engineering Colleges have been benefited during the academic year 2023-24.

During the year 2023-24 a total number of 2,71,710 girl students who are pursuing their education in Arts and Science Colleges have benefitted. This scheme has now been extended to Girl students studying in Tamil Medium in Government Aided Schools also.

Naan Mudhalvan is an ambitious scheme which aims at imparting employment-oriented skillset to the youth. Identifying the aspirations in early stage and providing a strong base for their employment is the special aspect of this scheme. Under this scheme a total number of 8,67,947 students studying in the colleges coming under the Directorate of Collegiate Education have been imparted skill training. In the job fairs conducted 63,665 students have participated and 15,753 students have been issued offer letters.

Tamil Puthalvan Thittam - in order to increase the enrolment ratio of Girl students in Higher Education, "Pudhumai Penn Scheme" has been introduced and it has brought a remarkable change in women education. Likewise, from the year 2024-25 "Tamil Puthalvan Scheme" is to be implemented to encourage the Male students who have studied 6th to 12th in Government schools and pursuing their Higher Education. Due to this, the enrolment ratio of Government school students will increase considerably. An amount of Rs. 1,000 per month will be awarded to the students. To implement this ambitious scheme, it is proposed to allocate Rs. 360 crore during 2024-25 financial year.

The Naan Muthalvan Scheme ? as per the direction of the Government of Tamil Nadu, the scheme is implemented to impart Industry relevant, employable and Entrepreneurial skills to the students. Under this scheme, in second semester English communication will be offered which is certified by the Cambridge University. Digital Skill will be provided in fourth semester certified by Microsoft, NSE etc.

NASSCOM - SKILLSDA training course for the final year UG and PG students of Thiruvalluvar University was conducted. The mega placement was conducted in the year 2023 for the trained students. More than 3,000 students from this University were placed to the reputed companies.

The Tamil Nadu Science and Technology Centre has established Periyar Science and Technology Centre with B.M. Birla Planetarium in Chennai, Anna Science Centre-Planetarium in Tiruchirappalli, Dr. Kalaignar Karunanidhi District Science Centre in Vellore and Regional Science Centre in Coimbatore. Planetariums in Chennai and Tiruchirappalli are engaged in Astronomy education.

The Tamil Nadu Science and Technology Centre, is implementing INSPIRE Award - MANAK from the year 2009 onwards (Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) programme in Tamil Nadu. Implemented in

coordination with Department of Science & Technology and National Innovation Foundation (NIF)-India. 83,987 students were honoured with this award and cash awards worth Rs. 47.77 crore was distributed.

The SAKURA Exchange Programme under the invitation of the Government of Japan, the students, who won Awards in the past INSPIRE Award - National Level Exhibitions and Project Competitions held in New Delhi were taken to Japan to visit Research Institutions. So far, 16 students from Tamil Nadu have visited Japan under this programme through Tamil Nadu Science and Technology Centre.

"Tamil Nadu Unmanned Aerial Vehicles Corporation" in partnership with Madras Institute of Technology, Anna University has been established in order to cater the drone-based needs of various departments of Government of Tamil Nadu through drone-based solutions and services. The Tamil Nadu Unmanned Aerial Vehicles Corporation has been registered under the Companies Act as 100 per cent Government owned private limited company. The corporation apart from designing, manufacturing and trading in all types of drones will also provide a large number of drone-based services like agricultural pesticide spraying monitoring, mapping, surveillance, search and rescue, volumetric analysis for the user department.

I would urge the Union Government to follow Tamil Nadu State Education Policy and the innovative, inclusive schemes to achieve the desired results throughout the Nation.

Thank You.

श्री बिद्युत बरन महतो **(**जमशेदपुर**) :** मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पेश किया गया है । वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए हैं जिसमे शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

इस बजट के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में किए गए ये सुधार और लाभ न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, बल्कि हमारे देश को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे । यह बजट हमारे शिक्षार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समग्र समाज की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा । हमारे युवा जो सरकारी योजनाओं और नीतियों के तहत किसी भी लाभ के पात्र नहीं हैं, उनकी मदद के लिए हम प्रमुख घरेलू संस्थानों में उत्तर प्रदेश शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की गयी है । आज ऋण राशि प्रतिषत वार्षिक दिवस पर एक लाख छात्रों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा ।

मेरे संसदीय क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ मांगो को मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं जिनका विवरण इस प्रकार है :-

· वर्तमान में मेरे संसदीय क्षेत्र में कई बड़े-बड़े PSU स्थित है जैसे UCIL, HCL, TATA इत्यादि । ऐसे में इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय का स्थापित होना अतिआवश्यक है । इसके स्थापित हो जाने से मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में सभी लोगो को विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के अवसर मिलेंगे ।

· जमशेदपुर में एक नया नवोदय विद्यालय के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को अपने बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के अवसर मिलेंगे ।

· जमशेदपुर एवम आसपास के विद्यार्थियों को इंजिनियरिंग इत्यादि की शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है । ऐसे में जमशेदपुर में एक आईआईटी जैसे एक संस्थान के स्थापना हो जाने से इन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा ।

अतः माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरी उक्त मांगो पर बजटीय प्रावधान कर इन्हें पूर्ण करने की कृपा करें जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के शिक्षा स्तर में वृद्धि हो सके । धन्यवाद ।

**SHRI SUBBARAYAN K. (TIRUPPUR):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. New Educational Policy is unacceptable. We reject it. Education should be shifted to the State list. Government is duty bound to provide education to the children of this country. But this Government has shifted its rightful duty to the hands of private entities. This Government says that as many as 80 Crore people are waiting at ration shops for free supply of rice and food grains. If they are waiting in queues at ration shops for free rice, how will they afford to provide education to their children by spending money. Privatisation of education sector is aimed only to deprive the children of common people, including the marginalised sections of the society in getting their education in India which is filled with poverty. We strongly oppose this modern Varnashrama Dharma or the Varna System which prevents our children in getting education. A Member of Parliament who spoke before made a mention about Swami Vivekananda. Whether Vivekananda said only one thing? We should understand, nurture every child as it is given birth with lots of knowledge. Further it should be a man making education ensuring all-round development of that child and the society. Whether the current policy is ensuring this? The right to free education of a child being brought up in a house is being denied and prevented by those in Government in the name of privatisation. I criticize this to be an offence. Lessons which are not related to knowledge and reasoning are included in the Syllabus. Students should be imparted scientific education. This education should be rationalistic. Sati system was in practice 100 years ago where the wife of the deceased was made to jump into the funeral pyre of her husband. This was considered divine in the past. Similarly this country had even refused to impart education to Crores of persons in the past. In this scenario, the actions of the rulers today expose that it is not easy to take forward science and general education.

There is a need to strongly fight against the odds in the society. Shri Sachithanandam MP who spoke before me told me that history in the history textbooks is revised. Hon Home Minister Shri Amit Shah says that the Indian History will be rewritten. Where will it end? History should be seen in the historical perspective. History should be exactly the real recording of the events as it happened. You cannot record this as per your whims and fancies. I repeat if you do so it is an offence. If the rulers today commit this blunder, the cycle of history will definitely punish them severely. They cannot escape. Who removed from the textbooks the lesson about genocide that took place in the year 2002 in Gujarat? Mughal era is being removed from History. If you remove them from the textbooks, will the History be changed? I want to say about Rig Veda. This was given by Saints of this land. Who printed the Rig Veda as a book and preserved otherwise it would have been eaten up by termites. He is none other than Max Mueller a Christian by birth. He took this Veda to the world. Dara Shikoh is a Mughal Prince who compiled the 50 Upanishads in Persian language and took it to world. But those in the present Government are into defaming the Mughal era and its emperors. They want to remove the reference of Mughals from our History textbooks which is unfair. I want to say one more important thing.

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude.

**SHRI SUBBARAYAN K.:** Within 2 minutes I will conclude. In the Kendriya Vidyalayas, the concerned regional languages should be taught. Medium of instruction should also be in the regional languages. In Tamil Nadu Tamil should be the medium of instruction. These issues are to be considered by the Government. NEET is being conducted. This PG-NEET is not conducted in Tamil Nadu but in other States. This is a wrong precedence. This is aimed to torture the candidates appearing for this NEET. It should be given up. I once again say that the New Education Policy is against the nation. It is like poisoning the mind-set of the people and hence it should be withdrawn. Thank you. Vanakkam.

**डॉ. संबित पात्रा (पुरी) :** माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने की अनुमति दी ।

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासम: सुहृत् । नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम् ॥

?विद्या जैसा कोई बंधु नहीं, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं, विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं, विद्या जैसा कोई सुख नहीं ।? जिसके पास विद्या है, जिसके पास सुख है, वही बलवान है, वही धनवान है । वह अपराजित होता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती, जिसके पास मां सरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है ।

सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में मौजूद सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा । आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है, मैं इसे बहस नहीं कहूंगा, क्योंकि यह बहस नहीं है, यह चर्चा है । जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर चर्चा होती हो, जिस राष्ट्र में शिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हों, वह राष्ट्र अपराजय है, वह राष्ट्र एक दिन विश्व गुरू अवश्य बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं हैं ।

सभापति महोदय, इस बजट में तीन शब्दों के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुदान दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं, चर्चा की गई है । वे शब्द हैं ? शिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार ।

सभापति महोदय, मैं इस सभागृह में बैठकर सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था । कुछ लोगों ने थोड़ी देर पहले हमें मनुवादी भी कहा और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विधाएं थीं, जिनमें कुछ जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था ।

महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था । उसके विषय में बहुत चर्चा हुई है । At the outset, I want to define this word ?Bharat?. भारत का अर्थ क्या है? ?भा? से रत हो जो भूमि, वह भारत है । ?भा? क्या होता है? ?भा? प्रकाश का मूल शब्द होता है । ?भास्कर?, जो प्रकाश देता है, वह भास्कर है । भारती माने सरस्वती, जो ज्ञान देती है, जो शिक्षा देती है, जो विद्या देती है, वह सरस्वती, वह भारती है । जो भूमिखंड अनादिकाल से अनादिकाल तक ज्ञान विद्या और शिक्षा से ?रत? हो, वही भारत है ।

मैं आप सभी को आकर्षित करना चाहूँगा, इस गृह में बहुत फोटो दिखाए गए हैं, भगवान की भी तस्वीर दिखायी गई हैं । मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसी तस्वीर दिखाऊँगा, जो तस्वीर आप सबके मन में बसती है । कल्पकांत होती है, एक कल्प के अंत के पश्चात् भगवान विष्णु, भगवान नारायण क्षीरसागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं । शेषनाग के ऊपर विराजमान होते हैं । पद पर उनके लक्ष्मी होती हैं । आँख अधमुंदी सी होती हैं, नारायण का एक हाथ उनके शीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है । भावी कल्प कैसा होगा, उसके विषय में नारायण चिंता करते हैं । इनोवेटिव आइडियाज कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं । जैसे ही he conceptualises how the *bhavi kalp* would be from his *nabhi padma*, जिस पदम के विषय में भी यहाँ बताया गया, उस पदम पर बैठकर भावी कल्प के, जिनके पास स्किल होता है, वे ब्रह्मा उपजते हैं । Brahma is skilled to produce the next Brahmand, next universe. Do you know who provides the resource? जब उनके पास इनोवेशन होता है, वे महालक्ष्मी की तरफ देखकर बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, मेरा डिमांड फॉर ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से यह ब्रह्माण्ड बनेगा । There is no gender in Vaikuntha. वैकुंठ में कोई नर नहीं, कोई नारायण नहीं, वही नारायण, नारायणी है, वही शिव, शिवि है । वही पार्वती है, वही शिव है, इसलिए यह धारणा गलत है कि नारी नर के पैरों के पास बैठी है । तात्पर्य है कि जहाँ आइडिया है, जहाँ इनोवेशन है, जहाँ विद्या है, जहाँ शिक्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं है, रिसोर्स अपनी बांहें अपने आप ही खुल जाती हैं । महालक्ष्मी ?तथास्तु? कह ही देती हैं ।

बंधुगण, जहाँ तक भारत के विषय में कहा गया, अभी मेरे भाई नालन्दा के विषय में बोल रहे थे । जब नालन्दा को बख्तियार खिलजी ने आग लगायी थी, तीन महीनों तक नालन्दा जली थी । वह ज्ञान का खजाना अभी भी अमिट है । मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूँगा, जो आग तब जली थी, वह आग आज बुझी है । भारत की आबादी के 40 प्रतिशत बच्चे और युवा हैं । यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है । This is the demographic dividend of India but it is a big challenge as well. यह एक बहुत बड़ा चैलेंज

भी है । शिक्षा, कौशल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं, इस बजट में रखे गए हैं,

I commend this Government. I applaud this Government. I applaud Narendra Modi ji, Dharmendra Pradhan ji, and Nirmala Sitharaman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this Budget.

What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, entrepreneurship, and innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasit Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe.

That is the reason why such importance has been given to skilling, employment generation as well as to the way forward. Flagship programmes like Samagra Shiksha, PM SHRI, PM-POSHAN have received increased allocation in this Budget. Let me commend the Government that in this Budget, for the Financial Year 2024-25, the amount of Rs. 73,498 crore is the highest ever allocation for the Department of School Education and Literacy.

Sir, let me present to you a comparative data and a comparative chart which would show what was the situation before Modi Ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. You would be astonished to learn that the total budget for school and higher education under the Ministry of Education for 2013-14 was Rs. 79,451 crore only, compared to Rs. 1.21 lakh crore this fiscal year. So, the growth in the Budget in the last 10 years has been a whopping 52.4 per cent. Similarly, in the case of school education, the growth in the Budget has been 39.5 per cent. In higher education, the allotment has increased by, I repeat 78 per cent. I emphasize it, there is an increment of 78 per cent in the allotment in higher education.

Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friends from this side and my good friends on that side have exchanged arguments about reservation. सभापति जी, मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि जो लोग आरक्षण के ऊपर इस प्रकार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, वे आज जवाब दें । कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां मौजूद हैं । आप बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि जो सैंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स जामिया मीलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है कि इन सैंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन्स में हमारे एससी और एसटी बंधुओं के लिए आरक्षण का प्रावधान रहे । मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2011 में जामिया मीलिया इस्लामिया से एससी और एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया । ठीक इसी प्रकार 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एससी, एसटी स्टूडेंट्स का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण समाप्त कर दिया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा । आज मैं सुन रहा था कि कोई यहां पेपर लीक के विषय में बोल रहा था ।

आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो । गिरेबान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो । नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ दिन पहले आया है और मैं अपनी सरकार को कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा क्योंकि जैसा धर्मेन्द्र प्रधान जी ने सदन में कहा, जब आप सदन में चिल्ला रहे थे, उन्होंने कहा था कि इंतजार करिए, we will come out clean on NEET examination. The highest court of this country has bided us. The highest court of this country has given its verdict. But let me read out, आपके पाप के चिट्ठे, दिल्ली सरकार के ?आप? नहीं, आपके पाप के चिट्ठे मतलब आपके पाप, वर्ष 2006 में कहां-कहां पेपर लीक हुए थे, मैं बताता हूं । वर्ष 2006 में सीबीएससी क्लास 12 एकाउंट्सी पेपर लीक, 2007 अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश पत्र परीक्षा पत्र लीक, एआईईईई, 2008 में पीएमटी प्री-मेडिकल पेपर लीक, 2012 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस परीक्षा पेपर लीक, 2014 में सीबीएससी कक्षा 10 और 12 का पेपर लीक । वर्ष 2013 में महाराष्ट्र का एसएससी एग्जाम पेपर लीक । वर्ष 2016 में कर्नाटक में पीयूसी परीक्षा पेपर लीक । उस समय कर्नाटक में श्री सिद्दारमैया की सरकार थी । वर्ष 2013 में राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, उस समय अशोक गहलोत जी की सरकार थी । वर्ष 2011 में हरियाणा बोर्ड परीक्षा पेपर लीक । उस समय हरियाणा में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी । वर्ष 2013 में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी परीक्षा पेपर लीक, वहां उस समय आपकी सरकार थी । आप जरा सोच कर देखिए, आपके गिरेबान के अंदर पेपर लीक भरा हुआ है । महोदय, मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पड़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए पांच फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है, जिसका नाम है - Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024 । जिसमें दस साल की जेल का प्रावधान है और एक करोड़ रुपये तक का फाइन रखा गया है ।

सभापति महोदय, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि 34 वर्ष बीत गए, यहां युवा सांसद बैठे हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ । कितने युवा सांसद हैं, इनसे पूछिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे? मैं गर्व के साथ कहूंगा कि वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में सीना ठोक कर कहा था कि हम सरकार में आएंगे, नई शिक्षा नीति लाएंगे और हमने वह कर के दिखाया है । यह मोदी की गारंटी है । नई शिक्षा नीति में आमूल-चूल परिवर्तन है । मातृभाषा के लिए सम्मान है । पूरी शिक्षा के प्रति एक कॉप्रिहेंसिव होलिस्टिक एप्रोच है । आप सोच कर देखिए, जो आज उस तरफ बैठ कर चिल्ला रहे हैं, 34 वर्षों तक ये मौन थे । 34 वर्षों तक इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई । शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, इस विषय में इनकी धारणा नहीं बन पाई । एक नरेंद्र मोदी को आना पड़ा एनईपी को लाने के लिए ।

सभापति जी, मैं जानता हूँ कि सयम की एक सीमा होती है, इसलिए मैं अपने अंतिम पक्ष में कुछ कम्पैरेटिव डेटा रखूंगा । ? (व्यवधान) One is regarding the status of educational indicators. बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों क्या कर दिया? मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया होता है कि स्टैटिस्टिक्स रखा जाए । आप अगर यहां आंकड़े रख देंगे, उनको कोई झुठला नहीं सकता है । आज मेरे हाथ में वे आंकड़े हैं, जिनको कोई झुठला नहीं सकता है । ये आंकड़े क्या कहते हैं ? gross enrolment ratio at primary level, 3.31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी नरेंद्र मोदी जी के आने पश्चात हुई है । ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यों में अपर प्राइमरी लैवल में 4 पर्सेंट की बढ़ोत्तरी नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात हुई है । प्यूपल-टीचर रेश्यो, आज मेरे कोई साथी कह रहे थे कि टीचर्स की संख्या कम हो गई है । बंधुगण, सुन लीजिए कि प्यूपल-टीचर रेश्यो, जो पीटीआर होता है, उसमें नौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी नरेंद्र मोदी जी के आने बाद हुई है । ठीक उसी प्रकार, मुझे तो तकलीफ होती है यह सोच कर कि स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी । आंकड़े कहते हैं कि 36 पर्सेंट इनक्रीज़ नरेंद्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के

बाद हुआ है, we have 36 per cent increment in electrification of schools. बच्चे अंधकार में पढ़ रहे थे । अंधकार से उजाले की तरफ लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है । यह छोटा विषय नहीं है । अगला, हैंड वॉश फैसिलिटी, मिड-डे मील का प्रोग्राम होता है, हाथ धोना अनिवार्य होता है । हाथ न धोएं तो बीमारी होगी । जो आंकड़ा मैं अब रखने वाला हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद 51 प्रतिशत इज़ाफा हुआ है, उन स्कूलों में जहां हैण्ड वॉश फैसिलिटी मिली है । मैं बहुत संवेदना के साथ कहना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इसमें कोई चिल्ला-चोट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं दिव्यांग बच्चों की बात करने वाला हूँ । Children with special needs, जब स्कूल जाते थे तो इनके लिए रैंप्स नहीं थे । मोदी जी ने इसके लिए स्पेशल बैठक की । इसके लिए एक अलग रूप से बैठक हुई है और उसका नतीजा रहा कि आज 14 प्रतिशत से अधिक इज़ाफा उन स्कूलों में हुआ है, जहां स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए रैंप्स की सुविधा है कि वे बच्चे आराम से जा कर शिक्षा ग्रहण कर सकें ।

महोदय, केवल इतना ही नहीं है । यहां बहुत सारी बातें आरक्षण के विषय को ले कर हुई हैं । उसके विषय में मैंने बताया, मेरे भाई जो वहां बैठे हैं, जो इस विषय को ले कर चिंतित भी रहते हैं, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए । मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो फॉर एससी, अनुसूचित जाति का जो एनरोलेंट रेश्यो होता है, वह वर्ष 2013-14 में 17.1 पर्सेंटेज था । यह वर्ष 2021-22 में बढ़ कर 23.1 प्रतिशत हुआ है, जो कि 35 प्रतिशत से अधिक का इज़ाफा है ।

This is my partisanship. We are standing for the betterment of the country. This is what we are standing for. Just imagine, the gross enrolment ratio for STs has increased by 67.2 per cent. एसटी बच्चों की एनरॉलमेंट संख्या बढ़कर आज 67.2 परसेंट हुई है । ऐसा क्यों न हो, क्या किसी आदिवासी ने इस देश में कभी सोचा था कि हम में से एक बहन राष्ट्रपति बन जाएगी?

सर, यह हमारे लिए भाषण का एक प्वाइंट हो सकता है । मगर, जरा सोच कर देखिए, किसी गाँव के पेड़ के नीचे बैठी एक आदिवासी महिला सोच रही होगी कि मेरी बहन हिन्दुस्तान की प्रथम नागरिक है । यह हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे, जो यहां बैठे हुए हैं । एक गरीब और आदिवासी से पूछिए कि उसको क्या मिला है? उनकी 67.2 परसेंट की वृद्धि हुई है ।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि जो हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स हैं, 6 आईआईटीज, 7 नए आईआईएम, 16 ट्रिपल आईआईटीज, 2 नए आईआईएसईआर,? (व्यवधान) क्या यह आपको नहीं चाहिए? अगर 6 नए आईआईटीज बन गए हैं, तो क्यों नाराजगी है? 6 नए आईआईटीज बने हैं । वे क्यों नाराज है, इसे मैं जानता हूं ।? (व्यवधान)

सभापति महोदय, घंटी बजने से पहले, मैं अपने क्षेत्र महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरण में जाकर एक एक विषय रखना चाहूंगा । मेरा भी एक डिमांड फॉर ग्रांट है । इसे भी मैं रख देता हूं ।

माननीय सभापति **:** आप एक मिनट में अपनी डिमांड रख दें ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** संबित पात्रा **:** मेरे बहन और भाई, यह विषय महाप्रभु जगन्नाथ जी के क्षेत्र का है ।? (व्यवधान) इसे आप सुन लीजिए ।

**HON. CHAIRPERSON:** Sambit Patra ji, please address the Chair.

डॉ. संबित पात्रा **:** सभापति महोदय, यह महाप्रभु जगन्नाथ जी की भूमि पुण्य भूमि है, पुरुषोतम क्षेत्र है । अभी थोड़ी देर पहले हमारे सदस्य प्रताप सारंगी जी ने बिल्कुल सही कहा है । वहां जिनको हम ओडिशा के गांधी कहते हैं, वह पंडित गोपबंधु दास जी हैं । इनको महापंडित गोपबंधु दास कहा जाता है । पुरी में बकुड़वन सत्यावादी नाम से एक क्षेत्र है । यह वर्ष 1909 में स्थापित हुआ था, जैसे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार बकुड़वन स्थापित किया गया था । वहां वन में शिक्षा दी जाती थी । यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्या है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भारत आजाद हुआ, तब वहां एक हाई स्कूल खुला था । बाद में राज्य सरकार ने वहां उड़िया भाषा के लिए एक यूनिवर्सिटी खोला । मैं आपके माध्यम से इस सदन और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वहां एक उच्च कोटि का, जिस प्रकार शांति निकेतन बनाया गया है, एक सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी बने । जहां उत्कड़ प्रदेश ओडिशा की बहुत सारी जो विद्याएं हैं, संस्कृति है, कला है, जगन्नाथ जी की परंपरा है, उसकी शिक्षा दी जाए, ताकि हम सब उससे उपकृत हो । इतना ही कह कर मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जय जगन्नाथ ।

माननीय सभापति**:** इससे पहले मैं अगले सदस्य का नाम लूं, मेरा सभी माननीय सदस्य से निवेदन है कि सदस्य अपनी बात बोलने के बाद तुरंत न जाए । कृपया आप दूसरे सदस्य की भी बात सुनें । अपनी बारी के बाद तुरंत बाहर न जाए । कृपया, दूसरों की जो ओपिनियन है, उसे भी आप सुनिए ।

**DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (PONNANI):** Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity to take part in this very important discussion on education.

Hon. Chairperson, Sir, we agree that our system of education has to respond positively to the changes, the changes in the surroundings and in the society of our country. And the changes are taking place at a lightning speed. The system of education that fails to respond to these changes will be futile. And, Sir, we should respond to these changes with long-term objectives and long-lasting shift, depending and emphasising on the everlasting humanitarian values.

At the very same time, it is very imperative that our system of education should centralise and focus on Indian identity, Indian reality. Our strength of Indian identity lies in its plurality. But it is very unfortunate and highly condemnable that the present Government?s educational policy fails to see the whole as a complex. It fails to see the Indian plurality with vividity and diversity. It fails to see that. It is very unfortunate and condemnable that the Government is following a prejudiced sectarian agenda of polarisation with regard to education.

Sir, coming to the pedagogy, we all agree that the pedagogy has to be revised and renewed. It has to be updated. There is no doubt about that. But this revision of the

pedagogy should not be and must not be for destroying and spoiling the pluralistic spirit of Indian culture.

Sir, it is foolish and a reflection of negative mind to emphasise one and to ignore the other. One important casualty of this present Government?s policy of education is history. सर, इतिहास को भविष्य के लिए, पॉस्टेरिटी के लिए, पॉजीटिव एम्स एंड ऑब्जेटिक्व्स के लिए इस्तेमाल करना है । It should not be used for destructive purposes. Every country will have its own history. History is a bundle of rights and wrongs. Whatever the people of the past have done, they have done. It is finished. It is foolish to use that history to destroy and spoil the peaceful coexistence of the present society. The Government?s policy of scrapping certain important parts of textbooks of history is condemnable. It should not be like that.

?याद?ए?माज़ी अज़ाब है या?रब, छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा ।?

History should not be like that, Sir. इतिहास एक अज़ाब नहीं बनना चाहिए । इतिहास को जहमत नहीं बनाना चाहिए । In the history, we will find everything. ?लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई ।? There is no meaning in dividing history. I would request the Government and particularly the hon. Minister to see India as a whole. And for that, one has to wear the Indian spectacles, not the lens of this community or that community, this sector or that sector. We should be ready to wear the Indian spectacles and Indian lens.

Sir, coming to the backward sections and the minorities, the budgetary allocations for the Ministry of Minority Affairs is reduced. I would like to know from the hon. Minister the reason for this reduction of budgetary allocations. The condition is that only 29 per cent of the youth of the minority community has access to education, according to the scientific data provided by the official surveys. The Government is following a policy of nullification of the scholarship schemes of the minority community. For example, the Maulana Azad National Fellowship Scheme. That means, the Government?s policies are very negative. It creates much hardships for the students. I would request the hon. Minister to consider the backward areas with regard to setting up of Central Schools, Kendriya Vidyalalyas. For example, the hon. Minister is present in the House. Our district Mallapuram has one Central School. My constituency Ponnani does not have even a single Central School. Kerala has 38 Central Schools, Kendriya Vidyalayas. I would like to request the hon. Minister to sanction a Central School in my Constituency Ponnani which is a part of the district of Mallapuram, which has only one Central School.

Coming to the coaching centres, on the one side, the confidentiality of the examinations is being compromised and, on the other side, there are so many coaching centres. The position is that an Indian student cannot survive without joining a coaching centre.

This condition should be changed. The Government should bring a change in that. Childhood is no longer a period of playing. Childhood is a period of playing. Instead of that, it is spent in the dungeon basement just to clear only one per cent selection rate in the examination. If you get rejected in these examinations ? we all know that 99 per cent of the students are rejected in these examinations ? then, you are left out.

Again, there is another problem. The NTA examination centres are often located at distant places. It creates much hardships for our students especially in the State of Kerala. I would like to request the hon. Minister to consider this aspect also. The Government has to consider the backward classes, the Minorities etc., in respect of allocation of funds for various schemes. The Government should not scrap certain parts of our history.

**HON. CHAIRPERSON:** Kindly conclude now.

**DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI:** Sir, please give me only one minute. What I would like to point out here is that the system of education should be shifted from text to context. I am reminded of a poem written by Shri Akbar Allahabadi.

?बढ़ाओ तजुर्बे अतराफे दुनिया में

सफर सीख ख्वास खुश्क तर सीख

गुलों में बर व बहर सीख?

This sense is very important; this intelligence is very important. I would like to request the hon. Minister to consider this kind of ailments in the system of education and come forward to correct the same. Thank you, Sir.

**ADV. PRIYA SAROJ (MACHHLISHAHR):** Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा ।

अर्जुन के तीर सा साध मरुस्थल से भी जल निकलेगा ।

इस कविता ने मुझे हमेशा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है । एक युवा को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हम सचमुच प्रयास करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं । एक युवा के तौर पर युवाओं का मुद्दा मेरे लिए हमेशा सर्वोपरि है । आज मैं एजुकेशन सिस्टम, नीट जैसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पेपर लीक की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए खड़ी हूं । यह मुद्दा हमारे युवा और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यता है ।

भारत भाग्यशाली है कि देश की कुल जनंसख्या में 60 परसेंट से अधिक युवा हैं और इनमें से अधिकतर छात्र हैं । युवा देश के विकास कार्यों में बहुत कुछ कर सकते हैं । हालांकि एजुकेशन सेक्टर को हमेशा इनसफिशिएंट बजट का सामना करना पड़ता है । सरकारी वादे भले ही बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन वादों को पूरा करते हुए नहीं देख रही हूं । इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों और कॉलेज की अव्यवस्थाओं पर पड़ता है । खासकर ग्रामीण क्षेत्रो में, सरकारी स्कूल में शिक्षक की भारी कमी है, भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपरेंसी की कमी के कारण लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है । इससे छात्रों के क्वालिटी एजुकेशन पर असर पड़ रहा है । किसी भी परीक्षा के पेपर लीक से छात्रों की मेहनत बेकार हो जाती है । मेरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की पुलिस कान्सटेबल परीक्षा, 2024, यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ पेपर लीक जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम में गंभीर खामियां हैं । In this digital age when the world is moving towards technological advancement, our schools lack basic technological facilities. The situation is particularly worst in the rural areas. It is imperative to connect the students with modern technology so that they can compete globally.

Sir, repeated incidents of paper leak weaken the trust of students and parents on the Government and on the education system. Such incidents indicate the serious flaws in our examination system, which need immediate rectification.

The National Testing Agency has faced significant criticisms for the delay in conducting the exams, which has serious implications on the students. Due to these delays, students are experiencing delays in their admissions to colleges which has resulted in shortened semesters. It is impacting their academic progress which is leading to a situation where a two-year post-graduate degree is effectively taking one-and-a-half years to complete. This burden disproportionately affects the students who come from the low socio-economic background. They face additional challenges due to extended timeline and financial pressure associated with delay in admissions. The NTA?s inability to conduct exam in a timely manner is not an administrative failure but it has bigger consequences for the educational trajectory on the millions of students across the country.

सर, उचित ट्रेनिंग, रूटीन इंस्पेक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता है । पेपर लीक में शामिल लोगों को सख्त सजा देने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों । छात्रों को विदेशों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं । हमें अपने शिक्षा संस्थानों को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा ताकि युवा बाहर के देशों में न जाएं और यहीं पर बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाएं ।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम्स के कंडक्ट में सुधार के ठोस से ठोस कदम उठाए जाएं जिससे विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो और देश की प्रगति सुनिश्चित हो ।

भाजपा सरकार कहती है ? सबका साथ, सबका विकास । इन्होंने तो केवल अपना विकास किया है । देश की जनता जाग चुकी है । पीडीए के मान-सम्मान में डकैती से रक्षा केवल इंडिया गठबंधन कर सकता है । यदि सरकार चाहती है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा पूरा हो तो जातीय जनगणना कराकर सबको हिस्सेदारी दे । धन्यवाद ।

**श्री कामाख्या प्रसाद तासा (काजीरंगा) :** माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं अपनी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूं कि मुझे अनुदानों की मांगों की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया ।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके दिशा-निर्देश में काबिल और एक्सपीरियंस्ड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेन्द्र प्रधान जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया और माननीय निर्मला जी ने बजट पेश किया ।

महोदय, 1.48 लाख करोड़ रुपये का एलोकेशन एजुकेशन, एम्पलायमेंट और स्किलिंग इंडिया के लिए किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं । एजुकेशन, एम्पलायमेंट और स्किलिंग पर फोकस करके और लक्ष्य रखकर जो बजट पेश किया है, मैं चाहता हूं कि यह विज़न सक्सेफुल हो । After 34 long years, our Government has announced a New Education Policy for the country. At the time of its announcement, the hon. Prime Minister described it as a new policy and as an educational dream of the nation in the 21st century. इसके लिए मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देता हूं । माननीय प्रधान मंत्री जी का यह सपना फुलफिल होगा । इसे फुलफिल करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरी ताकत लगा रहा है और पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है । एजुकेशन समाज और एजुकेशन सिस्टम से जो लोग जुड़े हैं, एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । प्रिंसिपल्स, वीसीज़, टीचर्स, प्राइवेट हो या सरकारी, सबने एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया है । असम राज्य में भी एजुकेशन पॉलिसी को इम्पलीमेंट करने के लिए जिस व्यवस्था का चिंतन किया गया है, मेरा मानना है कि वर्ष 2040 तक पूरी हो जाएगी ।

सर, पूर्व सदस्य ने आंकड़ा बताया है । अपोजिशन लीडर का क्रिटिसाइज करना स्वाभाविक है, वह तो क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन यह बात भी माननी पड़ेगी कि 34 साल बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई है और जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें पुरातन शिक्षा व्यवस्था को लौटाने की बात सोची गई है । वैस्टर्न एजुकेशन पॉलिसी को नकारकर इंडियन पॉलिसी को अपनाने की व्यवस्था की गई है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं ।

सर, एजुकेशन पॉलिसी में रिफार्म्स की बात कही जा रही है । चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कॉम्प्रिहेन्सिव फ्रेम वर्क, लोकल लैंग्वेज, स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्सेफुल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, जो वर्ष 2040 ही नहीं, 100 साल तक टिकेगी ।

**17.00 hrs**

उसके बाद टाइम टू टाइम इसका जो रिफॉर्म होना चाहिए, वह भी हो जाएगा । इंटरनेशनलाइज्ड और टीचर्स एजुकेशन और इंडीजिनस स्मॉल बिजनेस में जो फोकस रखा है, वह अच्छा है । उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी

ने एक बात बोली । इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ है, वह देश वापस आ रहा है । इसका मतलब देश का एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है कि यहां पढ़े हुए जो लोग बाहर गए, वे वापस आ रहे हैं । अत: एजुकेशन सिस्टम को भी मैं धन्यवाद देता हूं । हम लोगों की एक अर्जी है । हम लोगों की गवर्नमेंट ने रूसा को छोड़कर उच्च शिक्षा अनुष्ठान किया है और पीएम की जो स्कीम्स हैं- प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, (पीएम-यूएसपी) कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए सीएसएस, सेंट्रल सेक्टर इंट्रेस्ट सब्सिडी स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के लिए तथा हम लोगों की नोटिस के लिए ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम और पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम प्रगति, सक्षम, इन सबको लेकर जो सोच रहे हैं, फ्यूचर जेनरेशन यानी व्यक्ति निर्माण के लिए जो हम सोचते हैं, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात हम लोगों की पार्टी ने भी रखी है और व्यक्ति निर्माण के बाद राष्ट्र निर्माण भी हो जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है । इस रास्ते पर हम चल रहे हैं । हायर एजुकेशन तो ठीक है । जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स एजुकेशन की बात सोची है, टीचर्स की ट्रेनिंग और पावरफुल हो, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करेगी । मैं सोचता हूं कि टीचर्स की ट्रेनिंग को और मजबूत बनाने के लिए और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स ज्यादा ओपन करने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी सोचें ।

महोदय, प्रधान मंत्री जी सोच रहे हैं कि एक उन्नत विकसित भारत हो । यह अमृतकाल का बजट है और अमृतकाल के बजट में जो शुरुआत है, इसमें निर्मला मैडम ने एजुकेशन के ऊपर जो ट्रस्ट किया है, इस पर चाहे कोई हंसे या क्रिटिसाइज करे, उसे छोड़कर पॉजिटिविटी यह है कि एक शक्तिशाली, सक्षम भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने की जो व्यवस्था है, वह निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है । रीजनल लैंग्वेजेज की बात भी आई । इनको बढ़ाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी व्यवस्था की गई है । रीजनल लैंग्वेजेज को और आगे बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए । असम में यह व्यवस्था चलनी चाहिए । हर स्टेट ने अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की है ।

सर, मेरी एक रिक्वेस्ट यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कैंपस हैं, उनमें किसी-किसी जगह जो कैंपस लगे हैं, उनको स्ट्रेंथेन करने के लिए व्यवस्था की जाए । शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उसको भी फुलफिल किया जाए और उसको एक फुलफ्लेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बदला जाए । प्राइमरी एजुकेशन की बात करूं, तो बताऊं कि कांग्रेस यहां मौजूद है । इतने दिनों तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन असम में कम से कम 6 जिलों में 424 जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका सरकारीकरण नहीं करके चाय बागान के मालिकों के हाथों में दे दिया था । हमारी सरकार ने अभी इसको प्रोविंशलाइज किया है । इसके बाद केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील इसे शुरू करें, यह मैं आग्रह करता हूं ।

महोदय, मेरा आग्रह है कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का अभी आंकड़ा दिया गया है । सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाए जाएं और ब्रेन ट्रेनिंग की बात जो सब लोग कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से अपनी व्यक्तिगत इच्छा है । बाहर जाने की इच्छा कोई रुकवा नहीं सकता, लेकिन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन्स को सेंटर फॉर एक्सिलेंस बनाने हेतु जितनी व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था हमारी केंद्र सरकार की तरफ से की जाए । प्रधान मंत्री जी का जो ड्रीम है, उसे फुलफिल करने के लिए मैं अनुरोध करता हूं ।

सरकार के अनुदानों की मांग का मैं सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि एक विकसित भारत, एक सक्षम भारत बनाने के लिए एजुकेशन पॉलिसी को फुलफिल किया जाए । धन्यवाद ।

**KUMARI PRIYANKA SATISH JARKIHOLI (CHIKKODI):** Respected Speaker Sir, first of all, I would like to thank the people of my constituency, Chikkodi for electing me as their representative.

Firstly, I would like to mention Dr. Babasaheb Ambedkar ji who fought a case in Chikkodi court. So, it is an immense pride for me to come from that place. He says,

"The progress of any society depends on the progress of education in that society".

Sir, our country is facing a lot of issues with regard to education sector. These challenges are related to quality, accessibility, and equity in education. Since 2014 the annual Budget for the Ministry of Education has been steadily declining. This Budget has decreased funds for School Education to the tune of 16.8 per cent from the Revised Estimates and 7 per cent overall for the Ministry of Education. The UGC's budget has also been decreased by a staggering 53.35 per cent compared to the BE 2023-24 and 60.99 per cent compared to the RE for the previous fiscal year. This comes at a time when the National Testing Agency, an autonomous body under UGC has failed to properly conduct national examinations like the NEET and NET, putting the future of lakhs of students at risk. In the past 7 years, the country has witnessed 70 cases of exam leaks, across 15 States, affecting approximately 1.7 crore aspirants.

Sir, regarding my constituency, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that there has been a proposal for setting up of Kendriya Vidyalayas in Athani and Gokak. But this proposal has not been approved yet. I would humbly request the hon. Minster to approve it as soon as possible.

Due to the recent flood in my constituency, most of the school buildings have got deteriorated. Through you, Sir, I would request the hon. Minister to revise the format under which they provide Rs.2 lakh per school for renovation. This amount also has not been sanctioned so far.

Sir, privatization in education sector at a large scale has been seen in recent times. There are many students from SC/ST/OBC categories in my parliamentary constituency. They belong to poor families. I want to know what steps the Government has been taking to ensure that the people from rural background will be able to access reasonable education in today?s time.

Thank you, Sir, for allowing me to participate in the Demands for Grants of the Ministry of Education.

Thank you, Sir.

**SHRI MALVINDER SINGH KANG (ANANDPUR SAHIB):** I thank you, Sir for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Education for the year 2024-25.

Sir, when we talk about education, we think about our institutes, especially those which have historical or heritage value. Punjab University is a reputed educational institute. Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, hon. late Madam Sushma Swaraj ji and ex-PM late Dr. Inder Kumar Gujral ji have all been alumni of Punjab University. Hon. Minister Sir, recently we got the news that Manu Bhaker and Sarabjot Singh won medals for us in the on-going Olympic Games. Let me tell this august House that both these sportspersons have been alumni of Punjab University.

Sir, the problem today is that première institutes like Punjab University are facing financial crisis. I request the Central Government that to save these institutions, special financial grants should be given.

Under the able leadership of our Chief Minister Shri Bhagwant Mann, we are continuously working towards improving the standard of education in Punjab. I request the Central Government to release the pending amount of funds due to Punjab under two schemes of the hon. Prime Minister. One is P.M. Nutrition scheme. The second one is the P.M. Shri Scheme, i.e. P.M. Scheme for Rising India. This amount due to the State of Punjab should be released at the earliest.

Hon. Chairperson, we have over 58,000 educational institutes. We are number two in this matter. Many of these institutes are higher education institutes. The matter of concernn is that when you talk about world ranking, we stand at number 33. When we talk about higher education enrolment, 80 per cent students go to under-graduate institutions but only 12 per cent students enroll in post-graduate institutions. And in Ph.D., courses, only 0.5 to 0.6 per cent of the students get enrolled. This is a matter of grave concern. The Central Government must take this matter seriously.

Thirdly, Sir, I want to say something regarding history taught in our text-books. We teach the history of Babar. However, our first Guru Shri Guru Nanak Dev ji had called Babar a tyrant. Our Sikh Gurus had opposed the tyranny of Mughal rulers. Why this history of our Sikh Gurus is not made compulsory and taught to students of this country? The history of supreme sacrifice of Sahibzadas (sons of our tenth

Guru) is also not being taught in the history text-book. Why is this so? Baba Banda Singh Bahadur had initiated land-reforms first of all. Why his history is not being made compulsory for the students to study?

Sir, Kartar Singh Sarabha was the person who inspired martyr Bhagat Singh. When Kartar Singh Sarabha was only 18 years old, he came from U.S.A. and attained martyrdom for achieving freedom of India. Such names of our real heroes should not only be introduced in the syllabus but should be taught compulsorily.

I urge upon the hon. Minister, who is sitting here, to teach about these real heroes in our history books.

Sir, there is paucity of time. Lastly, I want to say that recently in Rajinder Nagar area of Delhi, a very unfortunate incident happened. Three of our UPSC aspirants died a painful death by drowning in the basement of a coaching institute. These are brilliant students. They spend lakhs of rupees to get coaching from the reputed educational institutes. Sir, the Punjab and Delhi Governments including Arvind Kejriwal ji, are bearing the cost of these brilliant students who get coaching for UPSC exam. The Central Government should also do the needful in this matter for UPSC and other exam aspirants. Thank you.

**श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर (बनासकांठा) :** केन्द्रीय बजट वर्ष 2024-2025 के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर, मैं अपने विचार एवं कुछ मांगों को व्यक्त करना चाहती हूँ । भारत में केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं । केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का संचालन करती हैं । शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय नीतियां बनाता और उन्हें लागू करता है, शिक्षा तक पहुंच में सुधार के शिए योजनाएं बनाता है और स्कालरशिप देता है ।

शिक्षा मंत्रालय के दो विभाग हैं: (1) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और (ii) उच्च शिक्षा विभाग । स्कूली शिक्षा विभाग । केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों के लिए जिम्मेदार है । यह राज्यों द्वारा लागू की जाने वाली कुछ योजनाओं को भी वित्त पोषित करता है, जैसे स्कूलों तक पहुंच और समग्र शिक्षण परिणामों में सुधार का प्रयास करने वाला समग्र शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय मध्याहन भोजन कार्यक्रम ।

उच्च शिक्षा विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर, आईआईएम और स्कूल ऑफ प्लानिंग एवं आर्किटेक्चर इत्यादि को वित पोषित करता है । यह उच्च शिक्षा के रेगुलेटर, यूजीसी और एआईसीटीई को भी वित्तपोषित करता है । यह विभाग उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को भी सहयोग देता है और उच्च शिक्षा के लिए स्कालर्स देता है । यह विभाग हमारे देश की अहम भूमिका के रूप होने के बावजूद इस विभाग मे आने वाले कुछ एजेंसियों की वजह से लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है जो कि इस सरकार की नाकामियों को दर्शाता है । अभी हाल में हुई नीट की परीक्षा में घटित घटनाओं से भी सरकार को बहुत सारी सीख लेने की जरूरत है ।

हमारे देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है ।

श्री आनंद भदौरिया **(**धौरहरा**) :** मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र कस्ता के मैगलगंज में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने की कृपा करें ।

दूसरा**,** लखनऊ स्थित शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने की कृपा करें तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सांसद कोटा पुन: बहाल करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

**SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI):** I would like to express my views on addressal of the critical state of education in our nation, a cornerstone of our development and future prosperity. Education is a fundamental right and a vital tool for empowerment, and yet, we face numerous challenges across both school and higher education sectors. This speech aims to shed light on these challenges and discuss the path forward; and also to address the pressing issues and challenges facing the education sector in India. As we reflect on the journey of our educational reforms, it is crucial to recognize both our achievements and the areas that demand urgent attention.

And also, I urge the Government to withdraw NEET in Tamil Nadu. NEET creates inequities by disadvantaging students from less privileged backgrounds and those in rural areas, despite their capabilities. It undermines our State?s educational autonomy and places undue stress on students and families. Our State has a tradition of excellence in medical education, and we should preserve it by using local, equitable admission methods. Let us prioritize fairness, support, and our students? well-being by discontinuing NEET and exploring alternative, more inclusive measures. Overview of Finances

For 2024-25, the Ministry of Education has been allocated Rs 1,20,628 crore, a decrease of 7 per cent from the revised estimate of 2023-24. The allocation breakdown is as follows:

Department of School Education and Literacy: Rs 73,008 crore (61 per cent of the Ministry's expenditure), a marginal increase of 0.7 per cent from the revised estimate for 2023-24.

Department of Higher Education: Rs 47,620 crore (39 per cent of the Ministry?s budget), representing a decrease of 17 per cent from the revised estimate for 2023-24.

A key factor contributing to the change in expenditure is the additional transfer to the Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) in 2023-24, totaling Rs 23,500 crore. This non-lapsable fund, sourced from secondary and higher education cess,

supports secondary and higher education schemes but was not allocated to specific schemes in 2023-24.

**Key Schemes in Education**

1. **Samagra Shiksha Abhiyaan**

Objectives: Implement the NEP and the Right to Education Act, bridge social and gender gaps, and strengthen teacher training.

Focus: Infrastructure improvement, learning standards, and teacher training.

2. **Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)**

Extends the Mid-day Meal Scheme to pre-school children.

Covers 11.8 crore students in 11.2 lakh schools.

3. **PM Schools for Rising India (PM-SHRI)**

Upgrade 14,500 schools with NEP principles, local linkages, and advanced technology.

Central share of Rs 18,128 crore over 2022-23 to 2027-28.

**Key Issues in School Education**

1. **Drop in Enrolment After Primary Level**

The NEP aims for 100% enrolment at all levels. While primary enrolment is close to 100%, it drops to 58% at the higher secondary level.

2. **Rising Enrolment in Private Schools**

The share of private unaided schools in total enrolment has increased, leading to higher educational costs for families.

3. **Dropout Rates**

Dropout rates increase at higher educational levels, particularly among Scheduled Tribes.

The 2024-25 budget for education reflects both continuity and change. While there is a marginal increase in the allocation for school education, the funding for higher education has seen a notable decrease. The reduction in funding for key higher

education bodies like UGC and AICTE and the increased allocation towards specific schemes such as PM-SHRI highlight the evolving focus areas within the education sector. Addressing dropout rates, improving private school affordability, and enhancing educational infrastructure remain critical challenges.

1. **Impact of COVID-19 on Education**

The COVID-19 pandemic has had a profound impact on our educational system. Funding delays under the Samagra Shiksha Abhiyaan (SSA) were exacerbated by the pandemic, leading to a review by the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. The committee has recommended faster mechanisms for fund utilization to ensure that educational projects are not stalled.

2. **Teacher Availability and Quality**

The National Education Policy (NEP) 2020 aims for a pupil-teacher ratio (PTR) of 30:1. While this target is met at the aggregate level, significant disparities persist across States. For instance, Jharkhand and Bihar face substantial shortages, with vacancies for teachers as high as 40 per cent and 32 per cent, respectively. The Standing Committee has emphasized the need for expedited teacher recruitment and suggested the creation of an Autonomous Teacher Recruitment Board at the state level.

Moreover, 10 per cent of Government school teachers lack professional qualifications, with states like Tripura and Nagaland showing particularly high percentages. Despite the decline in expenditures on teacher training under SSA, programs such as the National Initiative for School Heads and Teachers' Holistic Advancement (NISHTHA) are working to improve teacher capabilities through digital learning modules. However, as of June 2024, only 49 per cent of school heads and 43 per cent of teachers have been trained under this initiative.

3. **Learning Outcomes**

Learning outcomes remain a significant concern. The National Achievement Survey (NAS) reveals a decline in proficiency across most subjects and grades between 2017 and 2021. For example, proficiency in mathematics dropped from 46 per cent to 43 per cent. The NIPUN Bharat Mission and the Strengthening Teaching and Learning Results for States (STARS) program have been launched to address these issues, with increased allocations to improve learning outcomes and educational quality.

4. **Digital Infrastructure in Schools**

While 97 per cent of schools have separate toilets and 96 per cent have access to drinking water, digital infrastructure remains limited. As of 2021-22, only 26 per cent of schools have desktop facilities and 34 per cent have internet access. This digital divide impacts equitable access to technology, particularly between government and private schools. The Performance Grade Index (PGI) for districts indicates that 66 per cent of surveyed districts scored 30 per cent or lower on digital learning parameters, highlighting the need for significant improvements in digital infrastructure.

5. **Higher Education**

In higher education, socio-economic disparities persist. The Gross Enrolment Ratio (GER) was 28.5 per cent in 2021-22, with lower enrolment rates in states such as Bihar and Assam. Women?s participation in engineering remains disproportionately low, although they constitute a majority in overall STEM fields. Financial aid for students has seen a reduction in expenditure, with a significant ant drop in interest subsidy over recent years. The PM-Uchchatar Shiksha Protsahan Yojana (PM-USP) has been introduced to streamline student financial aid, with an allocation of Rs 1,558 crore for 2024-25.

6. **Quality of Higher Education Institutions**

The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) assesses the quality of higher education institutions, with 37 per cent of universities and 20 per cent of colleges accredited as of November 2023. However, the majority of accredited colleges have received grades of B or C, indicating room for improvement. The Higher Education Financing Agency (HEFA) has sanctioned loans worth Rs. 39,720 crore for infrastructure development in higher education institutions, but disbursement remains incomplete.

Our education system stands at a crossroads. While we have made strides in increasing enrolment and infrastructure, significant challenges remain in teacher quality, learning outcomes, digital access, and equitable opportunities in higher education. Addressing these issues requires a collective effort to implement the recommendations of the Standing Committee, ensure efficient fund utilization, and bridge the digital divide.

Let us commit ourselves to creating a robust and inclusive education system that equips every student with the knowledge and skills to thrive in the future.

**I. School Education**

Our efforts under the Samagra Shiksha Abhiyaan (SSA) have been substantial, with proposed funds amounting to Rs 51,000 crore for 2024-25. However, the release of these funds has been inconsistent. The Standing Committee on Education, Women, Children, Youth, and Sports has observed delays due to states not utilizing previously released funds and has recommended a review of mechanisms for faster fund utilization.

The National Education Policy (NEP) 2020 set a pupil-teacher ratio (PTR) target of 30:1. While the aggregate PTR meets this target at 26:1 for primary and 19:1 for upper primary levels, significant disparities persist among states. For instance, Jharkhand and Bihar report PTRs significantly above the target, indicating a critical need for better teacher distribution and recruitment.

Our schools are grappling with a high share of small schools with insufficient teachers. The NEP identifies smaller schools as challenging to manage, often lacking essential infrastructure. Additionally, teacher vacancies remain a concern, particularly in states like Jharkhand and Bihar, where vacancies are above 30 per cent. The Standing Committee has recommended forming an Autonomous-Teacher Recruitment Board at the state level to ensure transparent recruitment.

The quality of our teachers is another pressing issue. As of 2021-22, 10 per cent of Govemment school teachers lack professional qualifications, with states like Tripura and Nagaland facing the highest deficiencies. The National Initiative for School Heads and Teachers? Holistic Advancement (NISHTHA) aims to improve teacher training, yet only 49 per cent of targeted school heads and 43 per cent of teachers have been trained so far.

Learning outcomes are also under scrutiny. The National Achievement Survey (NAS) reveals a decline in proficiency across subjects and classes from 2017 to 2021. Proficiency in languages and mathematics has dropped, highlighting the need for improved teaching methodologies and learning resources. The NIPUN Bharat Mission and the STARS programme aim to address these issues, but significant challenges remain.

**II. Higher Education**

In higher education, the Gross Enrolment Ratio (GER) has improved but remains below the target of 50 per cent set by the NEP 2020. States like Bihar and Assam have notably lower GERs. Gender disparity is also evident, with women constituting only 29 per cent of undergraduate engineering students.

Financial aid for students has seen a reduction, with expenditure on interest subsidies dropping from Rs 1,950 crore in 2017-18 to Rs 873 crore in 2022-23. The PM-Uchchatar Shiksha Protsahan Yojana (PM-USP) aims to address this by merging various schemes, but the allocation for 2024-25 remains lower than previous budgets.

Private institutions dominate the higher education landscape, with 66 per cent of enrolments in private colleges. The NEP recommends treating educational institutions as nonprofits and ensuring transparency in fee structures, but challenges remain in regulating private sector costs.

Quality in higher education institutions is varied. The National Assessment and Accreditation Council (NAAC) grading shows that 37 per cent of universities and 20 per cent of colleges are accredited, with a significant proportion receiving lower grades. The Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyaan (RUSA) has faced underutilization of funds and a reduction in targets from RUSA 1.0 to RUSA 2.0, leading to recommendations for increasing targets.

Vacancies in faculty positions are another concern, with about one-third of posts in centrally-funded universities vacant. The faculty?s representation from SC and ST communities remains inadequate, further emphasizing the need for equitable recruitment policies.

Common entrance exams like NEET, JEE, and CUET are designed to streamline admissions but have faced criticism for increasing reliance on coaching and not ensuring a level playing field. The NEP?s recommendations for conceptual testing and university discretion in accepting entrance exams need to be revisited to better serve students from diverse backgrounds.

The employment landscape for graduates is concerning. The Working Population Ratio (WPR) for graduates is lower compared to other countries, with increasing unemployment rates among educated youth. The National Apprenticeship Training Scheme and recent initiatives provide internship to opportunities are steps in the right direction, but more comprehensive strategies are needed to improve employability.

**III. Research and Development**

India?s expenditure on R&D stands at 0.64 per cent of GDP, significantly lower than other countries like South Korea and the USA. Research funding is concentrated in specialized government departments, with universities contributing only nine per cent of the total expenditure. The establishment of the National Research Foundation aims to enhance research capabilities in HEIs, but challenges in integrating research with teaching persist.

In summary, while there have been strides in improving both school and higher education, substantial challenges remain. We must address issues related to funding, teacher quality, infrastructure, and student employability with a sense of urgency and commitment. By implementing the recommendations of various committees and policies, and ensuring better resource allocation and management, we can make significant progress toward an equitable and high-quality education system.

Let us commit to working together to overcome these challenges and build an education system that truly serves the needs of every student in our nation.

Thank you.

**SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI):** One of the foremost challenges facing India today is the high rates of unemployment among its youth, particularly its educated youth. In 2022, the rate of unemployment among youths with a secondary or higher level of education, 18.4%, and among graduates, 29.1%, was six times and nine times greater than the unemployment rate among persons who cannot read or write, respectively. This es that Indicates India's education system has failed to equip a large proportion of its students with the skills required for gainful employment in the modern world, and that it must be substantially reformed.

Under the New Education Policy 2020, India aims to increase its total expenditure on education to 6% of GDP, but this announcement was of little significance without a clear, time-bound roadmap to reach this level of public investment. At present, this figure hovers around 3%. Despite the government's lofty claims, however, Central government spending on education has declined marginally from about 0.39% of GDP in the Budget 2023-24 to 0.38% of GDP in 2024-25. This budget also utterly fails to realise the NEP's five pillars of access, equity, quality, affordability, and accountability in education, and is a step backward in many ways.

**Budgetary Allocation**

The budgetary allocation for schools increased by 4.2% from Rs 68,804 crore in 2023-24 to Rs 73,008 crore in 2024-25, a meagre growth from the revised estimate of Rs 72,473 crore in 2023-24. Higher education received Rs 47,619 crore in 2024-25, an increase of 7.68 percent from Rs 44,094 crore in 2023-24. However, this allocation falls significantly short of the revised estimates on spending for 2023-24, Rs 57,244.

**Centralisation of Education**

Funding for the University Grants Commission has been slashed by more than 60%, from a revised estimate of Rs 6409 crores in 2023-24, to Rs 2500 crores in 2024-25. Meanwhile, the allocation for grants to Central Universities has been increased by more than Rs 4000 crores. These universities are all controlled and funded by the Central government, and admissions to them are conducted on the basis of a common entrance test.

The New Education Policy expressed concern about the presence of over 800 universities and 40,000 colleges across India, which it termed the 'fragmentation' of education in the country. While there is certainly a need to better regulate and fund state and local institutions, the value these institutions offer is immense. They cater to the needs of students in backward and neglected areas, allow the socio-cultural diversity of the country to be reflected in the educational curriculum, and their decentralised autonomy is a bulwark against attempts to bring education under authoritarian control.

The NEP also proposes to dissolve several existing regulatory bodies including the UGC, AICTE and National Council for Teachers Education (NCTE) to create a singular entity called Higher Education Commission of India (HECI) to regulate key aspects of education. It is inevitable that this will be a top-heavy body with massive intervening powers. No other established and large federal system has such an overarching regulatory body for the entire country.

So, while any increase in investment in Central Universities is welcome, this reallocation of funds appears to be a part of the New Education Policy's dangerous tilt towards the over-centralisation of education. Moreover, it is the state

universities that are in the direst need of funds, and providing this is essential to realising the mission of providing equitable access to education.

**Funding**

In the 2023-24 Budget, the allocation for the Indian Institutes of Management was slashed by nearly 500%, from Rs 654 crores in 2022-23 to only Rs 300 crores. This year, funding for the IIMs has been further cut down by Rs 88 crores to Rs 212 crores. The quality of education offered by these institutions cannot be brought into question, but the exorbitantly high tuition fees they charge in the absence of substantial government funding have become a serious financial burden on students, excluding many who come from marginalised backgrounds. The fees for IIM Ahmedabad, for instance, rose from ₹ 4 lakh in 2007 to 27 lakh at present, making some of the best education India offers inaccessible to the vast majority of its citizens.

Perhaps even more concerning, however, is the continued imbalance in funding for flagship institutes like the IIT's, NITs and IIMs versus other institutes of higher education. IITS, NITs and IIMs together educate less than 5% of India's total students, yet they receive nearly 40% of the funding for 'Autonomous Bodies' under the Ministry of Education, which includes not only the UGC and Central Universities, but also the prestigious Indian Institute of Science (IISc) and Indian Institute(s) of Science, Education and Research (IISER). This government has repeatedly stated its commitment to 'democratising' education, but this will be an impossible task unless it looks into this inequitable distribution of funding that deprives the vast majority of India's students of a quality higher education.

**Examination Reform**

The examination irregularities that have rocked the country in the last few months, particularly the NEET-UG leak, have shaken students' faith in India's examination system. This Budget presented the government with an opportunity for course correction, by bringing in examination reform. Instead, the government chose to entirely neglect the subject, ignoring recommendations made by experts regarding the enhancement of security measures, such as developing advanced infrastructure for holding exams, setting up exam centres at government institutions and adequate staffing of permanent employees at the NTA.

**PM POSHAN**

The costing norms for the Supplementary Nutrition Programme under. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 have not been revised since 2017, ranging between Rs 8 per beneficiary per day for children below the age of six, to Rs 12 per beneficiary per day for the severely malnourished. The cost of food has soared in recent years, with inflation rates frequently hitting the double digits. Undoubtedly, it is no longer possible that the nutritional needs of the beneficiaries of the POSHAN Abhiyaan continue to be fulfilled by this meagre allocation. It is essential that the Cabinet Committee on Economic Affairs revise the costing norms under this programme to meet the needs of India's children.

**Startup India**

The Startup India Initiative in Higher Educational Institutions has been allocated no funds whatsoever. While it was allocated Rs 11.21 crores in the Budget 2023-24, revised estimates for the year suggest that nearly five times that amount of funds were utilised under the scheme. Rather than examining the reasons behind this overspending and considering a proportionate increase in the allocation, the government has opted to entirely neglect it.

**GST on Educational Products and Services**

The imposition of 18% GST on private schools and higher education institutes and coaching centres is a significant financial burden on parents. This tax is also levied on the services of EdTech platforms, which have made affordable coaching classes accessible to all sections of society. I urge the government to lower or eliminate the GST on these products.

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : मैं शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर अपने विचार रखना चाहता हूँ ।

मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर जो भारत - नेपाल की सीमा से लगा हुआ है**,** उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा आकांक्षी जनपद है । जो भगवान गौतम बुद्ध की धरती भी है । यह एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थली है यहाँ देश विदेश से लाखो तीर्थ यात्री और बौद्ध भिक्षु हर साल दर्शन करने आते हैं । आजादी के **77** साल बाद भी श्रावस्ती जनपद शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा है । जिसमें अनुसूचित जाति अनूसूचित जनजाति पिछडे और अति पिछडे वर्ग के लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं ।

आज जिस तरीके से पूरे देश में  बार-बार पेपर लीक हो रहा है सरकार कहीं न कहीं इसके लिए संवेदनशील नहीं है ।  इससे देश के गरीब बच्चों का समय और पैसा दोनों का भारी नुकसान हो रहा है। बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत ही महंगी हो गयी है ।  शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है । उच्च शिक्षा हेतु बच्चों को दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है ।  शिक्षा व्यवस्था की हालत जर्जर हो गई है ।  देश मे फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होना चाहिए ।

मेरा लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती है जिसका नाम आज भी उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जनपदों में सबसे नंबर एक पर आता है जहां आज भी शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं, इनफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों एवं स्टाफ की भारी कमी है । यहाँ आज भी अच्छे स्कूल नहीं है । इंटर कालेज नहीं है । इंजीनियरिंग कालेज नहीं हैं । तकनीकी शिक्षा के लिए कोई विद्यालय/ विश्वविद्यालय नही है ।

सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए । आज भी यहाँ के छात्रों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा की कोई सुविधा नही मिल पा रही है । जबकि इसी लोक सभा क्षेत्र से ही स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी बाजपेयी जी (पूर्व प्रधानमंत्री) भी चुन कर आए थे । यह क्षेत्र भगवान बुद्ध की तपोस्थली रही है । मेरी भारत सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार से मांग है कि मेरे दोनों जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर में अभी भी प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय की भी कमी है । नये विद्यालय बनावाए जाएं । इंटर कालेज, डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और तकनीकी शिक्षा के लिए विद्यालय/ विश्वविद्यालय खोला जाए और साथ ही देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए । उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए श्रावस्ती जनपद के साथ-साथ अन्य सभी पिछड़े हुये जनपदों को प्राथमिकता देकर शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए ।

आज देश में गरीब, मजदूर की संख्या बढ़ रही है अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था होगी तो देश के हर गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे जिससे शिक्षित समाज विकसित होगा । और एक-एक घर आगे बढ़ेगा, गाँव आगे बढ़ेगा, जिला आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा और इसी तरह पूरा देश आगे बढ़ेगा ।

आज पूरे देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर आक्रोश है । पिछले **7** सालों में करीब **70** बार पेपर लीक और परीक्षा रद्द हुये हैं । देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है । इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । धन्यवाद ।

**SHRI G. KUMAR NAIK (RAICHUR):** I would like to express my views on Budgetary Grants indicated for education. The speech of the hon. Finance Minister and the grants shown should be understood in the context of what is happening since the last 10 years when the NDA/BJP Government came to power.

The trends which could be easily summed up as four Cs - Centralization, communalization, corporatization and commodification.

**Centralization**

Education being a Concurrent Subject is the responsibility of the State government as well as the Central Government. RTE makes education a matter of right. At the centre of this process is the child. Hence you hear the word ?child centric?. Home is the first school. Next layer is the physical school located in the community. This is where the process of education happens. In this process, even the State Government is an entity further away, taking care of supply side like construction of schools, appointing teacher etc.

It is recognized that SSA is the instrument for realizing the goals of RTE. However, this Government believes in greater and greater centralization. States are being forced to sign MoU with the Ministry to implement PM SHRI programmes.

West Bengal, Delhi and Punjab have not received funds owing to their demand for flexibility and independence. Central Government wants to have a say in the class room transaction also as to what is being taught in the classroom and how it is taught.

Track record of the Central Government as a funding agency is also very poor. SSK funding is oblivious to the level of RTE compliance in the schools across the country.

Instead of being child centric, it is today PM centric or publicity centric. Beti Bachao, Beti Padhao for 2021-24 was allocated Rs. 605 core of which Rs. 409 crore were used for advertisement purposes only.

SSK grants are getting reduced. Sadly, most of SSK grants is garnered from various education cess.

**Communalization**

Directive principles encourage promotion of scientific attitude. What is happening with our syllabus is sadly astonishing and sad. Darwin?s Theory of Evolution, periodic table have been removed. History seems to be a favourite playground for the BJP. Reading history in a communal lens is a crime. It is detrimental to the development of child into a responsible, balanced and healthy citizen. You do not seem to have guts to learn from mistakes in recent past. References to Godse, Babri Masjid demolition have been removed. Truth cannot be brushed under the carpet.

**Corporatization**

School management seem to be taking the shape of corporate bodies keeping a profit and loss accounts with profit being the sole purpose. Unbridled expansion leading to chain of schools offering curriculum which is different from Government owned public school, curriculum of CBSE, ICSE and IB are pushed across the country. High fee structure ensures that this is only for rich sections of society. Education loans are designed to facilitate movement of students from Government owned institutions to private institutions. Education is no longer a public good. Now running a school is a profit making activity.

**Commodification**

Education service is today akin to cafeteria/mall. Each one to choose as per his choice mostly on the basis of the ability to pay. These trends which had begun earlier have been given impetus by the policies of the Government in the last 10 years. The Budget also pushes the sector in the same direction. Closure of Government schools in thousands every year is highly deplorable. Increase the Budget. Make the schools RTC compliant and ensure children/parents do not feel the need to move away from Government schools.

**Higher Education in universities**

Less said the better regarding the universities and higher education institutions. Budget for UGC have been drastically reduced by 61 per cent. Is this not a clear case of abdication by this Government?

I urge the Finance Minister to increase the allocation to the Education Department so as to get the sector back on track. Present trend of 4 Cs has to be decisively reversed and only then Sabka Saath Sabka Vikas can have some meaning.

**श्री अरुण कुमार सागर (शाहजहाँपुर) :** मैं शिक्षा मंत्रालय के बजट पर अपनी बात रखना चाहता हूँ । मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वर्ष 2024-25 के शिक्षा मंत्रालय के बजट में देश के व्यापक हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं और एजुकेशन बजट में 31 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोत्तरी की है.

शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है । इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरन्तर विकास करते है ।

हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय वित्त मत्री ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजट आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है । इससे यह राशि 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गई है । उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है, उसे बढ़ाने के लिए शिक्षा ऋण के लिए ई-वाउचर पेश किए गए हैं और महिलाओं को पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन का प्रावधान है । हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है । भारतीय संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन के लिए ई-वाउचर दिया जाएगा । ये ई वाउचर हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे । कामकामी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी ।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट में हायर एजुकेशन के लिए लोन और इंटर्नशिप से जुड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया है और निम्नांकित प्रावधान भी किए हैं :-

- सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएगी ।

- छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी ।

- घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता देगी । हर साल एक लाख छात्रों को ई-वाउचर दिए जाएंगे ।

- बजट में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का भी प्रस्ताव है ।

- सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की लोन सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करेगी. इससे हर साल 25 हजार स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी ।

इस बजट में सरकार ने 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने की भी एक योजना बनाई है । इसमें इंटर्नशिप भत्ते के रूप में 5000 रुपये महीने और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता भी देगी । हमारी सरकार देश के सभी गरीब छात्र/छात्राओं को माध्यमिक स्तर से लेकर हायर एजूकेशन की शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है । देश की शिक्षा प्रणाली में आजादी के बाद विगत 10 वर्षों में जो सुधार देखने को मिले हैं, वह इससे पहले नहीं दिखाए दिए । देश में स्टार्टअप संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है, और वर्तमान में भारत में 1 लाख 40 हजार स्टार्टअप्स चल रहे हैं. यह युवा उद्यमियों और नई तकनीकों के विकास का स्पष्ट संकेत है, जो भारत को आर्थिक मोर्चे पर और मजबूत बना रहा है । कांग्रेस ने दशकों तक केन्द्र में शासन किया है । लेकिन, उसने शिक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और आज वह बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेकर देश को गुमराह कर रही है ।

यह बहुत ही खेदजनक है कि विपक्षी दलों के गठबंधन, जिसमें कांग्रेस प्रमुख है, ने हाल ही में हुए लोक सभा चुनाव के दौरान भारतीय संविधान का यह कहकर खूब दुष्प्रचार करके आम लोगों को गुमराह किया कि आने वाले समय में भाजपा सरकार संविधान को बदल देगी । कांग्रेस ने आम लोगों को गुमराह करके राष्ट्र विरोधी कार्य करते हुए देश को कमजोर करने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। यह किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस जिसने दशकों तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव किया तथा बाबा साहेब को भी चुनाव हरा दिया तथा उन्हें भारत रत्न नहीं दिया और देश में आपातकाल लगाकर संविधान को समाप्त करने की कोशिश की, आज वही कांग्रेस संविधान की आड़ लेकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है । यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने संविधान दिवस मनाने का विचार सामने रखा, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया । यह सच्चाई है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े "पंचतीर्थ" विकसित किए गए । हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का स्पष्ट कहना है "हमारी सरकार संविधान का सम्मान करती है । अगर बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो वे इसे खत्म नहीं कर सकते । सरकार के लिए संविधान गीता, रामायण, महाभारत है । हमारे लिए संविधान ही सब कुछ है ।"

अंत में, मैं पुनः शिक्षा मंत्रालय के बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद सहित ।

श्रीमती भारती पारधी **(**बालाघाट**) :** माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया है । आज मैं इस सदन में वर्ष 2024-25 की डिमांड्स फॉर ग्रॉन्ट्स पर अपनी बात रखते हुए खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं ।

मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में ?सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? के मंत्र को अपने हर कदम पर अपनाया है । वर्ष 2024-25 के लिए जो अनुमोदन प्रस्तुत किया गया है, वह देश के हर वर्ग के उत्थान और विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । यह अनुमोदन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों के सुधार में नए आयामों को प्रस्तुत करता है ।

?जितने भी महान जवान हुए हैं,

जितने भी मेहनती किसान हुए हैं,

सभी अपने क्षेत्रों में शिक्षा से ही धनवान हुए हैं,

जब पूरे आज़ाद गगन में,

खुशियों के अपार चमन में,

शिक्षा का परचम लहराएगा,

भारत शिक्षित कहलाएगा ।?

महोदय, मैं आज इस सदन में अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट-सिवनी के लिए शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि शिक्षा ही वह साधन है, जिससे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं ।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी कुछ मांगें हैं, ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र बालाघाट का शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान हो सके । वहां नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए, ताकि बालाघाट के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े, क्योंकि मेरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र कहलता है । इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नए विद्यालयों की स्थापना की जाए । तकनीकी और पेशेवर शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाए । इससे हमारे युवाओं को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका होती है । नए शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके । नवीनतम शिक्षण तकनीकों और पद्धतियों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं । यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे शिक्षक उच्चतम मानकों के अनुरूप शिक्षण कर सकें । स्कूल भवनों का निर्माण और मरम्मत के लिए अनुदान मिले, ताकि स्कूल भवनों की मरम्मत और नए भवनों का निर्माण हो सके, जिससे छात्रों को सुरक्षित और सुसज्जित वातावरण मिल सके ।

महोदय, शिवनी-बालाघाट के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना के लिए अनुदान मिले । ई-लर्निंग, डिजिटल शिक्षा सामग्री, टैबलेट और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए । विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना की जाए । माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का समावेश किया जाए । इन अनुदानों के माध्यम से

शिवनी-बालाघाट के शिक्षा क्षेत्र में सुधार हो सके और वहाँ के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में अग्रसर कर सकें । मैं ऐसी अपेक्षा करती हूं । इससे शिवनी-बालाघाट के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकेगा और इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा । ऐसा मेरा मानना है ।

महोदय, बीते 10 वर्षों में मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय काम किये हैं, जैसे ?सर्व शिक्षा अभियान? के माध्यम से शिक्षा को नई ऊर्जा और दिशा मिली है । इस अभियान के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि हुई है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2022 के बीच प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर 96 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है । हम मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, ?राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020? एक मील का पत्थर साबित हुई है । इस नीति का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है । इसके तहत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो (GER) को 50 परसेंट तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जो वर्ष 2019-20 में 27.1 प्रतिशत था । ?दीक्षा? और ?स्वयं? जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने शिक्षा को घर-घर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । ?स्वयं? पोर्टल के माध्यम से दो करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन कोर्सेस में नामांकन किया है ।

महोदय, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई है । अब तक 10 हजार से अधिक स्कूलों में ये लैब्स स्थापित किए जा चुके हैं, जहां विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण मिलता है । मोदी सरकार ने रोजगार, शिक्षा और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े वित्त मंत्री द्वारा बजट 2024-25 में प्रस्तुत किये गए हैं । यह सब हो रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है । इन्ही प्रगतिशील आंकड़ों में बालाघाट-शिवनी के आंकड़े भी हों, मैं ऐसी कामना करती हूँ । इन अनुदानों के माध्यम से हम बालाघाट-शिवनी के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकें और वहाँ के बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की दिशा में अग्रसर कर सकें, मैं ऐसी अपेक्षा करती हूं । हम बालाघाट-शिवनी के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकें और इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में शामिल कर सकें, यही मेरा संकल्प रहेगा । अंत में मैं यही कह कर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी कि ?पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया? । धन्यवाद ।

**PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM):** Thank you, Sir. I shall be very brief because I have very little time.

I would like to say that education in India has dwindled to a bad situation. Currently, India has nearly 50,000 colleges and 1,100 universities. Fifty per cent of them are in the private sector. Education has become a place to make money by big capitalists. But this expansion in education shows lack of quality and uniformity.

Dear Member, would you let the Minister listen to my speech? ? (*Interruptions*) मंत्री जी, आप कृपया मेरी बात सुनें ।

I mentioned in the House the other day that there are no world-class institutions in India. BJP has got so much time. Why can you not build a single Oxford or Cambridge or Harvard or MIT or a University of California? Even you have not brought a university of the standard up to Singapore?s National University or the

Beijing University. Unless you can improve the standard of education in higher educational institutions, our best students will go abroad. Last year, I mentioned that 8,96,000 students went abroad from India. This is a brain drain which ought to be stopped.

I also want to mention that ? (*Interruptions*) मैं सीरियस बातें यहां बोल रहा हूं, आप कृपया उनको सुनिए । ? (व्यवधान) आप तो डॉक्टरैट हैं, लेकिन कहां से, मैं उसके बारे में यहां नहीं बोलना चाहता हूं । वह महुआ जी बोलेंगी ।

I want to mention that Budget Estimate for Education is only 2.7 per cent of GDP. It got reduced from 2.9 per cent in 2022-2023 to 2.7 per cent. Now, one has to remember that according to UNESCO and World Bank studies, every dollar invested in primary education returns 15 to 25 per cent. So, how can you expect the standard in India to improve with such meagre allocation for education? As Prof. Amartya Sen never tires of speaking that unless you can improve primary education and health, the country will never go forward.

India?s educational sector ranks 39$^{th}$ out of 67 countries in the IMD World Competitiveness Rankings 2024. I would like the Education Minister -- as he has got five years at hand if the Government lasts -- to at least make one world-class university that can compare with the best in the world. Otherwise, what is the point of having so many IITs, IIMs, IISERs, etc. at Central level? You are giving money, but you are not producing quality, and without quality you cannot compete.

You would say that well, Indians are doing so well abroad. There is one Sundar Pichai in Google and one Satya Nadella in Microsoft, but most of the Indians who are going abroad are working as cyber coolies in American multinationals. This should stop.

Lastly, I want to make a request to the Education Minister. I am told that you have influence in the ... * Why do not you persuade the ...* to stop interference in education? ? (*Interruptions*)

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **(**गोड्डा**) :** सर, माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं । ? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** सर, मैंने क्या गलत बोला है? ? (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Prof. Sougata Ray ji, please conclude.

? (*Interruptions*)

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **:** सर, इनका भाई ? * से है । यह क्या बात कर रहे हैं ।?(व्यवधान)

**PROF. SOUGATA RAY:** Sir, ... **has changed the history textbook. ? (*Interruptions*) They have omitted the Mughal period from our history. ? (*Interruptions*)

They have destroyed our university. There was one Vice Chancellor of Visva Bharati University, by name ...** who installed two plaques for Santiniketan, in which he wrote only his name and Shri Narendra Modi?s name. It is a matter of shame. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Please sit down. Please conclude.

*?(Interruptions)*

**PROF. SOUGATA RAY :** You have one ...**** who is a Professor in the Department of Electrical Engineering at IIT. He was made the Chairman of the UGC. Why? It is because he was recommended by the ...**** You cannot run the universities with such type of people. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** This is an allegation without any basis. It cannot be taken on record. Kindly be seated.

**PROF. SOUGATA RAY:** Education needs quality, not quantity. Education does not need political underpinnings. I ask the hon. Education Minister. He has got a good chance. He has won for the first time from Sambalpur. ? (*Interruptions*) Let him show some courage and get the ... **out of all this. ? (*Interruptions*)

**HON. CHAIRPERSON:** Let me remind the House that the Indian School of Business which is located in Hyderabad has a very good global rating. Kindly look at the global rating of it.

**SHRI ANIL YESHWANT DESAI (MUMBAI SOUTH-CENTRAL):** Sir, I would like to highlight a few points. Let the House be in order. The Education Ministry, I am not comparing it to employment and skilling, has solely got Rs. 1,20,628 crore out of which school education and literacy have got a substantial amount of Rs. 73,000 crore. The budget allocation for higher education is Rs. 47,620 crore. In the budget allotted for school education, there is seven per cent increase but in the budget allotted for higher education, there is 17 per cent reduction. Our National Education Policy, 2020, has recommended the Government to spend, at least, 6 per cent of the GDP towards education, and I think where we stand today, the budgetary allocation is not even half of what is recommended.

The school education and literacy programme, Samagra Shiksha Abhiyan, which is the flagship scheme of the entire school education system, entails that States will implement NEP under Right to Education for bridging the social and gender gap. It is a very important aspect which needs to be enforced in proper direction.

The second point is about improving teachers? training. I will just quote a situation of Maharashtra. Hon. Minister himself was there. He must be getting the reports. The Teachers Eligibility Test which was conducted in 2022-23 was a scam where the entire situation was shameful. It was just unbearable because it was related to education. A country like India which is an emerging economy and which will be Vikasit Bharat, the dream project of our hon. Prime Minister, in the times to come, of course, every citizen of India supports it. That needs to be taken seriously. How would contract based teachers deliver the best in this entire programme? How would they fit into NEP? That needs to be explained. It is about quality of teachers also. Imparting education to the students is the basic thing towards the progress of the nation. I am not going into details, but the hon. Minister will shed some light on the trajectory.

Another aspect is about upgradation of school infrastructure which includes drinking water, toilets, science labs, and computer classrooms. I am giving an example of rural Maharashtra and semi urban places where basic facilities are not there and that also becomes one of the reasons for dropouts. The dropouts are taking place at an alarming rate. This is one of the reasons.

The PM-POSHAN constitutes 10 per cent of the budget that is allocated. The Mid-day meal programme encompasses it. It stipulates calories and nutritional norms. It is catering to around 12 lakh students who are there in more than 11 lakh schools. So, this is a very important aspect. The quality of mid-day meals, which are being served in the rural areas speaks volume about the nutritionalities and how the things are going on. So, I want to ask the hon. Minister whether any checks and balances are there in place or not. Is there any audit being done or not? It is because this is going for the formative years of our children who will be shouldering the responsibility of Viksit Bharat and Aatmanirbhar Bharat.

Sir, another important issue is dropout rates. As I said, in primary, upper primary and secondary education, there is an alarming rate of dropouts which is a worrisome picture for the entire education system in India. With regard to Mean Years of Schooling in India, the United Nation?s report that was published in 2023-24 shows that in India, the mean years of schooling is 6.6 years, compared to the

United States? 13.6 years, United Kingdom?s 13.4 years, and South Africa?s 11.6 years. Brazil has the figure of 8.3 years; China has the figure of 8.1 years and even Bangladesh is much ahead of us with 7.4 years. सर, मुंबई में जेवियर्स कॉलेज है, which has built its own reputation. वह बहुत अच्छा इंस्टिट्यूट है, जिसका नाम आज पूरी दुनिया में अच्छे दिल से लिया जाता है । They are afraid that having come thus far and having earned that goodwill, somehow the Government is trying to take over it. The Government should have that kind of infrastructure. But in respect of certain institutes, which have built their institutes by their own hard work by putting in everything - their talent, their merit - the Government should not interfere in these kinds of institutes.

The last point, which I would like to make before concluding, is this. In school and college education, mother tongue should be taught. It is being propagated in your NEP. How far will it go? Propagating is one thing. But implementing is something different. Though we say in the neighbourhood our schooling should be in mother tongue, लेकिन यह कौन सिखाता है? कौन अपने बच्चों को वहां भेजता है? महाराष्ट्र में मराठी स्कूल्स आए दिन बंद हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं मिलते हैं । वहां पर बच्चों की संख्या नहीं होती है, वहां यह इस तरह से किया जा रहा है कि स्कूल्स बंद पड़ रहे हैं । The National Education Policy is envisaging that, and it is propagating that mother tongue should be given priority. Of course, we are not averse to English but at the same time, mother tongue is what we are looking for. How will that be tackled? I hope that the hon. Education Minister throws some light on this and enlighten the House in this regard as well.

Jai Hind. Jai Maharashtra.

श्री अनिल फिरोजिया **(**उज्जैन**) :** सभापति जी**,** मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है । मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं**,** वह भगवान महाकाल की नगरी और कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली है**,** जहां पर श्री कृष्ण रह कर अपनी शिक्षा को पूर्ण किया था । वह महाकवि कालीदास की कर्म भूमि है**,** मैं उस नगरी से आता हूं । आज मैं यशस्वी प्रधान मंत्री श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू करने का काम किया ।

माननीय सभापति जी**,** देश आजाद हुए 77 साल हो गए । 77 साल में तीन बार शिक्षा नीति बनी, लेकिन शिक्षा नीति लागू नहीं की गई । उसमें अमेंडमेंट किया गया । अगर शिक्षा नीति को बनाकर किसी ने इसे लागू करने का काम किया तो उनका नाम नरेन्द्र मोदी जी हैं । अगर किसी भी देश को समाप्त करना हो, उसको खत्म करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को समाप्त करो, उसके ऊपर कुठाराघात करो या उसकी संस्कृति पर कुठाराघात करो ।

हमारे देश में 200 साल नहीं, बल्कि 2 हजार साल से आक्रमण होते रहे । हमारा देश दो हजार साल गुलाम रहा, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का और उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को तहस-नहस करने का काम किया । अगर हम देखें तो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा खाक कर दिया गया, जहां पर हमारे पुरखों ने, ऋषि-मुनियों ने पांडुलिपियां संजोकर रखी थीं, वहां पर आग लगा दी गई । अगर उसका भी किसी ने जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण किया तो उनका नाम नरेन्द्र मोदी जी हैं ।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि शिक्षा नीति की समानता को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ प्रमुख बिन्दु हैं? शिक्षा नीति का उद्देश्य, शिक्षा की समानता को बढ़ावा देना था, लेकिन इसको क्रियान्वित करने में कांग्रेस सरकार असफल रही । वास्तविकता यह है कि नीति में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के असमानता को दूर करने के लिए कांग्रेस शासन ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाये ।

जहां तक हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा की बात है, मैं यहां पर अपने कुछ मित्रों को सुन रहा था, जो क्षेत्रीय भाषा का विरोध कर रहे थे । आज कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो, अगर उसको हम बढ़ावा देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग इंग्लिश जानें, यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग गुजराती जानें । अगर उस क्षेत्र के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करें तो वे आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं । अगर यह काम किसी ने किया तो उनका नाम नरेन्द्र मोदी जी हैं । कांग्रेस तो सिर्फ दिखावा करती रही । आज विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की, लेकिन उस दिशा में कोई भी ठोस कदम इन्होंने नहीं उठाया । ये शिक्षा की समानता की बात करते हैं । अगर आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो आपको शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा ।

महोदय, मैं वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात करूंगा, जो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई थी । इन्होंने वर्ष 1992 में इसे संशोधित किया । ये शिक्षा प्रणाली में सुधार का वायदा करते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में कहीं भी गम्भीरता नहीं दिखी । आज भी इसमें कई कमियां उजागर हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इन कमियों को कैसे हल किया है?

महोदय, कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और वर्ष 1992 में इसे संशोधित किया । इसके मुख्य बिंदु थे? सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सुरक्षित करना, लेकिन इसमें हुआ क्या? इसे न प्रभावी रूप से लागू किया गया, न इस पर ध्यान दिया गया, जिससे यह उद्देश्य अधूरा का अधूरा ही रह गया । महिला और अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के लिए विशेष योजना ? मैं यहां पर अपने मित्रों को सुन रहा था, जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे । अनुसूचित जाति, महिला?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** आप कृपया कन्क्लूड कीजिए ।

श्री अनिल फिरोजिया **:** मैं आपको दो उदाहरण देता हूं । तात्कालिक प्रधान मंत्री श्रीमान जवाहर लाल नेहरू जी ने, जब डॉ. अम्बेडकर जी ने संविधान में आरक्षण की बात की, तो सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया था तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे । उसके बाद?(व्यवधान) यह पटल पर है । मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उसके आगे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने अनुसूचित जाति वालों को ...* कहा कि ...***** को मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा ।?(व्यवधान) ये बात करते हैं । वही अम्बेडकर जी हैं, मैं इस सदन में खड़े होकर यहां याद दिलाना चाहता हूं कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने लोक सभा में हराया, उन्होंने लोक सभा में हराने का प्रयास किया ।?(व्यवधान) उसके बाद उनको राज्य सभा में भी आने नहीं दिया ।?(व्यवधान)

जिस डॉक्टर अम्बेडकर की ये दुहाई देते हैं, उस डॉक्टर अम्बेडकर को इस सदन में आने से अगर किसी ने रोकने का प्रयास किया, तो उनका नाम था- जवाहरलाल नेहरू । ?(व्यवधान) ये बात करते हैं जनजाति की । ?सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास??(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आप बैठ जाइए ।

?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** श्री अभय कुमार सिन्हा ।

?(व्यवधान)

श्री अभय कुमार सिन्हा **(**औरंगाबाद**) :** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

महोदय, बिहार में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं । पहला नालन्दा विश्वविद्यालय है, दूसरा महात्मा गांधी की धरती चम्पारण में महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय । तीसरा, भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु की धरती एवं ज्ञान और मोक्ष की धरती पर दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है ।?(व्यवधान)

माननीय सभापति **:** मैं आपको बाद में फिर बुलाऊँगा । अभी आप बैठिए ।

?(व्यवधान)

श्री अभय कुमार सिन्हा **:** महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि गया में जो दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है, उसका नामकरण सम्राट अशोक केन्द्रीय विश्वविद्यालय किया जाए । मैं सरकार से यह विशेष आग्रह करना चाहता हूँ । चूंकि सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं । जिस तरह से, चम्पारण में महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उसके तर्ज़ पर गया में, गया की धरती पर जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, उसका नामकरण सम्राट अशोक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में करने के लिए मैं सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करता हूँ ।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अफ़ज़ाल अंसारी **(**गाजीपुर**) :** माननीय पीठासीन सभापति जी, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ ।

माननीय लोहिया जी ने कहा था कि निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले समान । आज यह दुख का विषय है कि शिक्षा विभाग ने अनुदानों के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, उसमें यह अफसोसनाक स्थिति है कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जहाँ बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, वहाँ उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है । इसी क्रम में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन?(व्यवधान), जिसका बजट पहले से ही कम था?(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक सेकेंड रुकिए, अंसारी जी । इससे पहले भी माननीय स्पीकर साहब ने बताया था कि जब सदन में अपनी बात कहें, तो एक हाथ अपनी जेब में न रखें ।

श्री अफ़ज़ाल अंसारी : ठीक है, महोदय । बहरहाल, इस बार यह जो 40 करोड़ रुपए का जो बजट था, उसे घटाकर अब 30 करोड़ रुपए कर दिया गया है । इससे एक मानसिकता का पता चलता है । यह भी देखने की बात है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बजट में भी पहले की तुलना में भारी कटौती की गई है जबकि उसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता थी । बजट में एससी, एसटी और ओबीसी को मुफ्त कोचिंग के माध्यम से शिक्षा के लिए सहुलियत प्रदान करने का जो बजट था, वह भी पहले से बहुत कम है । लेकिन अफसोस की बात है कि इसके लिए जो 47 करोड़ रुपए थे, उसे भी घटाकर अब मात्र 35 करोड़ रुपए कर दिए गये हैं । इस प्रकार से, अगर देखा जाए, तो टॉप क्लास के एजुकेशन के क्षेत्र में भी एससी, एसटी के लिए जो पहले 111 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान था, अब उसमें भी बड़ी कटौती कर दी गई है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं दो पंक्ति की कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार सदन में रखना चाहता हूं ।

?देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब,

ज़िंदगी भर यही सोचता रह गया,

मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया,

ज़िंदगी भर जिसे पूजता रह गया ।?

आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टैक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में, शिक्षा में खास तौर से शिक्षा में जो कमजोर वर्ग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको शिक्षा के प्रति जागरुक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट में बढ़ाकर प्रावधान किया जाना चाहिए था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई है । यह इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है । वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है, एक तरफ वह शिक्षा है, जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा है । गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है, तो ?क? से कबूतर, ?ख? से खरहा और ?ग? से गधा पढ़ाया जाता है ।

दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और मॉन्टेसरी स्कूल्स हैं, इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से शिक्षा दी जाती है । दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके हमारे बच्चे आगे जाते हैं और जब किसी पद के कॉम्पीटिशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है, तो जो बच्चा ?क? से कबूतर, ?ख? से खरहा और ?ग? से गधा पढ़कर गया है और जो बच्चा ?क? से कंप्यूटर पढ़कर गया है, वहां जब मुकाबला होता है, तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस, उन विद्यालयों से आने वाले छात्र हैं, वे कामयाब होते हैं और सरकार की तरफ से अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांवों में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं, उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है ।

देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें? कैसे संतुलन बनाएं? जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है, वह इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा । उनके बच्चों को कक्षा दो, तीन, चार में पढ़ने के लिए दो हजार रुपए महीना, चार हजार रुपया महीना, पांच हजार रुपए महीना देना होता है । उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे, तब भी वह अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता, जो उसके लिए एक सपना है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन में मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए । सरकार का यह बजट, जिसमें अनुदानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, इनमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलियतें पहले से फ़राहम की जाती रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की आवश्यकता थी । लेकिन उनमें कटौती किए जाने से यह साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमान जी, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से अपने एक और भाव को कविता के रूप में रखना चाहता हूं । अभी बात नहीं समझ में आ रही है, अभी एक सज्जन बोल रहे थे । वे एक मिनट में शिक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सागर में चले जा रहे थे । सागर और शिक्षा की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं ?

?पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है,

खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है,

कमजोर की आहों को, मज़लूम की आहों को,

कमजोर समझ लेना, अब ज़ालिम हुकूमत के जाने की निशानी है ।?

**डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) :** महोदय, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के बजट की अनुदान माँगों पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, आज मैं इस सदन के समक्ष भारत सरकार द्वारा बजट 2024 में शिक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं और मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिसमें उत्तर प्रदेश के लिए भी कई योजनाएं शामिल है । बजट 2024 में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोक सभा में अपना 7 वाँ केन्द्रीय बजट पेश किया है । इस बार शिक्षा के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

महोदय, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत बजट 2024 की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस बजट में शिक्षा को युवाओं और महिलाओं में कौशल विकास तथा रोजगारपरक बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं । इसके लिए वर्ष 2024 के बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

महोदय, शिक्षा के द्वारा ही कोई समाज सभ्यता के उन्नत शिखर तक पहुँच सकता है । समाज की सभी समस्याओं का दुनिया में एक ही उपाय है और वह है अपने समाज को शिक्षित करना । मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं । नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य है शिक्षा को ज्ञानात्मक होने के साथ-साथ रोजगारपरक भी होना चाहिए । इस अनुशंसा का अनुपालन करते हुए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ।

महोदय, बेरोजगारी देश के सामने एक बड़ी समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही रही है । देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी बेरोजगारी को देश की चार प्रमुख समस्याओं में से एक मानते थे । इस बजट के द्वारा बेरोजगारी की इस समस्या के समाधान हेतु युवाओं एवं महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । इस अनुषंग से देश में युवाओं और महिलाओं में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो कि आज की परिस्थितियों में सार्थक एवं प्रासंगिक हैं ।

महोदय, प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है । इसके लिए परिणामोन्मुख दृष्टिकोण के साथ-साथ एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) का उन्नयन किया जाएगा । भारत की शीर्ष कंपनियाँ 5 साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी । साथ ही 5 हजार रुपये के मासिक मानदेय के साथ-साथ 12 माह की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप भी दी जाएगी ।

महोदय, बजट में युवाओं को शिक्षा ऋण की बहुत ही सार्थक योजना प्रस्तुत की गई है । इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु एक वित्तीय सहायता की व्यवस्था की घोषणा की गई है । यह योजना देश के करोड़ों युवाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी । जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे, उनके लिए यह योजना वरदान साबित होगी ।

महोदय, हमारी सरकार के इस बजट में शिक्षा के द्वारा महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है ताकि महिलाओं की रोजगार में अधिकाधिक सहभागिता हो सके । महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । कामकाजी महिलाओं के लिए महिला हॉस्टल एवं शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी ।

महोदय, अंत में, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बजट में शिक्षा को ज्ञानपरक होने के साथ-साथ रोजगारपरक बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है । यह बजट शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और महिलाओं की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला सिद्ध होगा । इस बजट में शिक्षा के लिए किए गए प्रावधान देश को प्रगति पर ले जाने वाले हैं । इसके लिए मैं अपनी वित्त मंत्री जी आदरणीय डॉ. निर्मला सीतारमण जी का और विशेष रूप से हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भारत रत्न किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के प्रति जो श्रद्धा है, उसके आलोक में मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का उन्नयन कर उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जुड़ सकें । धन्यवाद ।

**श्री सुदामा प्रसाद (आरा) :** सभापति जी, वर्ष 2020 में कोरोना काल के समय नई शिक्षा नीति आई थी । हम देख रहे हैं कि जो शिक्षा नीति लागू की गई है, उससे लगता है कि देश के करोड़ों जो भूमिहीन किसान हैं, कृषि मजदूर हैं, शहरी गरीब हैं जो फुटपाथ पर सब्जी बेचते हैं और ठेला चलाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, ऐसे लोगों को

शिक्षा से दूर किया जा रहा है । देश के अन्य हिस्सों में शिक्षा की क्या स्थिति है, यह मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन हजारों विद्यालयों का मर्जर कर दिया गया । जो गरीब और दलित लोगों के मौहल्ले में विद्यालय थे, वहां भवन और जमीन का अभाव दिखा कर बच्चों का ट्रांसफर दूर के स्कूलों में करके स्कूल बंद करवा दिए हैं । बिहार में ऐसे हजारों विद्यालय बंद किए जा चुके हैं और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव गरीबों के बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है और वे शिक्षा से दूर हो रहे हैं ।

सभापति जी, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शिक्षा को महंगा किया जा रहा है । उच्च शिक्षा में फीस बढ़ाकर, कोर्स की पढ़ाई को महंगा करके यह प्रयास किया जा रहा है कि लोग उच्च शिक्षा से दूर रहें । विश्वविद्यालयों में यूजीसी के जरिए जो ग्रांट दी जाती थी, उसे खत्म करके ?हेफा? लोन दिया जा रहा है कि विश्वविद्यालयों को यह लोन दिया जा रहा है और आपको इसे चुकाना है । इसकी भरपाई के लिए फीस बढ़ाई जा रही है । ऐसे विश्वविद्यालय कैम्पस की जमीन निजी कम्पनियों को किराये पर दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस चीज पर रोक लगनी चाहिए । पहले कम फीस थी तो बच्चे पढ़ लेते थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी । पहले स्नातक का कोर्स तीन साल का होता था, तब छह या सात हजार रुपये में पढ़ाई कम्प्लीट हो जाती थी लेकिन अब स्नातक होने के लिए चार साल का समय कर दिया गया है । इस वजह से इस कोर्स की पढ़ाई का खर्च 30 हजार रुपये तक हो गई है । जन हित में इस फैसले को वापस लेना चाहिए । वर्ष 1917 में पटना विश्वविद्यालय जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, भारतीय उप महाद्वीप के सबसे पुराने जो 7 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से यह एक है । मैं समझता हूं कि उस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सरकार को देना चाहिए । जो विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह हुआ, उसमें बिहार के हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी माननीय प्रधान मंत्री जी से यह अपील की थी कि इसे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए, लेकिन वह दर्जा अभी तक नहीं मिला है । मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए । इस विश्वविद्यालय की पहचान बिहार की अस्मिता से जुड़ी है । मैं समझता हूं कि सरकार को हमारी इस मांग को पूरा करना चाहिए ।

महोदय, हाल ही में नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ, उसने साबित कर दिया है कि यह सरकार न शिक्षा ठीक से दे सकती है और न परीक्षा ठीक से ले सकती है । बिहार और गुजरात सहित चार राज्यों की पुलिस ने कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है लेकिन अभी तक परीक्षा कैंसिल नहीं की गई है । करीब 25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है । मेरी मांग है कि उस परीक्षा को कैंसिल किया जाए और फिर से नई परीक्षा ली जाए ।

**18.00 hrs**

महोदय, एन.टी.ए. परीक्षा लेने में सफल नहीं है, कई पेपर्स लीक हुए हैं, इसलिए इसको भंग किया जाए और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, यह हमारी मांग है । अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप दी जाती थी, उस वजीफे को बंद कर दिया गया है । इसे क्यों बंद कर दिया गया है? इसे फिर से चालू किया जाए ।

महोदय, अन्त में, हम यह कहेंगे कि सरकार शिक्षा का भगवाकरण करना चाहती है । अब विश्वविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति में योग्यता आधार नहीं है, बल्कि चरण भक्ति आधार है । सिलेबस चेंज किए जा रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है । अभी डी.यू. की लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसे भारी विरोध के बाद सरकार ने वापस लिया । हमारे यहां एक चांदी होस्टल है, जहां 200 दलित छात्र रहते हैं । उसकी स्थिति जर्जर है । वर्ष 1990 में ही उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था । आपके माध्यम

से सरकार से हम मांग करते हैं कि नया होस्टल बनाकर दलित छात्रों को दिया जाए । मुचकुन्द दूबे आयोग की जो समान शिक्षा की सिफारिश है, उसको देश में लागू किया जाए । हमारे यहां कस्तूरबा विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति बहुत ही खराब है । वहां भोजन में दोनों टाइम चावल दिया जाता है । इस पर सरकार ध्यान दें ।

महोदय, प्राइवेट स्कूलों के नामांकन में गरीब बच्चों के लिए जो 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, उसको सख्ती से लागू किया जाए ।

महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

**HON. CHAIRPERSON:** Hon. Members, it is 6 o?clock right now. If the Members agree, I extend the time of the House up to 8 pm.

**SEVERAL HON. MEMBERS:** Yes, Sir.

श्रीमती शांभवी **(**समस्तीपुर**) :** मैं भारत सरकार के शिक्षा बजट 2024 के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ । हमारे देश के भविष्य को उज्जवल बनाने और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है । शिक्षा वह नींव है जिस पर हमारा समाज और राष्ट्र खड़ा होता है । यह हमारे बच्चों को न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें नैतिकता, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाती है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । हमारे शिक्षा बजट 2024 का उद्देश्य न केवल शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी सुधारना है । प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना हमारे एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण है । इस वर्ष, हमने स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुधारने और शिक्षण संसाधनों को अद्यतन करने के लिए ₹50,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे बच्चों को एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त हो ।

शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता का निर्धारण करती है । इसलिए, हमने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट रखा है । इसके अंतर्गत शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों, डिजिटल उपकरणों और शिक्षण विधियों से परिचित कराया जाएगा ।

डिजिटल युग में, ई-लर्निंग का महत्व बढ़ गया है । हमने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी । यह पहल उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी शिक्षा की पहुंच सीमित है ।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हमने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी, और अन्य प्रमुख संस्थानों को अधिक संसाधन प्रदान किए जाएंगे ताकि वे विश्वस्तरीय अनुसंधान कर सकें और हमारे देश की विज्ञान और तकनीकी प्रगति में योगदान कर सकें ।

कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है । हमने इस क्षेत्र के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशल सिखाए जाएंगे ताकि वे रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें । यह पहल विशेष रूप से उन युवाओं के लिए फायदेमंद होगी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते ।

महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है । हमने महिला शिक्षा के लिए ₹8,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, महिला विद्यालयों की स्थापना और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा ।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए हमने ₹12,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों के लिए छात्रावासों की स्थापना शामिल है ।

विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए हमने ₹5,000 करोड़ का बजट रखा है । इसके अंतर्गत विशेष शिक्षा कार्यक्रम, सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शामिल है ।

हमने शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है । इसके अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी, छात्रों और शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अवसर और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शामिल हैं ।

नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है । इसके अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर संरचनात्मक सुधार, पाठ्यक्रम में बदलाव और नई शैक्षिक पद्धतियों का समावेश किया जाएगा ।

यह बजट न केवल शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने का प्रयास करता है, बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी उच्चतम स्तर तक ले जाने का संकल्प है । हमारे देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक समृद्धि के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने युवाओं को एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करें । यह बजट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें विश्वास है कि इससे हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा ।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम सभी को मिलकर इस बजट को सफल बनाना है । हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज मेहनत करनी होगी ताकि वे कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें और हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें । धन्यवाद ।

**DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE):** Education is a case of difficult goals and unequal grounds. The disparity in skill levels among students and young people is creating an unequal competitive environment and lacking in job opportunities. This gap in skills not only hampers individual?s career prospects but also affects overall economic development. To address this issue, Government?s intervention is crucial. There is a pressing need for the Government to take proactive measures in equipping students with necessary skills and enhancing their capacity during their graduate studies.

There have been many schemes that the Government has introduced including 'Samagra Shiksha Abhiyan, which is key to States implementing 'Sarva Shiksha Abhiyan 'and allied schemes such as NIPUN, PM-SHRI and PM-POSHAN among the wide range of initiatives. As per the International Labour Organization (ILO), the unemployment rate often rises with higher levels of education because of the lack of associated skills. Between 2005 and 2022, unemployment among individuals with a technical degree increased from 18 per cent to 29 per cent while it rose from 5 per cent to 11 per cent for those without a technical degree. Additionally, more than half of all employed graduates in India are working in low-skilled jobs, as per the ILO report, which compared it to less than one-third in high-skilled roles. From 2005 to 2022, the percentage of graduate degree holders in high-skilled occupations rose from 11 per cent to 28 per cent. However, the proportion of those in low-skilled jobs also increased from 45 per cent to 53 per cent. This is alarming.

One effective strategy would be to implement comprehensive skill development programs that integrate seamlessly into the educational curriculum with vocational training, workshops, and internships tailored to various industries and professions. Moreover, regulation of training and coaching centres is essential to ensure that these institutions provide quality education and training at affordable fees. Particularly in Government schools, where resources may be limited, it is important to establish high standards for these centres to prepare students effectively for administrative services and other competitive fields.

Education is a fundamental right. Along with the infrastructure, quality of teaching, accessibility of institutions, road, bus, facilities, and hostels are also essential. Many of the students from economically deprived status cannot afford higher education. Scholarships, loan facilities, and reservations are essential. Education with emphasis on employment is the need of the hour. I request the hon. Finance Minister to make higher education more affordable. I request the hon. Education Minister to sanction Navodaya and Eklavya Schools in my constituency of Davanagere.

श्री पुष्पेंद्र सरोज **(**कौशाम्बी**)** : मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहता हूँ, जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है । आज हम सब देख रहे हैं कि कैसे शिक्षा की कमी और बेरोजगारी की समस्या ने हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है ।

भारत में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं । 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में बेरोजगारी दर 7.5% तक पहुँच चुकी है । यह चिंता का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षित युवा रोजगार से वंचित हैं ।

हमारे देश में शिक्षा की स्थिति भी बहुत ही दयनीय है । पिछले कुछ वर्षों में, 70 से अधिक परीक्षा पत्र लीक हो चुके हैं । यह शर्मनाक है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में इस तरह की धांधली हो रही है। प्रयागराज में, जब छात्र एनटीपीसी परीक्षा के परिणामों और अन्य परीक्षाओं की धांधली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे, तो उन्हें उनके घरों के अंदर पीटा गया । यह न केवल हमारे संविधान के खिलाफ है, बल्कि हमारे युवाओं के अधिकारों का भी हनन है ।

उत्तर प्रदेश में '69000 शिक्षक भर्ती घोटाला' एक और कड़वी सच्चाई है । इसमें पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया । यह एक बहुत बड़ा अन्याय है और इससे प्रभावित लोग आज भी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं ।

मैं सदन से दो अनुरोध करना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र कौशांबी से संबंधित हैं । पहला, अनुसूचित जाति के छात्रों को नवोदय विद्यालय कौशांबी में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जबकि वे योग्यता के सभी मापदंडों को पूरा करते हैं । यह स्थिति तुरंत सुधारी जानी चाहिए और योग्यता के आधार पर सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए ।

दूसरा, मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि कौशांबी में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए । 2022 में 6 एकड़ भूमि दी गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है । यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है ।

अंत में, मैं हमारे छात्रों और देश के भविष्य के लिए एक शायरी कहना चाहूंगा:

"किताबों में छिपे जो ख्वाब हैं, उन्हें साकार करना है,

हर बच्चे को शिक्षा का हक़ दिलाना है ।

मुश्किलें आएंगी, रुकावटें भी होंगी,

मगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है ।"

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) :** सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बजट में शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

महोदय, हिन्दुस्तान नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है । यहां नौजवान संभावनाएं तलाशता है, लेकिन दुर्भाग्य से नौकरी नहीं मिलने से और पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं से नौजवानों के अन्दर बहुत निराशा है । हमारे माननीय मंत्री जी छात्र राजनीति से आए हैं । वे मेरी इस बात पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि गांव,

ढाणी में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार कैसे मिले । मैं तो यह भी मांग करूंगा कि तमाम नेताओं के बच्चे, तमाम ब्यूरोक्रैट्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर ज्यादा अच्छा हो सके । आप तो जानते हैं कि शिक्षा पर राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हमें बातों के अलावा धरातल पर काम करने की और ज्यादा आवश्यकता है ।

**18.02 hrs**

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

महोदया, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान हमारे दो-तीन मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । भारत के सरकारी स्कूलों में लगभग 8.4 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं । यह संख्या अत्यंत चिंताजनक है और यह शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ।

प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी है । प्राथमिक शिक्षा किसी भी छात्र के शैक्षणिक जीवन का आधार होती है । मैं मांग करूंगा कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की जो कमी है, आप उनके लिए नौकरियां निकालें और सारे पदों को भरें ।

जहां तक शिक्षक-छात्र अनुपात की बात है तो कई सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक पर 60-70 छात्र हैं, जबकि आदर्श रूप से यह संख्या 30-35 होनी चाहिए । इससे शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत रूप से छात्रों पर ध्यान देना असंभव हो जाता है । कई स्कूलों में 10-20 छात्रों पर चार से पांच शिक्षक लगे हैं । जो पावरफुल होते हैं, वे अपने घर या शहर के नजदीक के स्कूलों में अपना ट्रांसफर करा लेते हैं और एक ही स्कूल में 8-10 शिक्षक लग जाते हैं, जहां उनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है । इसको भी आप नीति के अन्दर लाकर ठीक करेंगे । इस असमान व्यवस्था से शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हुए थे, तो शिक्षा को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया । इसका असर पूरी शिक्षा प्रणाली पर पड़ा । जो लोग ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग कर सकते थे, वे इससे जुड़े रहे, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे थे, जिनके अभिभावक सामाजिक व आर्थिक परेशानियों के चलते ऑनलाइन कक्षाओं में समायोजित नहीं कर सके ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर अत्यंत चिंताजनक है । वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा और आर्थिक संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं । इससे समाज में असमानता बढ़ रही है । अत: शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और तकनीक पर बल देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे छात्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

मंत्री जी, मेरे राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित जिन विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. से ग्रांट मिलती है, विगत चार सालों से उनकी ग्रांट बाकी है । आप उन्हें ग्रांट दिलाने के दिशा-निर्देश जारी करें ।

सभापति महोदया, एससी, एसटी, ओबीसी की जो छात्रवृत्तियां देश के अंदर बाकी हैं, उनको चालू किया जाना चाहिए । साथ ही, एससी, एसटी और ओबीसी का जो बैकलॉक है, उसको भरा जाए । आरक्षित वर्ग का एक डेटा मैं बता रहा हूँ । सरकार समानता की बात करती है, लेकिन एक अप्रैल 2024 तक देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक वर्ग के एससी के 736, एसटी 466, ओबीसी के 1446 पद रिक्त पड़े हैं । वहीं गैर शैक्षणिक पदों

का यह आंकड़ा क्रमश: 1466, 914 और 1960 है । मेरी मांग है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित देश के तमाम केंद्रीय संस्थानों में आरक्षित वर्गों के लिए जो पद निहित किए गए हैं, उन्हें जल्द जल्द से भरा जाए ।

शिक्षा मंत्री जी, हम भी कॉलेज, विश्वविद्यालय की राजनीति से यहां आए हैं । कॉलेज और विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे । इसलिए हमारी इच्छा रहती है कि हम छोटे भाइयों के लिए कुछ करें, बेरोज़गारों के लिए कुछ करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को सही शिक्षा मिले । आप प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन और ज्यादा अच्छे प्रयास कैसे हों, यह देखना चाहिए । नीट की परीक्षा के संबंध में हमें आपसे बड़ी उम्मीद थी कि आप उस परीक्षा को रद्द करेंगे । मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया । लेकिन हम आपसे दोबारा मांग करते हैं कि जिद्द छोड़ कर इस परीक्षा को दोबारा कराना चाहिए । जो एनटीए इस परीक्षा को करा रही है, पिछले साल 1.33 करोड़ और इस साल लगभग 50 लाख छात्रों की परीक्षा करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी महज एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और 14 अफसरों के भरोसे चल रही है । इसलिए मैं माँग करूंगा कि इस एजेंसी को बदलें ।

दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जिस तरह से तीन छात्रों की मौत हुई है, इस पर सदन में चर्चा हुई है । आपने इसके लिए एक कमेटी बना दी है । मंत्री महोदय, मेरी मांग है कि पूरे देश के कोचिंग संस्थानों के भवन सुरक्षा, फीस और छात्रों के किराए की एक एसओपी बनाई जाए । कोचिंग माफिया देश के सिस्टम पर हावी हो रहे हैं । उन पर कठोर कदम उठाए जाएं और दिल्ली में दिवंगत हुए तीन छात्रों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भारत सरकार प्रदान करे और आंदोलित छात्रों के साथ शिक्षा मंत्री जी खुद वार्ता करें ।

सभापति महोदया, मेरे राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां पर आपकी सरकार है । नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए जाएंगे । लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव उसके बाद हुए हैं । मेरी मांग है कि राजस्थान में भी छात्र संघ के चुनाव कराएं । आप छात्रों से बात करें और अपनी सरकार को निर्देश दें, ताकि छात्र संघों के माध्यम से अच्छे नेता इस देश को मिलें । हम लोग भी छात्र संघ के माध्यम से आए हैं, आप भी आए हैं । मेरा निवेदन है, आप राजस्थान सरकार से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं । पूर्ववर्ती सरकार के समय राजस्थान में मिड-डे मील योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ था । सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग लेखा विभाग तथा केंद्रीय सहकारी संस्थाओं, कार्यरत कार्मिकों की भूमिका इसमें शामिल थी और मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को ले कर ईडी ने वहां पर छापेमारी भी की थी । चहेती कंपनी को मनमर्जी से टेंडर दिए गए और एक सरगना कमलजीत सिंह राणावत, जिसे आंगनवाड़ी केंद्रों में घटिया फर्नीचर सप्लाई में गिरफ्तार भी किया जा चुका था, उसकी भूमिका भी इसमें शामिल थी । ? (व्यवधान) चूंकि इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र की होती है । तीन आईएएस अफसर ? मुक्तानंद अग्रवाल, भंवर लाल और मोहन लाल यादव व कॉनफेड के तत्कालीन निदेशक वीके वर्मा सहित 40 लोगों के खिलाफ एसीबी ने राजस्थान सरकार से एफआईआर की अनुमकि मांगी है । मेरी मांग है कि इस संदर्भ में भारत सरकार एक एफआईआर सीबीआई में दर्ज करवाए और जाँच करवाए, क्योंकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री की फैक्ट्री पर इस मामले में ईडी की रेड हुई थी । चूंकि मिड-डे मील का वितरण स्कूलों में होता है और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री पर इस मामले सहित कई पेपर लीक के आरोप लगे हैं और वे मिड-डे मील के मामले में संदेह के घेरे में हैं । यह पूरी जांच आपको करनी चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति **:** अब आपकी बात समाप्त होती है ।

श्री मनीष जायसवाल ।

? (व्यवधान)

श्री मनीष जायसवाल **(**हज़ारीबाग**) :** सभापति महोदया, माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मागों पर जो चर्चा हो रही है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदया, वर्तमान की शिक्षा को अगर हम समझें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास में जाएं । पूर्व में इस देश की क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है । इसके लिए दोषी कौन हैं? हम सभी जानते हैं कि पूर्व काल में यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था । हर क्षेत्र में ? चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हम लीडर थे ।

विश्व को हम दिशा दिखाते थे । अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारी सभ्यता पर वार किया, हमारी शिक्षा प्रणाली पर वार किया । अंग्रेजों से जब हमें मुक्ति मिली, वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ और अंबेडकर जी का संविधान बना, तो संविधान में उन्होंने प्रोविजन किया कि सबके लिए शिक्षा होगी, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो । सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा । अभी यहीं से विडंबना शुरू होती है ।

सभापति महोदया, कांग्रेस वर्ष 1947 के बाद आई । इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर ध्यान नहीं दिया । अगर शुरुआत से ही शिक्षा पर फोकस दिया जाता तो शायद हमारे देश में शिक्षा की जो वर्तमान स्थिति है, जिसमें हमारे लोग शिक्षित नहीं हैं, शायद यह स्थिति आज नहीं बनती । इसके पीछे एक सुनियोजित षडयंत्र है । कांग्रेस ने हमेशा इस देश में लोगों को एक वोट बैंक के रूप में ट्रीट किया है । अगर ये लोगों को पढ़ा देते, लोग समझदार हो जाते तो शायद इतनों सालों तक इनको वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभापति महोदया, आज इस देश में युवा पॉपुलेशन काफी है । अगर हम उनके एजुकेशन को देंखे तो एक बहुत बड़ी समस्या है । एक तरफ यह हमारा स्ट्रेन्थ भी है, आज हमारी युवा स्ट्रेन्थ है तो दूसरी तरफ, जब हम एजुकेशन में जाते हैं तो यही हमारे लिए एक बड़ी समस्या का कारण बनता है । लेकिन, उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है -

कश्तियों को बदलने की कोई जरुरत नहीं होती,

केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं ।

महोदया, वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति आती है । इस नई शिक्षा नीति पर देश को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं । अब आप एक तुलना देखिए । जब कांग्रेस की बारी आई, जब कांग्रेस ने इतिहास लिखा, तब उन्होंने क्या लिखा- महाराणा प्रताप की जगह इन्होंने अकबर को महान बताया । शिवाजी की जगह इन्होंने औरंगजेब को महान बताया ।? (व्यवधान) इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी को मिलना चाहिए था, महाराणा प्रताप जी को मिलना चाहिए था, भगत सिंह को मिलना चाहिए था, उसके बदलने में इन्होंने बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे लोगों को महान बताने का काम किया । यह इनका संस्कार है । ? (व्यवधान)

महोदया, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू की है । मुझे दो मिनट का समय दीजिए ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात पूरा कीजिए ।

श्री मनीष जायसवाल **:** सभापति महोदया, अभी आप आरटीई का हालचाल देखिए । राइट टू एजुकेशन में किस प्रकार से कांग्रेस ने बेईमानी की है । आज राइट टू एजुकेशन, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वह मिशनरी के

स्कूल्स हों, चाहे वह किसी भी माइनॉरिटी के स्कूल हो, उन पर राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब बच्चों को, उस समुदाय के गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है या नहीं है । मंत्री जी अभी यहां पर है । मैं उनसे मांग भी करूंगा कि कांग्रेस की इस भूल को वह सुधारने का काम करें ।

सभापति महोदया, अभी सौगत दादा नहीं है । वह यहां से चले गए हैं । उन्होंने आरएसएस पर प्रहार किया कि आरएसएस शिक्षा में अननेसेसरी दखलंदाजी करती है । विद्या भारती, जो सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन करती है, पूरे देश में सबसे अच्छी और आदर्श के साथ अगर किसी को शिक्षा प्रदान की जाती है तो इन स्कूलों में की जाती है । इसके पीछे आरएसएस का डायरेक्टली हाथ है ।

सभापति महोदया मैं मानता हूं कि शिक्षा की जो स्कीम हैं, वह इसकी नींव है । मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षिका है और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं ।

सभापति महोदया, आज झारखंड में पैरा-शिक्षकों की तरफ देखिए । बहुत सारी सरकारें आईं । लोगों ने उनको परमानेंट करने की बात कही, उनको अच्छा वेतनमान देने की बात कही, लेकिन आज तक उनको कोई भी राहत नहीं मिल पाई है । झारखंड के हालात पर मैं दो मिनट चर्चा करना चाहता हूं ।

माननीय सभापति **:** आप अपनी बात समाप्त करिए ।

श्री मनीष जायसवाल **:** महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा । आज झारखंड में, स्कूल्स में संडे की बजाए फ्राइडे को छुट्टी हो रही है । वहां हिंदू स्कूल्स को उर्दू स्कूल्स में बदला जा रहा है, और तो और स्कूल के गेट पर मीनार का शेप बना दिया गया है । ऐसी व्यवस्था में हम शिक्षा को सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं?

मैं कोयले के क्षेत्र से आता हूं । हमारे यहां मां छिन्नमष्तिका देवी का प्रभाव है । मंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर बहुत सारी कोल माइन्स हैं, तो एक इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स अगर हमारे यहां रामगढ़ में संचालित हो जाए तो बहुत लाभ होगा । साथ ही साथ, मैंने सलाह दी कि आरटीई में जो विसंगति है, जो माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन्स को छोड़ दिया गया है, उनको ऐड करना चाहिए । बहुत सारी बातें बोलने को थीं, लेकिन समय की कमी है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):** Thank you, Madam. A direct connection can be drawn between the policies of this Government and the continuing educational backwardness of Muslims. In both higher education and schooling, Muslims want to get formal education, but because of Government?s apathy and negligence, Muslims drop out of the educational system sooner than children of any other community.

The Government?s UDISE data that covers school education, says that Muslim students? representation gradually declines from Class VI onwards, reaching its lowest in Classes XI and XII. Enrolment percentage of Muslim students drops from 14.42 per cent in upper primary Classes VI to VIII to 10.76 per cent in higher

secondary Classes XI and XII. Only 76.37 per cent of Muslim students continue after elementary school compared to the national average of 81.26 per cent.

Madam, 28 States have a GER of 80 per cent for primary education, but only 12 States achieve 80 per cent at the secondary level. This shows a clear systemic bias against Muslims. Muslim children do not have the means to cross beyond primary education. But the Government has limited pre-matric and post-matric scholarships to Class IX and above. I want to know this from the Modi Government. Do the Muslims of this country have a fundamental right to education under Article 21A or do you want to make second-class citizen status of 17-crore Muslims permanent?

There are 1.79 lakh fewer Muslims pursuing higher education today. That was not the case till 2021. You unleashed your ideology on the biggest minority. I want to give them some bad news and good news to the nation. Those who say, we, Muslims do not teach our girls and oppress our women are wrong. I am quoting data. I can challenge anyone. More Muslim girls are enrolled at school level than boys. The Gender Parity Index for the rest of the population is 0.93, but for Muslims it is 0.99. The sad fact is that these girls and boys are not prevented from educating themselves because of some ?evil Muslim men? but because of crushing poverty and absence of Government support.

This Government?s Education Policy talks about universal access to education and ensuring universal literacy in India by 2047. But how can you achieve it when 14 per cent of the population is dropping out of education after primary level? How can you achieve it when about 25 per cent of rural youths in the age group of 14 to 18 cannot read a Class II level text fluently in their regional language, while more than half struggle with division (3-digit by 1-digit) problems, a skill usually expected to be achieved in Classes III and IV.

Over the years, there has been a shift in momentum towards private schools. Government data indicates a decrease in the share of Government schools in the elementary category from 87 per cent in 2006 to 62 per cent in 2022. Maybe the Mughals are responsible for this. This means that the Government has decided to leave the poorest Indians to for-profit schools and abandoned its responsibility under the RTE.

Madam, for Kendriya Vidyalaya, the Government has allocated Rs. 9,030 crore and for Navodaya Vidyalaya Rs. 15,800 crore. How is it that you have a vacancy of 6,653

in teaching and non-teaching staff? Would you blame Babar for this? I am sure that you will do it.

In Navodaya Vidyalaya, Rs. 15,800 crore have been allocated whereas 4,675 vacancies are there. The sanctioned strength in Navodaya Vidyalaya is 34,354 and in Kendriya Vidyalaya it is 56,703. You have passed a law five months ago about cheating and malpractice, but you are so great in implementing it that it took you five months. Maybe, you were waiting for the NEET paper to leak. This is what I can say about it.

I will show the classic example of favouritism over here. Jamilia Millia Islamia is allocated Rs. 3 lakh per student, Aligarh Muslim University is allocated Rs. 3.9 lakh per student and BHU gets Rs. 6.15 lakh per student. Why this favouritism? Rs. 1,558 crore have been allocated under the PM-USP. May I request the hon. Minister, through you Madam, to please have some liberal mindedness so that more Muslim students can get this?

In HEFA scheme, Rs. 39,720 crore have been sanctioned for 403 institutions out of which 22 are IITs and 12 are AIIMS. These people can pay back money. How can Jamia Millia and AMU pay back money? I do not know who has told you this. More importantly, 29 per cent of graduates and above in India are unemployed, and half of them do not do low-skilled jobs. This is sorry to understand.

May I come to Jamia Millia? There is no permanent Vice Chancellor in Jamia Millia. Why is it so? Why is it that a Registrar is not even qualified to hold that post? Why is it that a Standing Council is running the Jamia Millia? Please enquire why Rs. 438 crore have been given in HEFA? Has a competent construction company given it or someone has given it on the basis of favouritism? How is it that the present status of 100-years old Jamia Teachers Association, their office has been sealed, their body has been dissolved, there is no fund to run the University and to pay outsourcing staff, for building maintenance and there is no research grant? I demand that the Registrar and the Standing Council be immediately removed.

Now, coming to the Aligarh Muslim University, ? (*Interruptions*) AMU daily wage workers are 1,400 and temporary are 1,559. Why do you not regularize them? Why are you not giving separate funds, hon. Minister Garu, to the AMU branch at Murshidabad, in Malappuram and in Kishanganj? Do you want them to be closed?

As of July, 2023, the share of ST/OBCs in senior professors is even lower. I am just giving the figures. In Central Universities, there are 66.29 per cent general teaching

staff and SC/ST/ OBC is only 30 percent. In NIT, it is only 67 per cent and 33 per cent are ST/OBC. In IIT, it is 84.5 per cent in general category and for SC/ST/OBC it is 14 per cent. For IIM, it is 86.83 per cent in general and 11 per cent for SC/ST/OBC. Who is responsible for it? You are running the Government for 10 years. ? (*Interruptions*)

Lastly, NCERT has been given Rs. 500 crore. ? (*Interruptions*) I dare say that this Government has been distracted with fudging textbooks and teaching propaganda to children. ? (*Interruptions*)

Do you want me to sit down? Do you want to say it on record? ? (*Interruptions*) NCERT has removed the reference to Babri Masjid and 2002 riots. Why should people not learn from mistakes of the past? Should our children not learn about the Gujarat pogrom and the massacre of minority Muslims? Those who ignore history?s mistakes are bound to repeat them. It has made-up history and argued that Indians did not have migrant DNA. ? (*Interruptions*)

The truth is that the DNA shows that there were four waves of migration to India, namely from Africa, Iran, South-East Asia and Asian pastoral or the Aryans. There is scientific consensus on this. ? (*Interruptions*)

May I request this from the hon. Minister, through you? Why do you want to hide the killers of Mahatma Gandhi? Do you want to make Godse a freedom fighter? Let the children know who is a *deshbhakt*. Why are you trying to protect your ideological organisation?

In the end, I would appeal to the Government to fix their priorities. You need to construct more government schools, improve quality of schooling, and you need to make active efforts to reduce dropout rate of Muslims. You have your job cut out for you. Do not waste your time. Do not use school textbooks as a battleground for petty ideological quarrels. ? (*Interruptions*) The future of our children depends on the quality of their education. ? (*Interruptions*)

May I request the hon. Minister to concentrate on 14 per cent Muslims who have the highest dropout rate? We want this nation to become Viksit Bharat, but if you keep on unleashing the ideology of hatred, then you cannot become Viksit Bharat. Thank you, Madam.

एडवोकेट चन्द्र शेखर **(**नगीना**) :** माननीय सभापति जी, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं और जवाब भी उनको ही देना है ।

महोदया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए । सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत् उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए । एक क्लास, एक सलेबस होना चाहिए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है । जब पढ़ेगा नहीं भारत तो कैसे बढ़ेगा भारत? एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के बजट में कटौती की गई है । मेरी मांग है कि इसे बढ़ाया जाए और नए छात्रावास बनाए जाएं । मैं यूपी से आता हूं । हनुमान बेनिवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं । राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं ताकि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन सके और अपने हक के लिए लड़ सके । एससी, एसटी वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, इसका आंकड़ा अभी बहुत कम है ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र में नेटोर और नजीबाबाद में सरकारी डिग्री कॉलेज बनाया जाए । सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया जाए । भादोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए । नगीना लोकसभा क्षेत्र में नए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, आईआईटी और आईआईएम की भी स्थापना की जाए । आईआईएम में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए । हमारे साथी भी इसके बारे में कह रहे थे, इनकी इच्छा है और यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए । छात्रों को पोषण और विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाने चाहिए । स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी के रिक्त पदों को भरा जाए । जब टीचर होंगे तभी तो वे पढ़ाएंगे, टीचर कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं । एससी, एसटी छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा दी जानी चाहिए । स्किल डेवलपमेंट सैंटर खोले जाने चाहिए । कॉलेजों और आईआईटी में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए । बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलिएंट थे, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है ।

हमारे क्षेत्र में नवोदय स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए । यह ग्रामीण क्षेत्र है । हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सैंटर्स खोले जाएं जिससे शिक्षकों की कमी दूर होगी और बेरोजगारी भी घटेगी । बालिकाओं और महिलाओं के लिए अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक होस्टल उपलब्ध कराए जाएं । आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र, जो पढ़ाई में पीछे हैं, उनको विशेष सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें । पहली कक्षा से 12 वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए जिसमें संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मूल अधिकारों पर शिक्षा दी जाए । लोग जानते ही नहीं हैं कि उनके अधिकार क्या हैं और कर्तव्य क्या हैं क्योंकि संविधान पढ़ाया ही नहीं जाता है ।

स्कूलों में जातीय सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए । ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में ग्राउंड नहीं होगा, स्पोर्ट्स टीचर नहीं होंगे तो उनका शारीरिक विकास कैसे होगा? मिड-डे-मील स्कीम में भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाए क्योंकि दूषित मिड-डे-मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं और इस तरह की खबरें अखबारों में आती रहती हैं । हमारे साथी नागौर से हैं, हनुमान बेनिवाल जी जो कह रहे थे, इनकी मांग को भी माना जाए कि जिन लोगों ने घोटाला किया है, उनकी जांच हो और उन पर मुकदमा चले ।

राज्य में शिक्षा अधिकार नियम, 2002 के तहत छ: से 14 साल के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाए और इसका पालन सख्ती से किया जाए । जो संस्थान इस अधिनियम का पालन नहीं करते, उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए । शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षकों पर होने वाले जातिगत भेदभाव को रोका जाए । बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जाएं । घुमंतू जाति के बच्चों के

लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं । छात्राओं के लिए आत्म रक्षा और खेल की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

महोदया, एसपीक्यूईएम योजना को पुन: आरंभ किया जाए । यह योजना शिक्षा की गुणवत्ता और सुधार की महत्वपूर्ण योजना थी जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था । इस योजना के अंतर्गत एनआईओएस के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त और हाई स्कूल में इंटरमीडिएट पढ़ाई कराने का प्रावधान था । एनआईओएस एचआरडी मंत्रालय के अधीन चलने वाला ओपन बोर्ड है और इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है । आप मनुस्मृति शुरू करवाना चाहते हैं, यह गलत है । हम इसका विरोध करेंगे अगर कोई इस तरह का कदम उठाएगा । यह अच्छा नहीं है ।

मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी रामपुर में थी । आप शिक्षा की बात करते हैं, आज़म साहब, आप देखिए, राजनीतिक कारणों से जेल में बंद कर दिया है और उनके साथ किस तरह का अत्याचार हो रहा है । मैं मांग करता हूं कि राजनीतिक कारण छोड़कर उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का सरकार का लक्ष्य गलत है । इस तरह से आप रोक नहीं सकते हैं । बीएड के बच्चों का भविष्य खराब हो गया है । इनकी संख्या करोड़ों में है । एक नए आदेश के तहत प्राइमरी स्कूल में भर्ती नहीं हो सकते । इससे बीटीसी और बीएड के बच्चे परेशान हैं । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर ध्यान दें ।

मैडम, मेरा आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट आग्रह है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी लोग सरकारी लाभ लेते हैं, उन सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आएं । सरकारी स्कूलों में एक बड़ा भाग पढ़ता है । प्राइवेट स्कूल में नहीं घुस सकते हम लोग । बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं आज याद करता हूं, मां सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले जी को आज याद करता हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला । मैं आपसे फिर कह रहा हूं । संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाओ । बाबा साहब ने कहा- ?शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा, दहाड़ेगा? । शिक्षित होने के लिए हम लोग बोल रहे हैं । इसके साथ खेलना और इसका बाजारीकरण रोका जाए, साथ ही सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे । शिक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि आप ग्रामीण बच्चों पर ध्यान दें । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

**SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN):** Madam, thank you for giving me the opportunity to speak in this august House.

I would like to thank the voters of my constituency and the leaders of my Party.

Madam, I rise to speak on the Demands for Grants pertaining to the Education Ministry for the year 2024-25. The Government expenditure on education as a percentage of GDP remains alarmingly low. The Economic Survey 2023-24 highlighted a mere 2.7 per cent allocation, significantly below six per cent of the National Education Policy 2020. This underspending directly impacts the quality of education. The Union Budget has marginally increased the funding for higher education, allocating Rs. 47,619 crore, which is less than one per cent of the total budget. This funding is inadequate given the sector's growing demands. Public institutions face severe resource constraints. The neglect of R&D, lack of focus on

skill development, equity issues and absence of meaningful administrative reforms undermine its potential.

The Centre should prioritise funding and strengthen the existing universities before creating new ones as neglecting the current institutions in favour of new ones is counterproductive. Please remember the Karnataka education system has produced stalwarts like Sir Visvesvaraya and Infosys?s Narayana Murthy.

Furthermore, the scholarships, grants and financial aid programmes for the marginalised and economically disadvantaged groups have not seen significant enhancements. Ensuring equal access to quality education is crucial for social mobility and reducing inequality, which the Budget does not adequately support. In this background, I recall the UPA?s achievements like enactment and implementation of the Right of Children to Free and Compulsory Education that encouraged equitable education to all. This was the fulfilment of Dr. B.R. Ambedkar Ji?s dream to have a law on primary education. I would also like to highlight a long-pending proposal for the establishment of an Indian Institute of Technology (IIT) in the Hassan Constituency. Having an IIT will create a knowledge-based ecosystem that generates employment opportunities and contributes to the local economy. The State Government has notified and acquired land for the IIT.

Coming to my constituency, in the Taluks of Arsikere, Arakulgud, Bellur, Channarayapatna, Hassan, Holenarasipura, Sakaleshpura and Kadur, around 15 schools are there under the PM SHRI Scheme. Our district administration has proposed 151 PM SHRI schools. I request the hon. Minister, through you, to kindly approve 25 PM SHRI schools. It is my humble request. I urge the Government to increase this limit to avoid regional disparities and ensure fair distribution of resources.

Due to heavy rainfall in Karnataka and in my Hassan Constituency, around 200 mid-day meal preparation rooms have been damaged. I urge the hon. Minister to allocate special funds for their repairs.

Moreover, the Jawahar Navodaya Vidyalaya school in my constituency, which has been serving the students for 37 years, urgently needs renovation.

In conclusion, increasing our investment in education is essential for our nation's progress. Let us commit to making quality education accessible to all.

Thank you.

श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी **(श्रीनगर) :** धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एजुकेशन के ग्रांट्स पर जो डिस्कशन हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करते हुए पहली बात माननीय मंत्री जी के नोटिस में पहुंचाना चाहूंगा कि जो नीट का एग्जाम होने वाला है, शायद 11 अगस्त को नीट का एग्जाम हो रहा है, उसके लिए इन्होंने बच्चों के सेंटर्स आउटसाइड स्टेट्स रखें हैं । हरेक स्टेट से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं । इसी तरह से जम्मू-कश्मीर से भी बच्चे कह रहे हैं कि उनके सेंटर्स आउटसाइड स्टेट रखे गए हैं । वे 1000-2000 किलोमीटर के फासले पर रखे गए हैं । उनके लिए इतनी शॉर्ट नोटिस में लॉजिस्टिक वगैरह के साथ ट्रैवल करना लगभग नामुमकिन होगा । मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए या नीट के टेस्ट के लिए सेंटर्स उनके अपने ही स्टेट्स में रखे जाएं ।

दूसरा, जम्मू-कश्मीर में इन्होंने जो एकेडमिक ईयर चेंज किया है, वह अपनी मनमर्जी से किया है । जम्मू में एकेडमिक ईयर मार्च से शुरू होता है । वह ठीक है । हमेशा से वैसा ही चला आ रहा है । कश्मीर वैली में वेदर के लिहाज से हमारी जो एनुअल वेकेशन होती है, वह विंटर वेकेशन होती है । जैसे ही एकेडमिक शुरू होता है, उसके तुरंत बाद ही हमारा ईयरली वेकेशन शुरू हो जाता है । उससे जो वेकेशन का पर्पस होता है, वह सर्व हो जाता है, क्योंकि हमारे विंटर्स वेकेशन प्रोलांग्ड होते हैं । हमारी समर वेकेशन नहीं होती है । हमारी जो ईयरली वेकेशन होती है, वह विंटर वेकेशन होती है । ये जो एकेडेमिक ईयर चेंज करके मार्च में लाए हैं, उससे वेकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वह खत्म हो गया है । उससे पर्पस सर्व नहीं होता है । इसके अलावा बच्चों पर डबल एफर्ट्स का लोड पड़ता है । उनसे गुजारिश है कि वहां के क्लाइमेट को, वहां की ज्योग्राफी को नजर में रखते हुए एकेडमिक ईयर को चेंज करें, जैसे वह पहले था । हर चीज में एक निशान, एक मुल्क वगैरह लाना, अनरीजनेबल चीजें लाना सही नहीं होता है । हमारे रियासत में जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, उनके हवाले से कहना चाहता हूं कि उनके लिए कोई क्लियर कट स्कीम और कोई क्लियर कट रोडमैप लाया जाया । जम्मू-कश्मीर रियासत में जो पीएचडी होल्डर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, वे ओवर एज होते जा रहे हैं । अभी तक उनको रेगुलराइज करने के लिए न कोई स्कीम है और न कोई पॉलिसी है । उनके लिए कोई पॉलिसी लाई जाए । उनमें से बहुत सारे ओवर एज हो रहे हैं । बहुत सारे ओवर एज हो चुके हैं । उनकी सर्विसेज को रेगुलराइज किया जाए और उस हवाले से काम किया जाए ।

महोदया, इसी तरह से माइनोरिटीज के हवाले से जो अभी बात हुई, यहां पर जो स्कॉलरशिप थी, फेलोशिप थी, जिनको यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, उनको जो ऐड मिला करता था, उनको या तो बंद कर दिया गया है या 90 परसेंट हद तक फंडिंग कम की गई है । 10 स्कीमें ऐसी हैं, जिनसे पूरे मुल्क में माइनोरिटीज फायदा उठाती थीं, चाहे वह मौलाना आजाद स्कॉलरशिप हो, पढ़ो प्रदेश स्कीम, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, नया सवेरा, नया उड़ान स्कीम, हमारी जो स्पैम स्कीम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम था, उनको या तो बंद कर दिया गया है या 90 परसेंट हद तक उनकी फंडिंग कम कर दी गई है । यह माइनोरिटीज के साथ ज्यादती है । ये चाहते हैं कि माइनोरिटीज न पढ़ें । उनके एजुकेशन के हवाले से ये एक जंग लड़ना चाहते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है । मैं आपके हवाले से गुजारिश करना चाहता हूं कि ये इस पॉलिसी से बाज आएं । जो माइनोरिटीज पीछे रह चुके हैं, उनको एजुकेशन में सपोर्ट किया जाए, फंडिंग की जाए, उनका हाथ पकड़ा जाए, ताकि वे आएं और इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन करें तथा वे पढ़-लिखकर अपने सही मुकाम तक पहुंचें ।

सभापति महोदया, मुझे बोलने के लिए वक्त देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सतीश कुमार गौतम **(अलीगढ़) :** सभापति महोदया, आज सदन में जिस तरह से शिक्षा क्षेत्र की बात हो रही है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से केंद्र शासित यूनिवर्सिटी है । जब यह यूनिवर्सिटी बनी तो उसकी स्थापना से पहले बीएचयू केंद्र शासित यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी । बीएचयू में

एससी, एसटी, ओबीसी सब बच्चों को आरक्षण मिलता है । लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न ही एससी को आरक्षण है, न ही एसटी को आरक्षण है, न ही ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया था कि ये अल्पसंख्यक दर्जा है । जब वह केन्द्रशासित यूनिवर्सिटी है, तो उसको अल्पसंख्यक का दर्जा मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि केन्द्र सरकार के पैसे से ही यूनिवर्सिटी चलती है । उसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को आरक्षण न देकर उनकी शिक्षा को भटकाया जा रहा है, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं ।

एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की बात करती है । दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के एक शिक्षा मंत्री ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों का गला घोंटने का काम किया है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब बीएचयू में आरक्षण है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए । मेरी इस सदन के माध्यम से यह मांग है ।

माननीय सभापति **:** श्री राजकुमार रोत ? उपस्थित नहीं ।

सुश्री इकरा चौधरी जी ।

**SUSHRI IQRA CHOUDHARY (KAIRANA):** Thank you, hon. Chairperson, Madam. I rise to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Education. While the Union Ministry of Education recently celebrated the 4th anniversary of NEP ? 2020 with a week-long ?Shiksha Saptah?, this grandstanding does nothing to address the stark reality. And as a Member who has recently been a student too, I would like to shed some light on the facets that are not as rosy as the Government might think.

Despite the NEP-2020?s clear directive and the Kothari Commission?s long-standing recommendation for six per cent of the GDP in education, the Ministry of Education?s allocation is less than half of what has been recommended. The biggest cut has been for the University Grants Commission, which saw a 61 per cent dropping from Rs. 6,409 crore to only Rs. 2,500 crore this time. This will affect the higher education of our country.

Madam Chairperson, in 2020, India?s average learning-adjusted years of schooling was 7.1 years, lagging behind countries like Mexico, Kenya, Sri Lanka, Iran, UAE and even Palestine. The foundational skills are alarmingly weak among 14 to 18 years old. About 25 per cent of those surveyed could not read a Standard 2 level text in their regional language, and only 43 per cent could solve a simple division problem. Shockingly, nearly 43 per cent of undergraduate students also struggled with basic division. This report is a testament to the fact that in reality, our education system has failed to educate a large section of the population, especially the students from the underprivileged backgrounds dependent on the State-run education.

Madam Chairperson, higher education especially for women is crucial to gaining empowerment and employment. The AISHE report shows that only 10.4 per cent of colleges in the country were exclusively for female. In the constituency that I represent, and in other such areas in the country, patriarchal beliefs have prevented women from accessing co-ed colleges. Therefore, we need women-specialised institutions so that women can get educated and can go further in the society.

महोदया, पिछले सात सालों में देश भर में 70 पेपर्स लीक हुए हैं, जिससे दो करोड़ युवाओं की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं । ?नीट?, ?नेट? और अन्य ऐसे पेपर्स लीक हैं, जिससे हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है, जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है ।

इसी के संदर्भ में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है, वह 7.6 प्रतिशत हो गई है । वर्ष 2022 की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया था । A similar situation is with the NET and the DU?s LLB examinations. The abrupt cancellation and the mismanagement of the NTA are crucial issues that the Government needs to look into.

Madam Chairperson, I would also like to bring to your attention the discrimination against minorities in this budget allocation, especially in the case of closure of the Maulana Azad Foundation despite the Prime Minister?s vision of minorities progressing with ?Quran in one hand and computer in the other?. This undermines out efforts to boost the educational opportunities. What we also need in today?s time is the quality STEM education, as outlined by India?s National Education Policy ? 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for the 21st century challenges.

But, Madam, only 18.4 per cent schools have functional computer labs and there is a significant gender gap in STEM enrolment with only 28 per cent of females compared to 36 per cent males. While the Government now promotes digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party?s Government under Akilesh Yadav Ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012 effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. एजुकेशनल फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति काफी हद तक खराब है । हमें निचले 30 परसेंट देशों में रखा गया है । The intertwining of political agendas with Indian higher education has worsened the education system under the current Government. Key historical and scientific facts are being erased from textbooks to advance a certain kind of narrative. Mughal history is continuously distorted and erased but notably Darwin?s theory was removed from class 9 and 10 syllabuses in the 2021-22 academic year,

and the topic of evolution was completely removed from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India?s educational ethos.

Madam, when we are competing in the world with the firstclass countries, we also need to look into why our students need coaching inspite of having schools and higher education and those institutions funded by the Government. The incident of three students dying in the UPSC coaching centre has once again exposed the hard reality and plight of a significant segment of our population. These young individuals hopeful of securing Government jobs endure poor living conditions in places like Kota and Rajender Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcoming of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The National Education Policy fails to address why students rely on coaching in the first place.

So, Madam, I would like to end with certain demands to the Minister for my constituency. मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज, कैराना में बीएड, एलएलबी जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिलाएं अपने रोजगार खुद ढूंढ सकें । जनपद शामली के कैराना और ऊन ब्लॉक तथा सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं । मैं जनपद शामली में नया केन्द्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालन खोले जाने की मांग करती हूं । मां शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैम्पस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जाने की मांग करती हूं । उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का समायोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए, ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके ।

**SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE):** Hon. Chairperson, Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the general discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Education for the year 2024-25.

Madam, I am a first time Member of Parliament and I am really grateful that my first speech is on education itself.

Madam, the vision of the Prime Minister recognises that education must be amongst the foremost pillars in order to build Viksit Bharat.

Post-Independence, for reasons best known to those in power at the time, we continue to persist in the submissive system that was incorporated during the British Raj and that same system was strengthened until of course we had a complete transformation and overhaul with the New Education Policy in 2020.

With this overhaul, we had rekindling of the creative spirit in the Indian children. We had our interests and passions set free and most importantly, we have been allowed to move on to the path of knowledge which is the central tenet of the Bharatiya principle jnana marga.

Alongside this, it is extremely laudable that as part of our global goals, we also have understanding within the global community as well.

This is something that we are aspiring to achieve in conformity with the UN Sustainable Development Goals of ensuring quality and equitable education for all.

Madam, the Demands for Grants reflect these, especially the increased spending on education.

Since 2014, we have had an increased allocation of around 4.7 per cent and in this year particularly, this increase is approximately seven per cent. Nearly Rs. 73,000 crore is being spent on school education and Rs.47,619 crore is being spent on higher education.

Madam, this Demand for Grants reflects a further strengthening of transforming the Indian education system with an emphasis on skill-based learning, a much-needed technology-driven teaching environment and an increased investment in school education. It promises a robust system which will empower the future generations to build successful careers by fulfilling their aspirations.

It is a universal truth that education is a bullwork against perpetuation of poverty among the weaker sections of our society. In this matter, a huge impetus being given to accessibility to education is something which we must appraise. The Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Protsahan Yojana and a specific mention of Rs.10 lakh in the Budget for helping the youth who do not qualify for any other Government schemes and policies are enduringly the central principles of this Government.

Alongside this, we know that there is a huge push towards improving the infrastructure and quality institutes. For the last 10 years, we have seen that the number of universities have grown up from 400 to 1,100 and this Budget furthers the same idea as well.

PM Shri School, that is, Schools for Rising India, the National Mission on Education through ICT, Malaviya Mission Teacher Training Programme ? all of these contribute towards enhancing quality education through technology-based

learning and they have been given a huge push. The Samagra Shiksha Abhiyan, the allocation of nearly Rs.500 crore for the addition of the world-class institutions and the increased spending in the central universities etc., truly reflect our continued push towards building a robust infrastructure to back up our educational needs.

Madam, I want to say something which is very important for my constituency, Mysore. There is a need for fostering a spirit of innovation. In this matter, it is indeed enduring that the research and innovation initiatives have seen a marked increase from Rs.193 crore to Rs.355 crore. Alongside this, Centre of Excellence in Artificial Intelligence, promotion of academic research collaboration and the grants to Multidisciplinary Education and Research in Technical Education ? all of them have received a huge push which is indeed much more enduring as well.

Madam, my last point is not particularly connected with the Ministry of Education. Nonetheless, it is very important because we have finally seen a shift in the perspective in which education needs to be seen. Finally, we are looking at the moment when we enter into the education system all the way up to the point from which we start our careers as a continued process. It is indeed a laudable thing. This Budget also reflects it well by giving us internship in the top 500 companies as well as the Prime Minister?s package for employment and skilling.

I represent Mysore Kodagu Constituency. Mysore, as a city, has many legacies in respect of educational institutions. It has made a name for itself as an education hub even in modern times. This city, however, aspires for greater contribution and we require many more economic drivers. So, my kind submission to the Minister for Education is to set up an IIIT in Mysore. It will ensure the educational base for fostering the IT hub. Mysore has that much of potentiality.

Madam, I also represent Kodagu. Kodagu University is one of the newer universities in our State. Recently, we have seen tragedies happened with our brothers and sisters in Kerala. The University at Kushalnagar can serve as a centre for ensuring that climate-resilient crops. The infrastructure can be developed there to do research on climate-resilient crops. Being at the doorstep of Western Ghat, it is natural that it should be there. With these words, I conclude. Thank you once again for giving me the time.

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया । महोदया, देश में शिक्षा का जो हाल है, वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार से देश ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी आनी चाहिए थी, वह नहीं आ रही है ।

आज हम सब यहां हैं । मैं एसटी केटेगिरी से आता हूं । मैं यहां आ सका हूं तो इसके दो कारण हैं । पहला है, मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा है शिक्षा । अगर शिक्षा नहीं होती तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता ।

सभापति महोदया, अगर शिक्षण व्यवस्था की बात करें और विशेषकर आदिवासी इलाके की बात करें तो सबसे पहले यह देखा जाएगा कि वहां की भौतिक स्थिति क्या है । वहां पर कमरे नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारें नहीं हैं । वहां पर अध्यापक तक नहीं हैं । हम बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं । हम कहते हैं कि देश ग्रोथ कर रहा है, देश विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70 परसेंट विद्यालयों को खाली करा लिया जाता है, क्योंकि वह बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं होती है । आज देश के ये हालात हैं ।

मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूँ । मेरा संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा है । वहां पर 78 परसेंट आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि देश में एक ऐसा कोना भी है, जहां चाहे हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, वहां स्थिति यह बनी हुई है कि एक कमरे के अंदर तीन-तीन, चार-चार क्लास के बच्चे बैठते हैं । छठीं, सांतवीं, आठवीं और नौवीं क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं और हम दावा कर रहे हैं कि हम देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं । अगर एक कमरे के अंदर चार क्लास के बच्चे बैठेंगे तो टीचर किसको पढ़ाएगा और वे बच्चे डिग्री प्राप्त करके कहां जाएंगे, आगे जाकर क्या करेंगे? उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है ।

सभापति महोदया, वर्तमान में देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति की पॉलिसी लाई गई है, वह मेरी समझ के अनुसार निजीकरण को आगे बढ़ाने की नीति है । इसमें एक लॉ दिया गया है कि जो 6 साल का बच्चा होगा, वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा । देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय का कौन सा व्यक्ति ऐसा है, जिसके यहां जब 6 साल का बच्चा होगा, तभी वह एडमिशन कराएगा? ऐसी स्थिति में आने वाले 10 सालों के बाद सरकारी संस्थाएं खत्म हो जाएंगी । आज प्राइवेट स्कूल में तीन साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है और हम नई शिक्षा नीति में यह कानून ला रहे हैं कि जो बच्चा 6 साल का होगा, उसके बाद ही वह पहली क्लास में एडमिशन लेगा । वह कहां जाएगा? आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति लाई जा रही है, वह कहीं न कहीं घातक है ।

माननीय सभापति महोदया, देश के अंदर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय हैं । हम मानते हैं कि देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है, तो वह नवोदय विद्यालय से मिला है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केन्द्रीय विद्यालय हैं, उसमें पूरे देश से 8 लाख 88 हजार आवेदन आए थे, लेकिन प्रवेश 75 हजार 703 बच्चों को ही मिला है । इसका मतलब यह है कि केवल 8 परसेंट बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है ।

**18.59 hrs**

(Hon?ble Speaker *in the Chair*)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री राजकुमार रोत **:** अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है । मैं आदिवासी इलाके से आता हूँ । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आपको इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको औवेसी जी सलाह दे रहे हैं ।

? (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन **(**पूर्णिया**) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ । मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय जी को, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं ओर जो प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, उन दोनों की गुणवत्ता के बारे में बताना चाहता हूँ ।

आपसे मेरा आग्रह है कि शिक्षक की गुणवत्ता को जब तक आप समय-समय पर तीन साल, दो साल, चार साल या छह साल, तीन पीरियड के अंदर उनका एग्जामिनेशन या उनकी ट्रेंनिग नहीं लेंगे तो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा । सरकारी स्कूलों में और कॉलेजेज़ में 400 से 800 बच्चे हैं, लेकिन क्लास के हिसाब से सिर्फ सात, आठ या नौ रूम्स हैं । स्कूल और कॉलेज में स्थिति यह है कि मात्र 20 प्रतिशत बच्चियों के लिए शौचालय बने हुए हैं ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, आप छह बार के मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो आपको पता होगा कि स्कूल का क्लास रूम राज्य देखेगा या केन्द्र देखेगा?

श्री राजेश रंजन **:** सर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ । मैं केन्द्र पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ । मेरा कहना यह है कि बिहार या देश की जो सरकारी स्थिति है, आपको भी पता होगा कि बिहार से पढ़ने के लिए बच्चे सबसे ज्यादा कोटा में जाते हैं और कोटा में पिछले साल लगभग 600 से 700 बच्चे किस तरह डिप्रेशन के चलते आत्महत्या किए हैं, आपसे कोई चीज छिपी नहीं है । आप वहां पर गार्जियन बनकर जाते हैं । मैंने कई बार सभी संस्थाओं के चेयरमैन्स से बात की है । वे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं । मेरा सबमिशन इस बात को लेकर है कि बिहार के बंटवारे के बाद न तो एक भी नेतरहाट विद्यालय खुला, न सैनिक स्कूल खुला, न केन्द्रीय विश्वविद्यालय को तवज्जो मिली, न जमीन मिली, न नवोदय विद्यालय पर फोकस किया गया, न सेन्ट्रल स्कूल पर फोकस किया गया, न पंचायत में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों पर फोकस किया गया ।

**19.00 hrs**

हम ने पटना यूनिवर्सिटी को केन्द्रीय यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी । भारत सरकार के द्वारा एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय मोतीहारी में खुला है ।

शिक्षा मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि हर परिस्थिति में वहां के विश्वविद्यालय के वीसी के कदाचार की जांच होनी चाहिए, जो मातिहारी में है । मैं पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्व विद्यालय बनाने के लिए आपसे आग्रह करता हूं । पूर्णिया, कोसी, सीमांचल की दूसरी उपराजधानी है । ? (व्यवधान) क्या आप केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूर्णिया कॉलेज को देखेंगे?

दूसरा, आपको सरकारी कॉलेज में डीएलएड और बीएड को खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है । हम यह सुविधा और कस्बों में भी चाहते हैं । हम रूपौली में इंटर कॉलेज चाहते हैं । हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज सबसे कम हैं । मैं इनके लिए आपसे आग्रह करता हूं । मैं आपसे आंगनवाड़ी के बारे में कहना चाहता हूं । आंगनवाड़ी के लिए एक सोच बन गई है कि यहां अत्यंत पिछड़ा, दलित और आदिवासी आते हैं और खिचड़ी खा कर चले जाते हैं । आंगनवाड़ी की सेविका की न कोई क्वालिटी है, न कोई क्वांटिटी है, न ही उनकी तनख्वाह बढ़ती है और न ही वहां बच्चों के आने के लिए कोई सुविधा है ।

मेरा आपसे यह आग्रह है कि कॉलेजेज के बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जाते हैं । बच्चे क्लास से चले जाते हैं । स्कूल्स के 80 प्रतिशत बच्चे खिचड़ी खाने के बाद चले जाते हैं । वे नहीं पढ़ते हैं । कॉलेज के बच्चे नहीं पढ़ते हैं । वे कोचिंग में चले जाते हैं ।?(व्यवधान) डीपीएस के बारे में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि डीपीएस बहुत ज्यादा पैसा लेता है, उस पर रोक लगाई जाए । डीपीएस के संस्थापक लगातार गलत कर रहे हैं ।?(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम्स होते हैं । उन एग्जाम्स के तीन-चार महीने के बाद रिजल्ट्स क्यों आते हैं? बच्चे के मन में डर है कि हमारे रिजल्ट्स के साथ हेरा-फेरी होती है । यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या किसी अन्य कॉम्पीटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म्स भरे जाएं, उनके एग्जाम्स हों और 15 दिनों के अंदर उनके रिजल्ट्स निकाले जाएं और उनकी ज्वाइंनिंग की व्यवस्था की जाए ।?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, घड़ी देखिए और बोलिए । अगर आपको दो मिनट से ज्यादा बोलना है तो बैठ जाइए । अगर आपको दो मिनट में भाषण समाप्त करना है, तो बोलिए ।

श्री गोडम नागेश **(**आदिलाबाद**):** सर, मैं दो मिनट ही बोलूंगा ।

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय सदस्य, जब कभी भी आपको कह दिया जाए कि समय समाप्त हो, तो एक बार इशारा समझ जाएं । आप एक दल के सदस्य हैं, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप रोज बोलें । यह अधिकार सभापति जी का है, जो सीट पर बैठे हैं । आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री गोडम नागेश **:** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर हो रही चर्चा पर बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं आपके द्वारा यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जी को धन्यवाद देता हूं । मैं बोलने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी आपने मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया है । मैं तेलंगाना आदिलाबाद से चुन कर यहां आया हूं । मेरे संसदीय क्षेत्र के दक्षिण भाग में मां सरस्वती जी की मंदिर है । यह दक्षिण में कहीं पर भी नहीं है । उत्तर भारत में यह एक है । मैं उस क्षेत्र से चुन कर आया हूं । जो वक्ता सवेरे से बोल रहे थे, मैं उनकी बातें सुन रहा था कि शिक्षा का विषय कंरैंट लिस्ट में आता है ।

आप सभी यह जानते हैं । यहां पर केवल केन्द्र सरकार की रिस्पोंसिबिलिटी है, ऐसी कुछ बात आ चुकी है । मेरे पास जहां तक इनफॉर्मेशन है और यदि मैं गलत नहीं हूं, तो सेंट्रल स्कूल्स में केवल 0.7 परसेंट स्टूडेंट्स विद्या प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बना और तब से अब तक कितने साल बीत गए हैं । इस देश में एक अच्छी एजुकेशन नीति हो, उसके जरिये विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा मिले । देश के चार करोड़ युवाओं को सक्षम बनाने का यह बजट है । जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैंने वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 का बजट देखा है, इन 10 सालों के अंदर बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यह सब जानते हैं । जो उच्चतर शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को राज्य देखता है । उच्चतर शिक्षा में सरकार को जो काम करना है, वह सरकार काम कर रही है । प्राथमिक स्तर पर जो वैकेंसीज़ हैं, टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं, वे बहुत सारे राज्यों में रिक्त हैं । उच्चतर शिक्षा में भी ज्यादा वैकेंसीज़ हैं । उन वैकेंसीज़ की भर्ती के लिए आप राज्यों को आदेश दें । मैंने पहले ही कहा कि 0.7 परसेंट विद्यार्थी ही सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ते हैं

। सर्वशिक्षा अभियान में एडिशनल क्लास रूम्स के लिए पैसा दिया जाता है और शौचालय निर्माण के लिए पैसा दिया जाता है । रूरल एरिया में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में शौचालय की सुविधा नहीं है और एडिशनल क्लास रूम्स की भी सुविधा नहीं है । क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, सर्वशिक्षा अभियान में स्टेट्स को जो राशि जाती है, वे भी बराबर खर्च नहीं करते हैं । उसके यूसीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को न भेजने से यहां से और पैसा नहीं जा सकता है । वहां से यूसीज़ आने के बाद ही पैसा रिलीज होता है । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि राज्यों को हम जो पैसा दे रहे हैं, राज्यों की यह रिस्पोंसबिलिटी है कि वहां पर वे शौचालयों का निर्माण करें, एडिशनल क्लास रूम्स का निर्माण करें । देश में ओडीएफ का निर्माण हो रहा है और यह काम हम सब को साथ में करने की जरूरत है । मैं अब तेलंगाना प्रांत के लिए बात करूंगा । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अभी तक आप क्या बात कर रहे थे?

श्री गोडम नागेश **:** सर, इसी सदन ने वर्ष 2014 में सेपरेट तेलंगाना का बिल पास किया था और तेलगांना हमें दिया । तेलंगाना बनने के बाद हमारे तेलंगाना राज्य में पहले 10 जिले थे और अभी 33 जिले हो गए हैं । सर, वहां नवोदय स्कूल्स और केन्द्रीय विद्यालय की बहुत डिमांड है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि तेलंगाना के अधिक जिलों के लिए?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप अपने लोक सभा क्षेत्र के लिए मांग कीजिए न, आप पूरे तेलंगाना की बात कर रहे हैं ।

श्री गोडम नागेश **:** सर, मैं तेलंगाना के बाद अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आ रहा हूँ ।?(व्यवधान) जिस तरह से, तेलंगाना के लिए दिया गया है, वैसे मैं पिछले सप्ताह मंत्री जी से मिल चुका हूँ । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** पहले आपने देश की बात की, फिर राज्य की बात की । अब आप अपने लोक सभा क्षेत्र की बात कीजिए ।

श्री गोडम नागेश **:** जी सर । मैं अभी-अभी मंत्री महोदय से मिला हूँ । मेरे आदिलाबाद संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं । वहाँ पर एक ही नवोदय विद्यालय है, केन्द्रीय विद्यालय भी एक ही है । वहाँ एससी, एसटी की पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है । यह लिट्रेसी में भी कम है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र आदिलाबाद में एक और नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय मंजूर करें ।

इसी के साथ मैंअपनी बात समाप्त करता हूँ ।

**SHRI K. RAJASHEKAR BASAVARAJ HITNAL (KOPPAL):** Hon?ble Speaker Sir thank you very much for allowing me to participate in the discussion on Demands for Grants on the Ministry of Education.

Sir through you I would also like to thank my people of Koppala Lok Sabha constituency. Hon?ble Speaker Sir the government has neglected completely the education sector. It has no vision for education. In this budget 9 priority Areas were mention but there is no place for education in it. During UPA Government education was considered as fundamental right to Education Act (RTE). In RTE Act itself the UPA government has mentioned what are the basic Infrastructures

required for providing better quality education. However now the Government of India as conducted survey about the implementation of RTE. The compliance report mentioned that only 25% schools are having required infrastructure. Remaining 75 percentage of schools do not have basic facilities it shows the government has failed to give the basic intrastructure facilities to the schools. It is mentioned in the Government of India report itself.

Sir, the Union Government is talking about Vikasit Bharath. Our first Prime Minister Pandit Jawaharalal Nehru ji said that Student of today is the Citizen of tomorrow. If we want to build a better India, today we should give quality education. However, today the government is not able to give even basic facilities of education. There is no job guarantee for the students once they come out of colleges and universities. Another point is that the government is talking about giving education loan for students. Today, if students take loan to complete their education. If they do not get a job in the future, they will not be able to make repayment of it. So both students and their family would be suffered due to education loan.

Honble Speaker, Sir, they should also give a guarantee to get jobs.I would urge upon the Union government through you to take steps to fill the 75% gap by ensuring basic infrastructure in all schools.With these few words I conclude my speech and thank you Sir.

**डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा में शामिल होने एवं इसके समर्थन में अपनी बात कहने का मौका दिया ।

महोदय, फिर एक बार मोदी सरकार, अब होगा विकसित भारत का सपना साकार । इस भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं । तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस भूमिका में हैं । इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनकी नीतियों को भी जनता-जनार्दन ने ताकत दी है । यह लगातार जारी है । पॉलिसी पैरालिसिस की जो स्थिति थी, हम उससे बाहर निकले हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप जो काम हुए हैं, उनकी एक संक्षिप्त रूपरेखा और प्रभाव को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 में एसडीजी 61 परसेंट पर पहुंचा है । इसके साथ पीएम?श्री स्कूलों की संख्या का 14,500 तक पहुंचने का लक्ष्य है । इसमें से 10,080 स्कूल्स स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 30 स्कूल्स मेरे लोक सभा क्षेत्र के हैं । यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कौशल विकास और वैश्विक आयाम में युवाओं को तैयार करने के लिए है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार है । इसके तहत महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हम अपने नायकों की बात करें । इतिहास के जो प्रेरक प्रसंग हैं, वे भी हमें नई शिक्षा नीति में मिले हैं । इसकी भी यदा-कदा चर्चा होने लगी है । यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीपीएल के मामले में कहूंगा कि करीब 25 करोड़ आम जन उससे बाहर निकले हैं । उसके जो 12 इंडेक्स हैं, उनमें से एक इंडेक्स शिक्षा विभाग का है । यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है । इसका सबसे ज्यादा लाभ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिला है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल्स हैं, वे भी इस नीति के ही एक भाग हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में 750 स्कूल्स स्थापित होने जा रहे हैं । उनमें से 405 स्कूल्स क्रियाशील हुए हैं । इससे बहुत बड़ी संख्या में, 1,23,000 जनजातीय बालकों को लाभ मिला है । इसमें बड़ी संख्या में, आधे से ज्यादा प्रतिशत बालिकाओं का है । यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां शिक्षा की बात हो रही है और पूरा अमृत कालखंड शुरू हुआ है । जो औपनिवेशिक विरासत है, उससे भी बाहर निकलना है । मैं यह आग्रह करता हूं कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनमें जनजातीय अध्ययन केंद्र शुरू होने चाहिए, ताकि जनजातियों की जो मौलिक बात है, जो मौलिक संस्कृति है, वह सबके सामने आ सके । क्योंकि, अभी तक औपनिवेशिक सत्ता की, जो डिवाइड-एंड-रूल वाली विचार-दृष्टि है, वही पढ़ाई जाती रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर पर डॉ. जी. एस. घुर्ये यह कहते हैं कि आदिवासी हिंदू हैं । यह शब्द भी सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक की सरकारों द्वारा इसे निगलेक्ट किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, anthropology एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसे पूरे देश में विभेद करने के लिए, जनजातीयों के बारे में अलग से anthropology में पढ़ाने के लिए कहा गया है । शेष समाज के बारे में sociology में पढ़ाया जाता है, जबकि anthropology में केवल जनजातियों की पढ़ाई की जाती है । Anthropology आने वाले कालखंड में समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि यह औपनिवेशिक सत्ता द्वारा जनजातियों को अलग दिखाने की एक साजिश रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करता हूं, क्योंकि अमरकंटक और तेलंगाना के जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, वे काफी दूर हैं । वे लगभग 1,500 किलोमीटर दूर हैं । अगर यह राजस्थान में स्थापित होता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों के जनजातीय क्षेत्र की लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक में सीएसआर का सबसे कम प्रयोग हुआ है । ऐसा इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट दिखाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में वेदांता जिंक का काम करने वाला एक बड़ा माइनिंग इंटरप्राइजेज़ है, जिसमें भारत सरकार का भी भाग है । सीएसआर के तहत इस क्षेत्र में माइनिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की संभावना बनती है, क्योंकि अरावली का पूरा क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कीमती मिनरल्स मिलते हैं ।

इसके साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जब हम पूरे भारत में देखते हैं, तो पाते हैं कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है । गौ, गंगा और गायत्री पूरे भारत के लिए अपने आप में गौरव की बात है । अत: गौ विश्वविद्यालय मेवाड़ में स्थापित करने की यदि आप अनुमति दिलवाएंगे, तो हमारे गोगुंदा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1,000 बीघा गौचर भूमि भी है, जिसे देने के लिए ग्राम पंचायत और आसपास के सभी क्षेत्र तैयार हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी और इसके लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

प्रणाम ।

**SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI):** I express my strong support for the Demand for Grants for education. This education budget for 2024-25, with its allocation of Rs 1,20,628 crore to the Ministry of Education, is a testament to the hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji's commitment to shaping India's future through knowledge and skill development and marching towards a Vikashit Bharat.

At the heart of this budget is a clear focus on strengthening our education system from its very foundation. The allocation of Rs 73,008 crore for school education underscores this commitment. Within this, the Samagra Shiksha Abhiyaan stands out with its enhanced allocation of Rs 37,010 crorea 14% increase from last year. This flagship scheme, constituting 51% of the school education budget, will be instrumental in implementing the National Education Policy and bridging social and gender gaps in education.

Building upon this foundation, the government has demonstrated its dedication to student welfare through the PM POSHAN scheme. With a 25% increase in allocation, now at Rs 12,467 crore, this initiative will nourish the minds and bodies of 11.8 crore students across 11.2 lakh schools. This investment in our children's health is an investment in a more productive, healthier generation.

Taking school education to new heights, the PM Schools for Rising India (PM- SHRI) scheme has seen its allocation more than double to Rs 6,050 crore a remarkable 116% increase. This visionary program will upgrade 14,500 schools, aligning our education system with the NEP's goals and local entrepreneurial needs. It represents a significant step towards modernizing our school infrastructure and curriculum.

As we move up the education ladder, the budget's focus on higher education is equally impressive. The 29% increase in funding for Central Universities, taking it to

Rs 15,928 crore, coupled with substantial allocations to IITs (Rs 10,325 crore) and NITs and IIEST (Rs 5,040 crore), reflects the government's commitment to enhancing the quality of tertiary and technical education in India.

To make this quality education accessible to all, an innovative 3% interest subvention on education loans up to Rs 10 lakh has been introduced. This measure, supporting one lakh students annually, will open doors for countless aspiring scholars who might otherwise struggle to finance their higher education.

Looking to the future, the initiative to create digital public infrastructure for the education sector is a progressive step that aligns perfectly with our digital India vision. This forward-thinking approach will undoubtedly boost productivity and innovation in our education system.

While I wholeheartedly support this visionary education budget, I would like to bring to your attention some specific needs of my constituency, Pali, which 1 believe align well with the government's commitment to enhancing education across India.

Firstly, I humbly request the establishment of a new Kendriya Vidyalaya in Bilara, Jodhpur. Currently, the Pali Constituency is served by only two Kendriya Vidyalayas one in Tinvari, Osian, and another in Pali. The addition of a Kendriya Vidyalaya in Bilara would significantly enhance educational opportunities for the youth in this area, aligning with our government's goal of providing quality education to all.

Secondly, I would like to draw your attention to the Kendriya Vidyalaya in Pali. While it is 80 percent complete and classes are ongoing, there is a pressing need for its upgradation. Specifically, expanding its offerings from 10th class to 12th class would cater to a larger number of high school students in the region. This expansion would provide continuity in education and prevent students from having to seek alternatives in distant places for their higher secondary education.

Lastly, I propose that both existing Kendriya Vidyalayas in Pali and Tinvari be considered for upgradation under the PM Schools for Rising India (PM-SHRI) scheme. As this scheme aims to develop schools that will become exemplary in implementing NEP 2020 and showcase all its key aspects, upgrading these schools would not only benefit the students of Pali Constituency but also serve as models of excellence for the entire region.

These measures, if implemented, would significantly enhance the educational landscape of the Pali Constituency, aligning perfectly with the government's vision of providing quality education.

In conclusion, this education budget is a comprehensive and far-sighted investment in India's future. From strengthening the foundations of school education to enhancing higher education and leveraging technology, it reflects the government's holistic approach to creating a knowledge-based society. I wholeheartedly support this Demand for Grants and commend the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the diligent efforts of our Education Minister in crafting this transformative allocation.

श्री खगेन मुर्मु **(**माल्दहा उत्तर**) :** मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान जी का ध्यान G.K.CIET कॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र माल्दहा उत्तर में स्थापित है ।

G.K. CIET की स्थापना वहा के स्थानीय स्कूल छूट (School Dropout), बेरोजगार युवक युवती और ग्रामीण महिलाओं को Skill Development और Technical शिक्षा देकर रोजगार का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था लेकिन वह कॉलेज आज एक साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर रह गई है । इस पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है ।

स्नातक और ITI स्तर के कुछ पाठ्यक्रम जिसमे रोजगार के अनेक संभावनाएं है, उन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की जरुरत है जैसे Agriculture Engineering, Automobile Engineering, Interior Design, Computer Hardware & Networking, Diesel Mechanic, Air Condition and Refrigerator Repairing, Sericulture & Waiving Technology, Repair & Maintenance of Electrical & Electronic Gadgets आदि ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र माल्दहा उत्तर में 50 प्रतिशत आबादी संख्या लघु और 30 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाती और जनजाति से हैं और यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और रोजगार के दृष्टि से अति पिछड़े हुए क्षेत्र में से एक है ।

मैं शिक्षा मंत्री से G.K.CIET के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने का अनुरोध करता हूं ।

मेरे लोक सभा क्षेत्र माल्दहा उत्तर के लगभग ९०% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और संख्या लघु संप्रदाय से आते है और यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और उन्नयन के दृष्टिकोण से देश के पिछड़े क्षेत्रों में से एक है । इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं में उन्नति हेतु निम्नलिखित कदम उठए जाने की आवश्यकता है:-

- केंद्रीय विद्यालय की स्थापना,

- नवोदय विद्यालय की स्थापना,

- सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग संस्थानों की स्थापना ।

धन्यवाद ।

**SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE):** I would like to present my views on the Demand for the Grants in the Ministry of Education In 2024-25, the Union Government has allocated Rs 1,20,628 crore for Education, out of that School Education gets Rs. 73,008 crores and Higher Education Rs. 47,620 crores.

But the Government of Tamil Nadu in its State budget 2024-25, has allocated Rs. 52,253 crores for Education, out of which 44,042 crores for School Education and Rs 8,212 for Higher Education.

Tamil Nadu for its population of 8 crores is spending Rs. 52,000 crores for Education. Uttar Pradesh for its huge population of 24 crores has allocated Rs 84,000 crore Karnataka for its 7 crore population has allocated Rs. 40,945 crores, Maharashtra with a population of 13 crores has allocated Rs. 96,000 crores for Education. It is very obvious that the funds allocated by the union government for education very low comparing to the total spending by all the states put together. Even for establishing some Kendriya Vidyalayas the State governments allocate sufficient land through the District administration. But the Union Government enjoys maximum dominance and weild its power to infringe upon the federal rights of the States in Education through its Regulatory bodies like the UGC, AICTE, NCTE, NCERT, CBSE, It is very sad, undemocratic and unwarranted intrusion sir. The recommended government spending on education to be at least 6% of GDP. But the union government is lacking way behind in this regard. The Department of School Education funds for the Samagra Shiksha Abhiyan and PM-POSHAN schemes. The Madhyamik and Uchchatar Shiksha Kosh (MUSK) is a non-lapsable fund in which proceeds of secondary and higher education cess are credited.

Only two glittering announcements are made in the budget on education,

1) Interest subvention of 3% annually will be given for education loans up to Rs 10 lakh One lakh students will be supported every year.

2) Creation of Digital public infrastructure for the education sector to improve productivity and encourage innovation.

Our great poet Thiruvalluvar has written a separate Chapter containing 10 couplets about the importance of Good Education 2000 years ago.

"Kedil Vizhuchelvam Kalvi Oruvarkku

Maadalla Matrai Yavai"

-(Thirukkural 400)

"The wealth which can never decline is not riches but learning" (Thirukkural-400)

Tamil Nadu pioneers in higher education catering to the aspirations of the youth being locally appropriate and context- specific while also being globally relevant to the needs of all sections of the society in terms of access and equity thereby fostering inclusivity reaching to the marginalized and disadvantaged sections to evince an overall development of the people. The Education is greatest power in the world. The greatest tool for transformation and progress. Even kings considered educated people and learned philosophers a step ahead of them, Learned will be well respected and received wherever they go. Our Tamil poem reveals this,

"Mannanu Maasarak Katronukku Seerthookin

Mannanir Katron Sirappudaiyan;

Mannarkku than Desamallaar Sirappillai;

Katronukku Senra Idamellaam Sirappu.

-Moodhurai (26)

Tamil Nadu State Educational policy propounded by our Thanthai Periyar, Perarignar Anna Muthamil Arignar Dr. Kalaignar who have propelled a revolution in Education, Employment and Efficiency. The basic principles of Dravidian model government Equality, Social Justice, Women Liberation and Welfare Economy. Our Hon'ble chief minister Thalapathy MK Stalin's determined policies and dedication and will power to serve the people. As mentioned by our Hon.Chief Minister of Tamil Nadu Thalapathy Shri M.K. Stalin, "Dravidian model of Governance is that the society or economic condition or the political situation cannot be an obstacle for the students in pursuing their education".

One of the standing testimony to supremacy of Tamil Nadu in Education is that there are more than 1000 Technical Institutions in Tamil Nadu and includes 520 Engineering Colleges and 502 Polytechnic Colleges in Tamil Nadu, In my Vellore Parliamentary constituency there are several outstanding and world renowned

institutions which serve for the development of education in the country. The Gross Enrolment Ratio of Tamil Nadu in Higher Education stands first in India as per the data in All India Survey on Higher Education (AISHE). This is almost double the National average. In Tamil Nadu, Six State Universities are in Top 100 in Overall Category while Eight State Universities are in Top 100 in Universities Category. Six State Universities have secured A++ in NAAC, 2 State Universities have secured A+ NAAC while 4 State Universities have secured A in NAAC among the 13 State Universities. Alagappa University is ranked among Category | Universities by MHRD. Four Government Arts and Science Colleges are in Top 100 with Presidency College in the 3rd position for the 3rd consecutive year. Three State Universities are in Top 50 Research Institutions Category viz., Anna University (13), Bharathiar University (38) and Alagappa University (43) Sir, we have been inculcating the Outcomes-based curriculum for development of cognitive skills viz. Knowledge, Skills & Attitude (KSA) that fosters critical thinking, reflection, project-based learning, problem solving to match local and global needs and standards.

"KaRkai Nanre, KaRkai nanre

Pichai pukinum KaRkai Nanre".

As per this proverb, education is so much important in life. But our government of Tamil Nadu under the dynamic leadership of Thalapathy MK Stalin has initiated several path breaking schemes and innovative inclusive policies for promoting education among the poor. One of the most powerful tools and popular schemes implemented in Tamil Nadu is the incentivizing of Rs. 1,000/- to girt students who pass out from Government and girl students studying in Tamil Medium in Aided Schools to pursue higher education through Pudhumal Penn monthly stipend scheme. Introduction of Tamil Pudhalvan monthly stipend scheme of providing Rs. 1,000/- for boys who pass out from Government Schools to pursue higher education from the current academic year (2024-25). Chief Minister Research Grant (CMRG) for faculty members engaged in frontier areas of research and Chief Minister Research Fellowship (CMRF) to encourage scholars pursue research programmes in their preferred areas of study. Placement drives enabled by Naan Mudhalvan means I am the winner, post implementation of industry-oriented skilling courses.

"Yennenba Enai Ezhuthenba Ivvirendum

Kannenba Vaazhum Uyirkku".

Saint Tiruvalluvar praises education through this couplet.

Government Polytechnic Colleges will be upgraded to industry 4.0 standards in collaboration with Industry Partners at a cost of Rs. 3,014 crore. The Government have been working on establishing industry-aligned research parks in Chennai, Madurai and Coimbatore in collaboration with TIDCO. Enhancing quality in education includes appropriate accreditation in place. Measures have been taken to persuade Higher Educational Institutions (HEIs) l to go for NAAC accreditation and participate in NIRF, Times Higher Education and QS rankings to upgrade on par with peers at the National and international levels.

In order to increase the enrolment in Polytechnic Colleges and help the polytechnic students to excel in their studies, Free test books are being distributed to all the first year Diploma students of Government Polytechnic Colleges from the academic year 2007-08 by Muthamilarignar Dr. Kataignar. Under this scheme, the books are being distributed at free cost in the subjects of English, Engineering Physics, Engineering Chemistry and Engineering Mathematics.

The issue of free bus pass scheme to all the diploma students studying in Government Polytechnic Colleges was introduced by the Government of Muthamil arignar Dr. Kalaignar from the academic year 2007-08 to facilitate students to reach the Institutions without any financial burden. The waiver of tuition fees for Diploma students studying in Government Polytechnic Colleges from the academic year 2008-09 by the Government of Muthamilarignar Dr. Kalaignar. The Government have sanctioned the stipend, Post Graduate Assistantship of Rs. 6,000/- per month to the 1200 Postgraduate students studying in Government Engineering Colleges. A nation's future is decided in it's classrooms. Its future is built up by the educational policies presented by the Government.

The First Generation Graduate Scholarship scheme was started by the Government of Muthamiarignar Dr. Kalaignar with the objective of promoting higher education among the families where no member is a graduate. The scholarship is given to the students irrespective of their caste and income. In the academic year 2023-24, Rs.380 crore have been given to 1,57,342 first graduate students of Engineering Colleges.

Internship Training to the students of Government Engineering (2,500 students) and Polytechnic Colleges (7,500 students) towards financial support at the rate of Rs.16.600/- per student for 25 days Internship Training to enhance the technical

skill of the students covering 10,000 students every year. "The Tamil Nadu Admission to Undergraduate professional courses on preferential basis to students of Government Schools Act, 2021" was enacted in order to take affirmative action to bring about equality between students studying in Government schools and private schools. The Hon'ble Chief Minister has announced that, the entire fees such as Tuition. Fee, Hostel Fee, Transportation Fee, etc. be borne by the Government for these students admitted under this seats.

In order to motivate Government school students to aspire to join premier Higher Education Institutions like Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science and All India Institute of Medical Sciences, the Government will bear the full cost of their undergraduate education. The entire fees for all the years, have been sanctioned to the students by the Government.

In order to encourage and motivate the economically weaker section meritorious students to pursue their engineering courses (B.E./B.Tech.) the Government provide financial assistance from Chief Minister's Public Relief Fund. The financial assistance of Rs. 50,000/- each has been given to 24 students during the academic year 2023-24.

Women friendly Diploma courses have been introduced from the academic year 2022-23 in the following Colleges with a view to increase the women enrolment in Polytechnic Colleges and also motivate them to take up Higher studies for better employment opportunities (1) Mechanical Engineering (CAD) in Central Polytechnic College at Chennai (2) Office Management and Computer Application in State Institute of Commerce Education at Chennai (3) ECG Technology in Government Polytechnic College at Coimbatore (4) Web Technologies in Tamil Nadu Polytechnic College at Madurai (5) Bio-Medical Electronics in Government Polytechnic College at Nagercoil and (6) Interior Decoration in Dr. Dharmambal Government Polytechnic College for Women, Chennai for providing intensive coaching for 500 students in 11 Government Engineering Colleges for competitive examinations CAT/GMAT/GRE and IELTS/TOEFL from the year 2021-22. The intensive coaching would not only enable to succeed in these competitive examinations, but to enhance their employment opportunities with reputed firms at the National and International level .

Entrepreneurship Development and Innovation Programmes in Polytechnic Colleges through 5 Hubs in collaboration with Entrepreneurship Development Innovative Institute (EDII), Chennai. 5 ED Hubs have been established in 5

Polytechnic Colleges. The programmes conducted under 5 ED Hubs were merged with Naan Mudhalvan Scheme from October 2023.

CHIEF MINISTER'S RESEARCH GRANT SCHEME in order to motivate faculties, Research scholars and under graduate and post graduate students to do research on current challenges, "Chief Minister?s Research Grant Scheme" have been Introduced from the academic year 2023-24 and the Government have sanctioned a sum of Rs.50.00 crore as recurring grant towards the allocation of funds for all Government Higher Educational institutions and Universities in Tamil Nadu. For the year 2023-24, 61 projects are identified in Technical Education domain and funds being released. in Collegiate Education domain, action is being taken to identify the projects.

**Establishment of world skill academy and smart manufacturing technology centres**

In order to provide skills and develop the students as per World skills in Electrical Installation, Industrial Controls, Industrial Automation, Building Automation, World Skill Academy, Smart Manufacturing Centres are being established in 6 Government Polytechnic Colleges at Chennai, Coimbatore, Dharmapuri, Mayiladuthurai, Tiruchirappalli and Thoothukudi in collaboration with Schneider Electric India Ltd and the financial assistance of Tamil Nadu Skill Development Corporation, Chennai at a cost of Rs.10.00 crore.

PUDHUMAI PEN THITTAM The assistance of Rs. 1,000/- per month is being issued to Higher Education Pursuing Girls students who studied in Government Schools from sixth to twelfth standard under "Pudhumal Pen Thittam of Social Welfare Department. 4,039 students from Government Polytechnic Colleges and 12,135 students from Government Engineering Colleges have been benefited during the academic year 2023-24.

During the year 2023-24 a total number of 2,71,710 Girl students who are pursuing their education in Arts and Science Colleges have benefitted. This scheme has now been extended to Girl students studying in Tamil Medium in Government Aided Schools also.

Naan Mudhalvan is an ambitious scheme which aims at imparting employment-oriented skillset to the youth. Identifying the aspirations in early stage and providing a strong base for their employment is the special aspect of this scheme. Under this scheme a total number of 8,67,947 students studying in the colleges

coming under the Directorate of Collegiate Education have been imparted skill training. In the job fairs conducted 63,665 students have participated and 15,753 students have been issued offer letters.

TAMIL PUTHALVAN THITTAM in order to increase the enrolment ratio of Girl students in Higher Education, "Pudhumal Penn Scheme" has been introduced and it has brought a remarkable change in women education. Likewise, from the year 2024-25 "Tamil Puthalvan Scheme" is to be implemented to encourage the Male students who have studied 6th to 12th in Government schools and pursuing their Higher Education Due to this, the enrolment ratio of Government school students will increase considerably 1,000/ per month will be awarded to the student. To implement this ambitious scheme it is proposed to allocate Rs. 360 crore during 2024-25.

NAAN MUTHALVAN SCHEME As per the direction of the Government of Tamil Nadu, the scheme is implemented to Impart industry relevant, employable and Entrepreneurial skills to the students. Under this scheme, In second semester English communication will be offered which is certified by the Cambridge University. Digital Skill will be provided in fourth semester certified by Microsoft, NSE etc. NASSCOM-SKILLSDA training course for the final year UG and PG students of Thiruvalluvar University was conducted. The mega placement was conducted in the year 2023 for the trained students. More than 3,000 students from this University were placed tis the reputed companies.

Tamil Nadu Science and Technology Centre has established Periyar Science and Technology Centre with M. Birla Planetarium in Chennai, Anna Science Centre Planetarium in Tiruchirappall, Dr.Kalaignar Karunanidhi District Science Centre in Vellore and Regional Science Centre in Coimbatore. Planetariums in Chennai and Tiruchirappelli are engaged in Astronomy education.

Tamil Nadu Science and Technology Centre, is implementing INSPIRE Award-MANAK from the year 2009 onwards (Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge) programme in Tamil Nadu. Implemented in coordination with Department of Science & Technology and National Innovation Foundation (NIF)-India. 83,987 students were honored with this award and cash awards worth Rs.47.77 crore were distributed.

SAKURA Exchange Programme Under the invitation of the Government of Japan, the students, who won Awards in the past INSPIRE Award - National Level

Exhibitions and Project Competitions held in New Delhi were taken to Japan to visit Research Institutions. So far, 16 students from Tamil Nadu have visited Japan under this programme through Tamil Nadu Science and Technology Centre.

"Tamil Nadu Unmanned Aerial Vehicles Corporation" in partnership with Madras Institute of Technology, Anna University has been established in order to cater the drone-based needs of various departments of Government of Tamil Nadu through drone-based solutions and services. The Tamil Nadu Unmanned Aerial Vehicles Corporation has been registered under the Companies Act as 100% Government owned private Itd company. The corporation apart from designing, manufacturing and trading in all types of drones will also provide a large number of drone-based services like agricultural pesticide spraying monitoring, mapping, surveillance, search and rescue, volumetric analysis for the user department.

Before I conclude, I would like to remind the people who designed the NEP-2020 is not suitable throughout the vast country like India. It may suits the Hindi heartland. But States like Tamil Nadu, Kerala are marching well ahead without the NEP. The success of any government lies in providing quality, purposeful education. Education, Application of that education in life, Living a useful life are the mantras for life in Tamil Nadu. I would urge the union Government to follow Tamil Nadu State Education Policy and the innovative, inclusive schemes to achieve the desired results throughout the Nation. We are defeated by not getting proper education. We are defeated by not utilizing our learning. Even if the wealth accumulated by us and by our forefathers may vanish, but our education will not leave us in distress. Our education will come along as a support for life always.

श्री जिया उर रहमान **(**सम्भल**) :** मैं आपका ध्यान शिक्षा से संबंधित समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं जिस लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं उसमें शिक्षा के साधन नहीं हैं । सम्भल लोक सभा में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है इसके कारण छात्रों को अच्छे शिक्षा नहीं मिल पा रही है । दूसरी ओर इस क्षेत्र में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है और छात्र-छात्राओं को इसकी वजह से उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है । जिस कारण यह शिक्षा के क्षेत्र में अधिक पिछड़ा होता जा रहा है । मेरे लोक सभा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय की हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही खराब है । मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में दलितों से भी पीछे है । दूसरी ओर केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ भी सौतेला व्यवहार कर रही है । केंद्र सरकार लगातार मुसलमानों का बजट कम कर रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चार सेंटर बंद होने की कगार पर है केंद्र सरकार द्वारा छात्रों की जो छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है जिसके कारण गरीब अल्पसंख्यक छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जिससे मुस्लिम समुदाय लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है । दूसरी ओर शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भर्ती न होना एक गंभीर विषय है सभी समस्याओं पर ध्यान देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और शिक्षा समितियां को इन पर विशेष ध्यान देना होगा ।

**SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR):** I would like to express my views on the Demand for Grants for Education. Education is the key to social, economic, and political transformation. A well- educated population equipped with the right knowledge and skills is essential for our development. Education empowers individuals, uplifts communities, and drives national progress. It is not just for individual advancement; it is a powerful tool for societal change. It builds a knowledgeable, skilled, and innovative workforce that propels our nation forward. Investing in education is investing in the future of our country. Ensuring that every child, regardless of their background, has the opportunity to succeed and contribute to society. Quality education has always been given high priority in India's development policies, but it requires significant financial resources.

This year's allocation for education marks a pivotal moment for India's education sector. The allocation has increased by 6.8%, demonstrating the government's commitment to advancing education. I would like to congratulate the Hon'ble Finance Minister, who has outlined a comprehensive plan, allocating Rs 1.48 lakh crore for education, employment, and skill development. This is indeed commendable. We are paving the way for a brighter, more educated future for all Indians. By investing in education, we are not just building schools and colleges; we are building the dreams and aspirations of millions of young minds. This investment in our most valuable resource our people will drive innovation, economic growth, and social harmony. It will equip our youth with the skills and knowledge needed to compete globally and lead our country towards a future of unprecedented achievements.

This Government has integrated financial support for education, robust internship opportunities, and a strong focus on skill development. This holistic approach ensures that every segment of our society can contribute to and benefit from India's evolving economic landscape. Students studying abroad, especially in Ukraine, Israel, the UK, Canada, and Australia, have faced major challenges recently. The Government's decision to offer education loans of Rs 10 lakh for pursuing higher studies in India is a commendable step. This initiative will encourage students to study in India, where they will have a conducive learning environment. It will reduce brain drain. Additionally, the 3% reduction in education loan interest will alleviate financial stress for students and allow them to focus more on their studies.

The Government is taking significant steps to enhance vocational training and focus on STEM education, knowing that these areas can propel India towards becoming a global knowledge hub. Collaborative efforts between the government, private sector, and educational institutions are crucial to achieving these ambitious goals.

We must also recognize the importance of digital literacy in today's world. As we advance towards a 'Digital India,' this government is working towards integrating technology into our educational framework. The development of digital infrastructure in schools and colleges, along with training for teachers to effectively use digital tools, will ensure that our students are well-prepared for the future. Equitable access to digital resources will bridge the gap between urban and rural education, providing every child with the opportunity to excel.

Our visionary leadership has been putting a thrust on education, understanding its critical role in shaping the future of our nation. Recognizing that education is the cornerstone of a prosperous society, our leaders are committed to ensuring that every child, regardless of their background, has access to high-quality education. This commitment is reflected in the increased allocation of resources towards building robust educational infrastructure, improving teaching methodologies, and integrating technology into classrooms. Together, let us build a nation where every individual has the opportunity to learn, grow, and contribute to our shared prosperity.

With that, I support the Demand for Grants for Education.

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी ।

शिक्षा मंत्री **(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा विभाग की इस चर्चा को सभागृह में सफलता के साथ चलने की अनुमति दी । डिमांड फॉर ग्रांट्स में एजुकेशन पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय करके आज सफल चर्चा हुई है । कुल 44 ऑनरेबल एमपीज़ ने इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, अपने विचार रखे । उन्होंने आलोचना की, समालोचना की, शायद यह अच्छी बात है । प्रजातंत्र में सभी प्रकार के विचारों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए । आपने इस चर्चा के लिए अनुमति दी ।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा ऐसा विषय है, जिसमें भारत में सभी परिवारों में इसका संपर्क है । आंगनवाड़ी हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से सोची गई बाल वाटिका की कल्पना हो या शहरों में प्ले स्कूल्स की कल्पना हो । उस आयु से लेकर हायर रिसर्च तक, अध्यक्ष जी, हायर रिसर्च क्यों? शिक्षा एक ऐसा विषय है, जिसमें व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बना रहता है, तो फायदा रहता है । इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं । भारत जैसे देश में, जिसका आधार ही शिक्षा है, अगर हमें भारत की सभ्यता का मूल्यांकन करना है कि इसकी क्या-क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहली खूबी कोई आएगी, तो वह भारत की शिक्षा व्यवस्था

आएगी । इसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परम्परा, भारत में नवाचार की एक निरन्तर प्रक्रिया जारी रही है । आज इस सदन में सभी मान्यवर सदस्यों ने उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए अपने-अपने प्रजातांत्रिक अधिकार को रखते हुए अपने विचार रखे हैं । मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं । विशेषकर हमें यह अच्छा लगा कि इस सदन में जो पहली बार चुनकर आए हैं, वे इस पक्ष से हों या उस पक्ष से हों, जो नए सदस्य आए हैं, मैं उनके विचार सुन रहा था, सभी के विचार आदरणीय हैं, सभी के विचार बड़े उच्च कोटि के हैं । मैं सभी को स्वीकार भी करता हूं । प्रतिपक्ष के कुछ नए सदस्यों ने अपना मत फ्रैंकली रखा । शायद उनको लगा हो कि हम उनको नापसंद करेंगे । मैं आपकी अनुमति से बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि सारे विचार में अच्छाई की आवश्यकता है । मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो समाज और देश के लिए अच्छा होगा, उसके लिए काम करेंगे ।

अध्यक्ष जी, पिछले दिनों 29 तारीख हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का 29 जुलाई, 2024 को हमने चौथा जन्म दिन मनाया है । सभी ने कहा कि 34 सालों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई है । हमारा सौभाग्य है कि इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है । इसके कई सारे फीचर्स हैं । यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है । यह भारत के नवनिर्माण के लिए, विश्व के नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं के समाधान का रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों का दायित्व बनता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसका अहम दार्शनिक तत्व है । सर्वसम्मति से आज देश उसे स्वीकार करता है । शायद संविधान सभा के बाद, इसको बहुत विचार-विमर्श करके लाया गया है । हमारा युवाओं का देश है, यह नेशन ऑफ यूथ है, शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है कि जितनी दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है, जिस समय हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कर रहे हैं ।

महोदय, मैं पहले एक-दो विषय क्लेरिफाई कर देता हूँ और हाउस को आश्वस्त करता हूँ कि पिछले दिनों में जितना वित्तीय प्रबंधन होता था, मैं एक तथ्य आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वर्ष 2013-14 में शिक्षा के ऊपर, हाँ यह बात सही है कि कोठारी कमीशन से लेकर अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6 प्रतिशत तक का शिक्षा के ऊपर खर्चा करते । इसे मैं भी स्वीकार करता हूँ और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ ।

महोदय, वर्ष 2013-14 में जीडीपी का 3.84 प्रतिशत खर्चा होता था । अभी तक का जो लेटेस्ट है, जीडीपी के खर्चे में राज्यों के खर्च को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होती है । जो अभी तक पब्लिक डोमेन में वर्ष 2020-21 का एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार के लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी दर 4.64 है । हम लगभग 6 प्रतिशत पहुँचेंगे, यह हमारा विश्वास है । जिस तरह से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से हम एक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से लेकर वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर हम शिक्षा पर ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाकर हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे । मैं मानता हूँ कि यह उस दिशा में शायद हमारा सही प्रयास है । मैं एक और तथ्य वर्ष 2013-14 का राज्य और केन्द्र दोनों के सारे बजट को मिलाकर आपके सामने इस पवित्र गृह में रखता हूँ ।

अध्यक्ष जी, उस समय 4.3 लाख करोड़ रुपये खर्च होता था, जो आज बढ़कर 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है । यह नेट ग्रोथ है । इसी साल शिक्षा बजट में 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है । रोजगार के विभिन्न आयामों में लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था की गई है । महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट

में केंद्र सरकार, राज्य भी अपना अलग खर्च करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार 4520 करोड़ रुपये, समूचा 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये की व्यय व्यवस्था इसी साल के बजट में हुई है । यदि मैं आंकड़ों के साथ इसे कंवर्ट करूं तो वर्ष 2013-14 में जितना खर्च होता था और इस साल जितना वित्तीय प्रबंधन हुआ है, उसमें 78 परसेंट की ग्रोथ हॉयर एजुकेशन में । स्कूल एजुकेशन में तब और आज की स्पेंडिंग में 40 परसेंट की ग्रोथ हुई है । इस साल का खर्च और पिछले साल की तुलना में स्कूली शिक्षा में 7 परसेंट और हॉयर एजुकेशन में 8 परसेंट की ग्रोथ हुई है । सदन में ओवेसी जी मौजूद नहीं हैं । वे कोट कर रहे थे कि हॉयर एजुकेशन में कम प्रबंधन हुआ है । ऐसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी सुधार लेते तो अच्छा होता ।

अध्यक्ष जी, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए इस बजट में भरपूर सोचा गया है । शिक्षा को एक्सेसेबल करना, शिक्षा इक्वीटेबल हो, शिक्षा एफोर्डेबल हो, शिक्षा क्वालिटेबल हो और शिक्षा एकाउंटेबिलिटी के साथ रहे, ये पांच पिल्लर शिक्षा व्यवस्था के लिए सोचे गए हैं । शिक्षा की एक्सेसेबिलिटी में एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । जब वर्ष 2013-14 में हम दायित्व में आए तब हमारे सामने यूनिवर्सिटीज की संख्या 760 थी, जिसमें आज के समय तक 54 परसेंट की ग्रोथ हुई है और यूनिवर्सिटीज की संख्या 1168 हो गई है । आज आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी आदि उच्च शिक्षण संस्थानों में काफी वृद्धि की गई है । मैं केवल उच्च शिक्षण संस्थानों की बात नहीं करूंगा । हमारे राजस्थान के मित्र बैठे हैं । वे आदिवासी शिक्षा के बारे में उल्लेख कर रहे थे । मैं एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी पीएम-जनमन स्कीम लाए । विशेषकर हमारे देश में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है । उनकी कुल मिलाकर संख्या कुछ लाख होगी । ये वोट को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ?सबका साथ, सबका विकास? की बात कहती है । हम जो कहते हैं, उसे करते हैं । मैं उसका एक उदाहरण दूंगा । आज पीएम-जनमन स्कीम में तय किया है कि 500 होस्टल्स उन जिलों में बनाए जाएंगे और इनमें से 119 होस्टल्स का काम शुरू हो गया है । यह आदिवासी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है । आज इक्विटी के बारे में चर्चा हुई । कई मित्रों ने विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा कि बच्चियों की संख्या घट रही है और यह संख्या बढ़नी चाहिए । मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । उच्च शिक्षा में वर्ष 2014-15 को बेस मानते हुए यदि हम वर्ष 2021-22 की तुलना करें तो आज जीआर में बच्चियों की शिक्षा के अंदर 32 परसेंट की ग्रोथ हुई है । इन दिनों में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है । हमें आज गौरवान्वित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए कि लड़कियों के पढ़ने में स्टेम एजुकेशन में यदि कहीं बच्चियों के ज्यादा पढ़ने की संख्या किसी देश में ज्यादा है तो वह देश भारत है और इन दिनों 43 परसेंट की ग्रोथ हुई है । एस.सी. स्टूडेंट्स में 44 प्रतिशत की राइज हुई है । उसमें से भी 51 प्रतिशत राइज एस.सी. गर्ल्स स्टूडेंट्स में हुई है । आज के दिनों में एस.सी. गर्ल्स स्टूडेंट्स का पढ़ना बढ़ा है । एस.टी. स्टूडेंट्स में 65 प्रतिशत की राइज हुई है और इन दिनों उसमें 80 प्रतिशत फीमेल स्टूडेंट्स बढ़े हैं । ओबीसी स्टूडेंट्स में 45 प्रतिशत की राइज हुई है और उसमें महिलाओं की संख्या 49 प्रतिशत बढ़ी है ।

अध्यक्ष जी, मैं इंस्टीट्युशन्स की बात कह रहा था । वर्ष 2013-14 में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईआईआईटी, आइज़र, आईआईएससी जैसी 115 संस्थाएं होती थीं । देश की आज़ादी के बाद सात दशकों में मात्र 115 इंस्टीट्युशन्स थे । प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उसमें लगभग 50 प्रतिशत की ग्रोथ हुई और 42 नए इंस्टीट्युशन्स खुले हैं और आज 157 इंस्टीट्युशन्स देश में काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष जी, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही । पहले स्कूल शिक्षा में बच्चों को, विशेषकर जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत होती थी । हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परामर्श के तहत इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप किया । आजकल आप देख रहे होंगे, सभी सभाओं में, सभी स्कूल्स की पढ़ाई में इंडियन साइन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गयी है । आज के दिनों में दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग 27 प्रतिशत स्कूलों तक हमारी कवरेज बढ़ चुकी है ।

अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र ओवैसी जी कह रहे थे कि बच्चियों की, विशेषकर मुस्लिम बच्चियों के पढ़ने की संख्या घटी है । पर, तथ्य तो ऐसे नहीं कह रहे हैं । मैं आपके सामने इस गृह में इससे संबंधित तथ्यों को रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष जी, ?यूडाइस?, जो स्कूली शिक्षा का आकलन करती है, उसकी रिपोर्ट के तहत, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो ट्रांजीशन होता है, वह क्लास-V से क्लास-VI में होता है । उस पर हम एक ट्रांजीशन रेट निकालते हैं । आज देश में स्टैण्डर्ड-V से स्टैण्डर्ड-VI जाने में नेशनल एवरेज 93.2 है और मुस्लिम बच्चों में यह रेट 89.3 है । यह लगभग नेशनल एवरेज के नजदीक है । अपर प्राइमरी से सेकण्डरी में जाने में यानी क्लास-VIII से क्लास-IX में जाने में नेशनल एवरेज 88.8 है और मुस्लिम स्टूडेंड्स में यह एवरेज 82.2 है । सेकण्डरी से हायर सेकण्डरी में जाने में नेशनल एवरेज 78.4 है और मुस्लिम स्टूडेंट्स में यह 70.4 है । मेरे मित्र ओवैसी जी बड़े विद्वान हैं । मेरे मित्र ओवैसी जी और बाकी कई मित्रों ने यह कहा । मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कीजिए ।

महोदय, एक नई माननीय सदस्य आई हैं - इकरा हसन । उनकी सोशल मीडिया में खूब चर्चा है, मैंने उसको देखा है । आज आदरणीय सदस्य के भाषण को भी मैंने सुना । आपकी अनुमति लेकर मैं एक लघु मंतव्य दूंगा । वे बहुत अच्छा बोलीं । मैं सोच रहा था कि जब वे मन से बोल रही थीं तो ठीक बोल रही थीं, लेकिन जब पार्टी वाली चीज़ आ जाती थी तो वे थोड़ा भ्रमित हो जाती थीं । लेकिन, उन्होंने अच्छा बोला, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं । अभी कहा गया कि मुस्लिम को आप ऐसे क्यों देखते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को उनके निर्णय के कारण एक सौभाग्य मिला । अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन वर्ष 1875 में हुआ था । इतने दिनों में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई तो इन दिनों हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नईमा खातून है । वे उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, उन्होंने साइकॉलोजी में पी.एच.डी. किया है । उसी जाने-माने प्रोफेसर को इसी सरकार के द्वारा, किसी खैरात के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर वहां नियुक्त किया गया । यह कहा जाता है कि आप आर.एस.एस. के लोगों को ले आते हैं । पर, ऐसा नहीं है । ये आर.एस.एस. की नहीं हैं । अगर योग्यता के आधार पर कोई मुस्लिम महिला आगे बढ़ती है, तो हम सभी को इस पर नाज़ होना चाहिए, गौरव होना चाहिए कि इस सरकार ने निष्पक्ष होकर काम किया है । हमारे मन में किसी से भेदभाव करने की भावना नहीं है, बल्कि यह आपका दृष्टिकोण है, डराने का, भय पैदा करने का आपका एक चश्मा है । इसमें आपका कोई उद्देश्य होगा, पर यह लम्बे समय तक चलने वाली चीज़ नहीं है ।? (व्यवधान)

जावेद भाई, आप हमारे प्रिय हैं, आप बैठिए ।? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, अभी देश में गुणात्मक शिक्षा सभी का दायित्व है । किसी सदस्य ने कहा कि आप छह साल के बच्चों को पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा? अध्यक्ष जी, पहले 10+2 का मॉडल था । दसवीं तक पढ़ेंगे, फिर 11 वीं और 12 वीं करेंगे । मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक

महत्वपूर्ण फैसला किया है । अब पैटर्न होगा ? 5+3+3+4 यानि यह 15 साल हो गया । पहले 12 साल होता था, अभी 15 साल हो गया । क्योंकि साइक्लॉजिस्ट ने और विशेषज्ञो ने यह कहा कि बच्चा आयु आठ तक पहुंचते-पहुंचते उसका मानसिक विकास 85 पर्सेंट पूर्ण हो जाता है । यानि अगर हम उसको क्लास थ्री में शिक्षा की वातावरण में नाच-गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अगर उनको कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ अनुशासन में जोड़ेंगे तो उनका मानसिक विकास अच्छा होगा । इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा की पालना करते हुए बाल वाटिका की कल्पना की है । बाल वाटिका ? 1, 2, 3 फिर आयु छह से क्लास वन शुरू होती है । सर, इसके कारण हमारे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पॉवर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है । यह काम देश में शुरू कर दिया गया है ।

पीएमश्री के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । पीएमश्री 14,500 स्कूल, 27,360 करोड़ रुपये के अंदर इसको आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उसमें तेज़ी लाई जाएगी ।

अध्यक्ष जी, इन दिनों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है । वर्ष 2013-14 में महिला टीचर्स की संख्या 38.25 लाख होती थी, यह आज लगभग 48.76 लाख हो गए हैं । कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक शिक्षकों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, तब तक ये सारी चीज़ें कैसे होंगी । इस सरकार ने 613 डायट जिलों में हैं, मौजमूदा शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डायट को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस करने के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था की गई है । ऐसे ही हायर एजुकेशन में शिक्षक की कैपेसिटी बढ़े । टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स बनें, उसके लिए मालवीय मिशन के नाम पर देश में 117 टीचर्स कैपेसिटी के लिए नया-नया सेंटर्स खोलेंगे । नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऍफ टीचर्स के लिए एसओपी निकालमा गया है ।

अध्यक्ष जी, आज के समय में टैक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा बन चुका है । पीएम ई-विद्या के तहत देश में डेडिकेट भाषा आधारित टीवी चैनल के माध्यम से दीक्षा, स्वयं, स्वयंप्रभा, समर्थ ऐसे टैक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को एकाउंटेबल कराया जा रहा है । यह सब मैं सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों के बारे में कह रहा हूँ ।

अध्यक्ष जी, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने अनेक नए-नए उपक्रम शुरू किए हैं । आज आवश्यकता है कि एनईपी के कुछ थ्रस्ट एरिया हैं । अगर मैं उसमें दो चीज़ों का उल्लेख करूं, हमारी शिक्षा को धीरे-धीरे डिग्री बेस्ड एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर ले कर जाना पड़ेगा । शिक्षा और तालीम दोनों परिपूरक हैं । शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, तालीम उतनी ही महत्वपूर्ण है । स्किल्ड नहीं होंगे तो आज के समय में जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, उसमें हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे । इसको ध्यान में रखते हुए छठवीं कक्षा से स्किल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को, एआई, रोबोटिक्स, वीआर, एआर, ब्लाकचेन, आदि इस प्रकार की शिक्षा से ले कर, जिसमें रोज़गार मिल पाएगा, एन्ट्रप्रेन्योरशिप बढ़ पाएगा, ऐसे स्किल्स के प्रमोशन की कल्पना की गई है ।

अध्यक्ष जी, अटल इनोवेशन मिशन इस सरकार की एक नई उपक्रम है । हमारे देश के बच्चों के अंदर इनोवेशन करने की इनहेरेंट कैपेसिटी है । यह उनके डीएनए में है । अगर भारत के बच्चा के हाथ में कुछ भी आए तो उसमें से कुछ बनाने की वह दक्षता रखता है । यह कई बार प्रमाणित हुआ है । इसको विशेष कर स्कूल एजुकेशन की फॉर्मल सिस्टम पर लाया जाएगा । आइसोलेशन में कुछ लैबोरेटरीज़ होते थे, उनको एक मिशन मोड पर अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से एक जन आंदोलन के रूप में स्कूल्स में लागू किया जा रहा है । उसमें मेंटर की व्यवस्था है । उसमें लोकल इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन है । नई शिक्षा नीति में इसकी भी एक कल्पना की गई है ।

अध्यक्ष जी, सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर थर्स्ट दिया है । हमारे देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया है । माननीय प्रधानमंत्री जी उसका स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं । हमारे देश में इंडस्ट्री, एकैडमी और पॉलिसी मेकर, इन तीनों लोगों की नेटवर्क ठीक से हो, इसलिए कल भी मैंने राज्य सभा में चर्चा करते हुए एक विशेष रखा । इस पर राज्य सभा ने रूचि लेकर चर्चा की । । समाज जीवन के अनेक प्रमुख लोगों को पढ़ाने की अपने एक दायित्व मानते हैं । उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पर लेकर आना है । टाइम बाउण्ड पीरियड के लिए लेकर आना है, अनुरोध करके लेकर आना है । इस सरकार की एक रणनीति बनानी है । हमने इस पर जोर दिया है ।

अध्यक्ष जी, शिक्षा को जैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है, वैसे ही शिक्षा को जड़ से जोड़ कर भी रखना पड़ेगा । इसे रूटेड करना पड़ेगा । इसका मूल लिंक भाषा होगा । मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा । अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष कर माननीय प्रधानमंत्री जी की आग्रह के कारण उनके वक्तव्यों को मैं उद्धृत करना चाहूंगा । हमारे देश में भाषा को लेकर कई प्रकार के विमर्श हुए हैं । मोदी जी की सरकार इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है । भारत के सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, चाहे वह तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, असमिया हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, हिन्दी हो, सिंधी हो, ? (व्यवधान)

ओवैसी जी, निश्चित रूप से इसमें उर्दू भी है । शेड्यूल्ड 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है । उसमें संथाली भी आती है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पष्ट मानना है कि बच्चा अगर क्लास फाइव तक अपनी ही मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होगी । वह क्लास 8 तक अपनी मातृभाषा में पढ़े तो और अच्छा है । लेकिन, वह क्लास 5 तक पढ़े तो यह उसकी एक प्रकार से प्रमुख सिफारिश है । मैं इस सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के बच्चों को वैश्विक नेतृत्व लेने के लिए यह जरूरी है । ग्लोबल लीडरशीप और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज्यादा बच्चे इनोवेटर बनेंगे । ज्यादा बच्चे वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, वे आन्त्रप्रिन्योर बनेंगे, तब जाकर हम एक सुपर पावर बन पाएंगे । इसीलिए, हमारी भाषा को महत्व देना इस शिक्षा नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है ।

महोदय, इन दिनों बहुत सारे लोकल लैंग्वेज के बारे में भारत सरकार ने प्राइमर बनाया है । आज तक भारत के 77 स्थानीय भाषा में, भारत सरकार की एनसीईआरटी ने प्राइमर्स बनाया है ।

अध्यक्ष जी, आज चाहे जेई हो, नीट हो, सीयूटी हो, आज ऐसे 13 स्थानीय भाषाओं में परीक्षा हो रही है । अभी हमारे कुछ मित्रों ने एक विषय उठाया है । शायद उनके विषय के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहा है । अभी बड़ी आक्रमकता के साथ उन्होंने ने कहा कि आप सभी चीजों को एक आइडियोलॉजिकल एंगल से देखते हैं ।

अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है । भारत के ज्ञान-परंपरा पर आधारित हमारी शिक्षा नीति बने । मैं इस सदन में एक विषय को फिर से उठाऊंगा, पहले भी कई बार दोहराया हूं, आज भी आपकी अनुमति से दोहराऊंगा । हम सभी लोगों को एक चीज को भूलना नहीं चाहिए । वर्ष 1835 में भारत में उस समय के प्रशासक जो शिक्षा देते हैं, मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या भाषण दिया था । उन्होंने कहा था कि भारत एक अद्भूत देश है । भारत को ऐसे नहीं जीता जा सकता है ।

भारत में कई सारी विषयों में मूलभूत धारणाएं कुछ अलग हैं । जब तक हम उसकी संस्कृति को मटियामेट नहीं करेंगे, जमीन तक लेकर नहीं आएंगे, तब तक भारत को जीतना संभव नहीं है । इसलिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमें नष्ट करना पड़ेगा, एक पाश्चात्य ढांचे को हमारे ऊपर थोपना चाहिए । ऐसा मैकाले की रिकमेंडेशन है । हमें 21 वीं सदी में भारतीयता के ऊपर, अगर अनुमति दें तो मेरी बहन कनिमोझी जी हास्य कर

रही हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि भारतीयता का अर्थ क्या है । तिरुक्कुरल को सभी भाषाओं में पढ़ाना मेरे लिए भारतीयता है, शायद आप उससे सहमत होंगी । तिरुवल्लुवर के साहित्य को देश भर में ले जाना शायद यह मेरे लिए भारतीयता है ।

माननीय अध्यक्ष **:** इससे तो वे खुश हो जाएंगी । दूसरी आपने बोल दी, तो नाराज हो जाएंगी ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान**:** अध्यक्ष जी, वास्तव में कोई भेद नहीं है । भेद राजनीतिक कारण से है ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** We are saying to make it a national book.

**SHRI DHARMENDRA PRADHAN:** We are doing that. Hon. Member, you must know we are exactly doing that.

मैं अभी श्री अरबिन्दो जी को कोट करना चाहता हूं । मेरे मित्र ओवैसी जी आ गए हैं, अच्छा लगा । ओवैसी जी के साथ रहने से थोड़ा अच्छा लगता है । श्री अरबिंदो शिक्षा के बारे में कहते हैं, श्री अरबिंदो जी को मैं कोट करता हूं ।

?Education should be in accordance with the needs of modern life but include the core ideals and methods by initiating education?.

अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? इसमें क्या ऑइडियोलॉजी है । अगर मैं तिरुक्कुरल की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुवर की बात करुं, अगर मैं श्री अरबिंदो की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, यह तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष **:** कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है न, विचाराधारा को लेकर चलते हैं न ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** भारत का संविधान आइडियोलॉजी है । दूसरी आइडियोलॉजी काम नहीं करेगी । संविधान आइडियोलॉजी है । मेरी आइडियोलॉजी इसमें क्या काम आएगी? मैं संविधान की ओथ ले रहा हूं । गोलवलकर की आइडियोलॉजी काम नहीं आएगी न । ?(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** निशिकांत जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

डॉ**.** निशिकान्त दुबे **:** सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के सामने जाती हैं और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इंप्लीमेंट करना उस सरकार का काम है, जो उस विचारधारा पर जीतकर आई है । ? (व्यवधान) हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं । संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आस्था है । ?(व्यवधान) संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है ।

माननीय अध्यक्ष **:** मंत्री जी जो विषय रख रहे थे, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे । लालजी वर्मा जी, क्या आप कुछ कहेंगे?

श्री लालजी वर्मा **(**अम्बेडकर नगर**) :** ? (व्यवधान) जो संविधान की भी विचारधारा है ।

माननीय अध्यक्ष **:** संविधान की विचारधारा की बात नहीं हो रही है । संविधान की विचारधारा तो एक ही है ।

श्री लालजी वर्मा **:** संविधान के अनुसार हम चलेंगे । संविधान की जो मूल भावना है, उसको हम विकृत नहीं करेंगे । वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष **:** कभी संसद ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए ।

डॉ**.** संबित पात्रा **:** अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सभी पार्टियां अपनी-अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती हैं । अपनी विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती हैं । जनता जनार्दन है । मैं इसका समर्थन करता हूं । इसके पीछे का मूल भाव है कि संविधान समुद्र है । वह महासमुद्र है, जिसमें सारी आइडियोलॉजीज़ आकर समाहित होती हैं । चाहे हमारी आइडियोलॉजी हो, चाहे उनकी आइडियोलॉजी हो, उनको अंततोगत्वा समाहित समुद्र में ही होना पड़ेगा ।

माननीय अध्यक्ष **:** दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है, जिसमें सभी जातियों, धर्मों और भाषाओं की मान्यता है । यह ताकत भारत के संविधान में है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** मैं आपको मौका दूंगा ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप क्या बोलना चाहती हैं? कनिमोझी जी, आप बोलिए ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** Sir, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before when the British came here. There was a time when all the communities were not allowed to be educated. So, we should not go back to that period ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: शिक्षा लेने का कहां अधिकार नहीं था?

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सब बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब देंगे ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI :** Please read Manusmriti ? (*Interruptions*) My grandmother was not allowed to go to the college ? (*Interruptions*) I am not talking about the Constitution ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: भारत के संविधान में धर्म और लिंग के आधार पर शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया है । तमिलनाडु में किया हो मुझे नहीं पता ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात पूरी कर लें । आपने कहा कि आपकी ग्रैंड मदर को विद्यालय जाने से रोका । सामाजिक रूप से अलग-अलग प्रदेशों में इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे । लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं । संसद संविधान से चलती है । संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार नहीं रहा, डिबेट में भी नहीं है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वर्ष 1952 से पहले हमने अंग्रेजों लड़ाई इसीलिए तो लड़ी है ।

**SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI:** Dr. Baba Saheb Ambedkar said that caste is not the division of labour; it is a division of labourers. We should remember that. I am not saying that today the House does not run as per the Constitution. But there were days when caste system was the rule of the land. We cannot go back to that period. Today, the Constitution upholds social justice.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री**;** तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**) :** अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बने हैं, संसार में भी बनते हैं । शासन संविधान के अनुसार चलता है ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान **:** अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिशाल भी खड़ी कर रहे हैं । शायद हाऊस इसीलिए है कि एक अच्छा विषय पर पक्ष और विपक्ष रहे, चर्चा हो । उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है । डेमोक्रेसी की यही शर्त है ।

माननीय अध्यक्ष: भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से आज 400 करोड़ रुपये से 48 लाख करोड़ रुपये के बजट तक बढ़े हैं ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान**:** अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूं । मेरी इच्छा है कि मैं तमिलनाडु की भाषा को पढ़ूं और समझूं, सभ्यता को और जानूं । इस संसद की जब नींव रखी गयी थी । माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था, आप भी उस समय मंच पर उपस्थित थे । प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है । भारत प्रजातंत्र की जननी है । भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु के तंजावुर में चौथी सदी में उन दिनों पंचायती व्यवस्था कैसी रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि या चुने हुए व्यक्ति कोई गड़बड़ी किया तो उसे निकालना कैसे है? उसका भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था । यह मेरी भारत की सभ्यता है । इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूं ।

दूसरी बात महिलाओं के बारे में कही गयी । मैं जिस प्रांत से आता हूं, वह मेरे महाप्रभु का प्रांत है । मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ हैं । महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्म पत्नी महालक्ष्मी हैं । पन्द्रहवीं सदी में महालक्ष्मी माँ की एक लोक कथा है । महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात-पांत की बात की । महालक्ष्मी जी को यह बात पसंद नहीं आयी । महालक्ष्मी किचन की इंचार्ज थी, उन्होंने घर छोड़ कर किचन बंद कर दिया तो उनको भूखों रहना पड़ा, फिर उन्होंने माफी मांगी । महाप्रभु ने अपनी धर्मपत्नी से माफी मांगा कि हमें माफ करो, हम जात-पांत की बात नहीं करेंगे । पन्द्रहवीं सदी की मेरे यहां के फिलॉस्फर बलराम दास जी ने लिखा है । मेरी सभ्यता में महिलाओं को महिमामंडन किया है । मैं अर्धनारीश्वर का पूजक हूं । यहां भगवान शिवजी की फोटो दिखायी गई

थी । सम्बित पात्रा ने याद दिलाया था । शिव भगवान के आधे पार्वती और आधे शिवजी हैं । इसका अर्थ है कि मेरी सभ्यता अर्धनारेश्वर की पूजा करती है । यही मेरी आइडियोलॉजी है । ? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** यह तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** आप किसी की मदद न करें ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान**:** माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा पर चर्चा करते हुए कहा गया ? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** क्या आप कांग्रेस से मिले हुए हैं? ? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान**:** देश के लिए मिले हैं । हम तो देश का विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं । ? (व्यवधान) आप आगे बढ़ो । इसकी चिंता मत करो । ? (व्यवधान) हम देश को आगे ले जाने के लिए हैं । ? (व्यवधान) आपके मन में द्वेष है, आपके मन में असहिष्णुता है । ? (व्यवधान) मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है । ? (व्यवधान) हम बिरादरी के लोग हैं । ? (व्यवधान) देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे ।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** औवेसी जी, आप बोलिए ।

? (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी **:** किसी ने कहा था ? लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** यही तो सदन है ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान**:** माननीय अध्यक्ष जी, उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की गई । लालजी वर्मा जी, देश के सामाजिक और न्याय आंदोलन के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको सालों से जानता हूं । हमारा व्यक्तिगत परिचय अभी हुआ है । मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं । वर्मा जी, कुछ विषयों में सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए । अध्यापक पद निरंतर खाली होते रहते हैं । रिटायर हो जाते हैं और फिर नए लोगों को भरना पड़ता है । इन दिनों में यानी पिछले दो सालों हमारी सरकार ने लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की है ।

मैं एक नीतिगत बात कहना चाहता हूं । मैं सदन के सामने सब सदस्यों से कहना चाहता हूं, सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं और गिनाते हैं कि एससी की इतनी पोस्ट खाली हैं, एसटी की इतनी पोस्ट खाली हैं, ओबीसी की इतनी पोस्ट खाली हैं । साहब, ये पोस्ट कब से खाली हैं? किसी माननीय सदस्य ने कहा, नॉट फाउंड स्यूटेबल कोटा लगा देते हैं । सर, इस व्यवस्था को बंद किसने किया? माननीय प्रधान मंत्री जी ने दायित्व लिया । देश प्रधान मंत्री जी वर्ष 2019 में कानून लाए ?The Central Education Institutions (Reservation in Teachers? Cadre) Act, 2019. इसमें पहली शर्त है कि नॉट फाउंड स्यूटेबल वाली व्यवस्था रहेगी ही नहीं ।

अगर कैंडीडेट नहीं मिलता है । ? (व्यवधान) लालजी वर्मा जी, मैंने आपको इतने आदर से कह रहा हूं, डेमोक्रेसी को थोड़ा तो प्रेम करिए । मैं आपकी सारी बात सुन लूंगा, मैं चर्चा करूंगा । पहले आप तथ्य को सुनिए ।

साहब, हमने इसे खाली रखा है । पिछले दिनों क्या होता था? एससी, एसटी, ओबीसी के नाम पर पोस्ट रहती थी, एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया, दो बार इंटरव्यू का नोटिस दिया और तीसरी बार नॉट फाउंड स्यूटेबल करके जनरल कैटेगिरी की पोस्ट भर देते थे । माननीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद इसे खाली रखा । हम इसे भरेंगे । पहले असस्टिेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी अनिवार्य थी । हमने पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म किया । यह सब रातोंरात नहीं होता है ।

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, पहले 15 परसेंट कोटा नीट यूजी में रहता था । रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान प्रदत्त है और कई सालों से है । लाल जी साहब, क्या इसमें ओबीसी विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा था? वर्ष 2021 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार देश में मेडिकल शिक्षा में 27 परसेंट आरक्षण रखा । ? (व्यवधान) ज्योति जी, मेरी बहन, आप चुप बैठ जाएं । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता वाली सरकार है । हम भाषण नहीं देते हैं । हम सामाजिक न्याय में एक परिवार के न्याय को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं । हम सामाजिक न्याय में दलित, वंचित, गरीब, महिला आदि लोगों का दायित्व लेने वाले लोग हैं । हमने इसे करके दिखाया है । ? (व्यवधान)

**20.00 hrs**

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, एक मिनट । माननीय सदस्यगण, यदि सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही मंत्री जी के रिप्लाई के बाद, जिनके लिस्टेड शून्यकाल निकले थे और नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक घंटे का समय दिया जाएगा । बाकी बचे शून्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा । अभी 9 बजे तक कार्यवाही बढ़ाई जाती है । निशिकांत जी, सबसे अंतिम में आपका ही जीरो आवर लेंगे ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान **:** अध्यक्ष जी, हमारे हाउस के वरिष्ठ सदस्य, सौगत दा अभी नहीं हैं । सौगत दा की आलोचना की एक शैली है । मैं उसको स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं । मैं ओडिशा का हूं, अगर मैं उनको नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? हम ओड़िया लोग उनको ठीक से पहचानते हैं कि वह कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, व्यक्ति को ऊंचा करते हैं, नीचा करते हैं, हम ओड़िया लोग सब जानते हैं । उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बरबाद करते हैं । दादा के राज्य में ही देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, जिसका नाम जादवपुर यूनिवर्सिटी था । भारत सरकार ने उसको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस की मान्यता दी । यह मान्यता मिलने से पूरे एक हजार करोड़ रुपये भारत सरकार से मिलते हैं । आपने क्यों मना किया लेने से? हमने तो कोई शर्त नहीं रखी थी । आपको योग्य माना । आपने क्यों नहीं लिया । पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक ग्रामीण इलाके के बच्चे की रैगिंग करने से उसकी जान जाने तक की नौबत आई । क्या कोलकाता की पुलिस उस कैंपस में घुस पाई? आप दुनिया को ज्ञान बांटते हैं । आपकी नाक के नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कभी आपने देखा? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी, आप उनको जवाब मत दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : यह तो अच्छा तरीका है । आप कुछ प्रश्न उठाएंगे, उनके उत्तर देने से आप कहेंगे कि धनमंडल में क्या हुआ? भारत सरकार विद्यार्थियों हेतु नए-नए उपक्रम ला रही है । एक भारत, श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम चालू हो रहा है । युवा संगम के नाम पर देश के हर-एक राज्य का विद्यार्थी, तमिलनाडु के विद्यार्थी जम्मू-कश्मीर जाते हैं । गुजरात के विद्यार्थी सिक्किम जाते हैं । राजस्थान के कुछ विद्यार्थी मेरे राज्य ओडिशा में आए थे । उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे मिला । एक लड़का उसमें था, जिसने जिंदगी में दरिया कभी नहीं देखा था, समंदर नहीं देखा था । ओडिशा के बच्चे जो राजस्थान आए थे, उन्होंने कहा कि हम इंतजार करते थे कि शाम कब होगी? हमारे यहां शाम साढ़े पांच बजे हो जाती है । सूर्यास्त साढ़े पांच-छ: बजे तक हो जाता है । साढ़े सात-आठ हो गए, लेकिन यहां शाम को सूर्यास्त नहीं हो रहा है । ऐसे अनुभव युवा संगम में हमारे देश के बच्चों को हमारे शिक्षा विभाग ने दिलवाए ।

सर, अब परीक्षा में तनाव घटे, यह हटे, यह सभी अभिभावकों की प्रायॉरिटी है । पिछले 5-6 सालों में निरंतर और कोई नहीं, एक गार्जियन, एक पिता, एक बड़े भाई के नाते, एक दादा के नाते देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा में बच्चों से गपशप करने के लिए आते हैं । उसमें भी कुछ लोगों को सहिष्णुता नहीं है । वे मजाक करते हैं । अगर घर के बड़े बच्चों से आदर से बात करें, तो क्या वे मजाक के पात्र होंगे? क्या यही हमारी सभ्यता है? जिनके संस्कार जैसे हैं, वे वैसी ही बात करेंगे । 10 वीं और 12 वीं के बोर्ड एग्जाम होते हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परामर्श दिया है कि बोर्ड एग्जाम को दो बार करें । वर्ष 2025-26 से इस देश में राज्य के सीबीएससी बोर्ड से हम अनुरोध करेंगे कि दो बोर्ड एग्जाम लेने के लिए एक मूल सर्वशिक्षा को सुधारें, यह मैं मानता हूं ।

अध्यक्ष जी, हमें 21 वीं सदी की चुनौतियों को समझना है । भारत युवाओं का देश है, भारत ज्ञान आधारित देश है । भारत की नियति में एक बड़ी अर्थनीति बनना तय है । भारत सिर्फ अपने लिए सोचने वाला देश नहीं है । विश्व बंधुत्व की कल्पना वाला देश भारत है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और इस बार का वित्तीय प्रबंधन उस दिशा में एक बड़ा कदम है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने सभी माननीय सदस्यों की आलोचना, परामर्श, समालोचना को स्थान दिया । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष**:** आज जापान के महामहिम स्पीकर आए थे । जब उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर है । इसलिए, आईआईटीयन, जो स्किल करने वाले हैं, हम अधिकतम बच्चों को जापान में और जापान के बाद भारत में कहीं न कहीं नौकरी देना चाहते हैं । इस तरह से भारत की ताकत बढ़ती जा रही है ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में मैं जितने देशों में गया हूं, उन दुनिया के देशों में भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनके इनोवेशन की क्षमता, उनका चिंतन और उनके विचार के कारण भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है । यह हमारी शिक्षा का महत्व है ।

श्री नीरज मौर्य **(**आंवला**) :** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । शिक्षा का इतना महत्व है, इसके बारे में अभी माननीय मंत्री जी ने सबको बताया । हम उत्तर प्रदेश से आते हैं । उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी ऐसे गाँव हैं, जहां पर स्कूल नहीं पहुंचे हैं । ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को देखकर, उनकी व्यवस्था कैसे सुधरेगी, उसके बारें में जरूर ध्यान दें । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष**:** ओके । माननीय सदस्यगण, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर श्री राजेश रंजन और श्री हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं । मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

<u>कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए</u>

माननीय अध्यक्ष **:** अब मैं शिक्षा मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है:

?कि कार्य-सूची के दूसरे स्तम्भ के मांग संख्या 25 और 26 के सामने प्रविष्ट मांगों के शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों के भुगतान करने के निमित्त अथवा के उद्देश्य से, संबंधित धनराशियां, जो कार्य-सूची के तीसरे स्तंभ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा की रकमों से अधिक न हों, भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को लेखे पर प्रदान की जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

_____